बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 149

लचीले राजकोषीय लक्ष्य की सीमाएं

राजकोषीय मजबूती को लेकर केंद्र सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का वित्तीय बाजारों और अर्थशास्त्रियों ने स्वागत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश सालाना बजट में ऐलान किया है कि सरकार मौजूदा वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 फीसदी तक रखने का लक्ष्य रखेगी, जबकि अंतरिम बजट में इसके 5.1 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया गया था। यही नहीं, सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक सीमित रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है, यह एक ऐसा लक्ष्य है जो तब तो काफी मुश्किल लग रहा था जब साल 2021 में पहली बार इसका ऐलान किया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में सरकार के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह 2025-26 से आगे का भी खाका पेश करेगी।

वैसे तो सरकार ने 2025-26 के बाद अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की एक व्यापक रूपरेखा पेश की है, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा स्पष्टता की दरकार है। इससे निवेशकों, खास तौर पर लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था, '2026-27 के बाद हमारी यह कोशिश रहेगी कि हर साल राजकोषीय घाटे को इस स्तर तक रखा जाए जिससे जीडीपी के प्रतिशत हिस्से के रूप में केंद्र सरकार का कर्ज घटता रहे।'

बजट के बाद मीडिया से संवाद में वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने यह संकेत दिया कि राजकोषीय घाटा, जिसे कि कर्ज को नीचे की ओर ले जाते हुए सहारा दिया जा सकता है, जीडीपी के 3 फीसदी से ज्यादा रखा जा सकता है, जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में प्रावधान किया गया है। यह भी संकेत दिया गया कि सरकार सालाना निश्चित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की जगह लक्ष्य का एक दायरा तय कर सकती है।

इस संदर्भ में तीन ऐसे व्यापक मसले हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। पहला, सरकार को यह बताना चाहिए कि वह अगले वर्षों में, उदाहरण के लिए पांच साल में, ऋण में कितना कमी लाना चाहती है। मौजूदा साल में केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के 56.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है, जो कि 2023-24 में 58.1 फीसदी था। इसे और घटाते हुए जीडीपी के 40 फीसदी तक लाने में काफी लंबा समय लगेगा, जैसा कि एफआरबीएम ढांचे में सुझाव दिया गया है। मध्यम अवधि के लिए एक स्पष्ट ऋण लक्ष्य से यह तय करने में भी मदद मिलेगी कि सरकार एक निश्चित अवधि में राजकोषीय घाटे का कितना स्तर बनाए रख सकती है।

दूसरा, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य दायरा करने में समस्या यह है कि ऊपरी छोर, या ऊपरी छोर के निकट का स्तर ही वास्तविक लक्ष्य बन सकता है। इस संबंध में यह भी अहम होगा कि इस दायरे की सीमा या आयाम तय किया जाए। एक विस्तृत दायरा स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करेगा। बजट पर हमेशा कई तरह की मांगों का दबाव होता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई भी सरकार नागरिकों की हर जरूरत को यथासंभव तरीके से पूरा करना चाहेगी। इसलिए व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बजट में कठोर अंकुश लगाना महत्त्वपूर्ण है, खासकर तब जब ऋण और बजट घाटा अधिक हो। इसलिए यही उचित रहेगा कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का कोई दायरा न तय किया जाए।

तीसरा, मध्यम अवधि के लक्ष्यों को अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण क्षमताओं के आधार पर तय करना चाहिए। अगर सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी की जरूरतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो इससे निजी निवेश में कमी आएगी। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि घरेलू वित्तीय बचत जीडीपी के 5.3 फीसदी के साथ कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई है। इसलिए, समग्र राजकोषीय नीति प्रबंधन को, सार्वजनिक ऋण को पर्याप्त रूप से कम करने की आवश्यकता और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं से समझौता किए बिना बजट घाटे को वित्तपोषित करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।

बिनय सिन्हा

वास्तविक मुद्दों का सही दिशा में समाधान करता बजट

इस वक्त देश में बेहद साहसिक और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। समझा रहे हैं अजय छिब्बर

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आए पहले बजट में मतदाताओं के संदेश को समझने और स्वीकार करने की कोशिश की गई है। इस बजट का पूरा जोर रोजगार देने, कौशल विकास करने और ग्रामीण क्षेत्रों की हताशा दूर करने, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों के साथ-साथ उत्पादन के प्रमुख घटकों, श्रम एवं भूमि की बाधाओं को दूर करने पर है। इस बजट में भी प्राथमिकता बुनियादी ढांचे को दी गई है, जो मोदी के दूसरे कार्यकाल के बजटों की विशेषता थी। यह सब राजकोषीय घाटे को और भी कम करते हुए किया गया है। ये सभी बदलाव सही दिशा में हैं। लेकिन क्या घोषित किए गए कई प्रस्ताव और योजनाएं पर्याप्त होंगी? मेरी राय में बेहद साहसिक और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

बजट में प्रस्तावित रोजगार प्रोत्साहन योजना को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेरणा देने वाला कारक बताया है, जिससे कंपनियां अधिक श्रमिकों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित होंगी। लेकिन इतने से ही बेरोजगारी में ज्यादा कमी नहीं आएगी। इसके लिए कंपनियां अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की 10 फीसदी तक रकम इस्तेमाल कर सकेंगी, जिसके कारण उन्हें इसे अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। कौशल विकास पर खर्च में बढ़ोतरी भी स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन भारत को जिस पैमाने पर रोजगार की आवश्यकता है वह रोजगार सब्सिडी से नहीं आएगा बल्कि श्रम के ज्यादा इस्तेमाल वाले विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निजी निवेश से आएगा। पर्यटन सेवाओं में तेज बढ़ोतरी से भी लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बेरोजगारी के मुद्दे को नजरअंदाज किए जाने के बजाय इसका संज्ञान लिया जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार समस्या को समझती है लेकिन चुनावों के दौरान रोजगार के मुद्दे को महत्त्व नहीं दिया गया था।

बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यों के साथ काम करते हुए श्रम, भूमि और पूंजी सहित बाजार सुधार पर जोर दिया जाए, जो स्वागत योग्य कदम है। मगर इसका स्वरूप परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी यह सही तरीके से हुआ तब भारत को रोजगार वृद्धि की राह पर बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर जोर दिया जाना भी स्वागतयोग्य कदम है लेकिन अगर पूरा तंत्र उनकी वृद्धि को हतोत्साहित करता है तब एमएसएमई को सीमित लाभ ही हो पाएगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत श्रमिक उन कंपनियों में हैं, जहां 10 से कम श्रमिक काम करते हैं। श्रम कानूनों को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि कंपनियां छोटी ही क्यों बनी रहना चाहती हैं। दरअसल भारत में अधिकतर श्रम कानून उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जिनमें 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं।

महंगी उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) से अधिकांशतः बड़ी कंपनियों को फायदा मिलता है और रोजगार के ज्यादा मौके भी तैयार नहीं होते। उसे कंपनी जगत के दबाव के बाद भी विस्तार नहीं दिया गया है। इसे अधिक धन की नहीं बल्कि समीक्षा और सुधार की जरूरत है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा सरकार के बुनियादी काम हैं और कई तरह की सब्सिडी तथा योजनाओं के बावजूद इन्हें कम धनराशि मिल रही है। खेती से जुड़े शोध एवं विकास पर बढ़ते खर्च में वृद्धि और तिलहन तथा दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया जाना स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के संकट की बड़ी वजहों का समाधान नहीं निकाला गया है और यह संकट तब तक बना रहेगा, जब तक खेती के अलावा दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त मौके नहीं बनते। इसके लिए फसलों के मिश्रण में बदलाव कर अनाज और गन्ना से इतर भी देखना होगा क्योंकि ये दोनों भारी सब्सिडी पा रहे हैं, जल स्तर कम कर रहे हैं और देश के उत्तरी हिस्से की मिट्टी भी खराब कर रहे हैं। किंतु सरकार पहले ही पांच वर्षों के लिए देश की 60 फीसदी से अधिक आबादी को मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अधिक खरीद करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि होगी। ऐसे में गंभीर कृषि सुधार, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बड़ी चुनौती बने रहेंगे।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ही तरह बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर इस सरकार के बजट का भी प्रमुख बिंदु है। लेकिन बजट में राजकोषीय घाटा कम करने के संकेत दिए गए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत के बराबर घाटे का अनुमान लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है परंतु भारत को सार्वजनिक ऋण अनुपात घटाकर 60 प्रतिशत पर लाने और अगले बड़े संकट के लिए राजकोष को मजबूत बनाने के लिए मध्यम अवधि के लिहाज से अधिक आक्रामक स्तर पर राजकोषीय घाटा कम करने की जरूरत है। ऐसा करने का एक तरीका व्यापक निजीकरण कार्यक्रम है, जिसमें बुनियादी ढांचे के निवेश पर जोर दिया जाए।

बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से अधिक) और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत (15 प्रतिशत से अधिक) कर दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तरों के करीब है और समाज के आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें संपत्ति और सोने पर पूंजीगत लाभ कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है, जो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के बराबर है। साथ ही इंडेक्सेशन में बदलाव किया गया है, जिससे संपत्ति का लेन-देन अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है।

इसके अलावा विवादास्पद ऐंजल टैक्स को समाप्त करना अच्छा कदम है और इससे स्टार्टअप गतिविधि फिर तेज हो सकती हैं। आयकर पर मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई और कर स्लैब में वृद्धि करके मध्य आय वर्ग को कुछ राहत दी गई है। लेकिन केवल 2.2 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या ही आयकर चुकाती है, जिसका आधार बढ़ाने की आवश्यकता है।

आयात शुल्क घटाना या मोबाइल फोन, चुनिंदा चिकित्सा उपकरणों, महत्त्वपूर्ण खनिजों, सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं, चमड़ा, कपड़ा उत्पादन से जुड़े कच्चे माल, निर्यात और धातु के लिए इसे खत्म करना सकारात्मक कदम है। इसने मोदी के दूसरे कार्यकाल में लागू की गई पांच वर्षों की शुल्क बढ़ोतरी के फैसले को पलट दिया गया है। यह भी एक आशावादी संकेत है कि अगर भारत को निर्यात में प्रमुख शक्ति बनना है तब उच्च आयात शुल्क मदद के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे।

गठबंधन सरकार की जरूरतों के लिहाज से ही आंध्र प्रदेश और बिहार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में विशेष आवंटन किया गया था और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस पर काफी जोर दिया। लेकिन इन दोनों राज्यों को विशेष दर्जा नहीं दिया गया वरना अन्य राज्यों के लिए भी भविष्य में ऐसी मांग करने का रास्ता खुल गया होता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अभी संतुष्ट हैं। लेकिन क्या वे भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे, यह देखना बाकी है।

वित्त मंत्री ने मोदी के तीसरे कार्यकाल के इस बजट को अगले पांच वर्षों के लिए भारत की अमृत काल की यात्रा का खाका बताया है। बजट सही दिशा में है, लेकिन अगर भारत बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ के साथ आर्थिक वृद्धि के बजाय रोजगार के साथ आर्थिक वृद्धि पर जोर देते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तब अधिक मौलिक सुधारों और बदलावों की आवश्यकता होगी।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी सेंटर में विजिटिंग स्कॉलर हैं)

फायदेमंद साबित होने वाले तीन बदलाव

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नीति नियम

मिहिर शर्मा

सरकारों के लिए अपना रुख बदलना अक्सर कठिन होता है। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि आपने पहले जो कदम उठाया वह शायद गलत रहा हो। इसका यह अर्थ भी हो सकता है आपको उन लोगों की भी सलाह सुननी चाहिए जिनके बारे में आपकी धारणा है कि या तो उन्हें सही जानकारी नहीं है या वे आपके हित में नहीं सोचते। परंतु कोई बात या तरीका गलत साबित हो जाने के बाद भी उस पर टिके रहना कहीं ज्यादा खतरनाक है।

पिछले दिनों पेश किए गए आम बजट ने कम से कम तीन अहम क्षेत्रों में यह दर्शाया कि वित्त मंत्रालय मशविरों पर ध्यान दे रहा है और नीतिगत दिशा भी बदल रहा है। यह बात खास तौर पर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में आमतौर पर वर्तमान वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की अफसरशाही पर यह आरोप लगता रहा है कि वे आलोचना को सुनना नहीं चाहते।

पहला बदलाव शायद व्यापार और शुल्क नीति में हुआ है। कम से कम 2016 से केंद्रीय बजट का स्वर संरक्षणवादी रहा है। हर तरफ शुल्क दरों में इजाफा किया गया है और हम उस दौर में लौटते दिखे, जहां बजट भाषणों में विभिन्न हितधारी समूहों और देसी उद्योगों की मांग पर शुल्क दरों में बदलाव किया जाता रहा है। इससे न केवल रेंट सीकिंग (कोई नई संपत्ति बनाए बिना जोड़तोड़ से लाभ कमाना) को प्रोत्साहन मिला बल्कि देसी उपभोक्ताओं के लिए सामान महंगी भी हुआ। इसका यह अर्थ भी है कि भारतीय कंपनियां वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इससे हमारी निर्यात क्षमता पर बुरा असर पड़ा। वित्त मंत्रालय को बार-बार इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापारियों और उपभोक्ताओं की चिंताएं स्थानीय पूंजी की संरक्षणवादी मांगों के सामने अप्रासंगिक हो गईं।

इस बजट में ऐसे संकेत हैं कि अब संरक्षणवाद शायद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा कि निर्यात में होड़ करने की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि 'आम लोगों और उपभोक्ताओं के हित' भी समग्र रूप से लक्ष्य में शामिल हैं। यह ठोस प्रस्तावों में भी नजर आया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बजट में "उपभोक्ताओं के हित में" मोबाइल फोन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क कटौती का प्रस्ताव रखा गया।

वित्त मंत्री ने यह वादा भी किया कि अगले बजट के पहले 'दरों के ढांचे की व्यापक समीक्षा' की जाएगी ताकि उन्हें कारोबार के लिहाज से सहज और उचित बनाया जा सके। यह अन्य रचनात्मक सुझावों के लिए आमंत्रण प्रतीत होता है कि कैसे कम और स्थिर शुल्क दर उपभोक्ताओं और निर्यातकों दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। दूसरा बदलाव प्रत्यक्ष कर नीति में नजर आया। बजट भाषण में कर नीति के लक्ष्य के रूप में 'सामान्यीकरण' को अपनाने की बात कही गई। आय कर अधिनियम की व्यापक समीक्षा का वादा किया गया ताकि निश्चितता बढ़ाई जाए और मुकदमेबाजी में कमी आए। इसके लिए तथा शुल्क दरों की समीक्षा के लिए छह महीने का समय तय किया गया।

पूंजीगत लाभ कर में हुए बदलाव की काफी आलोचना हुई है। इसमें कर दर को बदला गया है और दीर्घावधि के लाभ पर इसे बदलकर 12.5 फीसदी कर दिया गया तथा इंडेक्सेशन भी खत्म किया गया। वित्त मंत्री ने इसका बचाव करते हुए इसे प्रत्यक्ष करों को तार्किक बनाना कहा। एक अवसर पर उन्होंने कहा कि लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हर तरह की आय पर कर की एक जैसी दर हो और यह उसी दिशा में आरंभिक कदम है। संभव है इसी के कारण आयकर अधिनियम की समीक्षा की बात हो। इस मौके पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि यह प्रतिक्रिया कर नीति पर लंबे समय से जताई जा रही चिंताओं के कारण थी।

अंतिम बदलाव भी महत्त्वपूर्ण है और वह इस सरकार की समग्र आर्थिक नीति की दिशा के बारे में है। मौजूदा सरकार की सबसे पुरानी और नुकसान पहुंचाने वाली आलोचना यह है कि इसमें नीतिगत दृष्टि का अभाव है। इसमें निश्चित रूप से पता है कि भारत कहां जा सकता है और उसे कहां जाना चाहिए ('विकसित भारत' इसका नवीनतम अवतार है)। वह लक्ष्य तय कर सकती है और कई बार उन्हें पूरा कर सकती है, लेकिन इसके पास ऐसे समग्र सिद्धांत नहीं हैं जो नीति निर्माण को दिशा दिखा सकें। इन सिद्धांतों के बिना नीतियों का चयन टुकड़ों में होता है। वे एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती हैं। सामूहिक सोच के इस अभाव के कारण सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया और आयात को कम करने का। उसने देशव्यापी स्तर पर श्रम कानूनों में सुधार किए बिना विनिर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश की। उसने नियमन मजबूत किए और नियामकों को कमजोर किया। यह सरकार के सामने मौजूद एक पहेली का जवाब भी है। पहेली यह कि उच्चस्तरीय अधिकारियों की व्यक्तिगत आश्वस्ति के बावजूद आखिर निवेशक क्यों कहते हैं कि उनके सामने अनिश्चितता के हालात हैं?

बहरहाल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अगले दौर के सुधारों का वादा किया जो छिटपुट लक्ष्य लेकर नही चलेंगे बल्कि एक नई 'अर्थ नीति के ढांचे' पर आधारित होंगे जो 'आर्थिक विकास को लेकर समग्र दृष्टिकोण' पेश करेगी। इसकी एक स्पष्ट वजह यह है कि समग्र ढांचा बनाना होगा ताकि राज्यों को कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए मनाया जा सके। वित्त मंत्री ने भी यही संकेत दिया जब उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में नया ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है। बहरहाल एकीकृत नीतिगत रणनीति की यह रियायत भी अतीत से एकदम अलग है। संभव है इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सके लेकिन अगर इसे लेकर होने वाली चर्चाएं पारदर्शी और सार्वजनिक हों तो सुधारों को वह ऊर्जा मिलेगी जो काफी समय से नदारद है। उपरोक्त तीनों में एक बदलाव साझा है: उनके बारे में पहले बता दिया गया है और कम से कम दो की समीक्षा का स्पष्ट वादा किया गया है। इन समीक्षाओं में सार्वजनिक मशविरा और होने वाली चर्चाओं के बारे में जानकारी देते रहना शामिल है।

वास्तव में इसे चौथा स्पष्ट बदलाव कहा जा सकता है। अपने कार्यकाल में कई बार सरकार इसलिए दिक्कतों में पड़ी है क्योंकि उसने मशविरे और सहमति निर्माण के फायदों की अनदेखी की। भूमि और कृषि कानून इसके बेहतरीन उदाहरण हैं क्योंकि उन अवसरों पर प्रधानमंत्री को खुद उन्हें वापस लेना पड़ा। परंतु अनेक अन्य कानून हैं जिन्हें पारित किया गया लेकिन इसके लिए राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। संशोधित दंड संहिता इसका एक उदाहरण है।

अब एकतरफा निर्णय लेना बंद करने का समय है। आम चुनावों में मतदाताओं की सबसे बड़ी मांग यही दिखी। शायद सरकार ने भी यह सुन और समझ लिया है।

आपका पक्ष

स्वास्थ्य सेवाओं का फौरन इलाज जरूरी

अगर भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को ई-बैंकिंग की तरह डिजिटल रूप से जोड़ दिया जाए, तो यह बहुत लाभकारी होगा। देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में, सभी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए एक वेब आधारित नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। भारत में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो वेब आधारित पोर्टल चला सकें। चिकित्सा कर्मचारियों के आईटी प्रशिक्षण के लिए संबंधित पोर्टलों को विकसित किया जा सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से स्थापित करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीकी और कानूनी ढांचे को भी मजबूत बनाना होगा। इसके लिए देश के कानूनों में भी कुछ फेरबदल करने पड़े, तो करने चाहिए। अगर सही तरह से देश में चिकित्सा स्वास्थ्य प्रणाली के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को वैज्ञानिक रूप से विकसित कर दिया जाता है, तो न सिर्फ इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी सुधार होंगे।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुधवार को श्रीनगर स्थित कश्मीर हाट में हथकरघा चलाती महिला

देश में हथकरघा उद्योग को मिले बढ़ावा

देश में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजी शासक लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की कोशिश की तो उसी समय कोलकाता (तब कलकत्ता) के टाउनहॉल में लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। इस कारण भी यह दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा देश की सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान भी है। इनमें हमारे देश के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। केंद्र सरकार देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त, 2015 को हथकरघा दिवस को मनाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने हथकरघा सामान की देश विदेश में प्रदर्शनियां भी आयोजित की, ताकि हथकरघा को विदेशों में भी पहचान मिले। भारत गांवों का देश है और गांवों में हथकरघा उद्योग काफी लोगों के रोजगार का जरिया भी है। लेकिन हथकरघा के सामान काफी महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने के लिए जैविक सामग्री की जरूरत होती है जोकि बहुत महंगी होती है, दूसरा इन्हें तैयार करने के लिए बहुत मेहनत और समय भी लगता है। देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कलाकृति और प्राचीन कौशल की राह चलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करने में आसानी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इंटर्नशिप योजना: सकारात्मक परिणाम की उम्मीद

रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना लागू करने की घोषणा की है। युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर इस योजना को पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है तो सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। इससे बेरोजगारी दूर होगी और युवाओं को नौकरी की तलाश भी घटेगी।

अमृतलाल मारू रवि, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस तबर की सेंट पीटर्सबर्ग, रूस से वापसी के दौरान जर्मन नौसेना के साथ उत्तरी सागर में संयुक्त रूप से समुद्री साझेदारी अभ्यास किया।

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरुवार 8 अगस्त 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

बांग्लादेश को लेकर संजीदगी ज़रूरी

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने को तैयार हैं। मोहम्मद यूनुस को आगे करने का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, आंदोलन के प्रमुख आयोजकों और बांग्लादेश की तीनों सेना प्रमुखों के बीच एक बैठक के बाद लिया गया। इधर बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद के देश छोड़ देने सहित जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसे लेकर जहां एक ओर भारत सरकार का कोई साफ बयान नहीं आया है वहीं सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से दीक्षित ट्रोलबाज अनेक तरह के भ्रम फैला रहे हैं। इससे न केवल भारत की आंतरिक समस्याएं बढ़ेंगी वरन दोनों देशों के बीच दूरियां भी बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इस मसले को समझने में दिक्कत होगी जो बेहद पेंचीदा और केवल बांग्लादेश नहीं वरन भारत के लिये भी संवेदनशील है।

इस मामले को जिस हल्केपन से लिया गया उसकी शुरुआत बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहकर लोगों को नाराज़ कर दिया कि 'यह इस देश का अंदरूनी मामला है और इस पर भारत को कुछ नहीं कहना है।' तब मोहम्मद यूनुस ने कहा भी था कि 'जब एक भाई के घर में आग लगी हो तो दूसरा भाई कैसे कह सकता है कि यह दूसरे घर का मामला है?' उल्लेखनीय है कि यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की है जिसका 64 देशों ने अनुसरण कर करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इस उपक्रम के लिये उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कायदे से जब बांग्लादेश में आरक्षण-विरोधी आंदोलन प्रारम्भ हुआ तभी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को अपना नज़रिया साफ करना चाहिये था। इसके साथ ही दक्षेस (सार्क) देशों के सबसे बड़े व सर्वाधिक प्रभावशाली नेता के रूप में भारत को सहयोग की पेशकश करनी चाहिये थी। यह बात बहुत साफ है कि वहां यदि राजनीतिक अस्थिरता होती है या फिर सैन्य सरकार बनती है तो इसका भी व्यापक और प्रतिकूल असर भारत पर पड़ेगा।

भारत सरकार इस मामले को लेकर कितना संजीदा है, इसका आभास मंगलवार को इस विषय पर हुई सर्वदलीय बैठक में देखने को मिला जिसमें सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनुपस्थित थे। लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 7 सदस्यों वाली आम आदमी पार्टी को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा सरकार इस अंतरराष्ट्रीय मसले पर आयोजित बैठक में भी सियासत करने की क्षुद्र हरकत से बाज नहीं आई। दूसरी ओर सभी विरोधी दलों ने, चाहे वे प्रतिपक्षी गठबन्धन इंडिया के हिस्से हों या न हों, सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया और बतलाया कि सभी दल इस मामले को लेकर सरकार के साथ खड़े हैं।

बांग्लादेश और भारत तकरीबन 4100 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। असम (262 किलोमीटर), त्रिपुरा (856 किमी), मिजोरम (318 किमी), मेघालय (443 किमी) और पश्चिम बंगाल (2217) राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई हैं। जिस तरह से वहां के हालात हैं, इन राज्यों पर भी उसका असर हो सकता है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्द्र की बैठक होनी चाहिये थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प. बंगाल है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर बांग्लादेश से लोग भागकर उनके राज्य में आते हैं तो उन्हें पनाह दी जायेगी। यह अब तक साफ नहीं है कि अन्य चार राज्यों का रवैया क्या रहेगा। चूंकि यह अंतरराष्ट्रीय मामला है अत: एक जैसी नीति अपनानी होगी। अलग-अलग राज्य वहां से आने वाले लोगों के लिये पृथक नीतियां नहीं अपना सकते। ममता के बयान से बांग्लादेश में थोड़ी नाराज़गी है इसलिये आवश्यक है कि स्वयं केन्द्र सरकार साफ करे कि आने वाले लोगों को लेकर उसका रुख क्या होगा।

इस गम्भीर मामले पर सोशल मीडिया पर अनेक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें लगता है कि वहां मुस्लिमों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिये यह जनक्रांति हुई है। वहां मंदिर तोड़े जाने की खबरें फैलाई जा रही हैं। इसके विपरीत ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि कई अल्पसंख्यकों के इलाकों तथा मंदिरों की रक्षा में बड़ी संख्या में ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और युवा तैनात हैं। लोगों को समझना होगा कि वहां शेख हसीना के खिलाफ इसलिये विद्रोह हुआ है क्योंकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को प्रश्रय दे रही थीं। इसके अलावा उन्होंने संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया था। पिछले चुनाव में धांधली करने के भी उन पर आरोप लगे हैं। वहां के लोगों का मानना है कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से चुनाव लड़कर बड़ा बहुमत पाया है अन्यथा बांग्लादेश को उन्होंने सेक्युलर और लोकतांत्रिक बनाये रखने की दिशा में कई कदम उठाये थे। वहां के लोगों का आर्थिक स्तर उठाने में भी उनकी नीति व कार्यक्रमों की सराहना होती है।

केन्द्र सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अपनानी चाहिये जो इस विषय पर झूठ फैला रहे हैं। वहां लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार जितनी बांग्लादेश के लिये ज़रूरी है उतनी ही भारत के लिये भी। ट्रोल आर्मी के सदस्य जैसे अपने देश में तानाशाह सरकार चाहते हैं वैसे ही वहां भी देखने के इच्छुक हैं- कम से कम उनके विचार तो यही बतला रहे हैं। भारत को वहां एक धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक सरकार बनाने में हरसम्भव मदद करनी चाहिये क्योंकि भारत के ज्यादातर पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध बिगड़ चुके हैं। उम्मीद है कि मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की नए सिरे से स्थापना कर राजनैतिक स्थिरता और शांति की ओर देश को ले जाएगी।

ओलंपिक या साज़िश का अखाड़ा

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

श्रीमान मोदी खुश हो सकते हैं कि विनेश फोगाट ओलम्पिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में आने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दी गईं। उनका वजन सौ ग्राम ज्यादा पाया गया, तो इसकी सजा ये मिली कि उन्हें फाइनल मुकाबला खेलने से रोका गया और इसके साथ ही उन्हें अब कोई पदक भी नहीं दिया जाएगा। यहां नरेन्द्र मोदी के लिए खुशी की बात यह है कि अब कम से कम उन्हें ये चिंता नहीं रहेगी कि अगर विनेश फोगाट ओलम्पिक में मिला पदक भी लोककल्याण मार्ग आकर उनके दरवाजे पर रख आतीं, तो फिर वे देश को क्या जवाब देते। वैसे भी देश को जवाब देना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा। इसलिए 2024 के चुनावी घोषणापत्र में 2036 में ओलम्पिक कराएंगे, जैसी घोषणा वे कर देते हैं और उनके समर्थक इसी में खुश हो जाते हैं।

विनेश फोगाट अगर बुधवार को कुश्ती का फाइनल मुकाबला खेलतीं तो फिर एक पदक मिलना तय ही था। स्वर्ण होता तो देश ज्यादा खुश होता, रजत होता, तब भी खुशी कम नहीं होती, क्योंकि पदक मिलना ही बड़ी बात थी। और विनेश फोगाट के मामले में ज्यादा बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उन्होंने पेरिस में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में अपने प्रतिद्वंद्वियों को ही धूल नहीं चटाई, बल्कि पूरी मोदी सरकार को बड़ी पटखनी दी। हालांकि मोदीजी के लिए इसमें भी खुश होने की बात थी, क्योंकि वे तब यह कह सकते थे कि विनेश ने उनकी बात मानते हुए आपदा में अवसर तलाश लिया। उनके असंभव, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्सों की कड़ी में यह किस्सा भी जुड़ सकता था कि मेरी पुलिस ने विनेश पर जोर आजमाइश की और मैंने उसके साथ नाइंसाफी होने दी, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसकी मजबूती परख सकें। इस तरह श्री मोदी बड़े आराम से विनेश फोगाट के पदक लाने का श्रेय ले लेते और उनके समर्थक इसे सही साबित भी कर देते। चंद्रयान से लेकर टी-20 वर्ल्ड कप तक सारी उपलब्धियों पर यही तो होता आया है।

किसी भी तरह की कामयाबी पर प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आ जाता है और उसके पीछे नाइंसाफी की जितनी कालिख है, वो सब छिपा दी जाती है। देश ने देखा है कि मोदी सरकार ने विनेश के सामने तमाम तरह की आपदाएं खड़ी कीं। सरकारी, कानूनी तंत्र की लिंचिंग पर्याप्त नहीं लगी तो मीडिया और सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों का भरपूर अपमान किया। मंगलवार को जब विनेश मैच खेल रही थीं, तो उसकी कमेंट्री साक्षी मलिक कर रही थीं। इधर देश में बजरंग पुनिया विनेश फोगाट पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को भाजपा की ट्रोल आर्मी का सदस्य बता रहे थे और पूछ रहे थे कि मोदीजी कब विनेश को फोन करके बधाई देंगे। लेकिन मोदीजी का न फोन आया, न ट्वीट आया। फिर जैसे ही बुधवार सुबह खबर आई कि महज सौ ग्राम ज्यादा होने से विनेश को मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उसके बाद ही नरेन्द्र मोदी का ट्वीट आ गया, जिसमें उन्होंने विनेश को चैंपियनों की चैंपियन बताया है और कहा है कि वे और मजबूत होकर वापसी करेंगी। मानो श्री मोदी इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे सांत्वना के दो बोल लिखकर अपना कद ऊंचा दिखाएं।

अब विनेश फोगाट किस तरह की वापसी करेंगी, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन पंक्तियों के लिखने तक खबर थी कि अपना वजन कम करने के लिए विनेश ने रात भर साइकिलिंग की, वेट लिफ्टिंग की लेकिन वजन फिर भी कम नहीं हुआ। उसके बाद वो निराश होती गईं और अंत में बेहोश हो गईं। उन्हें ओलंपिक विलेज के ही पॉलिक्लीनिक में इलाज के लिए ले जाया गया है।

अब विनेश फोगाट किस तरह की वापसी करेंगी, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन पंक्तियों के लिखने तक खबर थी कि अपना वजन कम करने के लिए विनेश ने रात भर साइकिलिंग की, वेट लिफ्टिंग की लेकिन वजन फिर भी कम नहीं हुआ। उसके बाद वो निराश होती गईं और अंत में बेहोश हो गईं। उन्हें ओलंपिक विलेज के ही पॉलिक्लीनिक में इलाज के लिए ले जाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वजन कम करने का सारा दबाव विनेश फोगाट अकेले झेल रही थीं। उन्हें इस हद तक व्यायाम क्यों करने दिया गया कि वे बेहोश ही हो जाएं। भारतीय ओलंपिक टीम का प्रबंधन, डॉक्टरों और आहार विशेषज्ञों की टीम क्या पेरिस घूमने गई है या उनकी कोई जवाबदेही मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है।

एक गंभीर सवाल यह भी है कि विनेश फोगाट को देश के सियासी अखाड़े में पस्त नहीं किया जा सका, तो क्या इसका बदला ओलंपिक के अखाड़े में लिया गया है। बुधवार सुबह ही जब खबर आ गई थी कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराया गया है तो सरकार ने फौरन कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री का ट्वीट करना ही क्या पर्याप्त था, क्यों एक वैश्विक नेता की हैसियत से अपने देश की खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने फौरन हस्तक्षेप नहीं किया। मान लिया कि खेल आयोजनों में राष्ट्राध्यक्षों की सीधी दखलंदाजी नहीं होती है, वहां के प्रोटोकॉल अलग होते हैं। लेकिन क्या फाइनल से पहले अयोग्य ठहराने वाले प्रकरण रोज होते हैं, जो सामान्य नियमों पर चला जाए। महाभारत में भी लिखा है कि असाधारण परिस्थितियों में आपद धर्म का निर्वाह करना पड़ता है। क्या यहां मोदी फिर से अपने धर्म के निर्वाह में नाकाम रहे। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का संसद में दिया बयान भी बेहद लचर था, जिसमें यह कहीं नजर नहीं आया कि मोदी सरकार को विनेश फोगाट के साथ हुई नाइंसाफी पर कोई अफसोस हो। बल्कि मंत्रीजी यह भी बता गए कि सरकार ने विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के लिए 70 लाख रूपयों की मदद की। 80 करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज का ढोल जिस तरह मोदी सरकार पीटती है, वही रवैया आज विनेश फोगाट मामले में अपनाया गया। जबकि हकीकत यह है कि जिसे सरकार मदद का नाम दे रही है, वह उसकी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी सरकार जनता के दिए टैक्स के पैसे से ही पूरी करती है, अपनी जेब से नहीं।

विनेश फोगाट को इंसाफ दिलाने के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा से आग्रह किया है कि वे इस संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। पी टी उषा अभी पेरिस में ही हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक दल किसी भी तरह की कोशिश करता नजर नहीं आया। याद रहे कि जब महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, तब पी टी उषा ने उनके रवैये का विरोध किया था। अब इस अभूतपूर्व संकट में पी टी उषा किस तरह विनेश फोगाट के साथ खड़ी होती हैं, यह देखना होगा। पेरिस ओलंपिक में नीता अंबानी की इंडिया हाउस में की जा रही मेजबानी की भी खूब खबरें आ रही हैं। नीता अंबानी आईओसी की सदस्य भी हैं, क्या उन्हें इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कर सकतीं तो फिर विनेश फोगाट के साथ खड़े होने के लिए इस्तीफे की पेशकश ही कर दीजिए, तभी तो देशप्रेम और खेलप्रेम की मिसाल कायम होगी, वर्ना यहां भी व्यापार प्रथम ही नजर आ रहा है।

वैसे इस पूरे प्रकरण में साजिश की बू शुरु से आई, इस पर आप सांसद संजय सिंह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने भी लिखा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक गंभीर बात कही है कि यह एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े में नहीं हरा पाया लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मैडल आज राजनीति का शिकार हो गया। यह देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता।

सवाल यह है कि ओलंपिक को अगर साजिश का अखाड़ा बनाया गया है तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ है।

शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश-भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

■ नित्य चक्रवर्ती

भारत आज बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जब पिछले पंद्रह वर्षों से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद को सेना के जनरलों और उनकी अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने मात्र 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब दिल्ली में हैं और राजनीतिक शरण के लिए किसी पश्चिमी देश से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं।

बांग्लादेश में पिछले तीन दिनों में घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी अंतिम समय में हुए घटनाक्रम के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी पड़ोसी देश में अचानक हुई घटनाओं से स्तब्ध हैं, जिसमें पिछले कई वर्षों से भारत की सरकारों ने राजनीतिक और आर्थिक पूंजी के मामले में सबसे अधिक निवेश किया है। पिछले कुछ वर्षों में घटित घटनाओं के इतिहास में जाये बिना, खासकर कोटा प्रणाली के खिलाफ शुरू में 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन और फिर अंतिम चरण में हसीना सरकार को हटाने के लिए एक व्यापक आंदोलन में बदल जाने के बाद, प्रदर्शनकारियों और सेना द्वारा दिये गये संकेत भारत के हितों के विपरीत हैं। भारत को अस्थिर द्विपक्षीय संबंधों के दौर के लिए तैयार रहना होगा।

आइये, बांग्लादेश में हसीना के बाद के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें। अभी सेना प्रमुख वकर-उज-जमां ने बांग्लादेश का प्रशासन संभाल लिया है। उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन के लिए अवामी लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के साथ सोमवार की रात बैठक की। चर्चा में दक्षिणपंथी विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी ने हिस्सा लिया। अंतरिम सरकार के संभावित प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ नामों पर चर्चा हुई। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस उनमें से एक हैं। वे हसीना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च निकाय छात्र समूह अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की पसंद प्रतीत होते हैं।

भारत को यह भी देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभावित न हों। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 12.9अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। बांग्लादेश को भारत का निर्यात कुल 11अरब अमेरिकी डॉलर है। भारतीय कंपनियों और भारत सरकार ने बांग्लादेश में बड़ा निवेश किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए भारत के साथ मिलकर तीस्ता परियोजना पर सहमति जताई है।

बांग्लादेश में उभरते राजनीतिक परिदृश्य के बारे में दो अहम सवाल हैं। क्या सेना प्रमुख वास्तव में सत्ता को नागरिकों और राजनीतिक दलों को सौंप देंगे, जैसा कि वे कह रहे हैं, या बांग्लादेश की सेना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना जारी रखेगी, जैसा कि उन्होंने पिछले वर्षों में कई मौकों पर किया है? फिर अगला सवाल, यदि सेना वास्तव में अंतरिम सरकार का गठन करती है और कुछ अंतराल के बाद चुनाव कराती है, तो कौन से राजनीतिक दल नये चुनावों में भाग लेंगे? यह मुद्दा भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

अभी तक तो ऐसा लगता है कि शेख हसीना काफी समय तक अपने देश वापस नहीं आयेंगी। उनके बेटे ने लंदन में बीबीसी को बताया कि वे राजनीति छोड़ देंगी। हसीना के अधिकांश परिवार के सदस्य लंदन में हैं। वे 77 वर्ष की हैं। निश्चित रूप से उनमें अवामी लीग को पुनर्जीवित करके नये शासकों से लड़ने के लिए अधिक राजनीतिक क्षमता नहीं बची है। यदि वे अंतत: राजनीति छोड़ने का फैसला करती हैं, तो अवामी लीग (एएल) का क्या होगा?

एएल की सुप्रीमो के रूप में, उनका वचन ही कानून था। वे अपने अनुयायियों के भरोसे पार्टी और सरकार दोनों पर प्रभावशाली तरीके से शासन करती थीं। उनमें से कई अब बदनाम और शक्तिहीन हो चुके हैं। सत्ता खोने के बाद, आवामी लीग के नेताओं पर प्रदर्शनकारियों द्वारा शारीरिक हमले किये जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश को बीएनपी और जमात के समर्थकों द्वारा उकसाया जा रहा है।

अब जब वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो उनमें से कई अपने परिवारों के साथ भारत जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, आवामी लीग को फिर से कौन खड़ा करेगा, जो बांग्लादेश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो वर्षों से भारत के साथ खड़ी रही है?

संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में, बीएनपी और जमात प्रमुख पार्टियां होंगी, क्योंकि वर्तमान में देश में आवामी लीग-विरोधी लहर चल रही है। बीएनपी ने पिछले चुनावों का बहिष्कार किया था। जमात को चुनाव अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि जमात बांग्लादेश के संविधान के सिद्धांतों के भीतर काम करने के लिए सहमत नहीं थी। जमात का अपना पार्टी संविधान है जिसे वह सर्वोच्च मानता है। अब भी, स्थिति वही बनी हुई है। अगर जमात को चुनावों में हिस्सा लेना है तो उसे बांग्लादेश के मौजूदा संविधान का पालन करना होगा, नहीं तो जमात की भागीदारी के लिए बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करना होगा। स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है।

एक और मुद्दा भेदभाव के खिलाफ छात्र समूह की भूमिका है। सोमवार को समूह ने कहा कि वे अंतरिम सरकार में सैन्य भागीदारी के पक्ष में नहीं हैं। वे नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी चाहते हैं। क्या छात्र समूह के प्रतिनिधि सत्ता साझा करने में रुचि रखते हैं? यदि हां, तो किस रूप में? यह समूह पहले ही कह चुका है कि अवामी लीग को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वे अवामी लीग के नेताओं और इसके पार्टी विंग के छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदर्शनों के दौरान उन पर हमला किया था। इस तरह, बांग्लादेश में अब अवामी लीग और बाकी के बीच एक बड़ा विभाजन हो जायेगा।

भारत के लिए, बड़ी चिंता का विषय बांग्लादेश में रहने वाले 130 लाख हिंदुओं की सुरक्षा है। बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 1800 लाख है। देश में जब भी कोई भारत-विरोधी आंदोलन शुरू होता है, तो अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा हमले का निशाना बनता है। हाल ही में हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों में निश्चित रूप से भारत-विरोधी भावना थी और अब शेख हसीना के जाने और अवामी लीग के विघटन के बाद हिंदुओं के असुरक्षित महसूस करने के कई कारण हैं। भारत सरकार का प्राथमिक कार्य हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर किसी कारण से पलायन शुरू हो जाता है, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी को सेना के साथ-साथ कुछ विदेशी देशों से बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, जो बांग्लादेश के नये शासकों को प्रभावित कर सकते हैं। यह इस समय भारत के लिए सबसे जरूरी काम है।

इसके अलावा, भारत को यह भी देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभावित न हों। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 12.9अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। बांग्लादेश को भारत का निर्यात कुल 11अरब अमेरिकी डॉलर है। भारतीय कंपनियों और भारत सरकार ने बांग्लादेश में बड़ा निवेश किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए भारत के साथ मिलकर तीस्ता परियोजना पर सहमति जताई है। सड़क और जलमार्ग दोनों में कनेक्टिविटी के लिए चौतरफा सहयोग है। ये सभी बांग्लादेश के हित में हैं। इन पर सख्ती से काम किया जाना चाहिए और अगर नयी सरकार इस संभावना के लिए तैयार है तो भारत को बांग्लादेश में और अधिक निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए।

सच तो यह है कि कूटनीतिक पहल के मामले में भारत अब बांग्लादेश में पिछड़ गया है। चीन इस उथल-पुथल को बांग्लादेश में नये शासकों के लिए चर्चित परियोजनाओं के अपने सेट को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में लेना चाहेगा, जिसे हसीना ने हाल ही में अस्वीकार कर दिया था। भारत को सतर्क, सजग लेकिन निश्चित रूप से सक्रिय रहना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बांग्लादेश में उसके प्रमुख हितों की रक्षा हो। साऊथ ब्लॉक को घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखनी होगी और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन सभी कार्यों में से प्राथमिक कार्य इस समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ललित सुरजन की कलम से

'रोशनी का घोषणापत्र'

'दुनिया की आधी आबादी जब तक अंधेरे की कैद में रहेगी तब तक एक रोशन दुनिया की कल्पना साकार नहीं हो सकती। हमारे देश में स्त्री जाति की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। कहने के लिए कानून तो बहुत बन गए हैं और यही नहीं, कानूनों को कठोर से कठोरतम बनाने की मांग भी हमेशा उठती रहती है; लेकिन जब तक समाज के नज़रिए में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक कानून बेमानी रहे आएंगे। प्रश्न उठता है कि समाज की सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या सचमुच आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं; क्या उनमें तकनीकी विकास के चलते आ रहे सामाजिक बदलावों का ध्यान रखा जा रहा है; क्या देश के राजनीतिक दल गौर करेंगे कि घिसी-पिटी युक्तियों से बात नहीं बनेगी। मैं देखता हूं कि मूल रूप में मातृसत्तात्मक रहे आदिवासी समाजों में भी पितृसत्ता की पकड़ मजबूत हो रही है। यह चिंताजनक है। ध्यान देना होगा कि बचपन से स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी के भाव को बढ़ाया जाए, पुरुष वर्चस्व को नकारा जाए, लड़के-लड़की दोनों का लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा इत्यादि में भेद न किया जाए, उन्हें एक-दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाए। हमारी स्कूली किताबें भेदभाव को बढ़ाती हैं। विशेषज्ञ इनका परीक्षण करें और वर्चस्ववाद के बजाय नर-नारी समता का संदेश देने वाले पाठ पुस्तकों में रखें जाएं। सिनेमा और टीवी में आदर्श भारतीय नारी की जो कपोल-कल्पित छवि बना दी गई है उसे तोड़ा जाए। मैं यहां तक कहूंगा कि लड़के के लिए बंदूक और लड़की के लिए गुड़िया जैसे खिलौने की मानसिकता का भी त्याग किया जाए।'

(देशबन्धु में 05 नवंबर 2018 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

पावन प्रसंग

ध्यान बिना ज्ञान नहीं

ध्यान की परम और गहन अवस्था में ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। ध्यान की अवस्था में ही उन्हें बोध हुआ था अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था. पर बुद्ध के जीवन में ध्यान उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होने तक ही सीमित नहीं थी। ध्यान तो मानो उनके रोम-रोम से झरता था, बहता था। जीवन के हर पल वे ध्यान में ही रहे। वे जब हँसते तो ऐसा लगता मानो स्वयं ध्यान ही हँस पड़ा हो और उनके अधरों पर मानो ध्यान ही मुस्कान बन अभिव्यक्त हो रहा हो। वे जब बोलते तो ऐसा लगता मानो स्वयं ध्यान ही बोलने लगा हो। वे जब चलते तो ऐसा लगता मानो ध्यान ही चल रहा हो। उनकी वाणी से, दृष्टि से मानो हर वक्त ध्यान ही प्रस्फुटित व अभिव्यक्त होता था। उन्हें देखकर-सुनकर ऐसा लगता मानो ध्यान ने ही बुद्ध का रूप धारण कर लिया हो।

वर्षों की ध्यान-साधना उनके अंदर इस गहराई तक उत्तर आई थी कि बोधप्राप्ति के बाद भी वे पल भर के लिए भी कभी ध्यान से रहित हुए ही नहीं इसलिए तो उनके सोने-जागने, हँसने-बोलने और चलने में भी ध्यान अभिव्यक्त हुआ करता था। भगवान बुद्ध के मिलने वाले चित्रों में हम उन्हें प्राय: ध्यानमग्न अवस्थाओं में ही देखते हैं। कभी वे पर्वत के ऊपर काली अंधियारी रात में खुले में बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कभी वे बारिश की रिमझिम फुहारों में बैठकर भी ध्यानमग्न हैं। कभी वे खुले में नदी के तट पर ध्यानमग्न हैं तो कभी काले-काले बादलों से भरे आकाश के नीचे किसी शिला पर बैठे हुए ध्यानमग्न हैं। कभी वे सूर्य से बरस रही गरमी में गृध्रकूट पर्वत पर ध्यानस्थ हैं तो कभी कंपकंपाती ठंड में भी जंगल में ऊंची-नीची जमीन पर पत्तों के आसन पर आसीन हो ध्यानस्थ हैं। कभी वे किसी शमशान वन में ध्यान करते हुए टहल रहे हैं तो कभी चारों ओर से दर्शनार्थियों से घिरे होकर भी ध्यानस्थ हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई दर्शनार्थी उनसे मिलने विहार में आते थे तो आनंद उन्हें यह कहते थे कि भगवान! इस समय ध्यान में अवस्थित हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रसंग बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ 'त्रिपिटक' में हमें सहज ही देखने को मिलते हैं। एक लंबे समय तक जनसामान्य के बीच रहते-रहते अक्सर बुद्ध कुछ पल के लिए एकांत सेवन को, एकांतवास में चले जाते थे।

कई बार वे भिक्षुओं से कहते थे- च्चभिक्षुओं! मैं कुछ समय एकांतवास करना चाहता हूं। एक भिक्षान्न लाने वाले को छोड़कर मेरे पास कोई दूसरा न आने पाए। बुद्ध के जीवन में ऐसे कई प्रसंग देखने को मिलते हैं। वर्षों तक ध्यान की गहन अवस्था में ही अंतत: बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान कभी भी किसी को निष्क्रिय नहीं बनाता। तभी तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद तथागत अहर्निश कर्मरत होकर सर्वत्र धर्म का, ज्ञान का प्रचार करते रहे। जिस अंतिम रात को उन्होंने शरीर छोड़ा, उस दिन भी संध्याकाल से लेकर रात के अंतिम पहर तक वे लगातार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों, शिष्यों और जनसमूह को उपदेश देते रहे। उनकी समस्याएं सुनते रहे। उन्हें समाधान देते रहे। तथागत का यह अनवरत कर्मयोग ध्यानाभ्यास से कभी रहित था ही नहीं। नाना प्रकार के लोगों से मिलते हुए, - पैदल चलते हुए, धर्मोपदेश करते हुए भी तथागत सदा ध्यान से, समाधि से युक्त थे। तथागत कभी ध्यान से रिक्त हुए ही नहीं। इस विषय की चर्चा त्रिपिटक के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें मिलती है। उनके मुख से निकले एक-एक शब्द उनकी सहज ध्यानावस्था के ही सूचक हैं। सचमुच साधकों के लिए बुद्ध का यह ध्यानस्थस्वरूप संसार के सबसे दिव्य और महानतम उद्धरणों में से है और सच कहें तो ध्यान से दिव्य और महानतम अनुभव इस भी दुनिया में दूसरा है ही नहीं। उस दिव्य व महानतम ध्यान की नई अभिव्यक्ति ही शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्तियों के द्वारा प्रस्तुत की है, जो अद्वितीय है, क्योंकि बुद्ध के इस ध्यानावस्था को देखकर हमारा चित्त शांति में, ध्यान में डूबने लगता है। इंद्रियां शमित होने लगती हैं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। वस्तुत: ध्यान ही तथागत के जीवन का सार है।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

उन्नत सड़क ही गांव को विकास से जोड़ेगा

हमारे देश के विकास में जिन क्षेत्रों का बहुत अहम योगदान है उसमें सड़कों की भी एक बड़ी भूमिका है। माना यह जाता है कि जिस क्षेत्र या गांव में सड़कें टूटी और जर्जर होंगी वहां विकास की कल्पना अधूरी होगी. यानि जिस क्षेत्र या गांव में सड़क की स्थिति बेहतर नहीं होगी वहां अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विकास की रफ्तार धीमी रहेगी। निवेश, जो अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ कहलाती है, इसी उन्नत सड़क पर निर्भर है. इसके इसी महत्व को समझते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है. राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के सड़कों को भी बेहतर किया जा रहा है लेकिन राजस्थान के राजपुरा हुडान गांव जैसे देश के कई ऐसे दूरदराज़ ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जो सड़क की खस्ताहाली के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं।

इस संबंध में 45 वर्षीय तेवाराम कहते हैं कि राजपुरा हुडान में कच्ची सड़क होने के कारण परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। इसके कारण राज्य परिवहन निगम की कोई बस गांव में नहीं आती है। लोगों को जिला मुख्यालय या अन्य शहर जाने के लिए गांव से तीन किमी दूर मुख्य सड़क तक पैदल जाना होता है। सड़क इतनी कच्ची और धूल से भरी हुई है कि यदि कोई निजी वाहन गांव में आता है तो आसपास का पूरा इलाका धूल से भर जाता है। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है ऐसे में इस सड़क की क्या स्थिति होगी, इसका आंकलन कोई भी सहज कर सकता है। तेवाराम बताते हैं कि कच्ची सड़क होने से केवल गांव का आर्थिक विकास ही ठप्प नहीं हुआ है बल्कि यहां का सामाजिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। बारिश के दिनों में राजपुरा हुडान का संपर्क अन्य क्षेत्रों से लगभग कट जाता है क्योंकि कोई भी गाड़ी वाला इस दौरान यहां आने को तैयार नहीं होता है।

लगभग 6 साल पहले इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किया गया था, लेकिन उसके बाद कभी भी इसकी मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से धीरे-धीरे यह सड़क चलने के काबिल नहीं रह गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत को बेहतर बना दिया है। इसके तहत अब तक लगभग छह लाख 80 हजार किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

मोनिका, लूणकरणसर राजस्थान

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

सम्पादकीय

दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस से टैक्स मांगने में सरकार ने कर दी जल्दबाजी

सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की नामी कंपनी इन्फोसिस को कर विभाग की तरफ से प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद बाजार एवं अन्यत्र असंतोष दिख रहा है। इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इन्फोसिस पर भारत एवं विदेश में उसके कार्यालयों के बीच हुए लेन-देन से संबंधित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की देनदारी बनती है। इन्फोसिस इस लेन-देन की व्याख्या स्वयं को उपलब्ध कराई सेवा के रूप में कर रही है परंतु, कर विभाग का तर्क है कि विदेश में कंपनी के कार्यालय या सहायक इकाइयां स्वतंत्र हैं, इसलिए कंपनी को उसे कर चुकाना चाहिए। कर विभाग के इस दावे पर स्थिति साफ नहीं है और उलझन बनी हुई है, जिससे बाजार में चिंता और बढ़ गई है। राज्य प्राधिकरण (कर्नाटक) ने भी नोटिस जारी किया था परंतु, अब उसने इसे वापस ले लिया है। कुछ पुराने कर, जिन्हें अब चुकाने के लिए कहा जा रहा है, वे समय से परे (टाइम बार्ड) हो सकते हैं या जल्द इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। यह दावा जुलाई में निर्गत एक परिपत्र में दिए गए एक प्रावधान से निष्प्रभावी हो भी सकता है और नहीं भी। अन्य आईटी कंपनियां, जिनकी विदेश में इकाइयां हैं, उनके समक्ष भी यह कर मांग रखी जा सकती है या नहीं भी रखी जा सकती है। यह भी संभव है कि उन्हें जुलाई में निर्गत परिपत्र से सुरक्षा मिल जाए या फिर न मिले। विदेश में सहायक इकाइयां या शाखा कार्यालय रखने वाली विमानन कंपनियों से भी ऐसी मांग की जा सकती है और नहीं भी। कर दावों पर जिस तरह उलझन की स्थिति बनी है सरकार को इससे निश्चित तौर पर बचने का प्रयास करना चाहिए। यह संभव है कि सरकार ने कानून में वर्णित विभिन्न समय सीमा का पालन करने की हड़बड़ी में इन्फोसिस को 32,400 करोड़ रुपये कर चुकाने के लिए कहा है। सरकार ने कर के रूप में इन्फोसिस से जितनी रकम मांगी है वह कंपनी के मुनाफे के आंकड़े के बराबर नजर आ रही है। यह कानून की मर्यादा का उल्लंघन और व्यावहारिक रूप से करदाता के लिए अवमानना है।

सरकार को कर मांगने से पहले सोच-विचार करना चाहिए था और समग्र कारोबारी मानकों के संदर्भ में निर्णय लेना था। परंतु, ऐसा नहीं हुआ और एक समय सीमा का पालन करने के लिए उसने आनन-फानन में फैसला ले लिया गया। संभव है कि सरकार ने सोचा होगा कि कंपनी से कर मांगने के बाद जांच-पड़ताल की जाएगी और कुछ अनियमितता दिखेगी तो वह नोटिस वापस ले लेगी। यह रवैया स्वीकार्य नहीं है और उन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जो कानून की गलत व्याख्या कर नोटिस भेजते हैं। पिछले दशक में हुए कर सुधार की मूल भावना अधिक पारदर्शिता एवं सटीक अनुमान पर आधारित है। ये दोनों बातें यह व्यावहारिक रूप में भी दिखनी चाहिए। आनन-फानन में भेजे गए ऐसे कर नोटिस इस मूल भावना के बिल्कुल उलट हैं और बाजार व्यवस्था में उलझन की स्थिति खड़ी करते हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी का सामान्य कारोबारी व्यवहार उचित रूप में कराधान के दायरे में लाया जाता है तो खुली चर्चा के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यहां स्थिति कुछ इस तरह है कि एक बड़ी कंपनी एक विशेष आचरण के साथ कई वर्षों से कर चुकाती आ रही है।

पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी।

ललित गर्ग

भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा?

इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है। हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीर-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है। भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं। भारत समर्थ है, शक्ति सम्पन्न है, दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिये उसे अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमाओं पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। क्योंकि भारत के सभी पडोसी देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तख्तापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कतई नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी। परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है।

वृष
स्नेहीजनों एवं मित्रों से उपहार मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि बनी रहेगी। सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों के खुश रहने से पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी।

मिथुन
पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख-शांति में दिन व्यतीत होगा। उनका सहयोग मिलेगा। दूरस्थ मित्र और स्नेहीजनों के साथ संपर्क लाभदायक साबित होंगे। अपनी प्रभावशाली वाणी से अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे।

कर्क
शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। आनंद की प्राप्ति, जीवनसाथी की निकटता और प्रवास-पर्यटन से आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज के दिन ज़रा सा भी असंयमित और अनैतिक व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

सिंह
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। पिता तथा सरकार से लाभ मिलेगा। आर्थिक योजना अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे। व्यापार-धंधे के लिए प्रवास की संभावना है। अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

कन्या
मानसिक दुविधा में होने के कारण आप महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे। पानी वाली जगहों तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों से सावधान रहें। परिवार या जमीन से संबंधित मामलों पर चर्चा और कहीं जाने की योजना टालें। दुर्घटना से बचें।

तुला
लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक होगा। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा। मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा।

वृश्चिक
उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। निर्धारित कार्यों में कम सफलता मिलेगी। आज आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। मीठी वाणी से आप लाभप्रद, सौहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे। उत्तम भोजन, भेंट उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी।

धनु
नौकरी-धंधे या व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ मुलाकात, प्रवास का आयोजन होगा। विवाहोत्सुक युवक-युवतियों के लिए सुनहरे अवसर आएंगे। पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा। घर के बुजुर्गों के जरिए लाभ मिलेगा।

मकर
वाणी की शिथिलता के कारण उग्र तकरार हो सकती है। सगे-संबंधियों के साथ अनबन होगा। मनोरंजन या घूमने-फिरने के पीछे पैसे खर्च होंगे। शारीरिक, मानसिक व्यग्रता कम करने के लिए आध्यात्मिकता सहायक साबित होगी।

कुंभ
शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ घर में भी आनंद का वातावरण रहेगा। दोस्तों से लाभ होगा। कार्य सफलता और प्रिय व्यक्ति का साथ आनंदप्रद रहेगा। आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि की संभावनाएं हैं।

मीन
परोपकार के लिए किए काम आपको आंतरिक खुशी देंगे। आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा। वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी। नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

शख्सियत

देश भक्ति का जज्बा भी अजीब चीज है दोस्तों हमारे पॉव जहां 6 डिग्री ठंड़ में रजाई में भी ठंडे पड़े रहते हैं वहीं भारत माता के वीर जहां दूर दूर तक बर्फ के पहाड़ नजर आते हैं जो माइनस 20 डिग्री में भी अडिग रहते हैं ये जज्बा ही देश प्रेम कहलाता है .....

नमस्कार साथियों हमारे शख्सियत कॉलम के स्टार हैं भारतीय सेना के जांबाज सिपाही रहे बिनोद कुमार यादव हैं बिनोद यादव का जन्म सन 1970 बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। बिनोद यादव का शुरू से ही सेवा में भर्ती होने और देश की रक्षा करने का जज्बा मन में था ऐसे में दसवीं तक गांव मुंगेर से ही पढ़ाई की और बड़े भाई एयरफोर्स में सन 1985 में अधिकारी बन गए। इन्हें भी भारतीय सेवा में जाने का जज्बा था इसलिए 10 प्लस 2 कर सन 1990 में आर्मी में पहली पोस्टिंग रॅजोडी जम्मू एंड कश्मीर में मिली। यहां देश की रक्षा के साथ उच्च शिक्षा लेने का संकल्प भी साथ चला और ग्रेजुएशन साइंस साइड से करते हुए यह विभिन्न चौकियों पर डटे रहे। लेह लद्दाख जहां माइंस 6 और 7 डिग्री टेंपरेचर होता है। वहां इन्होंने 24 महीने चेक पोस्ट पर अड़िग रह कर देश की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया। सन 2020 में ये सूबेदार बनकर फौज से सेवानिवृत हो गए। श्रीनगर से 150 किलोमीटर आगे पाक बॉर्डर गर्म पथरी पोस्ट जहां दूर-दूर तक बर्फ ही बर्फ है वहां बीएसएफ जवानों के साथ डटे रहे गर्म पथरी पोस्ट पाक बॉर्डर पर है यहां माइनस 20 टेंपरेचर है उसके बावजूद 3 महीने अविरल और अडिग कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा का जज्बा लिए ड्यूटी निभाई इन्होंने। भारतीय सेवा को अपने जवानी के 30 स्वर्ण वर्ष दिए। आर्मी ऑफिसर बिनोद कुमार ने बढ़ता राजस्थान से बात करते हुए कहा कि इंडियन आर्मी एक अनुशासन सिखाने वाली ऐसी संस्था है जो मनुष्य को जीना सिखाती है। खुद के साथ और औरों की रक्षा के लिए आर्मी का संकल्प ही देश भक्ति का जज्बा पैदा करता है। जब यह गर्म पथरी पोस्ट पर थे जहां 20 से 25 डिग्री टेंपरेचर चल रहा था ऐसे में सांस फूलने की दिक्कत

बिनोद कुमार यादव
(रिटायर्ड सूबेदार भारतीय सेना)

को लेकर भोजन नहीं करने की परेशानी के बाद इन्होनें जाना की कर्तव्य निष्ठा सच में अनुशासन के जरिए ही निभाई जा सकती है। 30 साल की अपनी नौकरी में इंडियन आर्मी के प्रति जज्बा देश भक्ति का उद्देश्य और एक बेहतरीन लीडरशिप, मौत के बीच जीना, निर्डर बनाना और मानवीय संवेदनाओं को समझना आर्मी सिखाती है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य व स्वस्थ्य जीवन की कामना करती है।

जय हिंद

आज का इतिहास

8 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- फ्रांस ने 1549 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- डेनमार्क और स्वीडन में 08 अगस्त 1700 को शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
- जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना 1864 में हुई।
- ए. टी. मार्शल ने 1899 में रेफ्रीजरेटर का पेटेंट करवाया।
- बोस्टन में पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत 1900 में हुई।
- रावलपिंडी संधि के तहत ब्रिटेन ने 1919 में अफगानिस्तान की आजादी को मान्यता दी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 में बम्बई (अब मुंबई) सत्र में 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पारित किया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमैन ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए।
- द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने 1945 मेर जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- पाकिस्तान ने 1947 में अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी।
- आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को 1967 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह की स्थापना के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की बैठक 1967 में आयोजित की गई।
- अफगानिस्तान में नौ साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी 1988 में शुरू हुई।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1991 में उत्तरी और दक्षिण कोरिया की सदस्याता को मंजूरी दी।
- चीन और ताईवान के जनप्रतिनिधियों ने 1994 को सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- ताइवान आज़ाद होने के लिए 2002 में जनमत संग्रह योजना से पीछे हटा।
- पन्द्रह छोटे देशों ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया।
- 2004 में जापान ने चीन को पराजित करके एशिया कप फुटबाल जीता।
- एक्सनाना गुसमाओ पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री 2007 में बने।
- तिब्बत के गंसू प्रांत में 2010 को भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 100 लोगों की मृत्यु हो गई तथा लगभग 2000 लोग लापता हो गए।
- तेजस्विनी सावंत 2010 को म्युनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं।
- पाकिस्तान के क्वेटा में 2013 को आत्मघाती हमले में 28 लोग मारे गए।

8 अगस्त को जन्मे व्यक्ति

- शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 1908 में हुआ।
- भारतीय लेखक भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ।
- भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक वुलिमिरि रामालिंगस्वामी का जन्म 1921 में हुआ।

विशेष आलेख

देश-चिंतन : देश में वर्ग विभेद से आर्थिक संवृद्धि में बड़ा अवरोध

संजीव ठाकुर

आजादी के बाद से भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध आते रहें हैं। देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी हो सकती है। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं,जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत क्लिष्ट बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए-नए रूप तथा आयाम देती आई है और समाज में वर्ग विभेद,आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लू सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते है बल्कि शासन प्रशासन के विरोध में भी सदैव खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाती ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा देश के समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिंदू,मुस्लिम जाति संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमां चुका है, वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़े देश में अशांत माहौल पैदा करने का एक बड़ा सबब बन चुके है और यही वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग-अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है। संविधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है। और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्व हीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी ,बेरोजगारी ,नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता,भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सर उठाये घूम रही हैं, हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नागरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवधारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा।

पडोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

-ललित गर्ग

भारत के पडोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा?

इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है।

हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था।

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं।

नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है।

भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं। भारत समर्थ है, शक्ति सम्पन्न है, दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिये उसे अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमाओं पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। क्योंकि भारत के सभी पडोसी देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तख्तापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कतई नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

उत्तर प्रदेश उप चुनाव में होगी योगी व अखिलेश दोनों की कड़ी परीक्षा!

अशोक भाटिया

उत्तरप्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने वाले विधायकों से खाली हुई सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक कर सरकार के मंत्रियों की ह्यस्पेशल टीमह्ल को एक-एक विधानसभा में उतार दिया है। यह सभी इसी हफ्ते से उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है । चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है पर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉमूर्ले को आगे बढ़ाने पर है। वहीं, सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनावों में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती होगी। इन उपचुनावों में दलित मतदाता की फैक्टर साबित हो सकते हैं। भाजपा और सपा, दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।

प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं इनमें कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी जिले की करहल और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त हुई मिल्कीपुर के साथ ही कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर विधानसभा सीट भी शामिल हैं। फूलपुर, मीरापुर, मझवा और सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होने हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से पांच सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे। भाजपा के पास तीन, निषाद पार्टी के पास एक और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक दल के पास एक सीट थी।

विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनावों में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में 2019 की 62 सीटों के मुकाबले पार्टी के 29 सीटों के नुकसान के साथ 33 पर आने के पीछे भाजपा के नेता भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गढ़े गए नैरेटिव को मुख्य वजह मान रहे हैं। जब चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग में भी दलित और ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था ।

भाजपा नेताओं ने बीएल संतोष को ये बताया था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का न होना लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के पीछे बड़ी वजह रहा है। दलित समाज इसे आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठा है। विपक्ष संविधान को लेकर भी भाजपा के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल रहा है , पार्टी के नेता ये भी मान रहे हैं। भाजपा के सामने संविधान और आरक्षण के मोर्चे पर विपक्ष के नैरेटिव से निपटने की चुनौती भी होगी। वहीं, मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता है। गाजियाबाद की सीट शहरी है और इसे भाजपा के लिए अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक हैं तो वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट-गुर्जर के साथ मुस्लिम मतदाता नतीजे तय करते हैं।

प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर भी उठती रही है और अब उनके लिए इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति हो गई है क्योकि योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू कम हुई है। हालांकि, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में मुख्यमंत्री योगी की सीधी भूमिका नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखने हुए विपक्ष की जीती सीट हासिल कर यह साबित करने का मौका है कि प्रदेश के जनमन पर उनकी छाप मद्धम नहीं पड़ी है। उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी को भी इस बात का अंदाजा हो गया है इस कारण वे खुद मोर्चा संभाल रहे है ।

प्रदेश में दलित वर्ग मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। सूबे में करीब 20 फीसदी आबादी दलित वर्ग की है और बसपा का वोट शेयर भी 19 फीसदी के आसपास रहता रहा है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, कुछ चुनावों में तस्वीर बदली है। हाल के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो बसपा का वोट शेयर 19 फीसदी से गिरकर 10 फीसदी से भी नीचे चला गया। बसपा को लोकसभा चुनाव में नौ फीसदी वोट मिले थे और पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के भी पीछे रही। बसपा का खाता भी नहीं खुला था।

इसके उलट, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे। अब कहा यह जा रहा है कि दलितों का मोह मायावती की पार्टी से भंग हुआ है। नगीना में जहां दलित नेतृत्व का विकल्प था, दलित मतदाताओं ने वहां उसे चुना और बाकी जगह भी मायावती से छिटका यह वोटबैंक सपा और भाजपा में बंट गया। भाजपा के नेताओं ने खुद समीक्षा बैठक में यह कहा कि दलितों ने पार्टी को वोट करने से परहेज किया। ऐसे में देखना होगा कि दलित मतदाताओं का रुख उपचुनाव में किधर रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले पहले भाजपा सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात करती थी। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के नेताओं के बयानों से सबका विश्वास नदारद नजर आ रहा है। राम मंदिर और अयोध्या के जिक्र से भी पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उपचुनाव में पार्टी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपने कोर मुद्दे पर लौटेगी? वरिष्ठ पत्रकार बताते है कि उपचुनाव में वैसे भी सत्ताधारी दल को एज रहता है। ये उपचुनाव प्रदेश से जुड़े हैं जहां सरकार की कमान पहले से ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे लेकिन पार्टी का जोर संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष के नैरेटिव की काट करने पर अधिक होगा।

मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे से रिक्त हुई है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से संसद पहुंच चुके हैं और इसी सीट में अयोध्या भी है। भाजपा के पास उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने का भी मौका होगा। प्रदेश में दूसरे नंबर पर पहुंचने से ज्यादा भाजपा को अयोध्या की हार सता रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा की कोशिश मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने की होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में नौ बार विधायक रह चुके अवधेश पासी के बेटे अजित प्रसाद के सपा से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें हैं। इसी कारण शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खुद इंटरेस्ट ले रहे है । हाल ही में उन्होंने चुनाव प्रभारियों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा की। चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। बूथ प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर उन्होंने विस्तार से पदाधिकारियों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ह्लहर घर तिरंगा (13 से 15 अगस्त)ह्व अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को प्रत्येक परिवार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकताओं में जोश भरा। बोले कि सरकार हर वर्ग के लिए विकास योजनाएं चला रही हैं। इसका लाभ भी आमजन को मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर हाल में आमजन से जुड़कर विकास के मुद्दे लोगों तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यकताओं से कहा कि विपक्ष की गुमराह करने की राजनीति का जवाब दें। इसके लिए पदाधिकारियों को सक्रिय रहना होगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जनता से छलावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की रक्षा भाजपा सरकारों के समय ही की गई। कांग्रेस के समय में अनेक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यकताओं से कहा कि विपक्षियों के दोहरे रवैये की पोल जनता के सामने खोंले।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ह्यबूथ जीतो चुनाव जीतोह्ल अभियान को गति देने के लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी अपने कार्यकताओं को कहा है । सभी बूथ समितियों को सक्रिय करने के साथ लाभार्थियों से लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे रखा है । चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है । बूथ प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर उन्होंने विस्तार से पदाधिकारियों को जानकारी दी जा रही है। प्रदेश की 10 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से भी अहम है। उपचुनावों को सपा-कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं कम ही हैं लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनावों के बहाने 'प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी' और मजबूत हो, इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज एक सीट ही जीत सकी कांग्रेस हाल के चुनाव में छह सीटें जीतकर उत्साह से लबरेज है।

काशी में होता है पाताल लोक के नागकूप का

-सुरेश गांधी

नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 09 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान शिव के गण माने जाने वाले नागों की पूजा की जाती है. भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन नागदेवता की पूजा करने और रुद्राभिषेक करने का खास महत्व होता है। इस दिन नागदेवत को दूध और लावा चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग व्रत भी करते हैं। पंचमी का आरंभ 8 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजकर 37 मिनट से होगा। इसका समापन 9 अगस्त को रात को 3 बजकर 15 मिनट से होगा। इस तरह उदया तिथि के अनुसार, नागपंचमी का त्योहार 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। पंचम तिथि सुबह 05.47 से 08.26 तक रहेगा. कुल मिलाकर 2 घंटे 39 मिनट के लिए पूजा का मुहूर्त है. दोपहर में 12 बजकर 13 मिनट से 1 बजे तक का समय भी पूजा के लिए शुभ है। इसके बाद प्रदोष काल में भी पूजा का शुभ महूर्त शाम को 6 बजकर 33 मिनट से रात को 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। नागपंचमी के दिन हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में शिव वास योग, साध्य योग और सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। कहते है जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष या फिर राहु-केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से सर्पदंश की रक्षा होती है। साथ ही आपके घर से सांप के काटने का भय भी दूर हो जाता है। नाग पंचमी की अनोखी मान्यताएं काशी में आज भी जीवंत हैं। मान्यताओं और परंपराओं के इस मेले में आज भी बड़ी संख्या में आस्थावानों का जमघट होता है। मान्यतय है कि यह कुंआ पाताल लोक से जुड़ा है। इस कुए को नागों का घर भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं की मानें तो तक्षक नाग इसी कुएं में निवास करते है। दावा है कि यहां के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष ठीक हो जाता है। अकाल मृत्यु का कारण खत्म हो जाता है।

सावन के महीने में भगवान शिव के गले का श्रृंगार कहे जाने वाले नाग देवता की भी पूजा की जाती है। इस खास दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि सावन की पंचमी तिथि को आस्तिक ने नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था। तभी से नागपंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वाराणसी के जैतपुर में स्थित नाग कुएं में विराजमान है नागेश्वर महादेव। श्रद्धालु यहां आकर नागेश्वर महादेव को दूध, लावा और तुलसी की माला से पूजा करते हैं, क्योंकि शेषनाग को तुलसी बहुत प्रिय है। खासकर नाग पंचमी के दिन पास पड़ोस ही नहीं देशभर से श्रद्धालु आते हैं। कूप में विराजमान नागेश्वर महादेव के दर्शन करते है। कहते है जिस किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में बार-बार सर्प या नाग देवता के दर्शन होते हैं, इस कुंड का जल घर में छिड़काव करने से इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है. मान्यता है कि नागपंचमी के दिन दर्शन करने व नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से काल सर्पदोष दूर हो जाता है। यहां के कुंए का पानी 43 दिन लगातार मंसा मां को चढ़ाने से उसके सारे दुख-दर्द कट जाते है। नागकुंड में दर्शन करने वालों की सुबह से ही कतार लग जाती है। मंदिर और कुंआ हजारो साल पुराना है। इस कुएं का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। इसे ह्यकरकोटक नाग तीर्थह्ल के नाम से जाना जाता है। इस नाग कुंड को नाग लोक का दरवाजा बताया जाता है। इसी स्थान पर महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र तथा व्याकरणाचार्य पाणिनी ने महाभाष्य की रचना की थी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि एक बार नागराज तक्षक वाराणसी संस्कृत की शिक्षा लेने आएं। लेकिन उन्हे गरुण देव से भय था जिसकी वजह से वह बालक रूप में बनारस आएं। गरूण देव को इस बात का पता चल गया कि तक्षक बनारस में है और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हालांकि अपने गुरू का प्रभाव होने के नाते गरुण देव को तक्षक नाग को अभय दान देना पड़ा। कहते है इस नागकूप पर महर्षि पतंजलि ने तपस्या की थी। महर्षि पतंजलि के इस तपोस्थली का उल्लेख स्कंद पुराण में है। महर्षि पतंजलि शेषावतार भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर हर साल उनकी जयंती इस स्थान पर मनाई जाती है। जयंती पर नागकुआं पर शास्त्रार्थ का आयोजन होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन स्वयं महर्षि पतंजलि सर्प रूप में आते हैं और बगल में नागकूपेश्वर भगवान की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद शास्त्रार्थ में बैठते हैं और शास्त्रार्थ में शामिल विद्वानों और बटुकों पर कृपा भी बरसाते हैं। इस अनादि परंपरा को जीवंत पर्व के दिन बनाया जाता है।

नागकूप के बारे में कहा जाता है कि पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस कूप के अंदर सात कूप है। इस कुंए की गहराई 100 फीट है। सिर्फ नागपंचमी के मौके पर ही दर्शन होता हैं। शास्त्रार्थ परंपरा युगों पुरानी वैदिक कालीन परंपरा से जुड़ी है। महर्षि पतंजलि की जैतपुरा में नागकूप में स्थापना मानी जाती है। पतंजलि की परंपरा शास्त्रार्थ की रही है, इस लिहाज से नागकूप में परंपरा का मान रखते हुए प्रतिवर्ष परंपराओं का अनुपालन किया जाता है। प्रतिवर्ष इसका निर्वहन नागकूप क्षेत्र में आज भी किया जाता है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में केवल तीन ही जगह कालसर्प दोष की पूजा होती है, उनमें यह नाग कुआं पहले स्थान पर है। कुआं के अंदर शिवलिंग हमेशा पानी में डूबा रहता है। नागपंचमी के दिन होने वाले मेले से पहले पंप द्वारा कुएं का सारा पानी बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसमें जो शिवलिंग स्थापित है उसका श्रृंगार व पूजा-पाठ करके वापस रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अपने आप एक घंटे में कुआं वापस भर जाता है। पानी आने का रहस्य आज भी बना है। कूप निर्माण को लेकर बताया जाता है, इसका जीर्णोद्धार संवत एक में किसी राजा ने करवाया था। इस हिसाब से इसका समयकाल लगभग 2074 साल पुराना है। महर्षि पतंजलि ने यहीं पर अपने गुरु पाणिनि के साथ कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसमें महाभाष्य, चरक संहिता, पतंजलि योग दर्शन प्रमुख हैं। महर्षि पतंजलि शेषावतार थे, इसलिए वे पर्दे की आड़ से अपने सभी शिष्यों को एक साथ सभी विषय पढ़ाते थे। किसी को भी पर्दा हटाने की परमिशन नहीं थी। इस कूप में पानी कहां से आता है यह रहस्य आज भी बरकरार है। अंदर कूप की दीवारों से पानी आता रहता है। सफाई के लिए दो-दो पम्पों का सहारा लेना पड़ता है। इसके चारों तरफ सीढ़िया हैं। नीचे कूप के चबूतरे तक पहुंचने के लिए दक्षिण से 40 सीढ़ियां, पश्चिम से 37, उत्तर और पूरब की ओर दीवार से लगी 60-60 सीढ़ियां हैं। इसके आलावा कूप में शिवलिंग तक उतरने लिए 15 सीढ़ियां हैं। कूप में दक्षिण दिशा ऊंची है, जिसमें 40 सीढ़ियां हैं, जो प्रमाणित करती है यह कूप पूरी तरह वास्तुविधि से बना है।

पौराणिक मान्यताएं

भगवान शिव के गले का हार नाग वासुकी हैं। वहीं जगत के पालनहार भगवान विष्णु भी नाग की शय्या पर शयन करते हैं। इसके अलावा विष्णु की शय्या बनें शेषनाग पृथ्वी का भार भी संभालते हैं। मान्यता है कि नाग भले ही विष से भरे हों लेकिन वह लोक कल्याण का कार्य अनंत काल से करते आ रहे है। इन्हीं नाग देव को मनाने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, जिससे नाग का भय न हो और साथ ही हमारी कुंडली में अगर कालसर्प दोष हो तो वह उसे समाप्त करें। राहु और केतु से पीड़ित व्यक्ति को यहां पूजा से काफी लाभ और फायदा मिलता है। यहां के जल को घरों में छिड़कने से सर्पभय नहीं रहता और पूजा से सर्पभय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत में राजा जनमेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था. ऋषि आस्तिक ने नागों को बचाने के लिए यज्ञ रोकने में सफल रहे. जिस दिन ये यज्ञ रुका वो दिन पंचमी तिथि था, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन नागदेवता की पूजा करने से आपका धन बढ़ता है और सर्पदंश का भय दूर होता है। इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। इस साल नागपंचमी के दिन कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिससे इस पर्व की शुभता और बढ़ रही है। इन शुभ संयोग के बीच में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है।

क्या करें और क्या नहीं

नागपंचमी पर नागदेवता को दूध लावा चढ़ाना शुभ माना जाता है। नागदेवता को दूध पिलाना संभव न हो तो किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध और लावा रख आएं। नागपंचमी पर भूलकर भी किसी सांप की हत्या न करें। अगर इस दिन सर्प दिख जाए तो इसे दूर से प्रणाम करके अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाएं। लेकिन भूलकर भी सांप को परेशान न करें। नागपंचमी के शुभ अवसर घर में या फिर मंदिर में रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध अर्पित करें।

नाग देवता ने निभाई थी भाई की भूमिका

एक कथा में नाग देवता ने भाई की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने बहन के लिए ऐसा हार बनाया, जो सर्प बन जाता था। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहता था, जिसके सात बच्चे थे। सेठ के सभी सात बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाली थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। जमीन खोदते समय बड़ी बहू की नजर एक सांप पर पड़ी और वह उसे खुरपी से मारने लगी। तब सबसे छोटी बहू ने उसे रोका और कहा कि इस सर्प ने कोई पाप नहीं किया है। सबसे छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। इतना कहकर सभी बहुएं घर लौट गईं। काम में व्यस्त छोटी बहू सांप से किया वादा भूल गई और सांप उसका इंतजार करता रहा। अगले दिन जब सबसे छोटी बहू को सांप से किया हुआ वादा याद आया, तो वह दौड़कर सांप के पास गई। उसने सांप के पास जाकर क्षमा मांगी और बोली, भाई, मैं काम में व्यस्त होने के कारण अपना वादा भूल गयी। सांप ने कहा, ह्यतुमने मुझे अपना भाई समझा, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, नहीं तो कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ ही नाग ने कहा, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें जो भी मांगना हो मांग लो। तब सबसे छोटी बहू बोली- मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तुम ही मेरे भाई हो। कुछ दिन बाद नाग मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके परिवार वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप सबसे छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहां सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू को आश्चर्य हुआ। एक दिन सांप की मां ने छोटी बहू से कहा, अपने भाई को थोड़ा ठंडा दूध पिलाओ।ह्व लेकिन छोटी बहू इस बात को भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह जल गया। सांप की मां बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सांप ने उसे शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि उसकी बहन के घर जाने का समय हो गया है। जैसे ही उन्होंने घर को अलविदा कहा, नाग के परिवार ने छोटी बहू को सोने, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से लाद दिया। जब छोटी बहू घर लौटी, तो बड़ी बहू को उसके धन से ईर्ष्या होने लगी। नाग ने सबसे छोटी बहू को गहनों के साथ हीरों का हार और एक माला भी दी। यह हार पूरे राज्य में चर्चा का विषय था। जब रानी को इसके बारे में पता चला, तो उसने यह हार मंगवाया। सबसे छोटी बहू को यह अच्छा नहीं लगा और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। सबसे छोटी बहू ने अपने भाई से कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह हार सबसे छोटी बहू के गले का हार बन जाए और कोई और पहने तो उसके गले में सांप बन जाए। बहन की बात मानकर भाई ने वैसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना, तो वह हार उसके गले में सांप बन गया। रानी चिल्लाने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने सबसे छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई, तो उसने कहा कि यह हार उसके गले का हार और दूसरों के गले का सांप बन जाता है। तब राजा ने अपनी सबसे छोटी बहू से हार पहनने को कहा। जैसे ही उसने उसे पहना, सांप एक हार में बदल गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना धन देकर विदा कर दिया।

डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी एक्सप्रेस लॉन्च किया

पटना। डीएचएल एक्सप्रेस, जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवाओं का विश्वस्तरीय अग्रणी प्रदाता है, रक्षाबंधन को खुशी बढ़ाने के लिए अपने रिटेल ग्राहकों को विशेष ऑफर और छूट दे रहा है। ये 19 अगस्त 2024 तक मान्य है, इनमें ग्राहक 0.5 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक के राखी और उपहार शिपमेंट्स को विश्वस्तर पर भेजने के लिए छूट और प्रमोशन पा सकते हैं। ये ऑफर डीएचएल के 700 से अधिक रिटेल सेवा बिंदुओं के व्यापक नेटवर्क और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। डीएचएल एक्सप्रेस 'राखी एक्सप्रेस' के माध्यम से इस त्योहार को मनाने वाले परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है, इसलिए खासकर इस त्यौहार के लिए तैयार किए गए प्रेम और खुशी का संदेश देने वाले उपहार भेजने के लिए 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। संदीप जुनेजा, वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल, डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया, ने इस ऑफर के बारे में बताते हुए कहा, राखी एक्सप्रेस, एक दिल से दी जाने वाली सेवा है जो हम हर साल अपने ग्राहकों को देते हैं।

ब्रीथफ्री ने अपनी मानसून यात्रा शुरू की

पटना। सक्रिय रोगी देखभाल के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप, सिप्ला की व्यापक रोगी सहायता पहल - ब्रीथफ्री ने अपनी मानसून यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी श्वसन स्वास्थ्य स्थिति को समझने में मदद करना है। इसलिये यह यात्रा अस्थमा और सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) जैसी फेफड़ों की पुरानी बीमारियों के लिए जांच तक पहुंच बढ़ाती है। तीन महीनों के दौरान, देश भर में 4,000 से अधिक शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 350,000 से अधिक लोगों की जांच की जाएगी। डॉ. एस के मधुकर, सलाहकार चिकित्सक एवं पल्मोनोलॉजिस्ट, पटना ने कहा कि ब्रीथफ्री मानसून यात्रा जैसी पहल समय पर जांच के साथ-साथ रोग प्रबंधन, सही उपकरण तकनीकों पर परामर्श और उपचार के पालन पर जोर देने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे मौसमों के दौरान जब ये स्थितियां गंभीर हो जाती हैं।

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों

20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में राज्यों के द्वारा उपवर्गीकरण करने को गलत ठहरा दिया था क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास होने का यह अर्थ है कि सिर्फ केन्द्र सरकार ही इस मामले में निर्णय ले सकती है। संविधान का अनुच्छेद 341 स्पष्ट रूप से कहता है कि एससी-एसटी आरक्षण में जातियां तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों को उपवर्गीकरण करने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिकार को कम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वो इस आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। देखा जाये तो यह मामला पूर्ण रूप से न्यायिक सक्रियता का बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके केन्द्र की शक्ति राज्यों को सौंप दी है। मेरा मानना है कि यह बहुत जटिल मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था, जब संविधान ने यह अधिकार केन्द्र के पास रखा हुआ था तो इसे केन्द्र के पास ही रहने देना चाहिए था। एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अंजाम क्या होगा, इसे अच्छी तरह से सोच समझकर करने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश दिये जा सकते थे ताकि सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान करते हुए केन्द्र इस पर आगे बढ़ता। सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। इस वर्ग में हजारों जातियां हैं, कुछ जातियां दूसरों से पिछड़ी हुई है। देखा जाए तो एससी-एसटी समुदायों की जातियों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तो अंतर है ही बल्कि उनके बीच ऊंच-नीच का भाव भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो ऐसी जातियों के लिए उपवर्गीकरण करके अलग से आरक्षण दे सकते हैं। सभी न्यायाधीशों ने अलग-अलग राय रखी है और यह आरक्षण पर एक बड़ा फैसला है, जिसके कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव दिखाई देंगे। कई राज्यों द्वारा ऐसी मांग की जा रही थी और वो मांग सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ कई शर्तें भी जोड़ी हैं। किसी एक जाति को शत प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जातियों का आरक्षण तय करने के लिए राज्यों के पास पुख्ता डाटा होना भी जरूरी है और राज्यों के उपवर्गीकरण की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाये हैं, उन पर भी दलित संगठनों और राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसे सही नहीं कहा जा सकता कि जो जाति या परिवार आगे बढ़ गया है, उसे ही आरक्षण का फायदा मिलता रहे और जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, वो पीछे छूट जायें। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, सिर्फ आरक्षण खत्म होने का शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन जातियों को आरक्षण का कम लाभ मिला है, वहां से आवाज आने वाली है, इसको समझना होगा। अंत में इतना कहूंगा कि जो समाज खुद को नहीं सुधारता है, उसे वक्त सुधारता है। जो काम सवर्ण जातियों ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ किया है, वही काम इन समुदायों की जातियों द्वारा दूसरी जातियों के साथ नहीं किया जाना चाहिए।

बांग्लादेश - शरणार्थी बनी शेख हसीना

बांग्लादेश में तख्तापलट की असली वजह विपक्ष का सफाया और देश की खराब आर्थिक स्थिति के साथ ही 1979 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के लिए नये देश में तीस फ़ीसदी का आरक्षण नौकरियों में देने का फैसला रहा। बंगाली नौजवान यह माँग कर रहे थे कि जिन लोगों ने मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया था, अब वे साठ पैंसठ के हो रहे होंगे। ऐसे में उन्हें नौकरियों की दरकार नहीं रही।

– राकेश अचल

बांग्लादेश में तख्ता पलट न अप्रत्याशित है और न इसे टाला जा सकता था,क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को चला रहीं थीं उसका हासिल यही होना था। शेख हसीना अपने मुल्क में तख्ता पलट होते ही पद से इस्तीफा देकर शरणार्थी बन गयीं हैं,लेकिन बांग्लादेश की आग की जलन आस-पड़ौस में भी महसूस की जा रही है। 53 साल के बांग्लादेश को ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं इसका विश्लेषण अब बहुत जरूरी हो गया है। आज से 53 साल पहले 1971 में बांग्लादेश जिन परिस्थितियों में बना था तब से अब तक बहुत कुछ बदला है। भारत ने 6 दिसंबर, 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी,हालांकि तब वह पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था,कोई 10 दिन बाद बांग्लादेश को पूर्ण आजादी तब मिली थी जब पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। बांग्लादेश स्वाभाविक रूप से भारत का मित्र है और पिछले 53 साल में तमाम उठपटक के बावजूद भारत और बांग्लादेश में अपवादों को छोड़कर कभी अनबन नहीं हुई। जानकार कहते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश के सबसे क़रीबी संबंध भारत के साथ ही हैं। सिर्फ़ व्यापार के स्तर पर बात करें तो दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार होता है, जो पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है।पाकिस्तान बनने के 24 साल बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ। क्यों हुआ ये सब जानते हैं। इसकी तफ्सील में जाना शायद जरूरी नहीं है। बांग्लादेश में तख्तापलट की वजह बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा समाप्त करने की मांग को लेकर पिछले महीने से छात्रों का आंदोलन है। आगे चलकर यह एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और आग ऐसी भड़की कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा वे यदि पलायन न करतीं तो मुमकिन है कि उन्हें भी हिंसा का शिकार होना पड़ता। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत की प्रमुख भूमिका रही उस बांग्लादेश में पाकिस्तान की राजनीति का रंग ज्यादा चढ़ा बजाय भारत की राजनीति के। दुनिया जानती है कि 170 मिलियन की जनसंख्या के साथ, जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश दुनिया का आठवां सबसे बड़ा देश है, और एशिया में जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा देश और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा (भारत, पाकिस्तान के बाद) सबसे बड़ा देश है। अधिकारिक बंगाली भाषा दुनिया में सातवीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसका उपयोग बांग्लादेश के साथ-साथ पडोसी राष्ट्र भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में भी किया जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत का एक पड़ौसी का ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भाषाई रिश्ता भी है। इसेआप रोटी-बेटी का रिश्ता भी कह सकते हैं। शेख हसीना भारत के नेहरू परिवार की राजनीति से मेल खाती राजनीति की उपज हैं। उन्हें अपने पिता शेख मुजीब की वजह से राजनीति में जगह जरूर मिली लेकिन आसानी से नहीं। उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया भी। शेख हसीना के पिता, माँ और तीन भाई 1975 के तख्तापलट में मारे गए थे। उस हादसे के बाद भी उन्हें राजनीतिक सफलता आसानी से नहीं मिली। उन्होंने 80 के दशक में बांग्लादेश में जनरल इरशाद के सैनिक शासन के खिलाफ मुहिम छेड़ी, उस दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जनरल इरशाद के बाद भी उन्हें जनरल की पत्नी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया से कड़ी और लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी।

शेख हसीना ने 1996 में चुनाव जीता और कई वर्षों तक देश का शासन चलाया। उसके बाद उन्हें विपक्ष में भी बैठना पड़ा। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन पर एक बार प्राणघातक हमला भी हुआ जिसमें वे बाल बाल बच गईं,एक बार फिर बांग्लादेश राजनीति के गहरे भंवर में फंस गया था तब देश की बागडोर सेना समर्थित सरकार ने संभाल ली, इस सरकार ने शेख हसीना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनका ज्यादातर वक्त हिरासत में ही गुज़रा। इस बीच वे अपने इलाज के लिए अमरीका भी गईं और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वे जेल से बचने के लिए शायद वापस लौट कर ही ना आएँ। लेकिन वे वापस लौटीं और दो साल के सैनिक शासन समेत सात साल बाद 2008 में हुए संसदीय चुनावों में विजय प्राप्त की। बांग्लादेश में तख्तापलट की असली वजह विपक्ष का सफाया और देश की खराब आर्थिक स्थिति के साथ ही 1979 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के लिए नये देश में तीस फ़ीसदी का आरक्षण नौकरियों में देने का फैसला रहा। बंगाली नौजवान यह माँग कर रहे थे कि जिन लोगों ने मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया था, अब वे साठ पैंसठ के हो रहे होंगे। ऐसे में उन्हें नौकरियों की दरकार नहीं रही। नाहक उनके परिजनों को आरक्षण मुहैया कराया जा रहा है। इस माँग पर हसीना ने 2018 में यह आरक्षण निरस्त भी कर दिया था पर उस आरक्षण के लाभार्थी कोर्ट गये। अदालत ने लाभार्थियों के पक्ष में फ़ैसला सुना दिया और यहीं से हिंसा भड़कना शुरू हुई। आज बांग्लादेश में वहां के गाँधी शेख मुजीबुर्रहमान ही नफरत के शिकार हो रहे है। उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रहीं हैं।

बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली कब होगी, कोई नहीं जानता। वहां चुनाव होंगे, कब होंगे ये भी अभी तय नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अग्निदग्ध होने से भारत की परेशानी बढ़ गयी है। शेख हसीना की मौजूदा परेशानी कितने दिन की है ये हमें और आपको नहीं पता। वे भविष्य में क्या करेंगी ये भी तय नहीं है लेकिन वे जिस आग से निकलकर भागी हैं उसकी लपटें हम भी महसूस कर रहे हैं। ईश्वर बांग्लादेश में शांति बहाली के साथ ही भारत को भी बांग्लादेश की त्रासदी से सबक लेने की शक्ति दे।

आतातताईयों द्वारा हर युग में विध्वंश किया गया जो आज भी जारी

– मदन सुमित्रा सिंघल

विद्रोह बगावत नफरत एवं बदले की भावना जब मनुष्य में आ जाती है तो विध्वंस की ओर बढना शुरू करता है ऐसे में उनके साथ भी ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो अब तक शांत इसलिए थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। झुंड हमेशा ही खतरनाक होता है कि वो रणनीति के तहत अचानक इकट्ठा होता है लेकिन पहले से निर्धारित होता है। इसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी ही होता है उसके साथ फिर अन्य मसले जुड़ जाते हैं। दुश्मन एवं चिंगारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए समय से पहले ही सामना करने से विनाश रोका जा सकता है। शायद ना भी रोक पाये फिर भी सजगता के साथ मुकाबला करना पड़ता है। हर युग में ऐसा होता आया है तो आज भी जारी है। श्रीलंका पाकिस्तान के बाद आज बंगलादेश में जो भी हो रहा है वो रातोंरात नहीं हुआ। एक सोची समझी साज़िश के तहत किया गया। 53 साल का देश खंडहर बनाया जा रहा है। संपतियों के साथ जींदा लोगों को जलाया जा रहा है। इस भगदड़ में भले ही टारगेट किसी को किया गया हो लेकिन मासूम लोगों को वो यातना भोगनी पड़ रही है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इस घटना के बाद जब शांति बहाल होगी तो सिवाय सर्वनाश के कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों में भगदड़ मचेगी सब कुछ लूटाने के बाद स्वरक्षा एवं परिवार को बचाने के लिए भागदौड़ करेंगे।

ईश्वर मंगल करें। स्थिति में तुरंत सुधार, होने से असमय किसी की मृत्यु ना हो किसी की संपत्ति के साथ माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो संभव हो करना ही होगा। कब तक मनुष्य अग्निपरीक्षा देगा कितनी बार शरणार्थी बनकर ठोकर खाता रहेगा।

(पत्रकार एवं साहित्यकार, शिलचर असम)

संगमेश्वर महादेव जहां नागराज शिवलिंग से लिपटते हैं

– पवन वर्मा

देवताओं व ऋषि-मुनियों की पावन भारत भूमि का कण-कण सदियों से पवित्रता व महानता का संदेश देता रहा है। यहां के पर्वत, नदियां, सागर, तीर्थ, व्रत, आदि आज भी किसी न किसी रूप में हमें अपनी महानता का एहसास कराते हैं। देवादिदेव भगवान शंकर जिन्हें नीलकंठ, आशुतोष, भोले भंडारी आदि अनेक नामों से स्मरण किया जाता है का अत्यंत प्राचीन तीर्थ हरियाणा के अरुणाय नामक कस्बे में है, जो पिहोवा से मात्र पांच कि.मी की दूरी पर है। इस जगह भगवान शिव का प्रसिद्ध श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि इस जगह पर सरस्वती और अरुणा का संगम था। शायद इसलिए इसे संगमेश्वर महादेव कहते हैं। प्राचीन काल में इस तीर्थ का अत्यधिक महत्व रहा है। ऐसा बताते हैं बाबा गणेश गिरी को भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा, मैं आदि अनन्त शिव हूं। यहां मेरी पूजा से देवराज इन्द्र भी ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुए थे। ऋषि विशिष्ट और ऋषि विश्वमित्र ने यही मेरी आराधना की थी। बाबा गणेश गिरि को यह स्वप्न बिहार के एक गांव में शिव पूजन के बाद आया कि आप सरस्वती और अरुणा के संगम पर जाकर शिव आराधना करो। इसके बाद वह अपने दो शिष्यों के साथ इस स्थानकी खोज में निकल पड़े और पिहोवा से पांच कि.मी. दूर उत्तर-पूर्व में अरुणा सरस्वती के संगम में वट वृक्षों के झुंड में रुक गये। तपस्या में लीन बाबा को एक दिन भविष्यवाणी हुई भक्त, तुम जिसकी खोज में हो वह यहां से कुछ ही दूर है। बाबा ने घने जंगल में पास ही दीमक का एक ढेर दिखाई दिया। वे चिमटे सेइस जगह को कुरेदने लगे। नीचे एक अत्यंत सुंदर पाषाण शिला दिखाई देने लगी। वह उसे उखाड़ने का प्रयत्न करने लगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो थक-हार कर लौट गये। रात्रि में भगवान शंकर ने पुन: स्वप्न में कहा है तपस्वी। मैं आदि अनन्त शिव हूं। मुझे उखाड़ने का व्यर्थ प्रयास मत करो। मैं पत्थर मात्र नहीं हूं। इसे असंख्य ऋषि मुनियों व राजा महाराजाओं की भक्ति प्राप्त हुई है अत: इस स्थान का उद्धार करके शिव आशीर्वाद प्राप्त करो। बाबा अंधेरे में ही उस स्थान की ओर भागे उस पिण्डी पर मणिमय सर्पराज फन फैलाए विराजमान थे। बाबा भोले शंकर की लीला समझ गए, दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और सर्पराज लुप्त हो गये। तब बाबा गणेश गिरि ने वहां निर्माण कार्य प्रारंभ किया और यहां पर अत्यंत सुंदर शिव मंदिर का निर्माण हो पाया। अरुण संगम तीर्थ की महिमा पुरातन काल में महाभारत, वामन पुराण, गरुड़ पुराण ब्रम्हवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वणित है। महाभारत में अरुणा संगम तीर्थ के बारे में कथा वर्णित है। कहते हैं कि ऋषि विश्वमित्र के श्राप से सरस्वती रक्त मिश्रित होकर बहने लगी थीं। बाद में ऋषि के श्राम से मुक्ति दिलाने के लिये असंख्य ऋषि मुनियों ने निरंतर जप और यज्ञ करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तो उन्होंने स्वयं प्रकट होकर सरस्वती को इस श्राप से मुक्त किया था। तब उस स्थान पर ऋषियों ने महादेव जी की स्थापना की थी। महाभारत में वर्णित एक श्लोक का सार यूं है-महर्षि लोमहर्षण जी तपस्वी ऋषियों को अरुणा संगम के बारे में बताते हुए यूं कहते हैं यहां तीन रातों का उपवास पूर्वक स्नान करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। घोर कलियुग आने पर अधर्म का प्रचार होने पर मनुष्य इस संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस महान पुण्य भूमि पर मंदिर में जो शिवलिंग की पिण्डी है वह भूरे रंग की है, जिसके दर्शन मात्र से ही शिवभक्त शिवमय हो जाते हैं।

कई बार इस शिवलिंग के ऊपर नागराज ने अपना पहरा दिया है। मंदिर के मुख्य द्वार से आगे बड़े द्वार से होते हुए एक नागराज सीधे मंदिर में उतरे और शिवभक्ति में लीन अनेक भक्तों के बीच से होकर शिवलिंग पर पहुंचकर उससे ऐसा लिपटे कि दो घंटे तक फन फैलाकर भगवान शंकर के साक्षात मौजूद होने का प्रमाण देने लगे। (विभूति फीचर्स)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सोशल मीडिया का बढ़ता प्रकोप घातक

– डॉ. वीरेन्द्र भाटी मंगल

वर्तमान में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बढ़ता ही जा रहा है यह मानव स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार सोशल मीडिया बच्चों से लेकर बडी उम्र तक के लोगों पर हावी हो चुका है, इसके बिना अनेक लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाती है। सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है बल्कि मानसिक दबाव भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते अचानक व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक परेशानियों से जुझना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए सोशल मीडिया के उपयोग को कम करना बहुत जरूरी है, निर्धारित समय अन्तराल जरूरी है, अन्यथा सोशल मीडिया के अति-उपयोग के दुष्परिणाम डरावने होने वाले है। अभिभावको को चाहिए वे स्वयं पर संयम रखते हुए विशेषकर बच्चों पर भी पूरी नजर रखें। बच्चों को समय-समय परं सोशल मीडिया से होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत करवाते रहना चाहिए। इसके साथ अनेक एप भी आ चुके है, जिनका उपयोग करते हुए बच्चे कितनी देर ऑनलाइन रहते है, इस पर भी निगरानी रखी जा सकती है। आज हमारे घर-परिवारों में सोशल मीडिया का यह प्रकोप बहुतायत में बढ रहा है। हर व्यक्ति युवा-पीढ़ी में बढ़ती इस लत व इससे होने वाली अनियमित जीवन शैली को लेकर चिंतित है, लेकिन यहां विचारणीय प्रश्न यह भी है कि आखिर हम कितने सोशल मीडिया के दुष्परिणामों को लेकर सजग है? सोशल मीडिया का यह घातक नशा चारों तरफ फैल रहा है, बच्चे, युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग आदि कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है। देर रात्रि तक यहां तक कि रात-रात भर अपने-अपने कमरों में दुबके परिवार के हर छोटे-छोटे बड़े सदस्य सोशल मीडिया की गिरफ्त में आकर अपना समय व्यतीत करने के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी चैपट कर रहे है। क्या इस मामले में केवल युवा ही दोषी है? इस बढ़ती घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिए युवाओं को तो कोसा जा रहा है, लेकिन मां-बाप व घर के बड़े भी अपने गिरेबान में भी झांकने का प्रयास करें तो काफी हद तक इस समस्या पर समाधान पाया सकता है। चिंता का विषय है यह नहीं है कि युवाओं में यह लत खतरनाक तरीके से पनप रही है, बल्कि चिंता इस बात कि भी है कि घर के सभी सदस्य सोशल मीडिया पर इतना समय व्यतित करते है कि आपस में संवादहीनता की स्थिति बन गई है।

हर घर में सोशल मीडिया के माध्यम से पनपी इस अनियमित जीवन शैली से तरह-तरह के रोग व समस्याएं सामने आ रही है। ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि आखिर इस पर रोक लगेगी कैसे? कौन युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगा। आज वे अभिभावक हक अपना खो चुके है, जो स्वयं दिन-रात सोशल मीडिया में डूबे रहते है, और युवाओं की चिंता करते हैं। बढ़ती यह लत परिवारों में बेहद खतरनाक साबित हो रही है। इससे जहां एक ओर परिवारों का बिखराब हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों की परम्परा खत्म हो रही है। वर्तमान में यह घर-घर कहानी बन गई है। युवा हो या प्रौढ़ सभी उठते ही सबसे पहले मोबाइल को ही उठाते है, वहीं देर रात्रि को सोते समय तक सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, किसने क्या फोटो लगाया है? और किसने क्या कमेंट किया? यह देखने में ही वह कई घण्टे बर्बाद कर देता है। इस मानसिक स्थिति में पास में ही बैठे परिवार के सदस्य या मां-बाप के सुख-दुख का पता ही नहीं चलता। अब व्यक्ति सोशल मीडिया के उपयोग से स्वयं में अकेलेपन को भी महसूस करने लगा है, इसके बाद भी सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इन सबके साथ सोशल मीडिया की लत हावी होती इस लत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक करने से संकोच नहीं करते। इससे अलावा सोशल मीडिया पर अधिक कमेंट पाने की लालसा में अश्लीलता का नंगा नाच भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है, जो बेहद चिंताजनक है। संस्कारहीन हो चुकी इस पीढी के कारनामे देखकर मां-बाप चिंतित है। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फोटो व वीडियो पर संतोषजनक कमेंट आदि नहीं आने से भी लोगों विशेषकर युवाओं में मानसिक रोग में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है कि एक व्यक्ति दिन भर में होने वाली सभी गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम अपलोड कर लेता है, जो कदापि उचित नहीं है। सोशल मीडिया से दूरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं में अनुशासन पैदा करना होगा। एक नियम बनाना होगा कि सोशल मीडिया का उपयोग कब व कितना करना है। विशेषकर जब व्यक्ति परिवार के साथ हो, तब मोबाइल फोन से उचित दूरी ही बनाकर रखे तो लुप्त होते रिश्तों के साथ भावनात्मक जीवन जीया जा सकता है।

(वरिष्ठ साहित्यकार व स्तम्भकार, लाडनूं, राजस्थान)

कविता

मेहताब

खिलीं-खिलीं सी हैं जुल्फे,
निखरा-निखरा सा हैं रूप.
धूप में भी निकल जाओ,
तो सबको छांव लगेगी।
तेरे शबनमी होठों की हंसी,
सबको गुलाब लगेगी।
महक उठेगा हर आंगन,
हर दिल में होगा स्पंदन।
तेरी एक ही मुस्कुराहट,
हुस्न की शराब लगेगी।
हर कोई देखेगा ख्वाब।
हर किसी को इश्क़ की,
तू एक मेहताब लगेगी।

संजय एम. तराणेकर

(कवि, लेखक व समीक्षक, संजय नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश)

बांग्लादेश की घटना पूरी तरह एक साजिश का हिस्सा है। क्योंकि शेख हसीना सरकार हमेशा से भारत के करीब रहीं हैं। इसका कारण भी है भारत ने ही पूर्वी पाकिस्तान को विभजीत करा बांग्लादेश बनाया। शेख हसीना के पिता और भारत की दोस्ती इसमें बड़ा हाथ रहा है। बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। वह भारत पर अटूट भरोसा करता है। शेख हसीना का परिवार जब भी संकट में आया भारत ने खुलकर मदद किया। कभी इंदिरा गाँधी ने बांग्लादेश की खुलकर सहायता किया।

बांग्लादेश की अस्थिरता किसकी साजिश ?

– प्रभुनाथ शुक्ल

बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपात स्थिति में त्यागपत्र देकर भारत में शरण लिया है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यह बांग्लादेश और उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सरकार विरोधी हिंसक और अराजक लोगों ने पूरे बांग्लादेश को अपने कब्जे में लें लिया है। इसके पीछे सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं एक बड़ी साजिश है। यह साजिश बांग्लादेश के साथ - साथ सरकार को अस्थिर करने की थीं। क्योंकि हिंसक भीड़ प्रधानमंत्री आवास में घूस गई। गृहमंत्री का सरकारी आवास भी जला दिया गया। बांग्लादेश सरकार में कई हिंदू नेताओं का कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने वाले और मुक्ति आंदोलन के प्रणेता मुजीबुर्र रहमान जो शेख हसीना के पिता हैं उनकी आदमकद प्रतिमा को जहाँ तोड़ दिया गया। वहीं उनके संग्रहालय को आगे हवाले कर दिया गया।हिंसक भीड़ हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यह सब एक सोची समझी रणनीति है। शेख हसीना को अपदस्त करना छात्र आंदोलन के बस की बात नहीं थीं। पूरी हिंसा को नियोजित ढंग से अंजाम दिया गया है। इस साजिश को समय रहते शेख हसीना और उनकी सरकार समझ नहीं पायी। इस पूरी साजिश में सेना, विपक्ष बेगम खलिदा जिया, पाकिस्तान और चीन की आंतरिक सहमति हो सकती है। जिसकी साजिश का शिकार शेख हसीना बन गई। हिंसा के बीच खालिदा जिया की रिहाई का आदेश आखिर क्या कहता है। बंगलादेश में छात्र सरकार की उच्चश्रेणी की नौकरियों में आरक्षण को खत्म करना चाहते थे। हलांकि सरकार उनकी मांगो पर विचार भी कर रहीं थीं। दूसरी तरफ मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन भी था। सरकार बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे को थोड़ा कम भी किया था, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। वह सीधे हसीना सरकार को बदलना चाहते थे। छात्रों की यह मांग उचित भी हो सकती है लेकिन यह विल्कुल जायज थीं ऐसा भी नहीं था।

बांग्लादेश में छात्रों और सरकार के बीच बातचीत न होना और छात्रों के प्रति सरकार की दमनकारी नीति ने भी हसीना की सत्ता के लिए अंतिम कील साबित हुईं। हसीना बल प्रयोग के जरिए छात्रों के आंदोलन को कुचलना चाहती थीं। लेकिन तक़रीबन 15 साल से सत्ता पर काबिज होना उनके लिए मुश्किल हो गया। जिसकी वजह से छात्र आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान समर्थित ताकतें सेना के साथ मिलकर साजिश रचने में कामयाब रहीं। बांग्लादेश की सेना में भी अब पाकिस्तान और आईएसआई परस्त लोगों की आमद बढ़ने से बांग्लादेश की यह दुर्गति हुईं है। बांग्लादेश में शेख हसीना को उखाड़ फेंकना बेगम खलिदा जिया की पार्टी नेशलिस्ट और जमाती के बस की बात नहीं रह गई थीं। क्योंकि हसीना साल 2009 से लगातार सत्ता में बनी थीं। जबकि खलिदा जिया 2018 के बाद से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैँ। बांग्लादेश में हसीना की आवामी लीग पार्टी पर लोगों का बड़ा भरोसा रहा है। हसीना के परिवार पर बांग्लादेश के लोग अटूट विश्वास रखते हैं। हाल के सालों में हसीना सरकार बांग्लादेश की आर्थिक विकास के लिए अच्छे खासे कदम उठाए थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान से बेहतर अर्थव्यवस्था बन गया था। ढाई करोड़ लोगों सरकार ने गरीबी से बाहर निकला था। लोगों की आय भी तिगुना हो चली थीं।लेकिन विपक्ष के खिलाफ हसीना सरकार की कड़ी नीति उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। इस साजिश में छात्रों का आंदोलन आग में घी का काम किया। लेकिन असली साजिश किसी तीसरे की है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण है। जबकि छात्र सरकारी नौजरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि सरकार अपने लोगों को सरकारी नौकरी का लाभ देती है। यह भी सच है की हसीना सरकार और अवामी लीग की लागातार जीत की वजह ऐसे भी लोग परेशान थे। पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था यह आरक्षण उन्हीं परिवारों के लिए है। जबकि छात्र इसे हटाने की माँग कर रहे हैं।

बांग्लादेश की घटना पूरी तरह एक साजिश का हिस्सा है। क्योंकि शेख हसीना सरकार हमेशा से भारत के करीब रहीं हैं। इसका कारण भी है भारत ने ही पूर्वी पाकिस्तान को विभजीत करा बांग्लादेश बनाया। शेख हसीना के पिता और भारत की दोस्ती इसमें बड़ा हाथ रहा है। बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। वह भारत पर अटूट भरोसा करता है। शेख हसीना का परिवार जब भी संकट में आया भारत ने खुलकर मदद किया। कभी इंदिरा गाँधी ने बांग्लादेश की खुलकर सहायता किया। बांग्लादेश देश से भागने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण लिया है। वह भारत को सबसे अपना दूसरा घर मानती हैं। हसीना की पढ़ाई - लिखाई भारत में हुईं है। जब उनके पिता बांग्लादेश में घिरे थे तो वे भारत में आ गई थीं। भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है। बांग्लादेश देश की सेना ने हसीना सरकार को अपदस्त करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर वह चाहती तो बांग्लादेश संकट का हल निकल सकता था। लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी उसने एक चुनी हुईं लोकतान्त्रिक सरकार का गला घोंटने का काम किया है। उसने आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए। देश भर में हिंसा और आगजनी के बाद सेना कहती रहीं कि हम अपनों पर गोली नहीं चलाएंगे। क्योंकि वह सरकारी सम्पत्ति और ईमारतों को आग के हवाले करने एवं कत्लेआम के बाद भी चुप बैठी दिखीं। सवाल उठता क्या सरकारी सम्पत्ति, संसद, संग्राहालय, सरकारी ईमारत बंगलादेश की नहीं थीं। जिस मुजीबर्र रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई उसे ही आग और हिंसा की भेंट चढ़ा दिया। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर ऐसा न होता क्या शेख हसीना वहां लागातार सत्ता में बनी रहती। बांग्लादेश की बहुतायत आबादी हसीना के साथ ख़ड़ी थीं यहीं बात सेना, विपक्ष और विरोधियों और पाकिस्तान को खल रहीं थीं। जिसकी वजह में छात्र आंदोलन की आड़ में अपदस्त करने की साजिश रची गई। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मजबूत होते सम्वन्ध से चीन और पाकिस्तान बौखलाया था। बांग्लादेश में विकास की सारी परियोजनाओं पर भारत का कब्जा हो रहा था जिसकी वजह से चीन की परेशानी बढ़ रहीं थीं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना की बढ़ती लोकप्रियता पाकिस्तान को खल रहीं थीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश को कभी खुश नहीं देखना चाहता है। वह बांग्लादेश में चरमपंथ की नई जमीन तैयार कर भारत से बदला लेना चाहता है। इसलिए वहां हिंदूओं की हत्या की जा रहीं और धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार फिलहाल बांग्लादेश की स्थति पर नजर रख रहीं है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार का गठन हो। बांग्लादेश में सैनिक शासन नहीं रहना चाहिए। इस संकट का हल निकलना चाहिए।

(वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं समीक्षक, हरीपुर, पत्रालय- अभिया जिला - भदोही, (उप्र)

दैनिक
जलते दीप
जोधपुर, गुरुवार 8 अगस्त 2024

ब्रिटेन में उग्र दक्षिणपंथ

ब्रिटेन में दक्षिणपंथी हिंसा की लहर के बीच आप्रवासियों व मुस्लिमों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंता का विषय है। सोशल मीडिया के जरिये भ्रामक प्रचार से समूह विशेष पर हमले ब्रिटिश समाज में विकट होती स्थिति को दर्शाता है। दरअसल, गत 29 जुलाई को साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट की थीम डांस पार्टी में तीन बच्चियों की नृशंस हत्या के बाद ब्रिटेन के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। इस घटना में दो वयस्कों के साथ कई अन्य बच्चे भी घायल हुए थे। इसके बाद पूरे ब्रिटेन में दक्षिणपंथी आंदोलनकारियों ने इस घटना का इस्तेमाल नफरत को बढ़ावा देने और अराजकता भड़काने में किया। कालांतर में हिंसा महज विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रही। दुकानें लूट ली गईं, कारों को आग लगा दी गई, मस्जिदों और एशियाई स्वामित्व वाले व्यवसायों को निशाना बनाया गया। यह चिंताजनक स्थिति ब्रिटिश समाज में पैर पसारती मानसिक रुग्णता को ही दर्शाती है। दरअसल, ब्रिटिश समाज में आप्रवासियों के प्रति धुर दक्षिणपंथियों की कटुता छिटपुट घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ही नजर नहीं आती, बल्कि ये घटनाक्रम ब्रिटिश समाज में व्यापक सामाजिक चिंताओं और राजनीतिक विफलताओं का भी परिचायक है। दरअसल, कई दक्षिणपंथी राजनेताओं ने आप्रवासन और सांस्कृतिक एकीकरण के बारे में गलत धारणाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने विभाजनकारी एजेंडे के लिये समर्थन जुटाने के लिये खतरनाक ढंग से गलत सूचनाएं फैलायीं। कहा गया कि हमलावर एक आप्रवासी मुस्लिम था। हालांकि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने दंगों को सुनियोजित साजिश बताते हुए घटनाओं की निंदा की है, लेकिन अभी ब्रिटिश समाज में सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह में हिंसक गतिविधियों में शामिल करीब चार सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। दंगइयों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस से संघर्ष करते नजर आ रहे थे। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति और आप्रवासियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। दरअसल, हाल के दिनों में देखने में आया है कि कई देशों में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन सूचनाओं को गलत ढंग से प्रसारित व प्रचारित किया गया। वास्तव में भ्रामक सूचनाओं के तंत्र पर अंकुश लगाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की जरूरत है। देखने में आया है कि सुनियोजित ढंग से प्रचारित सूचनाएं लोगों को कट्टरपंथी बनाने और हिंसा को भड़काने के लिये प्रयोग की जाती हैं। सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल, ब्रिटिश सरकार को अंतर्निहित उन सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जिसके जरिये दक्षिणपंथी स्थानीय लोगों का भावनात्मक दोहन करते हैं। मसलन बेरोजगारी और अपर्याप्त सामाजिक सेवाओं की समस्या को दूर करना चाहिए, जिसके बहाने आप्रवासियों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से ऐसे भय के माहौल में सहिष्णुता और एकता के मूल्यों को बनाये रखने की सख्त जरूरत है। भविष्य में प्रवासियों के खिलाफ ऐसी हिंसा दोबारा न पनपे ब्रिटिश सरकार को अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा और समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए। अब चाहे वे किसी भी देश से आए हों। मीडिया और राजनीतिक नेताओं से जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए। उन्हें नफरत फैलाने वाली भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए। ब्रिटेन में डेढ़ दशक बाद व्यापक रूप से पनपे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। दरअसल, इस दौरान दक्षिणपंथियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस को भी निशाना बनाने से परहेज नहीं किया। इस घटनाक्रम के चलते प्रदर्शनकारी तथा आप्रवासियों के समर्थक कई बार आमने-सामने नजर आए। एक पक्ष कह रहा था कि ब्रिटेन को बाहरी लोगों से मुक्त कराया जाए तो दूसरी तरफ आप्रवासियों का समर्थन करने वाले नारे लगा रहे थे कि यहां शरणार्थियों का स्वागत है। बहरहाल, हाल की हिंसक घटनाओं ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री स्टार्मर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए हैं। बकायदा इस संकट को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सुरक्षा अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई गई। निश्चित रूप से दक्षिणपंथियों की हिंसा से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

पड़ोस में हिंसा का बड़ा खतरा

बांग्लादेश से प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के साथ ही वहां उनके खिलाफ चल रहा आंदोलन अब कुछ दूसरे निशानों की तरफ मुड़ गया है। इसमें उनकी अवामी लीग पार्टी के नेता और पदाधिकारी तो हैं ही जिन्हें सरकार भी गिरफ्तार कर रही है, और हसीना विरोधी प्रदर्शनकारी भी उन्हें मार रहे हैं। कुछ भरोसेमंद समाचार माध्यमों की खबरों को देखें तो पता लगता है कि अवामी लीग के 20 नेताओं की लाशें मिली हैं, बांग्लादेश के 64 जिलों में से करीब आधे जिलों में हिन्दुओं पर हमले हो रहे हैं। इसके पहले भी हमेशा ही बांग्लादेश में हिन्दू मंदिरों पर कभी-कभार हमले होते रहते थे, लेकिन अब हिन्दुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है, और बांग्लादेश के एक मशहूर गायक राहुल आनंद का 140 साल पुराना घर भी लूटपाट के बाद जला दिया गया है। शेख हसीना के मंत्री और पार्टी के दूसरे नेता देश छोडक़र भाग रहे हैं, भारत से वहां पढऩे गए हुए छात्र कई दिनों से भारत लौटते आ रहे थे, और हिन्दुओं या भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का एक दबाव भारत सरकार पर बना हुआ है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कल संसद में कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश के हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में 19 हजार भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से करीब 9 हजार छात्रों में से अधिकतर भारत लौट चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताते हुए कहा है कि बांग्लादेश के बारे में भारत में एक मजबूत राष्ट्रीय सहमति हमेशा से रही है। कल तक जयशंकर ने बांग्लादेश से हिन्दुओं या भारतीय नागरिकों को निकालने के किसी फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन कल से अब तक वहां लगातार जो वारदातें हो रही हैं, वे वहां भारतीयों और हिन्दुओं के खतरे में होने का संकेत है। वहां हिन्दुओं और हिन्दुस्तानियों को शेख हसीना का समर्थक माना जाता था, इसलिए वहां हसीना-विरोधियों की सोच इनके खिलाफ हमेशा से रहते आई है। 1992 में हिन्दुस्तान में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में अलग-अलग वक्त पर हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा होती रही है, और हिन्दू धर्मस्थलों को भी कई बार निशाना बनाया गया है। आज की दुनिया तमाम धर्मों, देशों, नस्लों और नागरिकताओं के बीच जटिल अंतरसंबंधों की जगह बन चुकी है। विश्व राजनीति के एक सबसे बड़े भारतीय जानकार बाबा कहे जाने वाले रामदेव ने बांग्लादेश की आज की हालत पर एक बहुत ही अनोखी और मौलिक सोच सामने रखी है, और उन्होंने देश के पड़ोस में इस्लामिक कट्टरवाद के पहुंचने की चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश बना सकता है, तो हिन्दू भाईयों की रक्षा के लिए वहां दखल भी दे सकता है। आरएसएस ने भी उम्मीद जाहिर की है कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिन्दुओं की हिफाजत के लिए उचित कदम उठाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, और वहां की जो तस्वीरें दिख रही हैं, उनके मुताबिक जगह-जगह मुस्लिम समुदाय के लोग लाठियां लिए हुए हिन्दू मंदिरों और हिन्दुओं के घरों की हिफाजत में जुटे हुए हैं। वे रात-दिन वहां पर गश्त दे रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की बड़ी खबर यह है कि वहां के नोबल शांति पुरस्कार विजेता मो.युनूस को वहां फौज द्वारा बनाई गई अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है, और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों की यह एक प्रमुख मांग थी, जिस पर युनूस ने यह कहा है कि वे इस मांग को भला कैसे ठुकरा सकते हैं।

प्रसंगतः रास्ते की रुकावट

विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गाँव से 6-7 मील दूर दूसरे गाँव जाती थी। एक दिन जाते-जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उन में एक विद्यार्थी कम है। ढूँढ़ने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है। उसे एक विद्यार्थी ने पुकारा, 'तुम वहाँ क्या कर रहे हो?' उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया, 'ठहरो, मैं अभी आता हूँ।' यह कह कर उस ने धरती में गड़े एक खूँटे को पकड़ा। जोर से हिलाया, उखाड़ा और एक ओर फेंक दिया फिर टोली में आ मिला। उसके एक साथी ने पूछा, 'तुम ने वह खूँटा क्यों उखाड़ा? इसे तो किसी ने खेत की हद जताने के लिए गाड़ा था।' इस पर विद्यार्थी बोला, 'लेकिन वह बीच रास्ते में गड़ा हुआ था। चलने में रुकावट डालता था। जो खूँटा रास्ते की रुकावट बने, उस खूँटे को उखाड़ फेंकना चाहिए।' वह विद्यार्थी और कोई नहीं, बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।

आखिर हसीना कैसे शुमार हुई तानाशाहों में

यह कैसे हो सकता है कि शेख हसीना जिन्हें अपना पूरा परिवार नरसंहार में गंवाया हो और उसके बाद दिल्ली के पंडारा रोड के एक घर में अपनी बहन रेहाना और किशोर भाई रसेल के साथ बतौर राजनीतिक शरणार्थी रहना पड़ा, और इस दौरान उनके प्रिय बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त ताकतें सत्तासीन हो गईं क्योंकर उन्होंने खुद को इतना बिखरने दिया कि उन्हीं तानाशाहों का प्रतिबिम्ब बन गईं, जिनसे कभी नफरत थी? अब जबकि उन्हें दिल्ली के पास हिंडन वायुसेना अड्डे पर या उसके पास 'भारतीय सेफ हाउस' में रहना पड़ रहा है और केवल एक घंटे की दूरी पर, दिल्ली में रह रही और विश्व स्वास्थ्य संगठन में नौकरी कर रही अपनी बेटी साइमा वाज़ेद से मिलने तक की अनुमति नहीं है, तो शायद वे कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांकेगी कि कैसे और क्यों उन्होंने इस मनहूस स्थिति को बनने दिया।

– ज्योति मल्होत्रा

सोमवार सायं को बांग्लादेश में भड़के अराजक आंदोलन के दौरान एक 'प्रदर्शनकारी' द्वारा बंगबंधु मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथोड़ा चलाने की तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली था। हमें लगता है यह किसी आंदोलनकारी छात्र का काम नहीं हो सकता-कतई नहीं -भले ही वह बंगबंधु की बेटी से कितना भी नाराज़ क्यों न हो। यहां तक कि अगर शेख हसीना उस वक्त भी चुप रहीं, जब पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे आंदोलन में 'देखते ही गोली मार दो' आदेश के बाद सुरक्षा बलों के हाथों 300 से अधिक मारे गए और यह हुक्म और किसी ने नहीं बल्कि उनकी आवामी लीग पार्टी के महासचिव ओबेदुल कादर ने दिया था। यदि बंगबंधु जीवित होते तो वे भी इन वैचारिक तौर पर विकृत लोगों का निशाना बन जाते, जिन्हें 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए हुए लासानी युद्ध के बारे में तो बहुत कम या ज़रा इल्म नहीं है।

वे बांग्लादेश के उस राष्ट्रपिता की पुत्री हैं जो कभी गलत नहीं कर सकते थे, शेख हसीना तो लोकतंत्र की बेटी हैं, जो 15 अगस्त 1975 की मनहूस रात को हुए नरसंहार से बच गई थीं ङ्कजब उनके बाकी परिवार को विद्रोहियों द्वारा क्रूरता से खत्म कर दिया गयाङ्क सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वे और उनकी बहन रेहाना, उस दिन धानमोंडी के पुश्तैनी घर में मौजूद नहीं थीं। आज हसीना को उन तानाशाहों की जमात में रखा जा रहा है जो अपनों का खून बहाने से पहले जरा नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें यही करना पड़ता है, अपना बचाव सर्वप्रथम जो होता है।

पर यह सब हो गुजरने की नौबत बनी कैसे? शेख हसीना कैसे ओबेदुल कादर को अनुमति दे सकती हैं कि जो कोई प्रदर्शन करने की जुर्रत करे, उसे मार डाला जाए? स्पष्टतः 1971 की क्रांति खुद को दोहरा रही है। यह अपने संतान खुद खाने जैसा है। बताया जा रहा है, ढाका में दो हफ्ते पहले हुई अभागी पत्रकार वार्ता में कादर ने कहा कि यदि छात्र अपना आंदोलन बंद कर घर वापसी नहीं करते तो 'इन्हें सीधा करने' को अपनी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हुक्म देना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि शेख हसीना की पार्टी वालों ने ढाका और चटगांव में प्रदर्शनकारी निर्दोष विद्यार्थियों पर गोलियां चलाईं? यह अभी जांच का विषय है। लेकिन यूनिसेफ ने कहा है कि जुलाई माह के आंदोलन में कम से कम 32 छात्र मारे गए हैं।

यह कैसे हो सकता है कि शेख हसीना जिन्हें अपना पूरा परिवार नरसंहार में गंवाया हो और उसके बाद दिल्ली के पंडारा रोड के एक घर में अपनी बहन रेहाना और किशोर भाई रसेल के साथ बतौर राजनीतिक शरणार्थी रहना पड़ा, और इस दौरान उनके प्रिय बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त ताकतें सत्तासीन हो गईंङ्क क्योंकर उन्होंने खुद को इतना बिखरने दिया कि उन्हीं तानाशाहों का प्रतिबिम्ब बन गईं, जिनसे कभी नफरत थी?

अब जबकि उन्हें दिल्ली के पास हिंडन वायुसेना अड्डे पर या उसके पास 'भारतीय सेफ हाउस' में रहना पड़ रहा है और केवल एक घंटे की दूरी पर, दिल्ली में रह रही और विश्व स्वास्थ्य संगठन में नौकरी कर रही अपनी बेटी साइमा वाज़ेद से मिलने तक की अनुमति नहीं है, तो शायद वे कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांकेगी कि कैसे और क्यों उन्होंने इस मनहूस स्थिति को बनने दिया।

जनवरी माह में, जब विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा दूसरी बार भी आम चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बाद, शेख हसीना ने इस निर्णय पर हेकड़ी पूर्ण रुख अख्तियार करते हुए, बीएनपी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, यह एक तरह से उनके चेहरे पर थूकने जैसा था। भले ही ये दो महिलाएं, शेख हसीना और पिछले सालों से अस्वस्थ चल रही बीएनपी प्रमुख खालिदा ज़िया, एक-दूजे को सख्त नापसंद करती हों, किंतु लोकतंत्र के पहले नियम का तकाज़ा है कि चाहे आप किसी विपक्षी नेता से कितनी भी दिली नफरत क्यों न करते हों, फिर भी उसे अपनी बात कहने का मौका तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हसीना अड़ी रहीं और भारत सरकार के पास उनकी दलीलों को मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहा लेकिन यदि भारत उनके अधिनायकवादी तौर-तरीकों से चुनाव के जरिये सत्ता में वापसी का समर्थन न करता रहता तो बंगाल की खाड़ी उन मगरमच्छों का आशियाना बन जाती, जिनका प्रशिक्षण और पोषण पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान करता आया है। विडंबना है कि वह आकलन भी एकदम सच था। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित अपने से पहले के प्रधानमंत्रियों की भांति नरेंद्र मोदी को भी अहसास रहा कि भारत के पास शेख हसीना का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब 2001 से 2006 के बीच बीएनपी सत्ता में रही, तब न केवल भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके को गहरी उथल-पुथल में धकेला गया बल्कि पाकिस्तान परस्त तत्वों ने चटगांव बंदरगाह से होकर बांग्लादेश में आधुनिक हथियारों की खेपों की खेपें उतारीं।

यह एकदम सच है कि शेख हसीना की ढाका में वापसी भारत के लिए एक बड़ा वरदान रही। केवल 1971 के नाते से नहींङ्कयह सरगर्मी आरंभ से रही, जब विशेष रिश्ता कायम हुआ, जो न केवल मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना के बीच था बल्कि दोनों मुल्कों के नागरिकों के मध्य भी और ये संबंध शेख हसीना के पिछले 15 सालों के प्रधानमंत्रित्व काल में भी बने रहे।

भारत और शेख हसीना के नेतृत्व वाले बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में एक बिल्कुल नई किस्म की साझेदारी बनी, जो बाकी दक्षिण एशिया के लिए आदर्श उदाहरण बनी। सड़क, रेलवे, पारगमन का अधिकार, आम नागरिकों को आने-जाने की अनुमति, रक्षा क्षेत्र में मदद, जो कोई भी नाम लें, उस क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश की जुगलबंदी कायम रही।

तब फिर ऐसा क्या हुआ? सोमवार को ढाका में बांग्लादेशी आंदोलनकारी द्वारा शेख मुजीब की मूर्ति के सिर को हथौड़े से तोड़ने और देशभर में हिंदू परिवारों पर हुए हमले साफ दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे से कोई ताकतें यह सब करवा रही हैं। सबसे बड़ा शक पाकिस्तान परस्त जमात-ए-इस्लामी संगठन पर है। वे लौट आए हैं। बांग्लादेश में इतिहास कभी भी वास्तव में इतिहास नहीं रहा। अब पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए बंगाल की खाड़ी में 'खेला' करने के लिए यह परिस्थिति जन्य मौका है।

यह भी उतना ही सच है कि शेख हसीना के सिवाय एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास जमात-ए-इस्लामी और इसके राजनीतिक मुखौटे बीएनपी से मुकाबला करने का माद्दा हो। लेकिन हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब जबकि हिंडन वायुसेना अड्डे पर वे ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक शरण की अनुरोध स्वीकार करने की बाट जोह रही हैं, शायद लंदन से अनुमति आने तक उनके लिए ढाका में बने रहना सुरक्षित न होता। अवश्य ही उन्होंने भारत से अस्थाई पनाह देने की गुहार लगाई होगी। उन्हें आने देकर मोदी सरकार ने सही किया है। और दोस्त होते किसलिए हैं भले ही अगला गलत क्यों न हो।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बांग्लादेश के हालात से बहुत सतर्क रहना होगा

– अशोक मधुप

बांग्लादेश में महीनों से सुलग रही आरक्षण और सरकार विरोधी चिंगारी सोमवार को भीषण आग के रूप में फूटी। 300 लोगों की मौत के बाद सेना भी उग्र भीड़ को संभाल नहीं पाई। नतीजतन करीब डेढ़ दशक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा है। शेख हसीना भागकर फिलहाल भारत आई हैं। सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना ने इंग्लैंड की सरकार से शरण मांगी है।बांग्ला देश में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब प्रदर्शनकारियों ने देश के चीफ ऑफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़-फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने घर में मौजूद कार, फर्नीचर के साथ घर का सारा समान लूट ले गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कॉन समेत देशभर में कम से कम चार मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्ला देश के अल्प संख्यक डरे और सहमें हैं। वहां क्या हालात बनेंगे? वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी , इस पर भारत को नजर रखनी होगी। ये भी देखना है कि सरकार कैसी बनता है? उसका भारत के प्रति नजरिया कैसा होगा? नई सरकार कहीं इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा तो नही देगी।उसका रूख पाकिस्तान और चीन संमर्थक तो नही होगा ? भारत को अपने देश की सीमा को पूरी तरह बंद रखना होगा, ताकि वहां के हालात से डरे नागरिक अपने भारत में न आ सकें।

1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करने की मांग के साथ पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारी आखिर फिर से इतने हिंसक होकर सड़कों पर क्यों उतर आए। असल में हिंसा की यह नई लहर तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने असहयोग का आह्वान किया। इसमें लोगों से कर या बिजली बिल का भुगतान न करने और रविवार को काम पर न आने का आग्रह किया गया। सोमवार को जब कार्यालय, बैंक और कारखाने खुले, तो प्रदर्शनकारियों ने लोगों को काम पर जाने से रोकना शुरू कर दिया। सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू की परवाह किए बिना ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग इलाके में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों व वाहनों में भी आग लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे पर अड़े रहे। 14 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों के पोते-पोतियों को मिलेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बयान के बाद, 'तुई के, अमी के रजाकार, रजाकार' के नारे लगाने शुरू कर दिए और हिंसा ज्यादा भड़क गई।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा गठित रजाकार क्रूर अर्धसैनिक बल था। रजाकारों ने मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के खिलाफ अत्याचार किया। आज भी यह शब्द वहां अपमानजनक माना जाता है। इसका इस्तेमाल देशद्रोहियों और अत्याचारियों के लिए किया जाता है।

बांग्लादेश में उथल-पुथल व तख्तापलट का इतिहास1975 से शुरू होता है।हसीना के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या कर दी गई। जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया।1981 गेस्ट हाउस में घुसकर विद्रोहियों ने जियाउर रहमान की हत्या की। हालांकि, सेना का बड़ा तबका वफादार होने से तख्तापलट नाकाम रहा।1982 रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुस सत्तार को हुसैन मुहम्मद इरशाद के नेतृत्व में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इरशाद राष्ट्रपति बन गए। 2007 सेना प्रमुख ने एक कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया, जो 2009 तक सत्ता पर काबिज रही।2009 अर्धसैनिक बलों का विद्रोह.. में 70 लोगों की हत्या, इनमें से अधिकांश सैन्य अधिकारी थे।2012 सेना ने कहा, शरिया या इस्लामी कानून से प्रेरित तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया है।

स्पष्टतौर पर बांग्लादेश में सुलग रही हिंसा के केंद्र में आरक्षण है। बांग्लादेश की जनसंख्या17 करोड़ है और देश में लगभग 3.2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं।1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के वंशजों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे लोगों के वंशजों को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। 10 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए भी है। अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर पांच प्रतिशत व विकलांगों को एक फीसदी आरक्षण का प्रावन है। पिछड़े जिलों में रहने वालों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।बांग्लादेश में बेरोजगारी से परेशान युवक इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार, हसीना के रिश्ते में बहनोई हैं।सेना प्रमुख जनरल वकार वहां सबसे अहम चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने ही शेख हसीना के देश छोड़कर जाने और इस्तीफे का एलान किया। 20 दिसंबर, 1985 को बांग्लादेश की सेना में शामिल हुए जनरल वकार की छवि एक बेहद अनुशासित अधिकारी की रही है। जानकारों का मानना है कि हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना और वकार का कमान संभालना एक सोचा-समझा निर्णय है। शेख हसीना के देश छोडने के बाद देश के सेना प्रमुख ने कहा है कि वो सभी से बातचीत करके देश में अंतरिम सरकार बनवाएंगे !बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले सत्तारूढ़ रही आवामी लीग पार्टी ने आरोप लगाया है कि देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का हाथ है। आवामी लीग के मुताबिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग दिखाती है कि विरोध-प्रदर्शनों के पीछे असल में छात्र नहीं, देश के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल- बीएनपी और प्रतिबंधित संगठन- जमात-ए-इस्लामी की रणनीति है। इनका मकसद किसी भी तरह से देश की सत्ता हासिल करना है।

बांग्लादेश में देशव्यापी आंदोलन के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। खालिदा जिया विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख हैं और 1991-96 और 2001-06 के दौरान दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।राष्ट्रपति बोले- खालिदा जिया की रिहाई के बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा।

बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी नेताओं ने सोमवार को छात्रों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद देश में पैदा हुए हालात में किसी को भी लूटने का मौका न मिले, और उनसे अपनी मांगें होने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया।

बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी है।देखना यह है कि बांग्ला देश में अब किसकी सरकार बनती है।उसका भारत के प्रति रूख कैसा होता है?नई सरकार भारत समर्थक होगी या कट्टर इस्लाम का रास्ता स्वीकार कर पाकिस्तान को अपना आका मानेगी।हालाकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार शेख हसीना के नजदीकी और रिश्ते में बहनोई लगतें हैं ।उनसे उम्मीद है कि बांग्ला देश शेख हसीना के पद चिंहों पर चलेगा, किंतु वहां के राष्ट्रपति का रूख अभी देखना होगा।उसी रूख के आधार पर भारत को अपनी नई नीति बनानी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं हैं। वह सिर्फ अपने हित देखता है। -हेनरी किसिंजर

ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचने वाली विनेश फोगाट को कुछ ग्राम अधिक वजन होने के चलते अयोग्य घोषित किया जाना चौंकाने वाला है। गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण होना ही चाहिए, लेकिन उनका खाली हाथ रह जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कुछ ग्राम वजन और उम्मीदें

ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचने वाली विनेश फोगाट को ऐन फाइनल मुकाबले से पहले निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित किया जाना चौंकाने वाला है और यह उनके साथ उन करोड़ों देशवासियों के लिए भी झटका है, जो उनसे 'स्वर्ण' की उम्मीद लगाए हुए थे। उल्लेखनीय है कि ओलंपिक के नियमों के अनुसार, पहलवानों को प्रतियोगिता के दिनों में अपने वजन-वर्ग में ही रहना होता है। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही हैं, इससे पहले तक वह 53 किलोग्राम के वर्ग में हिस्सा लेती थीं। फाइनल वाले दिन तक विनेश का वजन पचास किलोग्राम की स्वीकार्य सीमा से करीब सौ ग्राम अधिक था और यही प्रतियोगिता में उनके बाहर होने की वजह बना। दरअसल वजन में कमी लाना एक ऐसी लड़ाई है, जिससे खासकर पहलवानों को जूझना ही पड़ता है। इसमें खिलाड़ियों को जो मुश्किल आती है, वह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक के शब्दों से जाहिर होती है कि पहलवान केवल वजन घटाने के लिए ही पदक के हकदार हो जाने चाहिए। हालांकि खासकर पहलवान अपने शरीर को पहचानते हैं और उसके अनुरूप ही अपने वजन को नियंत्रण में रखते हैं। फोगाट के साथ यह स्थिति कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में क्वालीफाइंग राउंड के दौरान भी वह कुछ सौ ग्राम ज्यादा वजन के चलते बाहर हुई थीं। हालांकि तब एक दूसरे वर्ग में खेलते हुए विनेश अच्छा कर रही थीं, लेकिन फिर चोट की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी वह कुछ खास नहीं कर पाई थीं। ऐसे में, पेरिस ओलंपिक में उन पर सबकी नजर थी। गौरतलब है कि पिछले साल की शुरुआत में, फोगाट उन तीन भारतीय पहलवानों में से एक थीं, जिन्होंने भारत के कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर

कथित आरोप लगाए थे। अब विनेश के ओलंपिक से बाहर होने पर बातें होंगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि उनके लिए अब तक यह ओलंपिक शानदार रहा था और उन्होंने फाइनल राउंड तक पहुंचने के क्रम में मौजूदा चैंपियन जापान की युई सुसाकी को हराने के साथ ही यूक्रेन व क्यूबा की खिलाड़ियों को भी हराया था। फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से होना था, जिन्हें वह पहले भी हरा चुकी हैं। गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ग्राम वजन अधिक होने की वजह से विनेश को ओलंपिक से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, तो यह दुर्भाग्य ही है।

शिकार बनीं हसीना

शेख हसीना दक्षिण एशिया की जटिल अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनीं। वह अमेरिका और चीन के हितों में बाधक बन रही थीं। आईएसआई और खालिदा जिया के पुत्र लंदन से साजिशें रच रहे थे। जमात के इरादे स्पष्ट थे। जाहिर है, छात्र आंदोलन की आग में कई ताकतें रोटियां सेंक रही थीं।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपी-आईडीएसए

इसमें तनिक भर भी संदेह नहीं है कि शेख हसीना के नेतृत्व में दक्षिण एशिया में उभर रही राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग कई देशों की आंखों में चुभ रहा था। भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने न केवल विद्रोह और आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र में व्यवस्था कायम की, साथ ही, आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। ऐसे परिदृश्य में जब वह इसी वर्ष जून से पहले बांग्लादेश पर मजबूती से नियंत्रण रखती दिखाई दी हों, तो उनके तख्तापलट में विदेशी भागीदारी के होने का संदेह जताया जाना, चौंकाता नहीं है।

हसीना के तख्तापलट में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताने वाले अक्सर अमेरिका को प्रमुख संदिग्ध के रूप में इंगित करते हैं। दरअसल, बांग्लादेश की आजादी से भी पहले वहां के एक सैन्य अड्डे पर अमेरिका की नजर है। इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका ने सेंट मार्टिंस द्वीप पर सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति के बदले पूर्वी पाकिस्तानी नेताओं को समर्थन की पेशकश की थी। यह बात दीगर है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की आजादी के बाद भी अमेरिका इसके लिए प्रयास करता रहा। यह मुद्दा खासकर वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बांग्लादेश यात्रा के दौरान द्विपक्षीय यात्राओं में अक्सर उठता रहा। हाल ही में शेख हसीना ने भी खुलासा किया था कि अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने बांग्लादेश में अमेरिकी सैन्य अड्डे के प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया था। हालांकि अपने राष्ट्रवादी रुख और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को नहीं बेचेंगी। इसके अतिरिक्त, अमेरिका बांग्लादेश को अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति में शामिल करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसका लक्ष्य अमेरिका के साथ उसके रक्षा संबंधों को मजबूत करना और उसे

सैन्य उपकरण बेचना है। बांग्लादेश ने अमेरिकी हथियारों में तो रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें इंडो-पैसिफिक ढांचे के तहत खरीदने से इन्कार किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका प्राथमिक सैन्य आपूर्तिकर्ता चीन नाराज हो जाएगा।

हसीना को सत्ता से बेदखल करने में एक और विदेशी शक्ति के शामिल होने का संदेह है और वह है चीन। बहुआयामी संबंधों के बावजूद भारत और बांग्लादेश की बढ़ती निकटता से चीन के असंतोष का बढ़ना छिपा नहीं है। कई रिपोर्ट तो यह खुलासा भी करती हैं कि चीन ने हसीना को सलाह दी थी कि वह अपनी चीन यात्रा से पहले भारत की यात्रा न करें। हालांकि हसीना ने चीन की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था

चीन मुख्य रूप से अपनी बेल्ट ऐंड रोड पहल (बीआरआई) परियोजनाओं और देशों के साथ व्यक्तिगत सैन्य सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का इच्छुक रहा है। गौरतलब है कि चीन और भारत दोनों ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी पर जल प्रबंधन परियोजना में रुचि जताई है। हालांकि अपनी भारत यात्रा के दौरान शेख हसीना ने यह पुष्टि की थी कि वह भारत के साथ संवेदनशील और राजनयिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को भारत को सौंपेंगी। दरअसल, बांग्लादेश की भविष्य की जल संबंधी जरूरतों के लिहाज से तीस्ता नदी के ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका के कर्ज संकट के बाद दक्षिण एशियाई देश चीन से कर्ज लेने में जो अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं, उसने भी हसीना के निर्णय में बड़ी भूमिका निभाई।

जुलाई की अपनी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा संकट को कम करने के लिए पांच अरब डॉलर के कर्ज को हासिल करने की हसीना की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं, जब चीन ने महज दस करोड़ डॉलर की पेशकश की। यही नहीं, उन्हें अपेक्षित प्रोटोकॉल भी नहीं मिला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें पर्याप्त समय तो नहीं ही दिया, चर्चा को आगे बढ़ाने का दायित्व भी प्रधानमंत्री ली केकियांग पर छोड़ दिया। निराश होकर हसीना को अपना दौरा छोटा करना पड़ा। चीन के इस रुख के व्यवहार से गहरी रणनीतिक गणनाओं के संकेत मिलते हैं, जो उनके तख्तापलट में चीन की भागीदारी के बारे में लगाए जा रहे अनुमानों को मजबूत आधार भी देते हैं।

दक्षिण एशिया में चीन का सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तान भी संदेह पैदा करता है। भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते पाकिस्तान को हमेशा से ही नागवार गुजरे हैं। हसीना के कार्यकाल से पहले पाकिस्तान के आतंकी समूह बांग्लादेश में अपेक्षया ज्यादा आजादी के साथ काम करते थे। 2009 में हसीना द्वारा बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने बांग्लादेश राइफल्स के भीतर विद्रोह भड़का कर उनकी सरकार को अस्थिर बनाने का असफल प्रयास भी किया था।

हालांकि हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन ने हसीना के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दीं। ओपनपी के साथ ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध करने वाले जमात-ए-इस्लामी कैडरों ने भी छात्र आंदोलन का पूरा फायदा उठाया। नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम लड़ा गया, तब जमात ने अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उनके सदस्यों को ही रजाकार कहा जाता था। यह संकेत भी मिलते हैं कि विपक्षी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने कथित तौर पर लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों के चलते लंदन में रह रहे तारिक अब बांग्लादेश वापसी कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी भागीदारी साबित करना तो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये देश खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन यह स्पष्ट है कि छात्र आंदोलन ने अराजकता की जो आग भड़काई, उसमें कई विदेशी ताकतों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। भू-राजनीतिक पेचीदगियां यह भी रेखांकित करती हैं कि शेख हसीना किस तरह दक्षिण एशिया की जटिल अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनीं।

जीवन धारा

अल्बर्ट आइंस्टीन

हम सभी कलाकार हैं और अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तर्क और ज्ञान 'ए' से 'जेड' तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी।

कल्पना करना सीखें और सुंदर संसार बनाएं

जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि मानो कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा यह कि मानो सब कुछ चमत्कार है। हम सभी एक कलाकार हैं और अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है। कल्पना दुनिया को घेर लेती है। तर्क और ज्ञान आपको 'ए' से 'जेड' तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। हमारा जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। और कभी गलती करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मनुष्य उस समग्रता का एक हिस्सा है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, समय और स्थान में सीमित एक हिस्सा। वह खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी सब से अलग अनुभव करता है, यह चेतना का एक प्रकार का दृष्टि संबंधी भ्रम है। यह भ्रम हमारे लिए एक प्रकार का कारागार है, जो हमें हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारे सबसे करीबी कुछ लोगों के प्रति स्नेह तक सीमित कर देता है।

हमारा काम सभी जीवित प्राणियों और पूरी प्रकृति को उसकी सुंदरता में गले लगाने के लिए अपनी करुणा के दायरे को बढ़ाकर खुद को इस कैद से मुक्त करने का होना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग छोटी-छोटी बातों में सत्य के प्रति लापरवाह हैं, उन पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा जो सोचते हैं, उससे चीजें अलग होती हैं। कुछ बातें, जो सही हैं, वे हमेशा लोकप्रिय नहीं होतीं और जो लोकप्रिय है, वह हमेशा सही नहीं होता। और आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसको हम लोगों ने ही बनाया है, वह हमारी सोच की प्रक्रिया है। सोच बदले बिना हम इसे बदल नहीं सकते। इस बदलाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग हार मानते हैं, जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बुद्धि स्कूली शिक्षा का परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयास करने होते हैं। हमें उस एकांत में रहना चाहिए, जो युवावस्था में कष्टदायक है, लेकिन परिपक्वता के वर्षों में सुखद हो। कुछ लोग हमारे आसपास केवल इसलिए अच्छे हैं, क्योंकि वे दंड से डरते हैं और पुरस्कार की आशा करते हैं, तो यह वास्तव में बहुत दुखद है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा न हो और भविष्य में आपके बच्चे बुद्धिमान बनें, तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान बनें, तो उन्हें अधिक परियों की कहानियां सुनाएं। जिज्ञासा के अतिरिक्त जो अपना कारण है। जब कोई अनंत काल, जीवन और वास्तविकता की अद्भुत संरचना के रहस्यों पर विचार करता है, तो वह विस्मय में पड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस रहस्य को थोड़ा-बहुत समझने का प्रयास करता है, तो यह पर्याप्त है।

प्रकृति को गहराई से देखें

सूत्र

केवल दूसरों के लिए जीया गया जीवन ही जीने योग्य है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए नहीं जीना चाहता, सभी अपने लिए जीना चाहते हैं। और इसका परिणाम उन्हें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को गहराई से देखना होगा, और तभी हम कुछ सीख पाएंगे और सब कुछ बेहतर समझ पाएंगे।

दूसरा पहलू

वैज्ञानिक डेविड कीथ सूर्य की कुछ रोशनी को रोकने के लिए आकाश में एक प्रदूषक पदार्थ का छिड़काव करना चाहते हैं।

सूरज की किरणों को रोकने की खतरनाक योजना

डेविड कीथ 1991 में जब स्नातक के विद्यार्थी थे, तब फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फटा और आकाश में दूर तक राख के बादल छा गए थे। माउंट पिनाटुबो से निकला 1.7 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में फैल गया, जो सूर्य की कुछ ऊर्जा को धरती तक आने से रोक रहा था। इसी वजह से अगले वर्ष उत्तरी गोलार्ध के औसत तापमान में एक डिग्री फारेनहाइट की गिरावट आई थी।

उस घटना का जिक्र करते हुए, 60 वर्षीय डॉ. कीथ कहते हैं कि उससे उन्हें एक अद्भुत विचार आया कि समताप मंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छिड़कने से दुनिया भर के तापमान को कम किया जा सकता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सकेगा। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर, इस तरह के हस्तक्षेपों को गंभीरता से लिया जा रहा है। वैश्विक तापमान लगातार रिकॉर्ड 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिससे चरम मौसमी घटनाएं, घातक गर्मी की लहरें और समुद्र का स्तर बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह गर्मी अगले कई दशकों तक यों ही बढ़ेगी। वार्मिंग का मुख्य कारक, जीवाश्म ईंधन का जलना बताया जाता है, जो बेरोकटोक जारी है। यही वजह है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की दिशा को तकनीकों के सहारे उलट देने के प्रयासों में पूरी दुनिया रुचि दिखा रही है, जिसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वैक्यूम करके भूमिगत करने के वृहद प्रयास पहले से चल रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक बादलों को चमकाने के प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस भेजने के तरीके ईजाद कर रहे हैं। अन्य लोग महासागरों व पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में सक्षम बनाने के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। लेकिन समताप सोलर जियोइंजीनियरिंग इन सब विचारों से परे है। इस विधि के जो समर्थक हैं वे इसे तापमान को कम करने का सस्ता और तेज तरीका मानते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक व पर्यावरणविद आशंकित हैं कि इस तकनीक के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित आपदाएं भी आ सकती हैं। इसके विपरीत डॉ. कीथ कहते हैं, 'अगर तकनीक से तापमान को केवल एक डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फारेनहाइट तक भी कम कर दिया जाता है, तो यह हर दशक में गर्मी से होने वाली लाखों मौतों को रोकने में मदद कर सकती है।' वह कहते हैं, 'सोलर जियो इंजीनियरिंग पर जोर देने का तर्क मजबूत है।'

डेविड गेस्स

पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की दिशा को तकनीकों के सहारे उलट देने के प्रयासों में पूरी दुनिया रुचि दिखा रही है, जिसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं।

डॉ. कीथ कहते हैं, 'अगर तकनीक से तापमान को केवल एक डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फारेनहाइट तक भी कम कर दिया जाता है, तो यह हर दशक में गर्मी से होने वाली लाखों मौतों को रोकने में मदद कर सकती है।'

आंकड़े

राजकोष

देश के राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र का खास योगदान है। पांच वर्षों में केंद्र व राज्यों को मिलाकर करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

2023-24	7,51,156
2022-23	7,48,718
2021-22	7,74,425
2020-21	6,72,719
2019-20	5,55,370

आंकड़े करोड़ रुपये में और 2023-2024 के अनंतिम हैं। | स्रोत : PPAC

पृथ्वी पर अवतीर्ण होने से पहले गंगा के सवाल का जवाब देते हुए भगीरथ ने कहा कि जब संत आपके अंदर स्नान करेंगे, तो उनके स्पर्श से सारे पातक धुल जाएंगे।

गंगा ने पूछा-पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा

अंतर्यात्रा
संकलित

इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र भगीरथ भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर की तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा जब भगवान शंकर की जटा से निकलकर आगे बढ़ रही थीं, तो भगीरथ दिव्य रथ में सवार होकर आगे-आगे जा रहे थे। वह गंगासागर के पास पहुंचे और कपिल की तीव्र दृष्टि से भस्म हुए अपने पूर्वजों की राख को गंगाजल में प्रवाहित कर उनकी मुक्ति करवाई।

श्रीमद्भागवत में गंगा के अवतीर्ण होने से पहले उनके और भगीरथ के बीच संवाद का वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पाप धोएंगे, तो उनके पाप भी मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जब इतने सारे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा? भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, 'जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है, जो शांत, ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब आपके अंदर स्नान करेंगे, तो उनके अंग स्पर्श से आपके अंदर प्रवेश करने वाले समस्त पातक (पाप) धुल जाएंगे, क्योंकि समस्त पातकों का नाश करने वाले श्रीहरि संतों के हृदय में विराजमान रहते हैं।' इसके बाद गंगा जी ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। भगीरथ ने गंगा जी से कहा कि आपने हमारे ऊपर जो दया की है, उससे जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक ये पृथ्वीवासी आपका गुणगान करते रहेंगे।

आज का इतिहास

8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत

देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया था। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आठ अगस्त का दिन अफगानिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। 1988 में आठ अगस्त के दिन ही नौ वर्ष के युद्ध के बाद अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी की शुरुआत हुई थी। 1509 में विजय नगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1609 में वेनिस की सीनेट ने गैलिलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया। 1763 में वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ। 1876 में थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया। 1899 में ए.टी. मार्लन ने रेफ्रीजरेटर का पेटेंट कराया। 1900 में बोस्टन में पहली डेयिस कप श्रृंखला की शुरुआत। 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म। 1919 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आजादी को मंजूरी दी।

एआई के ऊर्जा खपत के आंकड़े चौंकाते हैं

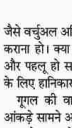

एआई डाटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली-पानी का उपयोग हो रहा है। पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा।

मुकुल श्रीवास्तव | मुद्दा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन रही है। वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर स्मार्ट होम हर जगह एआई है। चाहे चैट-जीपीटी जैसे एआई जनित प्लेटफॉर्म पर जटिल प्रश्नों के हल जानना हो या गूगल व एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स पर अपनी आवाज से कोई काम कराना हो। क्या अचंभित करने वाली तकनीक के कुछ और पहलू हो सकते हैं? जो पर्यावरण व मानव सभ्यता के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं?

गूगल की वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में गूगल के डाटा केंद्रों पर कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट में तेरह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उसके डाटा केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बिजली की खपत बढ़ने से हुई। वर्ष

2023 में उसके डाटा केंद्रों ने पहले की तुलना में 17 फीसदी अधिक बिजली का उपयोग किया। एआई टूल्स के इस्तेमाल से यह वृद्धि और बढ़ेगी। एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है, जिनमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े समाधान भी शामिल हैं। लेकिन बढ़ती एआई तकनीक ने एक भारी कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। अध्ययनों से पता चलता है कि एआई चैटबॉट चैट-जीपीटी पर पूछी गई एक साधारण जानकारी, गूगल खोज की तुलना में 10 से 33 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है। वहीं, इमेज आधारित प्लेटफॉर्म पर इससे कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होती है। दरअसल, एआई मॉडल सामान्य गूगल खोज की तुलना में अधिक डाटा को प्रोसेस और फिल्टर करते हैं। अधिक काम का मतलब है कि कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक काम करने से उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए डाटा केंद्रों पर अधिक शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग और अन्य ठंडे उपाय किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के एक अध्ययन के मुताबिक साल 2022 में, गूगल ने अपने डाटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए लगभग 20 अरब लीटर ताजे पानी का उपयोग किया। बीते साल माइक्रोसॉफ्ट की जो लेट खपत में पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में डाटा केंद्रों की खपत वैश्विक बिजली की खपत का 1 से 1.3 प्रतिशत है, मगर जैसे-जैसे एआई टूल्स का उपयोग बढ़ेगा, यह खपत भी बढ़ती जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, यह आंकड़ा तीन प्रतिशत तक जा सकता है। इसके विपरीत, बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बावजूद, ई-वाहनों की वैश्विक बिजली खपत केवल 0.5 फीसदी है। वहीं, कई देशों में डाटा केंद्रों की ऊर्जा खपत उनकी राष्ट्रीय मांग की दहाई हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। आयरलैंड जैसे देश जहां टैक्स में छूट और प्रोत्साहन के कारण डाटा केंद्रों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। आयरलैंड सेंट्रल स्टैटिस्क ऑफिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यह हिस्सेदारी 18 प्रतिशत पहुंच गई। भारत में भी एआई और डाटा केंद्रों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यहां इनके ऊर्जा और जल खपत के आंकड़े अभी सीमित हैं, लेकिन एआई के बढ़ते उपयोग के साथ, यह स्थिति बदल सकती है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बंगलूरू पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। बंगलूरू में डाटा केंद्रों की संख्या सोलह है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बंगलूरू के अलावा दिल्ली, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में भी डाटा केंद्रों में पानी की खपत बढ़ गई है। भारत में स्थापित डाटा केंद्रों की क्षमता दो हजार मेगावाट से 2029 तक 4.77 हजार मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। जिसमें पहले से पानी की कमी से जूझ रहे भारत के सिलिकॉन वैली की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां डाटा केंद्रों के शीतलन के लिए अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकृत कर इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं भारतीय डाटा केंद्र अब भी ताजे पानी की आपूर्ति पर निर्भर हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 176 (रजि.नं. 13045/59 आएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

विचार

एषा ब्राह्मी स्थिति : पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।

भावार्थ : हे अर्जुन! चित्त में परमशांति की स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त होकर जो योगी हो जाता है, फिर वह कभी मोहित नहीं होता। वह अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाता है।

ओलिंपिक में अनहोनी

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेरिस ओलिंपिक में पदक की सुनिश्चित दावेदार विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गईं। उनसे स्वर्ण पदक की आशा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले के सभी मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई नामी पहलवानों को हराया था, लेकिन अंतिम मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वजन सौ ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही उनका सपना तो टूटा ही, देशवासियों की आशाओं पर भी तुषारपात हो गया। चूंकि एक तरह से हाथ आया पदक फिसल गया, इसलिए अफसोस अधिक है। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रसंग से सबक भी लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो। इस ओलिंपिक में विनेश ने 53 किलोग्राम के अपने स्वाभाविक भार वर्ग को छोड़कर 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ना तय किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह अपने वजन को नियंत्रित रखने का उतना अभ्यास नहीं कर पाईं, जितना आवश्यक था। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जितनी किसी खिलाड़ी की होती है, उतनी ही उसके कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी। विनेश के मामले में कहां क्या चूक हुई, इसकी जवाबदेही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की है। उन्होंने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा है और यह स्पष्ट किया है कि विनेश का वजन नियंत्रित रखने के लिए वह सब कुछ किया गया, जो संभव था, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ भूल-चूक हुई ही। यह किन कारणों से हुई, यह सामने आना चाहिए।

विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने और इस तरह भारत के पदक से वंचित होने पर देशवासियों की ओर से अपनी निराशा व्यक्त किए जाने के बीच कुछ नेताओं की ओर से जैसे अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं, वे उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शा रहे हैं। यह समझ आता है कि उन्हें न खेल की जानकारी है और न ही खेल के नियमों की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे जो मन में आए, वह बोल दें। कोई विनेश के साथ साजिश की कहानी गढ़ रहा है तो कोई उन्हें अयोग्य करार देने में किसी नेता का हाथ देख रहा है। यह सब इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ धरना-प्रदर्शन में भाग लिया था। निःसंदेह विनेश का मुकाबले से बाहर हो जाना और उन्हें कोई पदक न मिलना आहत करने वाला है, लेकिन खेलों के अपने नियम होते हैं। वे हमारे या किसी अन्य के हिसाब से नहीं बदल सकते। विनेश के मामले में साजिश की कहानियां गढ़ रहे लोग इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ था। इस मामले में कम से कम नेताओं की प्रतिक्रियाएं जगहंसाई कराने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है।

उद्योगों से प्रदूषण

प्रदेश में उद्योगों से हो रहा प्रदूषण अब चौतरफा चिंता का कारण बन चुका है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने यह स्वीकारा है कि प्रदेश में लगभग 60 ऐसे स्पंज आयरन व सीमेंट प्लांट हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। यह भी कहा गया कि ये उद्योग तय मानकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण औद्योगिककुनियों के साथ आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह प्रदूषण खतरा बना हुआ है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही जिस अव्यवस्थित तरीकों से यहां के शहरों में उद्योग लगाए गए, आज उसका दुष्परिणाम प्रदेश के सभी बड़े नगर भुगत रहे हैं। वायु प्रदूषण को लेकर तय मानकों को लेकर प्रदेश में गंभीरता नहीं दिखाई गई। मनमाने तरीके से उद्योग लगे और मनमाने तरीके से ही संचालित होते रहे। आज भी स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। कोरबा, रायपुर, जांजगीर चांपा, भिलाई, बिलासपुर जैसे नगरों के लाखों लोग इस प्रदूषण के साथ जीने को विवश हैं। राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में दिया गया यह तर्क कि ये उद्योग तय मानकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सर्वथा अस्वीकार्य है। यदि ये उद्योग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार का संबंधित विभाग क्या कर रहा है, अब इसे लेकर सरकार को हाई कोर्ट को लिखित में अवगत कराना होगा। देशभर में होने वाले स्वच्छ वायु वाले नगरों के सर्वे में प्रदेश के कई शहर स्थान पाते रहे हैं। समझा जा सकता है कि इन नगरों में रहने वाले लोग किस स्तर का जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं। समय की मांग है कि पूर्व से जो अनदेखी जानबूझकर की गई, अब उन्हें पूरी गंभीरता के साथ सुधार किया जाए। आशा है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में शीघ्रता के साथ कदम उठाएगी।

समझा जा सकता है कि इन नगरों में रहने वाले लोग किस स्तर का जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं। समय की मांग है कि पूर्व से जो अनदेखी जानबूझकर की गई, अब उन्हें पूरी गंभीरता के साथ सुधार किया जाए। आशा है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में शीघ्रता के साथ कदम उठाएगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

नईदुनिया जनमत — कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए?

आज का सवाल
क्या स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी वापस लेने की मांग सही है?

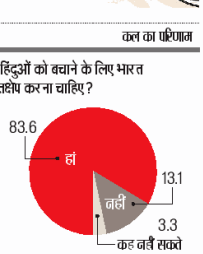

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अस्थिर पड़ोसियों से घिरता भारत

ऋषि गुप्ता

बांग्लादेश में तख्तापलट और अराजकता के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है। यह स्थिति भारत के हित में नहीं

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के मुद्दे पर भारतीय संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ बैठक के बाद स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया और 'कुछ समय के लिए' उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत में हैं और माना जा रहा है कि वह किसी तीसरे देश में शरण मिलने तक यहीं रहेंगी। यदि इस हालात को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक असाधारण स्थिति है, जहां भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मदद भी करनी है। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई अनधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम से देश के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति पैदा हो गई है। भारत के समक्ष 1971 वाली स्थिति फिर एक बार बन पड़ी है। बांग्लादेश में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समूह खासकर बड़ी संख्या में हिंदू भारत में शरणार्थी के तौर पर आने की गुहार लगा सकते हैं। इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं।

अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता है, जिसकी भरी-पूरी आशंका है तो भारत की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ गुटों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इसके चलते ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे हैं। पाकिस्तान आज तक भारत को अपने विभाजन यानी बांग्लादेश के निर्माण का कारण मानता रहा है और वह कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी और असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया जाए। बांग्लादेश में अराजकता के बीच दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है, जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीते दिनों ही नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। ओली को 'इंडिया आउट' अभियान का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी राजनीतिक साख मजबूत करने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया है। चूंकि ओली की 'राष्ट्रवादी छवि' भारत विरोध से बनी है, लिहाजा भारत के लिए जरूरी है कि वह स्थिति पर नजर रखे। यदि नेपाली जनता पुरानी पार्टियों और पुराने नेताओं की कार्यशैली

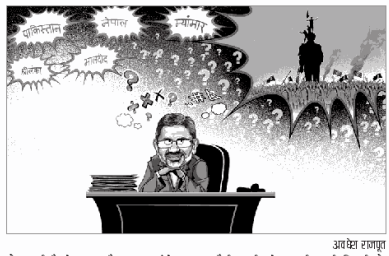

अवधेश राजपूत

से ऊबती है तो 2006 जैसा जन आंदोलन छिड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका सीधा असर खुली सीमा के चलते भारत पर होगा। नेपाल के बगल में ही भूटान है, जो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर फिक्रमंद है और एक मित्रतापूर्ण सहयोगी रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने वहां भी अपनी पैठ बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भारत के लिहाज से भूटान में स्थिति नियंत्रण में है।

पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी ढुबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। यहां विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं। यहां अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा एजेंसियां भारत-म्यांमार सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। यदि बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश में साथ आती हैं तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। नई दिल्ली के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी लुक-ईस्ट और एक्ट-ईस्ट नीति में सुरक्षा पहलुओं को भी शामिल करे। म्यांमार में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। यह सही है कि श्रीलंका धीरे-धीरे भारत और आइएमएफ की मदद से आर्थिक मुसीबतों से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी वहां भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। मालदीव भी इस मामले में अलग नहीं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोध में लगे हुए हैं। उन्होंने भी ओली की तरह 'इंडिया आउट' अभियान चलाया, फिर वह चाहे भारतीय सैन्य अधिकारियों का मालदीव से भारत वापस भेजने का मुद्दा रहा हो या फिर उनकी सरकार के मंत्रियों का भारत और भारत के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ टीका-टिप्पणी का मामला।

पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही भारत के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हाल में जम्मू में हुए आतंकी हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाने का काम किया है। यदि पड़ोसी देशों की परिस्थिति और आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत इन सभी देशों की सीमाओं के जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दक्षिण एशिया में बड़े लंबे समय से भारत की केंद्रीयता को सभी समस्याओं की जड़ माना जाता रहा है और भारत पर लगभग सभी पड़ोसी देश हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते आए हैं, लेकिन क्या अब वही देश अपनी आंतरिक हलचल के चलते भारत के सामने मौजूद सुरक्षा संकट पर नई दिल्ली के साथ खड़े होंगे? इसका जवाब संभवतः नकारात्मक ही मिले। दक्षिण एशिया में जैसी असामान्य परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए भारत को असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत को हर कीमत पर अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है और पड़ोसी देशों में सिविल सोसायटी समूहों के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों और क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है कि वे भारत की चिंताओं को समझें और अपने स्तर पर पाकिस्तान और चीन पर दबाव डालें, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत को परेशान करने के लिए नई तिकड़में न कर सकें।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

युवाओं में कौशल विकास की चुनौती

बजट पेश होने के बाद उसके प्रस्तावों पर अमल की दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में सभी की निगाहें रोजगार सृजन की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर टिकी हैं, जिन्हें हालिया बजट का सबसे विशिष्ट पहलू माना जा रहा है। कौशल, नवाचार और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विशेष प्रविधान किए हैं। इसमें इंटर्नशिप योजना को खासी चर्चा भी मिली है। इससे न केवल रोजगार के आकांक्षियों के हितों की पूर्ति होगी, बल्कि उद्योगों को भी अपने अनुकूल कौशल से लैस लोग मिलेंगे। इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बल्कि निवेश संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे सरकार की यह मंशा भी प्रकट हुई है कि अगले पांच वर्षों में वह रोजगार, कौशल और एमएसएमई पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को भुनाने की राह में कार्यशील आबादी में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी न होने का संज्ञान भी सरकार ने लिया है। इसके लिए कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल के निकट महिला हास्टलों और शिशु देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी फोकस किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में भी उल्लेख है कि देश में बढ़ते कार्यबल के समायोजन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करनी होंगी। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई। बजट में युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। कुल मिलाकर, पांच साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षित, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए बजट में प्रविधान है कि पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को शुरुआती चार वर्षों में ईपीएफओ में योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन

डा. सुरजीत सिंह

यह समझा जाना बहुत आवश्यक कि अपने देश में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है

बढ़ाने होंगे रोजगार के अवसर • फाइल

दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। नियोक्ताओं को सहायता देते हुए यह उपाय भी किया गया है कि सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के संबंध में नियोक्ता के ईपीएफओ में अंशदान के लिए उन्हें दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री की यह पहल औपचारिक रोजगार सृजन की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है, जिससे सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिकता के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी। इससे अधिक स्नातकों को नौकरी के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

भारत में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। बढ़ती श्रमशक्ति और कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की दृष्टि से पांच वर्षों में देश की 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना एक बाजी पलटने वाली योजना सिद्ध हो सकती है, लेकिन तभी जब कंपनियां इस योजना में रुचि दिखाएं। इस योजना में 5,000 रुपये के मासिक भत्ते और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता आकर्षक पहलू हैं। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल प्रदान करना है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान करने के साथ ही हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के तीन प्रतिशत ब्याज में छूट भी मिलेगी। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 1000 आइटीआइ को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा। उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे नई उभरती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर जोर देने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलने के आसार हैं। प्रत्येक वर्ष 25,000 कुशल व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक का गारंटीकृत ऋण प्रदान करना निश्चित रूप से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने से इस क्षेत्र की तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है। पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल विभाग का नाम भी बदलकर कौशल, रोजगार और आजीविका कर दिया है। बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन से आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, केंद्र के स्तर पर तमाम पहल तभी सफल हो पाएंगी, जब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करेंगी। इन कार्यक्रमों को यदि गंभीरता से लागू किया जाता है तो भारत को एक अग्रणी स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

ऊर्जा

संबंधों की सजीवता

किसी की संगति में ही इस व्यक्ति के प्रति गहरी समझ और संवेदना विकसित होती है। यह मेलजोल प्रायः लोगों की समान रुचियों, सोच और जीवन की दिशा पर आधारित होता है। एक दूसरे के सान्निध्य और संगति में दोनों एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और एक मजबूत संबंध की नींव रखते हैं। यह संबंध तब फलता-फूलता है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे के महत्व को समझते हैं। स्मरण रहे कि कोई भी संबंध सब कुछ सह लेता है, लेकिन उपेक्षा नहीं सह सकता है।

समय के साथ व्यक्ति का सोच और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी-कभी ये बदलाव धीरे-धीरे व्यक्ति को अपने पूर्व संबंधों से दूर भी कर देते हैं। किसी नई जिम्मेदारी या नई रुचियों के कारण व्यक्ति पुरानी मित्रता को उतना समय और महत्व नहीं दे पाता है,जितना पहले देता था। इस प्रक्रिया में वह दूसरे व्यक्ति को उपेक्षित महसूस करा सकता है। प्रायः व्यक्ति को उस संबंध में वह अनुभूति नहीं मिलती, जो पहले अनुभव होती थी। जब किसी संबंध में नवीनता समाप्त हो जाती है, तो उदासीनता का भाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति उस संबंध को महत्व देना बंद कर देता है।

इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने संबंधों के प्रति संवेदनशील रहे। अगर किसी संबंध में कोई परिवर्तन आता भी है तो इसे ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है और उनके महत्व को पुनः स्वीकार कर सकता है। संबंधों में उतार-चढ़ाव और परिवर्तन सामान्य हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को महत्व देना और उसकी उपेक्षा न करना हमारे संबंधों की मजबूती के लिए एक आवश्यक अवयव है। आपसी सम्मान, संवाद और समझदारी से ही हम अपने संबंधों को सार्थक और सजीव बनाए रख सकते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

पाठकनामा

letter@naidunia.com

भारत को रहना होगा सतर्क

'अराजकता में डूबा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में दिव्य कुमार सोती ने आशंका जाहिर की है कि चीन और अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। वहां उन्हें कठपुतली सरकार मंजूर थी। चूंकि चीन अधिनायकवादी देश है तो यह बात समझ में आती है, मगर अमेरिका जो पुराने लोकतंत्रों में से एक है। उसे तो बांग्लादेश में लोकतंत्र प्रेमी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए था। उसे भारत का भी ध्यान रखना चाहिए था, जिससे उसके मित्रतापूर्ण संबंधों के कई फायदे हैं। बहरहाल वह देखने वाली बात है कि उन राष्ट्रों में लोकतंत्र कभी सफल नहीं रहा, जहां मजबूती कट्टरपंथी ताकतें मजबूत रही हैं। लिहाजा लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी तरह के कट्टरपंथ को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। जहां कट्टरपंथ अपना सिर उठाता है या उठाने की आशंका रहती है, वहीं विदेशी महाशक्तियों के दखल संभव होते हैं। भारत को नई परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है। विभाजन के बाद से भारत के साथ एक दुर्भाग्य यह जुड़ गया है कि हमारी ही भूमि से अलग हुए टुकड़े हमारे अशांत पड़ोसी बन गए हैं। भारत को इसलिए भी चौन्स रहना होगा ताकि इन पड़ोसियों के मंसूबे भारत में सफल न होने पाएं।

– मुकेश कुमार मनन, पटना, बिहार

जिस इस्कान ने पेट भरा, उसी से धोखा

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बने इस्कान मंदिर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। यह वही मंदिर था, जिसने 1971 के युद्ध में लाखों भूखे बांग्लादेशियों को भोजन करवाया था। बांग्लादेशी लोग तब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और दरबदर थे। तब इस्कान के स्वामी प्रभुपाद ने हिंदुओं से मदद की अपील कर 25 लाख डालर एकत्रित किए थे और दो लाख भूखे बांग्लादेशियों छह माह तक भोजन खिलाया गया। इसे ही कहते हैं सांप को दूध पिलाना। हिंदुस्तान ने उस समय लाखों लोगों को शरण दी थी। हर जनता ने शरणार्थी सहायता टैक्स अदा किया था ऐसे एहसान फरामोश देश और उसके लोगों को कभी सहायता नहीं देना चाहिए। बेहतर होगा कि बांग्लादेश की सीमा सील की जाए।

– अरविंद जैन, शंकुक मार्ग, प्रीयंज, उज्जैन

विनेश मामले में राजनीति बंद हो

समाचार : भारतीय पहलवान विनेश फोगाट तय सीमा से 100 ग्राम अधिक वजन के कारण ओलिंपिक में अयोग्य करार दी गईं।

टिप्पणी : यह 100 ग्राम वजन देश के करोड़ों देशवासियों के मन पर कितना भारी पड़ा है, इसका अंदाजा किसी को न होगा। बहरहाल, हम भारतीयों को इस मामले में तार्किक होना चाहिए, न कि भावुक। इसमें मूर्खतापूर्ण राजनीति बंद हो।

– रामेश्वर पवार, वेदनगर, नानाखेड़ा, उज्जैन

इजरायल से सीखें अपनी रक्षा करना

बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है, वह भारत के रहवासियों को बहुत कुछ सिखाता है। वहां मंदिरों को तोड़ने सहित हिंदुओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वैसी घटनाएं हिंदुओं के साथ बीते 1000 वर्षों से हो रही हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि न तो हिंदुओं ने कोई सबक सीखा और न ही स्वयं की सुरक्षा के लिए कभी तैयार या सन्नद्ध दिखे। भारत के नागरिकों को अब इजरायल के यहुदियों से अपनी सुरक्षा करना सीखना चाहिए। इजरायल छोटा सा देश है और चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद न तो वह कभी किसी से हारता है और न ही पीछे हटता है। वहां की सरकार और नागरिक ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अपनी व अपने धर्म की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहां जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ आदि के नाम पर लोग आपस में झगड़ने और बंट जाने के बजाय एकजुट होकर अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। वह कौम कठोर परिश्रम करती है और ज्ञान तथा विज्ञान को साधती है। इसके उलट हमारे यहां जाति, पंथ में बंटे हुए लोगों को खुद की सुरक्षा का होश नहीं है। अब समय है कि सब संभलें और अपना दृष्टिकोण सही दिशा में करें।

–हरिहर चौहान, इंदौर व प्रदीप वर्मा, राजगढ़

पोस्ट

अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके मंदिरों की रक्षा क्यों और किससे करनी पड़ी रही है?

हारिस सुल्तान@TheHarrisSultan

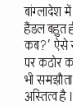

फलस्तीन के मसले पर लगातार बोल रहे देश के प्रमुख मुसलमानों से सवाल है कि क्या आपके पास अपने पड़ोस में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द है?

आमना बेगम अंसारी@Amana_Ansari

बांग्लादेश में फैली अराजकता की आड़ में बहुत से एक्स हैंडल बहुत ही धूर्तता से लिख रहे हैं, 'भारत में यह सब कब?' ऐसे सभी लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं। राष्ट्र के होने से हम सबका अस्तित्व है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

इमरान शकील खान@Imran_Shakeel_

विनेश फोगाट का 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य सिद्ध होना बेहद अफसोसनाक है। उनके अपने रूझ-पसीने के साथ पूरे देश के साधनों और आशाओं पर पानी फिरा है, लेकिन एक-दूसरे को कोसने में लगे नियमतोड़ मानसिकता वालों के लिए सबक है कि थोड़ा-बहुत चलता है का जुगाड़ बाकी दुनिया में नहीं चलता।

शिवकांत@shivkant

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/18897 जागरण प्रकाशन लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस प्लॉट नं. 47/3, भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर से मुद्रित एवं तीसरी मंजिल, कृष्णा ग्लोरी कॉम्पलेक्स, साई नगर, होटल बेवीलॉन इन के पीछे, जेल रोड, रायपुर से प्रकाशित
फोन नं. 0771-4711000 फैक्स : 0771-4711024 इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com संपादक : सद्गुरु शरण* *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार

****

सन्मार्ग
पटना, गुरुवार 08 अगस्त 2024
www.live7tv.com

घर के मुखिया को सर्वप्रथम खुद नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसका प्रभाव लोगों पर होता है। कई बार घर के बड़े लोग सबके लिए नियम कानून बना देते हैं, लेकिन खुद उसपर अमल नहीं करते। ऐसे घर में खुशियों का वास ज्यादा दिन तक नहीं रहता। इसलिए हमेशा सदस्यों के साथ-साथ खुद भी नियमों का पालन करें और सबके लिए प्रेरणास्रोत बनें।

चाणक्य

जीएम फसलों की मंजूरी को बने राष्ट्रीय नीति

पंकज चतुर्वेदी

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जेनेटेकली मोडिफाइड यानी जीएम सरसों की भारत में व्यावसायिक खेती करने की सरकारी मंजूरी के खिलाफ याचिका पर खंडित फैसला दिया। जहां न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना का आकलन था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी की 18 और 25 अक्तूबर, 2022 को सम्पन्न जिस बैठक में इसकी मंजूरी दी गई, वह दोषपूर्ण थी क्योंकि उसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति संजय करोल का मानना था कि जीईएसी के फैसले में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने जीएम सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ने की बात जरूर की। हालांकि, दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि केंद्र सरकार को जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाएगा।

वैसे जीईएसी आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों के लिए देश की नियामक संस्था है। लेकिन दो जजों की पीठ ने निर्देश दिया कि चार माह के भीतर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जीएम फसल के सभी पक्षों के परामर्श से जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे जिनमें कृषि विशेषज्ञों, जैव प्रौद्योगिकीविदों, राज्य सरकारों और किसान प्रतिनिधियों सहित हितधारक शामिल हों। किसी से छुपा नहीं कि भारत में खाद्य तेल की जबरदस्त मांग है। साल 2021-22 में 116.5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन करने के बावजूद भारत को 141.93 लाख टन का आयात करना पड़ा। अनुमान है, अगले साल 2025 -26 में यह मांग 34 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। हमारे खाद्य तेल के बाजार में सरसों तेल की भागीदारी 40 फीसदी है। दावा किया गया कि यदि सरसों उत्पादन में जीएम बीज का इस्तेमाल करेंगे तो फसल 27 प्रतिशत अधिक होगी, जिससे तेल आयात खर्च कम होगा। हालांकि यह सोचने की बात है कि 1995 तक देश में खाद्य तेल की कमी नहीं थी। फिर बड़ी कंपनियां इस बाजार में आई। आयात कर कम किया गया और तेल का स्थानीय बाजार बैठ गया। दावा यह भी है कि इस तरह के बीज से पारंपरिक किस्मों की तुलना में कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है और मुनाफा अधिक। लेकिन जीएम फसलों, खासकर कपास को लेकर हमारे अनुभव बताते हैं कि ऐसे बीजों के दूरगामी परिणाम खेती और पर्यावरण के लिए भयावह हैं। समझना होगा कि जीएम फसलों को उत्पाद के मूल जीन को कृत्रिम रूप से संशोधित किया जाता है। आमतौर पर किसी अन्य जीव से आनुवंशिक सामग्री डाली जाती है जिससे उन्हें नए गुण दिए जा सकें जैसे अधिक उपज व पोषक तत्व, कम खरपतवार, कम रोग, कम पानी हो सकते हैं।

भारत में धारा सरसों हाइब्रिड-11 (डीएमएच-11) को देशी सरसों किस्म वरुणा और यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा-2 के संकरण से विकसित किया गया है। इसमें दो विदेशी जीन बार्नेज और बार्स्टार शामिल हैं, जिन्हें बैसिलस एमाइलोलिके फैसिएन्स नामक मृदा जीवाणु से पृथक किया गया है। दावा है कि इस बीज से उपज को 3-3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है।

हमारे देश में अभी तक कानूनी रूप से केवल बीटी कपास एकमात्र जीएम स्वीकृत फसल है। बीते 17 सालों में कपास के बीज दावों पर खरे उतरे नहीं। बीटी बीज देशी बीज की तुलना में बहुत महंगा है और इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना ही पड़ा। फसल ज्यादा नहीं, लेकिन हर साल बीज खरीदना मजबूरी हो गई। विकसित देशों में भी ऐसे बीजों से उर्वर क्षमता व पौष्टिक तत्व कम हुए हैं। बीटी कॉटन बीज बनाने वाली कंपनी मोनसेंटो ने 1996 में अपने देश अमेरिका में बोलगार्ड बीजों का इस्तेमाल शुरू करवाया था। इसके नतीजे निराशाजनक रहे। दुनियाभर में कहीं भी बीटी फसल को खाद्य पदार्थ के रूप में मंजूरी नहीं मिली है। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन के बीटी बीज कुछ खेतों में बोए जाते हैं, लेकिन इस उत्पाद को इंसान के खाने के रूप में इस्तेमाल पर पाबंदी है। यूरोप में भी इस पर सख्त पाबंदी है। ऐसे में भारत में सरसों तेल के लिए बीटी पर मंजूरी शक पैदा करती है।

जीएम बीजों से उत्पन्न सरसों के फूल मधुमक्खियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस तरह के बीजों से उत्पन्न सरसों के फूलों में मधुमक्खियों को परागण तो मिलेगा नहीं, उलटे कुछ जानलेवा कीटों की वे शिकार हो जाएंगी। इससे उनके खत्म होने की आशंका है। वहीं जीएम बीज हमारे पारंपरिक बीजों के अस्तित्व के लिए खतरा है और अब बदले हुए नाम से इन्हें बैंगन-टमाटर आदि के लिए पिछले रास्ते से घुसाया जा रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार कोई दो साल पहले जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नई फसल प्रजातियां विकसित करने के शोध को मंजूरी दे चुकी है। चालाकी से जेनेटिकली मोडिफाइड के नाम पर जीन एडिटिंग तकनीक शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैसे यूरोपीय यूनियन में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जीन एडिटिंग तकनीकी और जीएम फसल अलग नहीं। जाहिर है, अदालतें जब जीएम बीजों पर कोई फैसला देंगी तो जीनोम एडिटेड प्लांट्स के नाम से ये बीज बाजार में बिक रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शानुसार गठित होने वाली कमेटी में इस नई तकनीक को यूरोपियन यूनियन की तरह जीएम ही मानना होगा।

हसीना का निष्कासन

भले ही प्रथम दृष्ट्या, बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन की वजह आरक्षण विरोधी आंदोलन से उपजा आक्रोश बताया जा रहा हो, मगर इस आक्रोश की बुनियाद सात माह पूर्व हुए चुनाव में अनियमितताओं के बाद ही पड़ गई थी। हाल के दिनों में व्यापक पैमाने पर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद त्यागकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पिछले करीब तीन सप्ताह में हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में तीन सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। दरअसल, इस संकट की मूल वजह एक लोकतांत्रिक नेतृत्व का तानाशाह बनना बड़ा कारण रहा। वास्तव में लगातार चार बार प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने जनाक्रोश को हल्के में लिया। जिससे बांग्लादेश के जनमानस में गहरे तक यह भाव पैदा हुआ कि उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि, पाक परस्त राजनीतिक दलों ने इस आक्रोश को अपने लिये सत्ता का रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन इस संकट को शह देने में कई विदेशी ताकतें भी पीछे नहीं रही। दरअसल, महज सात माह पहले हुए आम चुनावों के बाद से ही देश में जनाक्रोश धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। दक्षिणपंथी रुझान वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य राजनीतिक दलों ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था। हालांकि,शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में तो आई, लेकिन विपक्षी दल जनता में यह संदेश देने में कामयाब रहे कि चुनावों में धांधली हुई है। इस तरह चुनावों के संदिग्ध तौर-तरीकों ने शेख हसीना की जीत को धूमिल कर दिया। जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अच्छा संदेश नहीं गया। तभी पिछले महीनों में अपनी सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु शेख हसीना ने भारत व चीन की यात्रा की थी। हालांकि, इस दौरान देश में स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। वास्तव में शेख हसीना लगातार विस्फोटक होती स्थितियों का सावधानी से आकलन नहीं कर पायी। आरक्षण आंदोलन को दबाने के लिये की गई सख्ती ने आग में घी का काम किया। हालांकि, लगातार चौथी बार सरकार बनाने वाली शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश के मूल में तात्कालिक कारण अतार्किक आरक्षण ही रहा, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल व उनके आनुषंगिक संगठन सरकार को उखाड़ने के लिये बाकायदा मुहिम चलाये हुए थे। दरअसल, वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों के लिये उच्च सरकारी पदों वाली नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण का विरोध छात्रों ने किया।

ओपी जिन्दल: महान व्यक्तित्व एवं प्रेरणा स्रोत

उत्तम कुमार सिन्हा

ओपी जिन्दल, जिन्हें प्यार और सम्मान से बाऊजी पुकारा जाता है, एक महान दूरद्रष्टा थे। मातृभूमि के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरताकी राह दिखाई। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता से ओपी जिन्दल ग्रुप जैसे विशाल औद्योगिक समूह की स्थापना की, जो आज राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है, पूरी मानवता को भी एक नई दिशा दिखा रहा है। वे जननायक थे, जिन्होंने आजीवन दलितों-पिछड़ों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के लिए संघर्ष किया। बाऊजी की दूरदर्शिता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 50 साल पहले ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और देश का भाग्य बदलने में अग्रणी भूमिका निभाई। बाऊजी की 94वीं जयंती पर शत शत नमन। हरियाणा के हिसार जिले स्थित नलवा गांव में 7 अगस्त 1930 को एक किसान परिवार में जन्मेओपी जिन्दल को बचपन से ही मशीनों से लगाव था। उनकी मौलिक सोच, बदलाव लाने का उनका जुनून और इन सबसे बढ़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये गए उनके प्रयास ने उन्हें मशीनों से बात करने वाले शख्सियत के रूप में विश्व विख्यात कर दिया।उनका जन्म भले ही हरियाणा में हुआ हो, लेकिन पूरा भारत उनकी कर्मभूमि था।जिन्दल ने 1952 में कोलकाता के निकट लिलुआ में एक स्टील पाइप, बेंड और सॉकेट फैक्ट्री लगाई और जन्मभूमि की सेवा के लिए वे वापस हिसार लौट आए। 1960 में उन्होंने हिसार में एक फैक्टरी लगाई जो आधुनिक भारत का एक गौरवपूर्ण मंदिर यानी ओपी जिन्दल ग्रुप का आधार बनी।

वे एक जन्मजात इंजीनियर थे। उन्होंने स्वदेशी तकनीक पर आधारित जिन्दल इंडिया नामक एक पाइप मिल की स्थापना की, जिसे आज जिन्दल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। 1970 में उन्होंने जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड की स्थापना की और शुरू से ही अनुसंधान पर ध्यान दिया। इसके बाद जिन्दल सॉ, जेएसडब्ल्यू, जिन्दल स्टेनलेस और जिन्दल स्टील एंड पावर के रूप में इस वटवृक्ष का विकास हुआ जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टील, पावर, माइनिंग, एवं इन्फ्रास्ट्रक्टर सेक्टर में उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। हिसार में सफलता के बाद बाऊजी ने छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्य प्रदेश) को अपनी कर्मभूमि बनाया, जहां से उन्होंने पूरे विश्व में समूह के विस्तार की योजना बनाई। रायगढ़ में जेएसपी का कोयला आधारित स्पंज आयरन प्लांट, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा है, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। 1990 के दशक में उन्होंने सीजीपी (कोयला से गैस बनाने का प्लांट) आधारित डीआरआई (डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन) यानी स्पांज आयरन प्लांट के बारे में सपना देखा, जिसे जेएसपी के ओडिशा स्थित अंगुल प्लांट में सपना किया उनके बेटेनवीन जिन्दल ने। दुनिया में अपनी तरह के इस पहले प्लांट से बाऊजी की दूरदृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है।

एक अग्रणी उद्योगपति के रूप मेंबाऊजी ने सफलतापूर्वक सिर्फ उद्योग स्थापित नहीं किये बल्कि अपने प्लांट के आसपास रहने वाले समुदायों के कल्याण के लिए भी सदैव चिंतनशील रहे। आज भले ही सीएसआर (कंपनी सामाजिक दायित्व) आम बोलचाल में शामिल हो गया है लेकिन बाऊजी शुरू से ही समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने जहां कहीं भी फैक्टरी लगाई, वहां के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। उनका दर्शन था,ह्वह उद्योग सफल नहीं हो सकता, जिसके आसपास का समाज विफल हो।ह्व

इस्पात जगत के पुरोधा, स्वच्छ राजनीति के शिखर पुरुष और सामाजिक विकास के जननायकओपी जिन्दल ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। उनके जीवन और उपलब्धियों को आधुनिक प्रबंध सिद्धांतों में शामिल कर पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ओपी जिन्दल ग्रुप जैसे विशाल औद्योगिक समूह के संस्थापक और अग्रणी राजनेता होने के बावजूद बाऊजी ने कभी भी अपने कार्यालय का दरवाजा बंद नहीं रखा। आम हो या खास, सभी के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहे। उन्होंने कभी कोई सचिव नहीं रखा और वे लोगों से सीधे मिला करते थे। वे सभी के लिए सदैव सुलभ और उपलब्ध थे।अपने लोगों से वे हद से ज्यादा स्नेह करते थे और उनका ख्याल रखते थे। सुख-दुखमें उनके अभिभावक थे।

बाउजी ने राजनीति में आकर जनसेवा की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की संपन्नता के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। वे तीन बार हिसार से विधायक रहे और 1996 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद बनकर राष्ट्र की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। 2005 में वे हिसार से पुनः विधायक बने और उन्हें हरियाणा का ऊजार्मंत्री बनाया गया।

समाजसेवा के प्रति समर्पित रहते हुए बाऊजी ने यह सुनिश्चित किया कि गरीब, जरूरतमंद, दलितों औरपिछड़ों को आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों से लाभ मिले।उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने के पर्याप्त अवसर पैदा हों।

समाज के संतुलित एवं सौहार्द्रपूर्ण विकास की सकारात्मक सोच रखने वाले बाऊजी का ह्वराष्ट्र प्रथम-लोग प्रथमह्व का दर्शन आज ओपी जिन्दल ग्रुप की नीतियों और कार्यक्रमों की आधारशिला है। संपूर्ण ओपी जिन्दल ग्रुप राष्ट्र के प्रति बाऊजी की प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है।

बाऊजी उम्मीद के दीपपुंज थे। जो कोई उनके पास आता, वो उनका मुरीद बन जाता था। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके लाखों प्रशंसक थे। ये उनके दिये हुए संस्कार ही हैं कि उनके चारों बेटेपृथ्वीराज जिन्दल (जिन्दल सॉ),सज्जन जिन्दल (जेएसडब्ल्यू),रतन जिन्दल (जिन्दल स्टेनलेस) औरनवीन जिन्दल (जेएसपीएल) आज उद्योग जगत के अग्रणी सितारों में गिने जाते हैं। ये सभी एक बेहतर कल के निर्माण के प्रति समर्पित हैं। इसी कड़ी में तीसरी पीढ़ी के सुश्री स्मिनू जिन्दल,पार्थ जिन्दल,अभ्युदय जिन्दल औरवेंकटेश जिन्दल बाऊजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

बाऊजी के बारे में कहा जाता है कि जहां दूसरों ने दीवारें देखीं, वहां उन्होंने दरवाजे देखे। वे समस्या में भी समाधान देखते थे और यही वजह है कि आज करोड़ों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलकर सुख, शांति और समृद्धि की जोत प्रज्ज्वलित कर रहे हैं। बाऊजी ने देश और लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताया। उनका यह दर्शन ओपी जिन्दल ग्रुप का अनवरत मार्गदर्शन कर रहा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

परीक्षाओं के लिए जान पर खेलते बच्चे

क्षमा शर्मा

पिछले दिनों से दिल्ली के कोचिंग सेंटर चर्चा में हैं। बारिश के कारण एक बेसमेंट में पानी भर गया और तीन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उससे पहले यूपीएससी की ही तैयारी करने वाला एक बच्चा बारिश में करंट लगने से मर गया। हर साल लाखों बच्चे अपनी आंखों में तमाम सपनों को लिए यहां आते हैं और जीवन के बहुमूल्य वर्ष लगा देते हैं।

कोचिंग सेंटर्स में देश भर से आए बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। वे किन विकट परिस्थितियों में रहते हैं, इसे मीडिया ने बार-बार दिखाया और बताया है। कितनी कम जगह के लिए उन्हें भारी किराया देना पड़ता है। कैसा खाना मिलता है। मकान मालिक बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा लेते हैं। उस पर रात-दिन की मेहनत। लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं होता, कोई नहीं जागता। न सरकार, न कोचिंग सेंटर्स के मालिक, न ही बच्चे, न बच्चों के माता-पिता। मीडिया भी। क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स बड़े विज्ञापनदाता भी हैं। आखिर इनसे कौन दुश्मनी मोल लेकर अपनी आय का नुकसान करे। न ही सरकारी अधिकारियों को कभी इस बात का खयाल आता है कि वे उन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। हां, जब दुर्घटना हो जाती है, तब जिम्मेदारी एक से दूसरे पर डाल दी जाती है।फिल्म बारहवीं फेल में भी हम ये सब देख चुके हैं। यह फिल्म बहुत सफल भी हुई थी। बच्चे ही नहीं उनके माता-पिता चाहते हैं कि किसी तरह बच्चा आईएएस या, आईपीएस, अथवा अन्य सेवाओं में एक बार आ भर जाए तो न केवल उसकी जिंदगी बन जाए बल्कि माता-पिता की भी और दहेज भी मोटा मिले। एक बार एक खबर पढ़ी थी कि जो बच्चे आईएएस बन जाते हैं, उनका नाम लिस्ट में देखकर उनके घर में बड़ा वाहन रुपये लेकर लोग पहुंच जाते हैं। और रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। यूपीएससी का इम्तिहान देने के लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं जबकि चयन कुछ ही का होता है। एक सफल के पीछे हजारों असफल खड़े रहते हैं। कई-कई बार तो दशकों इसमें निकल जाते हैं, मगर सफलता के साथी सब हैं असफलता की कहानी कोई नहीं कहता। न ही उस संघर्ष और जी तोड़ मेहनत के बारे में बताया जाता है कि वर्षों तक अठारह-बीस घंटे मेहनत करने और सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया।

आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों की सफलता का प्रतिशत औरों से ज्यादा है, इसीलिए बच्चे दिल्ली आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे बिहार से आते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2002 से 2012 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अठारह हजार, एक सौ चौहत्तर बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। मगर सफल सिर्फ दो हजार, दो सौ इकतालीस बच्चे ही हुए थे। सफलता का प्रतिशत इतना कम होने पर भी इस परीक्षा की तैयारी करने वाला हर बच्चा सोचता है कि वह अपने परिश्रम से जीत हासिल कर लेगा, पर ऐसा होता बहुत कम के साथ है।

यूपीएससी को कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अफसोस होता है कि बच्चों के परिजन, साथ में जहां रहकर ये तैयारी करते हैं वे सेंटर्स, न इनके स्वास्थ्य का खयाल रखते हैं न इनकी मामूली सुविधाओं का। ये पैसे बरसाने वाली मशीनें हैं, जो जितनी बड़ी संख्या में आएंगी लोगों की जेबें उतनी ही फूलती जाएंगी। तभी तो दिल्ली में कुल कोचिंग सेंटर्स की संख्या पांच सौ तिरासी है और सिर्फ सड़सठ के पास सुरक्षा मानकों को पूरे करने वाले प्रमाण पत्र हैं। आखिर बिना सुरक्षा मानक पूरे किए इन सेंटर्स को क्यों चलने दिया गया।

फिर कोचिंग सेंटर्स हमेशा अपनी सफलताओं को बहुत रंगीन बनाकर पेश करते हैं। बहुत से इसमें झूठ-सच का सहारा भी लेते हैं। इसमें एक उदाहरण देना काफी होगा। करीब सत्ताईस-अट्ठाईस साल पहले एक युवा का न केवल आईआईटी बल्कि देश के बहुत से इंजीनियरिंग संस्थानों में चुनाव हुआ था। जैसे ही रिजल्ट आया कोचिंग संस्थानों से फोन आने लगे कि वह युवा अपना फोटो उन्हें छापने की अनुमति दे। जिसमें वे कह सकें कि इस युवा ने इतनी सफलता इसलिए पाई कि अमुक संस्थान से ट्रेनिंग ली थी। वे इसके लिए बड़ी रकम देने को भी तैयार थे। जबकि इस युवा ने खुद ही पढ़ाई की थी। इस युवा ने कोचिंग संस्थान वालों से मना कर दिया। ऐसा आज भी होता है। कोचिंग संस्थान चाहे यूपीएससी के हों, इंजीनियरिंग के हों, अथवा मेडिकल या एमबीए के, अधिकांश की कहानी कमोबेश एक जैसी ही होती है। कोटा में भी यही हाल देखने को मिलता है। वहां तो और भी कम उम्र के बच्चे मेडिकल की तैयारी करने आते हैं। बहुत बार इतने निराश होते हैं कि जान दे देते हैं।

लेकिन अन्य परीक्षाओं के साथ यूपीएससी की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। खास तौर से तब जब वे असफलता से जुड़ी हों। बहुत बार इस आशा में कि बच्चा बड़ा अफसर बन जाएगा, माता-पिता अपनी जमीन, खेत मकान सब कुछ बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, मगर जरूरी नहीं कि उनका बच्चा सफल ही हो। और कई बार ऐसा होता है कि एक सफलता की आशा में पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भारत में माता-पिता का ध्यान अक्सर सरकारी नौकरी पर रहता है। और यदि नौकरी सरकारी है और ऊपरी कमाई वाली भी है तो कहना ही क्या। क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन भर के लिए पक्की समझिए। इसीलिए विवाह के मामले में भी लोग उन लड़कों को पसंद करते हैं जिनकी सरकारी नौकरी होती है। कई साल पहले यह लेखिका एक ऐसे दक्षिण भारतीय लड़के से मिली थी जो बहुत पढ़ा-लिखा था। अपने हुनर में माहिर था, मगर बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद उसकी शादी दो कारणों से नहीं हो रही थी, एक तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी और दूसरे वह विदेश में नौकरी नहीं करता था। दोनों में से एक भी बात होती तो शायद उसकी शादी समय पर हो गई होती। उत्तर भारत में भी ऐसी ढेरों कहानियां मौजूद हैं। जो लोग तमाम प्रयासों के बावजूद यूपीएससी में सफल नहीं हो पाते, इसका दुःख उन्हें जिंदगी भर सालता रहता है। अपने ही किसी साथी को बड़ा अफसर देख उनका दुःख और बढ़ जाता है। फिर जिस सपने को लेकर दिल्ली आए थे, वह पूरा नहीं हुआ तो वे अपने नाते-रिश्तेदारों, अड़ोसी-पड़ोसियों की नजर में गिर जाते हैं। तरह-तरह का अपमान झेलते हैं।

समाज में शक्ति और अधिकार के प्रति इतना सम्मान है कि बाकी मानवीय गुण पीछे छूट जाते हैं। इस मामले में महान लेखक जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त का ही पहला वाक्य याद आता है-अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।

सुभाषित

जो छिद्रान्वेषण किया करता है और मित्रता टूट जानेके भयसे सावधानी बरतता हैं, वह मित्र नहीं है।
❐ ***गौतम बुद्ध***

यूनुसकी अग्निपरीक्षा

बंगलादेश इन दिनों गम्भीर संकटके दौरसे गुजर रहा है। हिंसा और उपद्रवकी वारदातें काफी बढ़ गयी हैं। आगजनी और मारकाटका सिलसिला थम नहीं रहा है। सबसे गम्भीर चिन्ताकी बात अल्पसंख्यक हिन्दुओं और मन्दिरोंकी सुरक्षाको लेकर है। मन्दिरोंमें तोड़फोड़की घटनाएं हो रही हैं और हिन्दुओंको मारा जा रहा है। बंगलादेशकी कुल आबादीकी ८.६ प्रतिशत हिन्दुओंकी आबादी है। इसके अतिरिक्त १९ हजार भारतीय हैं, जिनमें नौ हजार भारतीयोंकी स्वदेश वापसी हो गयी है। शेष भारतीयोंके बीच एयर इण्डियाकी सेवाएं साहसिक और प्रशंसनीय है। बंगलादेशकी जो भयावह स्थिति है, उसमें हिन्दू आबादी पूरी तरहसे असुरक्षित है। उन्हें अपनी प्राणरक्षाके लिए जीवन और मृत्युके बीच जूझना पड़ रहा है। वहांसे हिन्दुओंने पलायन शुरू कर दिया है। शेख हसीनाके देश छोड़नेके बाद उनकी पार्टी अवामी लीगसे जुड़े नेताओंपर हमले हो रहे हैं और सम्पत्तियोंको क्षति पहुंचायी जा रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीनने संसद भंग कर दी है और आन्दोलनकारी छात्र नेताओंके कहनेपर नोबेल पुरस्कारसे सम्मानित मोहम्मद यूनुसको अन्तरिम सरकारका प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया है। उन्होंने अपना कार्यभार सम्भाल लिया है। साथ ही पूर्व प्रधान मंत्री बेगम खालिदा जियाको रिहा भी कर दिया गया है। देशमें अराजकता और हिंसाके ताण्डवके साथ ही राजनीतिक अस्थिरताकी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जो गम्भीर चिन्ताकी बात है। पड़ोसी देशकी यह स्थिति भारतके हितमें नहीं है। नवनियुक्त प्रधान मंत्री मोहम्मद यूनुसके समक्ष गम्भीर चुनौतियां हैं और इसका सामना करना आसान नहीं है। सबसे पहले हिंसापर काबू पाना होगा और शान्तिकी बहाली होनी चाहिए। अल्पसंख्यक हिन्दुओंके जान-मालकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। शेख हसीनाकी पार्टी अवामी लीगका तो सफाया हो रहा है लेकिन अन्य दलों और शान्तिप्रिय राजनेताओंके साथ सामंजस्य बनाकर मोहम्मद यूनुसको पूर्वाग्रह और दुराग्रहोंसे मुक्त होकर कार्य करना पड़ेगा। कट्टरपंथी ताकतोंपर भी नियंत्रण लगानेकी जरूरत है। मोहम्मद यूनुसके लिए यह अग्निपरीक्षाकी घड़ी है, इसमें वह सफल हो पाते हैं या नहीं यह उनकी कार्यशैलीपर निर्भर करता है। चीनके हस्तक्षेपसे भी उन्हें दूर रहनेकी जरूरत है, क्योंकि जिन देशोंमें चीनका हस्तक्षेप बढ़ा उसकी बर्बादीके कई उदाहरण मौजूद हैं। भारतके प्रति उन्हें सकारात्मक रुख अपनाना होगा। यह दोनों देशोंके हितमें होगा। बंगलादेशकी जो मौजूदा स्थिति है, उसपर संयुक्त राष्ट्रको भी सजग दृष्टि रखनी होगी। वहां शान्तिबहाली पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

वकीलोंको नसीहत

पथभ्रष्ट वकीलोंपर शिकंजा कसते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालयकी यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण और न्यायसंगत है कि न्यायिक प्रक्रियाके दुरुपयोगकी छूट किसीको भी नहीं दी जा सकती है। हैरान करनेवाली बात है कि काले कोटमें एससी-एसटीके झूठे केसमें फंसाकर धन हड़पनेके काले धन्धेमें कर्तव्यहीन वकीलोंका एक संघटित गिरोह सक्रिय है। उच्च न्यायालयमें इसी तरहकी एक याचिकापर सुनवाईके दौरान यह खुलासा हुआ कि प्रयागराजमें वकालतके बजाय दूसरा धन्धा करनेवाले कुछ वकीलोंका गिरोह महिलाओंको शामिल कर एससी-एसटी एक्टके तहत झूठे आपराधिक केसमें निर्दोष लोगोंको फंसाकर चार्जशीट दाखिल होनेपर सरकारसे पीड़िताको मिलनेवाले धनका आपसमें बंटवारा करता है। इसी तरह एक अधिवक्ताको भी दुष्कर्मके मामलेमें फंसाया गया था। मामलेकी गम्भीरता और वकालत जैसे पवित्र पेशेको देखते हुए न्यायमूर्ति डाक्टर गौतम चौधरीने दाखिल याचिकापर सीबीआईको प्रारम्भिक जांचका आदेश दिया था। साथ ही कुछ मामलोंकी जांच एसआईटीसे भी करायी थी। जांचमें ५१ ऐसे आपराधिक केसोंका खुलासा हुआ, जिसमें वकीलोंको फर्जी मामलोंमें फंसाया गया था, न्यायिक प्रक्रियापर सवाल खड़ा करता है। न्यायिक प्रक्रियाका दुरुपयोग करनेवालोंके विरुद्ध कड़ी काररवाई की जानी चाहिए। फर्जी केसोंमें फंसाकर सरकारी धनकी बंदरबाटकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। भ्रष्ट वकीलोंके गैंगपर मुकदमा चलानेका उच्च न्यायालयका फैसला उचित और न्यायसंगत है। यह उन वकीलोंको नसीहत है जो ऐसे मामलोंमें संलिप्त हैं। अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्थाके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो जनताकी निगाहमें सम्मानित हैं। अपने पेशेके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना इनका उत्तरदायित्व है। जिस तरह एक सड़ी मछली पूरे तालाबको गंदा कर देती है उसी तरह गलत कार्य करनेवाला वकील, वकालतके पेशेको बदनाम कर देता है। ऐसे वकीलोंका बहिष्कार होना चाहिए ताकि उन्हें भी अपनी करनीपर ग्लानि पैदा हो और अपने पेशेके प्रति ईमानदारी बरतें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

लोक संवाद

प्रकृतिका रौद्र रूप

महोदय,-पश्चिमी हिमालयमें इस वर्ष फिर प्रकृतिने अपना रौद्र रूप दिखाया है। हिमाचल प्रदेशमें सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां १३ लोगोंकी लाशें मिली हैं और अभीतक ५५ लोग गुम हैं। कुल मिलाकर ६८ लोग कालका ग्रास बन चुके हैं। शिमला-कुल्लूकी सीमापर समेज गांवमें सबसे अधिक तबाही हुई है, जहां ४१ के करीब बहुमूल्य जानें गयी हैं, जिनमें आठसे दस तो विद्यालयके होनहार छात्रोंको हमने खोया है, जो विद्यालयके लिए पुरस्कार जीतनेवाली खेल प्रतिभाएं थीं। एक परिवारके तो १४ लोग कालका ग्रास बने हैं। इस दु:खका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। मंडीकी चुहार घाटीके राजबन गांवमें दस लोग कालका ग्रास बने हैं। कुल्लू जिलाका मलाणा बांध आंशिक रूपसे टूट गया है। पंडोह बांधके दो गेट खुल नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किलसे खुले हैं। चंबाके राजनगरमें भी बादल फटनेसे भारी तबाही हुई है। समेज गांवकी दुर्घटनाका आरंभ श्रीखंड महादेवके नीचे बादल फटनेसे हुए भूस्खलनसे हुआ है। यह काफी ऊंचाईवाला क्षेत्र है। आम तौरपर छह-सात हजार फुटसे ज्यादा ऊंचाईवाले क्षेत्रोंमें बारिश फुहारोंके रूपमें बहुत धीमी-धीमी होती थी। अब तो ऐसे क्षेत्रोंमें भी बादल फटने लगे हैं। लाहुल और स्पीतिमें भी बादल फटनेकी घटनाएं हुई हैं। स्पीतिके रोंगटोंग प्रोजेक्टकी जल इन टेक व्यवस्था बह गयी है। यह सामान्य घटनाएं नहीं हैं। जब २०-३० वर्ग किलोमीटर या इससे कम क्षेत्रमें एक घंटेमें दस सेंटीमीटरसे अधिक वर्षा हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। १९७० और २०२३ के बीच अकेले हिमाचल प्रदेशमें ही इस तरहकी घटनाओंमें पंद्रह गुणातककी वृद्धि हुई है। ऊष्ण कटीबंधीय मौसम विज्ञान विभागसे संबंधित एनआर देशपांडेने भी एक शोधमें १९२६ से २०१५ के बीचके आंकड़ोंके अध्ययनके आधारपर बादल फटनेकी घटनाओंमें वृद्धिकी बात कही है। वह इनमेंसे कई घटनाओंको बादल फटनेकी लघु घटनाके रूपमें भी परिभाषित करते हैं। -**के.बी.उपमन्यु, वाया ईमेल।**

बंगलादेशमें कट्टरपंथियोंसे दहशत

बंगलादेशमें सरकार विरोधी प्रदर्शनोंके क्रूरताकी हदतक हिंसक हो जानेसे विधि-व्यवस्था नाकाम हो चुकी है। चारों ओर अराजकता और बदहवासीकी स्थिति है। सरकार विरोधी प्रदर्शनोंमें 'लोक' और 'तंत्र' दोनोंको भारी नुकसान हुआ है, जिसकी अंतिम परिणति हुई कि प्रधान मंत्री शेख हसीनाकी सरकारका तख्तापलट हो गया।

❐ चेतनादित्य आलोक

बंगलादेशमें सत्ताकी बागडोर सेनाके हाथोंमें है। हालांकि सेनाने वहां अंतरिम सरकारके गठन करवानेकी बात कही है। फिलहाल, शेख हसीनाको सत्तासे बाहर करनेके लिए बंगलादेशमें जिस तरहका आन्दोलनके पीछेसे राजनीतिक अभियान चलाया गया, उसने दुनियाके दूसरे इस्लामिक देशोंके शासकोंके होश उड़ा दिये हैं। वैसे देखा जाय तो बंगलादेशमें इससे पहले भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती रही हैं और तख्तापलट होते रहे हैं। हालांकि इस बार तो शेख हसीनाको अपनी जान बचाकर देश छोड़ भागनेके लिए कमसे कम ४५ मिनटका समय भी दिया गया, जबकि इससे पहले बंगलादेशमें कई बार खूनी सैन्य तख्तापलट भी हुए हैं और वहां 'मार्शल लॉ' यानी 'सैन्य कानून' लागू किये गये हैं। गौरतलब यह भी है कि १९७१ में पाकिस्तानसे अलग होकर बंगलादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसे आजादी दिलानेमें भारतने अहम भूमिका निभायी थी, जबकि आज वहांपर बसे भारतवंशी हिन्दू हर प्रकारके संकटोंसे घिरे हुए हैं।

आज बंगलादेशमें हिन्दुओंके लिए अपनी अस्मिताको बचाये रखना मुश्किल हो रहा है। वैसे पहले भी इस्लामिक कट्टरपंथियोंकी ओरसे उनपर बार-बार हमले किये जाते रहे हैं। उनके मठ-मंदिरोंको जलाया और ध्वस्त किया जाता रहा है और देवी-देवताओंकी मूर्तियोंको भी बेरहमीसे तोड़ा और अपमानित किया जाता रहा है, लेकिन शेख हसीनाके पलायनसे इस बार कट्टरपंथियोंको पूरी छूट (फ्री हैंड) मिल गया। यही कारण है कि वे ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। देखा जाय तो बंगलादेशके संस्थापक रहे और 'बंगबंधु' कहे जानेवाले बंगलादेशके प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीब-उर-रहमानको भी वहांके इस्लामिक कट्टरपंथियोंने नहीं बख्शा, न तो तब, जब वे जीवित थे और न ही अब, जबकि बंगलादेशमें उनकी स्मृतियां मात्र ही बची हुई हैं। ऐसेमें भला हिन्दुओंके प्रति इस्लामिक कट्टरपंथियोंके तरफसे नरमी अथवा किसी प्रकारके सहयोगातमक रवैयेकी कल्पना भी कैसे की जा सकती है। फिलहाल, अभी १५ अगस्त १९७५ की उस बेहद खौफनाक घटनाको याद करना जरूरी है, जिसकी चर्चा एंथनी मैस्करेनहासने अपनी पुस्तक 'बंगलादेश-ए-लीगेसी ऑफ ब्लड' में की है। गौरतलब है कि सेनाके कुछ बागी अधिकारियोंने शेख हसीनाके पिता शेख मुजीब-उर-रहमान समेत उनके परिवारके २० लोगोंको मौतके घाट उतार दिया था। शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना केवल इसलिए बच पायीं, क्योंकि घटनाके समय वे दोनों जर्मनीमें थीं। हालांकि शेख मुजीब-उर-रहमान यदि भारतकी सलाह मान लेते तो वह घटना नहीं घटती, लेकिन वे यह माननेके लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी अपनी ही सेनाके लोग उनके खिलाफ इस प्रकार बगावत कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने रॉ के संस्थापक आरएन कावके द्वारा चेताये जानेपर कहा था कि ये (हमारी सेनाके लोग) मेरे बच्चे हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचायंगे। फिलहाल, १९७५ में बंगलादेशके तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीब-उर-रहमानकी हत्याके बाद जेनरल जिया उर रहमानने सत्ताकी बागडोर अपने हाथोंमें ले ली थी। इस प्रकार बंगलादेशमें पहली बार १९७५ में मार्शल लॉ लागू हुआ। इसी प्रकार १९८२ में जेनरल हुसैन मोहम्मद इरशादने भी एक सैन्य तख्तापलटके माध्यमसे सत्ता संभाली और बंगलादेशमें मार्शल लॉ लगाया था। हालांकि बंगलादेशके वर्तमान संकटके परिदृश्यमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईका हाथ होनेसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल आईएसआईपर संदेह करनेका वाजिब कारण यह है कि बंगलादेश स्थित पाकिस्तान समर्थक कट्टर संघटन जमात-ए-इस्लामीको उसका वरदहस्त हमेशासे प्राप्त रहा है और इस बार वहां स्थितियोंको बिगाड़नेमें जमात-ए-इस्लामीका पूरा हाथ भी रहा है। इस कट्टर संघटनने आन्दोलनकारियों, जिनमें अधिकतर विश्वविद्यालयोंके विद्यार्थी शामिल रहे हैं, को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया है। जमात-ए-इस्लामी वही संघटन है, जिसने १९७१ के मुक्ति संग्राममें पाकिस्तानका साथ दिया था। दूसरे शब्दोंमें कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जमात-ए-इस्लामीने आईएसआईकी बन्दूकोंको आन्दोलनकारियोंके कंधेपर रखकर शेख हसीनाकी सरकारको निशाना बनाया। हालांकि आन्दोलनकारी विद्यार्थियोंकी मांग उचित प्रतीत होती है, जिसके अनुसार १९७१ में पाकिस्तानके विरुद्ध आजादीकी लड़ाईमें शामिल रहे बंगलादेशी मुक्ति-योद्धाओंको दिया जाने वाला ३० प्रतिशत आरक्षण समाप्त करना था, क्योंकि आन्दोलनकारी मानते हैं कि इससे देशमें बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगोंको रोजगार नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि १९७२ में पहली बार मुक्ति-योद्धाओंको आरक्षण दिया गया था। उसके बाद उनके बच्चोंको वह आरक्षण दिया गया और इस बार वहांपर यह व्यवस्था लागू कर दी गयी थी कि मुक्ति-योद्धाओंकी अगली पीढ़ी यानी उनके पोते-पोतियोंको भी वह आरक्षण दिया जायगा। इसी बातसे आन्दोलनकारी विद्यार्थी बेहद नाराज थे। आन्दोलनकारियोंका आरोप यह भी है कि आरक्षणकी सुविधा पानेवाले अधिकतर मुक्ति-योद्धा हसीनाकी पार्टी अवामी लीगके समर्थक रहे हैं। वहीं, खालिदा जियाकी सरकारके दौरान बंगलादेशमें आतंकवादी संघटनों, कट्टरपंथियों और उग्रवादियोंको खूब प्रश्रय मिला, जिससे वहां उन सबको फलने-फूलनेका अवसर मिला। यहांतक कि उस दौरान कुछ आतंकवादी और उग्रवादी संघटन बंगलादेशकी धरतीसे भारतके विरुद्ध अपनी गतिविधियां भी चलाते थे। तब उल्फा तथा कई अन्य भारतविरोधी उग्रवादी संघटनोंने बंगलादेशमें अपने पैर जमा लिये थे। हालांकि इस बार हसीना सरकार आन्दोलनकारियोंकी आरक्षण समाप्त करनेवाली मांग माननेके लिए तैयार हो गयी थी, लेकिन अड़चन यह थी कि इस बार बंगलादेशमें आरक्षण वाली व्यवस्था कोर्टके एक फैसलेके बाद लागू की गयी थी। इसलिए उसे कोर्टके माध्यमसे ही वह समाप्त करना चाहती थीं। बता दें कि इसके लिए सरकार कोर्टमें एक याचिका भी लगाना चाहती थी, किन्तु उससे पहले ही राजनीतिक खेल कर दिया गया। वैसे इस प्रकरणमें अब चीन और अमेरिकाकी ओर भी अंगुलियां उठनी शुरू हो गयी हैं। फिलहाल बंगलादेशमें उत्पन्न संकटका कारण चाहे जो भी हो, किंतु कट्टरपंथी इसे अपनी बड़ी जीत मानते हैं और अब फ्री हैंड मिल जानेके बाद उनका प्रयास होगा कि बंगलादेशमें कोई उनका चहेता ही सत्ताकी बागडोर संभाले। शायद खालिदा जिया।

बंगलादेशके वर्तमान संकटके परिदृश्यमें अमेरिका सहित पाकिस्तानका हाथ होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल आईएसआईपर संदेह करनेका वाजिब कारण यह है कि बंगलादेश स्थित पाकिस्तान समर्थक कट्टर संघटन जमात-ए-इस्लामीको उसका वरदहस्त हमेशासे प्राप्त रहा है। इस बार वहां स्थितियोंको बिगाड़नेमें जमात-ए-इस्लामीका हाथ है। इस कट्टर संघटनने आन्दोलनकारियोंको समर्थन दिया है। जमात-ए-इस्लामी वही संघटन है, जिसने १९७१ के मुक्ति संग्राममें पाकिस्तानका साथ दिया था।

संतुलन नहीं बना सकीं शेख हसीना

शेख हसीनाकी आर्थिक उपलब्धियां सराहनीय थीं, उनके द्वारा कठोर शक्तिका इस्तेमाल और लोकतांत्रिक मानदंडोंकी अवहेलना अंततः उनके पतनका कारण बनीं। बंगलादेशको असमानताओंकी चुनौतीका सामना करना पड़ रहा है।

❐ सैयद मुनीर

बंगलादेशके मित्र और पड़ोसी, उस देशमें पिछले कुछ हफ्तोंमें चल रहे राजनीतिक नाटकको देख रहे थे, हर किसीके दिमागमें एक सवाल सबसे ऊपर था, क्या बंगलादेशकी सबसे लंबे समयतक सेवा करनेवाली प्रधान मंत्री इस संकटसे निबट पायंगी, जैसा कि उन्होंने पहले कई मौकोंपर किया है। २००९ में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावके माध्यमसे सत्तामें आनेके बाद उन्होंने बादमें तीन मौकों, २०१४, २०१८ और २०२४ में बड़े पैमानेपर गैर-भागीदारीवाले और विवादास्पद चुनावोंकी अध्यक्षता की। वह लगभग अजेय लग रही थीं, सत्तापर उनकी पकड़ पूरी तरहसे थी। घटनाओंके एक चौंकानेवाले मोड़में, हसीनाने सोमवारको इस्तीफा दे दिया, जिससे उनके १५ सालके शासनका अचानक अंत हो गया। शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनोंके रूपमें शुरू हुआ आन्दोलन जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमें बदल गया, जिसने हसीनाके बढ़ते अधिनायकवादी शासन और अनियंत्रित भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और मनमानीके प्रति गहरे असंतोषको उजागर किया, जिसने देश और विदेशमें उनकी जो भी आर्थिक और विकास सफलताएं दिखायीं, उनपर पर्दा डाल दिया। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम एक स्पष्ट चेतावनीके रूपमें कार्य करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओंके क्षरणके सामने केवल आर्थिक प्रगति ही एक नेताकी लोकप्रियताको बनाये नहीं रख सकती। हसीनाके कार्यकालमें उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धियां दर्ज की गयीं। उनके नेतृत्वमें बंगलादेश दुनियाके सबसे गरीब देशोंमेंसे एकसे इस क्षेत्रमें सबसे तेजीसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओंमेंसे एकमें बदल गया, यहांतक कि अपने बड़े पड़ोसी भारतसे भी आगे निकल गया। देशकी प्रति व्यक्ति आय एक दशकमें तीन गुना हो गयी और विश्व बैंकका अनुमान है कि पिछले २० वर्षोंमें २५ मिलियनसे अधिक लोगोंको गरीबीसे बाहर निकाला गया। हसीनाकी सरकारने घरेलू धन, ऋण और विकास सहायताके संयोजनका इस्तेमाल करके गंगापर २.९ बिलियनके पद्मा ब्रिज जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू कीं। हालांकि ये आर्थिक लाभ एक बड़ी कीमतपर आये। २०१४, २०१८ और २०२४ के संसदीय चुनावोंमें कम मतदान, हिंसा और विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कारकी वजहसे बाधाएं आयीं। हसीनाकी सरकारने नियंत्रण बनाये रखनेके लिए कठोर शक्तिपर अधिकसे अधिक भरोसा किया, जिससे भय और दमनका माहौल बना। २०१८ में लागू किया गया डिजिटल सुरक्षा अधिनियम सरकार और सत्तारूढ़ पार्टीके कार्यकर्ताओंके लिए आलोचकोंको चुप कराने और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, विशेष रूपसे ऑनलाइनको दबानेके लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया। प्रेसकी स्वतंत्रताको नुकसान पहुंचा और नागरिक अधिकारोंको व्यवस्थित रूपसे दबा दिया गया, क्योंकि हसीनाने सत्ताके एकमात्र केन्द्रके रूपमें अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी, वैसे-वैसे अमीर और गरीबके बीच असमानता भी बढ़ी। बैंक घोटाले बढ़े और ऋण चूककर्ताओंकी सूचीमें उछाल आया। सीएलसी पावर, वैस्टर्न मरीन शिपयार्ड और रेमेक्स फुटवियर जैसी कम्पनियां चूककर्ताओंकी सूचीमें सबसे ऊपर हैं, जिनके खराब ऋण ९६५ करोड़से १६४९ करोड़ बंगलादेशी टकातक हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचारने समग्र आर्थिक प्रगतिके बावजूद जनतामें असंतोषको बढ़ावा दिया। हालमें छात्र आंदोलन, जो हसीनाके पतनका कारण बना, सिविल सेवा नौकरियोंमें कोटा हटानेकी एक साधारण मांगके रूपमें शुरू हुआ। ढाका विश्वविद्यालयमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनोंके रूपमें शुरू हुआ यह आन्दोलन जल्द ही अन्य कुलीन संस्थानों और फिर आम जनतातक फैल गया। स्थिति तब और बिगड़ गयी, जब अवामी लीगकी छात्र शाखा, बंगलादेश छात्र लीगके सदस्योंने प्रदर्शनकारियोंपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे एक गैर-राजनीतिक आन्दोलन एक व्यापक विद्रोहमें बदल गया। प्रदर्शनोंके प्रति हसीनाकी प्रतिक्रिया उनके लिए विनाशकारी साबित हुई। पिछले महीनेके अंतमें छात्रोंके खिलाफ पुलिस और अर्धसैनिक बलोंको तैनात करनेका उनका फैसला उलटा पड़ गया, जिससे व्यापक जन-आक्रोश भड़क उठा। सरकारके कठोर रवैये, जिसमें देखते ही गोली मारनेके आदेशके साथ सख्त कर्फ्यू लगाना शामिल था, ने आंदोलनको और भड़कानेका काम किया। हसीना द्वारा प्रदर्शनकारियोंको रजाकारके रूपमें गलत तरीकेसे लेबल करनेसे, जो १९७१ के युद्धके दौरान सहयोगियोंसे जुड़ा एक शब्द है, तनाव और बढ़ गया। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शनने गति पकड़ी, उन्हें माता-पिता, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित समाजके विभिन्न वर्गोंसे समर्थन मिला। आन्दोलन अपनी शुरुआती मांगोंसे आगे निकल गया और १५ सालके डर और उत्पीड़नके खिलाफ निराशाकी सामूहिक अभिव्यक्ति बन गया। छात्रों द्वारा अपनी मांगें पूरी होनेतक प्रधान मंत्रीके साथ बातचीत करनेसे इनकार करना गहरे अविश्वास और आक्रोशको दर्शाता है। शेख हसीनाका पतन उन नेताओंके लिए चेतावनी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताकी कीमतपर आर्थिक विकासको प्राथमिकता देते हैं। अपने पूर्ववर्तियों, जैसे अलोकप्रिय सेना प्रमुख एच.एम. इरशाद, जिन्हें जेलमें डाल दिया गया था, लेकिन वह देश छोड़कर नहीं भागे, के विपरीत हसीनाका जाना बंगलादेशके राजनीतिक परिदृश्यमें एक महत्वपूर्ण बदलावको दर्शाता है। उनका जाना एक तानाशाहकी तरह है, जो एक गुप्त स्थानसे हैलीकॉप्टरमें भाग रहा है और उग्र भीड़ उसके आधिकारिक आवासको लूट रही है, यह फिल्मोंके दृश्योंकी याद दिलाता है। बंगलादेशमें हुई घटनाएं आर्थिक प्रगतिको लोकतांत्रिक शासनके साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेहीके साथ संतुलित करनेके महत्वको रेखांकित करती हैं, जिसके अभावमें बहुतोंकी कीमतपर केवल कुछ ही लोग लाभान्वित होते हैं, जबकि हसीनाकी आर्थिक उपलब्धियां सराहनीय थीं, उनके द्वारा कठोर शक्तिका इस्तेमाल और लोकतांत्रिक मानदंडोंकी अवहेलना अंतत: उनके पतनका कारण बनीं। जैसे-जैसे बंगलादेश आगे बढ़ रहा है, उसे अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओंमें विश्वास बहाल करते हुए अपनी आर्थिक गतिको पुन: प्राप्त करने और हालके वर्षोंमें उभरी असमानताओंको दूर करनेकी चुनौतीका सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीनाका इस्तीफा एक सबक है, जो न केवल बंगलादेशमें, बल्कि दुनियाभरमें गूंजता है, जो सामाजिक-आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्योंके बीच नाजुक संतुलनको उजागर करता है, जो उन लोगोंके लिए कम मायने नहीं रखता, जिनके लिए ये कभी परस्पर अनन्य नहीं रहे हैं।

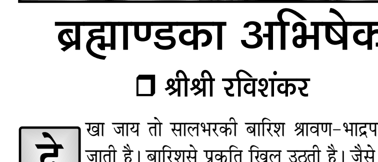

ब्रह्माण्डका अभिषेक

❐ श्रीश्री रविशंकर

देखा जाय तो सालभरकी बारिश श्रावण-भाद्रपदमें हो जाती है। बारिशसे प्रकृति खिल उठती है। जैसे प्रकृति खिल उठती है वैसे ही भगवान शंकरकी आराधना करके हम भी खिल उठते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पुराणोंमें कहा गया है अलंकार प्रियो विष्णु अभिषेक प्रिय: शिव:। आप देखेंगे कि मंदिरोंमें भगवान विष्णु हमेशा सजे-धजे रहते हैं, भगवान विष्णुको सजानेमें आनन्द आता है, परन्तु शंकर जी अभिषेकसे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए लोग शंकर जीपर ही जल चढ़ाते हैं। शंकर जी सारी प्रकृतिमें निहित हैं। कहते हैं, ब्रह्मांड व्याप्त देहाय माने उनका शरीर इस सारे ब्रह्मांडमें व्याप्त है। इसलिए उनके ऊपर जलकी वर्षा भी ब्रह्मांड ही करता है। सावनके महीनेमें पृथ्वीका अभिषेक होता है। सब कुछ धुल जाता है और पृथ्वी खिल उठती है। ये भूमि भगवानके पैर हैं और आकाश, नक्षत्र, तारे सब शंकर जीके गलेके हार हैं। शंकर जी स्वयं ही अपना अभिषेक कर रहें हैं। सावनके महीनेमें सारी प्रकृति ईश्वरके रसमें डूब जाती है। जब प्रकृति परमात्माके रसमें डूबती है तब मनुष्यको भी उसमें डूबना आवश्यक है। इसीलिए सावनके महीनेमें शंकर जीकी आराधना की जाती है। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार पार्वती जी भगवान शंकरसे पूछती हैं कि हम परब्रह्मकी गति कैसे प्राप्त करें। तब भगवान शंकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अपने दिलमें एक सुर चल रहा है। आपके भीतर एक अनहद नाद हो रहा है, मौनमें बैठकर उस नादको सुनें। मान लीजिए यदि आपमें उसकी क्षमता नहीं है और आप वह नहीं सुन पा रहे हैं तो जरा चुप रहकर देखें आप पायंगे कि अपने भीतर ही एक नाद, एक अभग्न-अटूट शब्द चल रहा है। उस आवाजको सुनते-सुनते आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। आजके युगमें तो एयर कंडीशन या पंखा चलता है, उसकी आवाज सुनते-सुनते भी आप ध्यानमें जा सकते हैं। कभी किसी भी झरनेके पास बैठकर आंखें बंद करके उस झरनेकी आवाज सुनें। आजकल तो आप ये घरपर भी कर सकते हैं। घरमें ही एक छोटा-सा पानीका झरना लगा लीजिए और उसको सुनते-सुनते थोड़ी देर ध्यानमें बैठ जाइये। कहते हैं जो इस शब्दमें स्नान कर लेता है वह परमब्रह्मकी ओर चल पड़ता है। जो इस अभग्न नादको सुननेमें निपुण हो जाते हैं, उनके अंदरकी बाकी सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। वे आनंदमयी परब्रह्मकी अपनी चेतनामें लौट जाता है। पुराणोंमें कहते हैं कि प्रकृति श्रावण मासमें शिवजीका अभिषेक करती है। शंकर माने जो सबका शुभ और मंगल करनेवाले हैं। इसलिए श्रावण मासमें रुद्रपूजा करते हैं।

पाकिस्तानको करारा जवाब होगा सुदृढ़ जम्मू-कश्मीर

❐ पूनम कौशिक

पांच अगस्त २०२४, यह ५ अगस्त, २०१९ की पांचवीं वर्षगांठ थी और राज्यमें सितंबरमें विधानसभा चुनावकी संभावनाओंको तलाशा जा रहा है, विशेषकर इसलिए कि इस संघ राज्य क्षेत्रमें बढ़ते आतंकवादी हमलोंके चलते सुरक्षा परिदृश्य बिगड़ा है और इस वर्ष अबतक आतंकवादी हमलोंमें ५० से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं। संघ राज्य क्षेत्रमें पाकिस्तान समर्थित संघटनों लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन एवं अन्य संघटनों द्वारा निरन्तर संघर्ष जारी है, जिसमें आतंकवादियोंने अबतक शांत रहे जम्मू क्षेत्रको अपना खेलका मैदान बना दिया है और वहांपर वे बार-बार हमले कर रहे हैं। वस्तुत: पिछले दो माहमें घात लगाकर हमले करनेकी घटनाएं नियमित रूपसे घट रही हैं और ये हमले विशेषकर पीर पंजालके दक्षिणी भागमें हो रहे हैं, जहांपर लम्बे समयतक आतंकी घटनाएं देखनेको नहीं मिली थीं। हालके हमलोंमें सेनाके दो अधिकारी और दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गये, जिनमेंसे एक लश्कर-ए-तोयबाका विस्फोटक विशेषज्ञ था। उसके बाद पिछले सप्ताह राजौरीमें सेनाके काफिलेपर हमला हुआ, जिसमें एक सैनिक घायल हुआ।

अधिकारियोंके अनुसार ६०० से अधिक उच्च प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादी कुपवाड़ा, डोडा, पुंछ और राजौरीकी गलियोंमें छिपे हुए हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण हैं। बीएसएफ प्रमुख और उपप्रमुखको हालमें हटाया जाना सुरक्षा समस्याकी गंभीरताको दर्शाता है। यही नहीं, आतंकवादियोंने संघ राज्य क्षेत्रमें नागरिक प्रशासन और पुलिसमें भी घुसपैठ कर दी है और इसका प्रमाण यह है कि दो सिपाहियों सहित आठ सरकारी कर्मचारियोंको इस मामलेमें निलंबित किया गया है। यही नहीं, स्थानीय जिहादी स्लीपर सैल सक्रिय हो गया है और उन्हें स्थानीय लोगोंका समर्थन प्राप्त है, क्योंकि स्थानीय लोग इस बातसे नाराज हैं कि बाहरी लोगोंको वहां भूमि खरीदने और बसनेकी अनुमति दी जा रही है। इससे यह आशंका पैदा हो रही है कि विधानसभा चुनावोंमें और विलंब हो सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालयने इस संबंधमें समय-सीमा निर्धारित की है। आज घाटीका राजनीतिक क्षेत्र ऐसा बन गया है कि इसे पहचाना नहीं जा सकता। यहांतक कि यहांकी स्थिति समझनेवाले क्षेत्रीय दलों नैशनल कांफ्रेंस और पीडीपीके पास भी २०१९ के बाद कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और यही स्थिति भाजपाके स्थानीय नेताओंकी है। नैशनल कांफ्रेंसके नयी दिल्ली स्थित नेता सज्जाद लोन अपनी जमानत बचानेमें भी सफल नहीं रहे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि इंजीनियर राशिद जैसे नेताओंके पुन: उभरनेको किस तरह रोका जा सकता है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियमके तहत जेलमें थे और जिन्होंने जेलमें रहकर नैशनल कांफ्रेंसके उमर अब्दुल्लाको हराया। इस तरहके नेता क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलोंके समीकरण बिगाड़ रहे हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि युवा और स्थानीय लोग इंजीनियर राशिदके साहसिक चुनावी कार्यसे प्रभावित हैं। इन चुनावोंमें भाजपाका प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा और वह लद्दाख सीट हार गयी, जबकि २०१९ में उसने केवल यही सीट प्राप्त की थी। जम्मूकी दो सीटोंपर उसे २०१९ की तुलनामें कम वोट मिले हैं और यह सब तब हुआ जब संवैधानिक और प्रशासनिक रूपसे सरकार हर कदम उठानेके लिए स्वतंत्र थी। वह किसी भी तरहका प्रयोग कर सकती थी और प्रतिरोध या विरोधको दबा सकती थी।

आज स्थिति यह है कि घाटी सुरक्षित है और वहां पर पर्यटन खूब फ्ल.फूल रहा है। वहां २१.३ मिलियनसे अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। नि:संदेह घाटीमें आर्थिक और शासनके क्षेत्रमें लाभ और सुधार हुआ है। सेवा प्रदायमें सुधार हुआ है। एक हजारसे अधिक लोक सेवाओंका डिजिटलीकरण किया गया है। छह हजार करोड़ रुपयेसे अधिककी निवेशकी बड़ी परियोजनाएं पूरी होनेवाली हैं। तथापि जैसा कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका कहना है कि आर्थिक और प्रशासनिक उपायोंके परिणाम प्राप्त करनेके लिए धैर्यकी आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हमें आतंकवादी रोधी कारवाईमें तेजी लानी होगी और युवाओंके कट्टरपंथको रोकनेके लिए कदम उठाने होंगे। दृष्टिसे लोगोंने चुनावमें विश्वास व्यक्त किया और इसका प्रमाण यह है कि राज्यमें हिसारहित मतदान हुआ और ३५ बूथोंमें सर्वाधिक ५८.६ प्रतिशत मत पड़े। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि घाटीमें चेरीके फूल खिल रहे हैं। स्पष्टत: राज्यका दर्जा बहाल करनेके लिए एक सोची-समझी रणनीतिकी आवश्यकता है और इसे एक निर्धारित समयमें पूरा किया जाना चाहिए। केन्द्रको यह समझना होगा कि जम्मू-कश्मीर मुद्देके समाधानमें स्थानीय लोगोंकी भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि वे इसमें मुख्य हितधारक हैं और प्रशासनमें लोगोंकी भागीदारीके माध्यमसे अलगावकी भावनाको समाप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर केन्द्र सरकारको दोहरी रणनीति अपनानी होगी। एक ओर लोगोंकी आकांक्षाओंको पूरा करना होगा और उनके घावोंपर मरहम लगाना होगा, युवाओंको अलगाववादसे बचाना होगा और इसके लिए रोजगारके अवसर सृजित करने होंगे तथा विकास कार्योंको आगे बढ़ाना होगा। साथ ही आतंकवादियोंका मुकाबला कड़ाईसे करना तथा उनका सफाया करना होगा। स्वराष्ट्र मंत्रालयके एक अधिकारीके अनुसार सरकार कश्मीर घाटीकी उपेक्षा नहीं कर सकती किन्तु साथ ही हमें जम्मू क्षेत्रको भी सुरक्षित बनाना होगा और इसके लिए एक नया सुरक्षा तंत्र बनाना होगा। इस क्षेत्रमें सुरक्षाबलोंकी तैनातीको तर्कसंगत बनाया जा रहा है। आतंकवादी घाटी और जम्मू क्षेत्रकी जीवन रेखा राजमार्गोंको निशाना बना सकते हैं, इसलिए स्थानीय पुलिसके साथ राजमार्गोंपर सीआरपीएफकी तैनाती भी की गयी है। देखना यह है कि क्या जम्मू-कश्मीरकी जनता विकासके वायदोंसे संतुष्ट होती है, क्योंकि विकास कश्मीरियोंकी शिकायत नहीं रही। उनकी शिकायत भारतीय सुरक्षाबलोंकी अस्वीकार्य कठोरता रही है और इसके चलते सरकार लोगोंका दिल नहीं जीत पायी। सभी दलोंकी बड़ी-बड़ी छात्र इकाइयां हैं तथा उन्हें अपनी छात्र इकाइयोंके शिष्टमंडलोंको जम्मू-कश्मीरमें भेजना चाहिए और उन्हें वहां कश्मीरके युवाओंके साथ समय बिताना चाहिए। पाकिस्तान और उसके एजेंटोंके उकसावेके बावजूद राज्यके लोगोंके साथ भावनात्मक एकता स्थापित की जानी चाहिए। हालांकि वहां अनेक खराब तत्व हैं, किन्तु आशा की जाती है कि कश्मीरी मित्रताको नहीं ठुकरायंगे या उसका प्रत्युत्तर हिंसाके रूपमें नहीं देंगे। इसका एक समाधान, जैसा कि प्रधान मंत्रीने स्वयं कहा है कि राज्यमें स्थिति सामान्य होनेके बाद जम्मू-कश्मीरका राज्यका दर्जा बहाल किया जायगा और इससे वहांके लोगोंको अपने मुख्य मंत्री और विधायकोंको चुननेका अवसर मिलेगा। भारत सरकारको विश्वास है कि कश्मीरियोंको मुख्य धारामें लानेके उसके प्रयास सफल होंगे। भारत सरकारने राज्य सरकारकी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानोंमें सामाजिक और शैक्षिक रूपसे पिछड़े वर्गोंके लिए आरक्षण लागू किया है और इससे राज्यमें चल रही विसंगति समाप्त हुई है। हमें इस बातको ध्यानमें रखना होगा कि सुदृढ़ और स्थिर जम्मू-कश्मीर पाकिस्तानके लिए एक करारा जवाब होगा और बहुलवादी हिन्दू भारतीय समाज और यहां फल-फूल रहे लोकतंत्रके लिए एक सौगात होगी। मोदीको भारतके राष्ट्रीय हितोंको आगे बढ़ाने तथा कश्मीरियोंको सही मायनोंमें यह अहसास कराने कि वे भारतके हैं, के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए और कश्मीरियोंको भी संकीर्ण भावनासे ऊपर उठकर इस बातका स्वागत करना चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब घाटीमें सामान्य स्थितिकी बहाली हो।

बांग्लादेश में विद्रोह

शेख हसीना का इस्तीफा

बांग्लादेश में विद्रोह के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वे भारत आ गईं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 'दीवाल की लिखावट' नहीं पढ़ पाईं। जनता उनके खिलाफ हो गई थी। उनके सामने इस्तीफा देने और मित्र देश भारत भाग आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शनों ने बांग्लादेश को पंगु बना दिया था। शुरुआती चिनगारी छात्रों की इस मांग से लगी कि स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को मिल रहा आरक्षण समाप्त किया जाए जो बाद में राजनीतिक सुधारों और हसीना के इस्तीफे की मांग में बदल गई। प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकरावों में 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद यह अशांति अपने शिखर पर पहुंच गई। आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने हसीना के आधिकारिक आवास पर हमला बोल दिया। शेख हसीना का राजनीतिक कॅरियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। वे बांग्लादेश के संस्थापक तथा पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। हसीना की राजनीतिक यात्रा 1975 में उनके पिता तथा परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या के बाद शुरू हुई। बाद में बांग्लादेश के सैनिक शासनों के दौरान वे भारत में निर्वासित रहीं। हसीना को 1981 में अवामी लीग का अध्यक्ष चुनाव गया और इसके बाद वे बांग्लादेश चली गईं। उन्होंने अवामी लीग को पुनर्जीवित कर इसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनाने में सफलता पाई। अवामी लीग के आम चुनाव में विजय पाने के बाद शेख हसीना 1996 में प्रधानमंत्री बनीं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के आरोपों के कारण उनकी पार्टी को 2001 में पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन

2008 के चुनाव में अवामी लीग की असाधारण विजय के बाद वे 2009 में सत्ता में वापस आईं। इसके बाद 2009-2024 तक के उनके प्रधानमंत्री कार्यकालों में काफी आर्थिक प्रगति हुई, पर स्वेच्छाचारी कार्यशैली के कारण अंततः उनका पतन हुआ। अपने कार्यकाल में उन्होंने सत्ता अपने हाथों में केन्द्रित करने के प्रयास किए जिससे उन पर 'तानाशाही' तथा 'विरोध को कुचलने' के आरोप लगे। लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण तथा प्रमुख विकास लक्ष्य पाने में उल्लेखनीय सफला प्राप्त की। 15 साल के लंबे शासनकाल के बाद वे संभवतः जमीनी यथार्थ से कट गई थीं। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले लोगों को गद्दार कहा, कर्फ्यू लगाया तथा उन पर गोली चलाने के आदेश दिए। यह भयंकर गलती थी जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनके पतन से नई दिल्ली चिन्तित है। भारत को अब बंगाल की खाड़ी में विपरीत राजनयिक माहौल का सामना करना पड़ेगा। हसीना सरकार के विकल्पों में दक्षिणपंथी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी, जातीय पार्टी और सेना है। ये सभी भारत को एक प्रभुत्वकारी शक्ति मानते हैं और उसे किनारे रखना चाहेंगे। बांग्लादेश में अस्थिरता खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सुरक्षा चिन्ता बढ़ाने वाली है। शेख हसीना की विदाई ने राजनीतिक परिस्थितियां व्यापक रूप से बदली हैं। हसीना के स्थान पर चाहे जो आए, भारत-बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश अब चीन के निकट जा सकता है। ऐसे में नई दिल्ली को अंतरिम सरकार से बेहतर संबंध बनाते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी, जातीय पार्टी तथा सेना के जनरलों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। बांग्लादेश में नए चुनाव होने तक वहां अस्थिरता बने रहने तथा विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष तेज होने की संभावना है।

उर्वरकों पर टैक्स का तार्किकीकरण

कई बार चर्चा और संस्तुतियों के बावजूद टैक्स दरें निर्धारित करने की जिम्मेदार जीएसटी परिषद अभी करों में विसंगतियां दूर करने में सफल नहीं हुई है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

पांच साल से अधिक समय बीतने के बाद आज भी उर्वरक उद्योग 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' का सामना कर रहा है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां कच्चे माल-आरएम पर तैयार उत्पाद की तुलना में ज्यादा टैक्स लगता है जिनका उत्पादन में प्रयोग होता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत बजट में इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है। उर्वरकों तथा उनके उत्पादन में प्रयोग होने वाले आरएम पर मुख्यतः वस्तु एवं सेवाकर-जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इसका काम टैक्स की दरें निर्धारित करने के साथ पंजीकरण प्रक्रिया, करों के भुगतान, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग व अन्य संबंधित मामलों संबंधी निर्णय करना होता है। इसलिए कर लगाने संबंधी विकृतियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी जीएसटी परिषद पर होती है।

इस मुद्दे पर चर्चा जीएसटी परिषद की 2021 सितंबर में आयोजित 45वीं तथा जून, 2022 में आयोजित 47वीं बैठक में की गई, पर इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इस बीच 9 अगस्त, 2023 को रसायन एवं उर्वरकों पर स्थाई समिति ने संस्तुति की कि केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद को उर्वरकों तथा इनके उत्पादन में प्रयोग होने वाले आरएम पर टैक्स की दरें घटाने का प्रस्ताव करे। 22 जून, 2024 को आयोजित 53वीं बैठक में परिषद ने यह मामला दरों के तार्किकीकरण पर निर्णय करने के लिए मंत्रियों के समूह-जीओएम के पास भेज दिया ताकि उर्वरकों पर टैक्स लगाने को तार्किक बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। ऐसे में सबसे पहले हमें उर्वरकों पर टैक्स के वर्तमान ढांचे पर गौर करना चाहिए।

किसानों को सस्ते उर्वरक दिलाने के लिए सरकार उनके अधिकतम खुदरा मूल्य-एमआरपी को कम स्तर पर रखती है जिसका उत्पादन और वितरण की लागत से कोई संबंध नहीं है। वह निर्माताओं को एमआरपी से अधिक खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। यूरिया के मामले में एमआरपी लागत का लगभग दसवां हिस्सा है, जबकि बाकी उर्वरकों के मामले में कीमत लगभग एक तिहाई है। जब सरकार बजट से भारी धनराशि उर्वरको को सस्ती कीमत पर किसानों को देने के लिए खर्च करती है तो उन पर टैक्स लगाने का कोई अर्थ नहीं है। इसके कारण लागत में हुई वृद्धि के लिए सरकार निर्माताओं को अतिरिक्त प्रतिपूर्ति करती है। यह 'एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने' की तरह है। उर्वरक सप्लाई श्रृंखला के दो मुख्य आयामों पर टैक्स दो अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है जिसमें से एक जीएसटी व्यवस्था और दूसरी पूर्व-जीएसटी व्यवस्था में आती है। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट-डीएपी, अमोनियम सल्फेट, आदि तैयार उर्वरकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगती है। इनमें अधिकांश आरएम सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, आदि भी जीएसटी में आते हैं। जहां सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, वहीं फास्फोरिक एसिड पर 12 प्रतिशत कर लगता है। लेकिन घरेलू यूरिया के लगभग सारे उत्पादन में प्रयोग होने वाली प्राकृतिक गैस-एनजी पर पूर्व-जीएसओ व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगता है। उर्वरक-उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली बिजली को भी जीएसटी के बाहर रखा गया है।

जीएसटी एक अकेला राष्ट्रव्यापी टैक्स है जिसमें निवेशों के भुगतान हेतु सेटआफ टैक्स की व्यवस्था है। इसने पूर्व-जीएसटी युग के एक दर्जन से अधिक टैक्सों को अपने भीतर समाहित किया है जिनमें केन्द्रीय एक्साइज़ ड्यूटी-सीईडी, सेवा कर तथा बिक्री कर-वैल्यू एडेड टैक्स-वैट शामिल हैं। जीएसटी पर संविधान संशोधन कानून, 2016 में जहां एनजी को शामिल किया गया है, वहीं इसे 'ज़ीरो रेटेड' रखा गया है। इसका अर्थ है कि यह पूर्व-जीएसटी व्यवस्था में बनी रहेगी। हालांकि, जीएसटी परिषद ने कई बार एनजी पर कर तय करने का एजेंडा अपनी बैठकों में रखा, पर इस पर निर्णय हमेशा टाल दिया गया।

पूर्व में निर्धारित की गई जीएसटी व्यवस्था में टैक्स के कारण एनजी और बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन-ओएनजीसी व आयल इंडिया लिमिटेड-ओआईएल जैसी तेल कंपनियां जीएसटी दायरे से बाहर हैं ओर वे निवेशों, कंज्यूमेबल व उपकरणों की खरीद पर भुगतान किए टैक्स पर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं। इस कारण इनकी कीमतें बढ़ती हैं। हालांकि, उर्वरक प्लांटों को सप्लाई की जाने वाली एनजी पर सीईडी नहीं लगता है, पर वैट के कारण इसकी कीमत बढ़ती है जो आंध्र प्रदेश में 24.5 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इस पर अन्य स्थानीय करों, जैसे गुजरात के 'खरीद टैक्स' के कारण राज्य के बाहर बिक्री होने वाली यूरिया बनाने में प्रयोग होने वाले निवेश का खर्च बढ़ जाता है। बिजली के मामले में बिजली कंपनियों को निवेशों पर भुगतान किए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है जिनमें उपकरण, भंडार, आदि शामिल हैं जिनका प्रयोग बिजली के उत्पादन व वितरण में होता है। इससे कीमत बढ़ती है।

संविधान के प्राविधान 53 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की राज्य सूची राज्यों को बिजली की बिक्री और उपभोग पर टैक्स लगाने का अधिकार देती है। इसका अपवाद केन्द्र सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिजली है। बिजली ड्यूटी के लिए भी बिजली कंपनियों को कोई आफसेट नहीं मिलता है जिससे उर्वरक प्लांटों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की लागत और बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में जहां सामग्री जीएसटी के अंतर्गत आती है और लागत नहीं बढ़ती है, वहां भी इन्वर्टेड टैक्स ढांचा नकारात्मक प्रभाव डालता है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड आदि पर लगने वाली उच्च जीएसटी तैयार उर्वरकों पर लगने वाली कम जीएसटी से काफी अधिक है। इसका नतीजा 'अनुप्रयुक्त' इन्पुट टैक्स क्रेडिट-आईटीसी के रूप में सामने आता है क्योंकि आउटपुट टैक्स इन्पुट टैक्स से कम होता है। सरकार द्वारा उर्वरकों का एमआरपी बहुत कम स्तर पर रखे जाने के कारण यह स्थिति लगातार खराब हो रही है। इस तथ्य को देखते हुए कि किसानों को उपलब्ध उर्वरक की कीमतें उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं, ऐसे में आदर्श रूप से उसे ऐसी लेवी में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके लिए उसे अतिरिक्त सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। यदि वह लेवी लगाना चाहती है तो आदर्श रूप से सप्लाई श्रृंखला की सभी चीजें जीएसटी के अंतर्गत लाई जानी चाहिए। इसके साथ ही उर्वरकों तथा सभी निवेशों और आरएम को न्यूनतम 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा जाना चाहिए।

चूंकि उर्वरकों पर टैक्स की दर पहले से 5 प्रतिशत है, इसलिए आरएम पर टैक्स की दरें घटा कर 18-12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत करनी चाहिए। जिंक, बोरान, मैंगनीज़, आयरन, आदि लघु पोषकों पर टैक्स को भी 12-18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इसकी संस्तुति स्थाई समिति ने की है। ये लघु पोषक पौधों की वृद्धि तथा संतुलित पोषण प्रयोग के लिए जरूरी हैं। इसी प्रकार एनजी और बिजली को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ला कर इन पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन केवल आरएम पर टैक्स घटाने से अनुप्रयुक्त आईटीसी की समस्या हल नहीं होगी। इसका समाधान केवल तभी हो सकता है जब सरकार किसानों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण-डीबीटी के अंतर्गत सब्सिडी दे और उर्वरक निर्माताओं को किसानों से पूरी कीमत वसूलने की अनुमति दे।

यूरिया के मामले में हमने देखा है कि एमआरपी को बहुत कम रखने पर इसका दुरुपयोग बढ़ जाता है तथा वह खेती के बजाय अन्य कामों में प्रयोग होने लगती है। उत्पाद के अंतिम प्रयोग पर आधारित मूल्य व्यवस्था तथा उनके उत्पादन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग टैक्स लगाने वाली व्यवस्था में करापवंचन व दुरुपयोग अवश्यंभावी हो जाता है। इससे बचने तथा किसानों को सस्ते उर्वरक दिलाने का एकमात्र रास्ता

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कष्टों को दूर करने का उपाय है स्वीकारोक्ति

> जब हम वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो हमारा आक्रोश कम हो जाता है और दर्द भी काफी हद तक कम हो जाता है।

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

अगर आप किसी से पूछें कि दुख क्या है? तो वे बस यही कहेंगे कि यह हमारे जीवन में होने वाली नकारात्मक घटनाओं के कारण होता है या उनका परिणाम होता है। हालांकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक अर्थों में, दुख कभी भी वह नहीं होता जो होता है, यह वह होता है जो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आप महसूस करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुख एक भावना है और हमारी सबसे मजबूत भावनाएं हमारी भावनाओं के अलावा और कुछ नहीं हैं, और जब भावनाएँ नकारात्मक हो जाती हैं, तो वे दर्द देती हैं। तो, सरल शब्दों में, दुख हमारी नकारात्मक भावनाओं और हमारे दर्द के प्रति हमारा प्रतिरोध है। यह हमारे दर्द के बारे में दर्द है। इसलिए, हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि दुख हमारी भावनाओं का परिणाम है न कि हमारे जीवन की घटनाओं का।

हम सभी अपने दैनिक जीवन में दर्द का अनुभव करते हैं क्योंकि यह अपरिहार्य है और यह मानव होने का एक हिस्सा है। हालाँकि, हममें से कितने लोगों ने जीवन के इस दार्शनिक प्रश्न पर विचार किया है - हमें दर्द क्यों होता है? या हमारी नकारात्मक भावनाओं का कारण क्या है? हमारा दर्द किसी प्रियजन को खोने, अपनी नौकरी खोने, किसी बुरे ब्रेकअप, किसी जानलेवा दुर्घटना या किसी अन्य तरह के आघात या स्थिति से गुज़रने से हो सकता है।

हालांकि, जब हम वास्तविकता का सामना करने या उसे स्वीकार करने से छिपते हैं, तो हम पीड़ा पैदा करते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे और बुरे के एकमात्र निर्माता हैं और इसलिए दूसरों को दोष देना व्यर्थ है - यह उचित

नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था या मैं इसे और सहन नहीं कर सकता! आदि। हममें से अधिकांश लोगों में अपने भीतर गहरे में अनुभव किए जाने वाले दर्द से लड़ने की गहरी प्रवृत्ति होती है, हालांकि, ज़्यादातर मामलों में इसका उल्टा असर होता है और हम दुगने दर्द का अनुभव करते हैं। इसके पीछे का कारण हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने दर्द को टालते हैं और, कुछ मामलों में, उसे छिपाते हैं या दिखावा करते हैं कि यह मौजूद नहीं है। हम अपने अंदर गहरे में अपने दुख के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन इसे खुले तौर पर स्वीकार करने की हमारी ज़िद के कारण इसके बारे में कुछ नहीं करते। एक समझदार व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करेगा और मन पर बोझ डालने के बजाय हल्का हो जाएगा क्योंकि स्वीकार करने का मतलब है कि आप अपनी वास्तविकता को नकारने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और आप इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि कभी-कभी दर्दनाक भावनाओं को स्वीकार करने से हमारा दुख कम हो सकता है क्योंकि हम अब उनसे भाग नहीं रहे हैं या उन्हें दूर नहीं कर रहे हैं। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं या आप इसे बदलना नहीं चाहते हैं, यह सब हमारे दुख को कम करने के बारे में है, इसलिए यदि आपको किसी ने चोट पहुंचाई है।

तो यह स्वीकार करना सबसे अच्छा है कि हां आपको चोट लगी थी और फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ें बजाय इसके कि क्यों, कैसे, क्या... याद रखें! माफ़ करना या न करना हर किसी का विशेषाधिकार है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वीकार करना ज़रूरी है वरना हम व्यर्थ विचारों के दलदल में फंस जाएंगे।

एक बार जब हम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है और दर्दनाक स्थिति हम पर अपनी शक्ति खो देती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भावनात्मक दर्द हमारे सभी जीवन का एक आंतरिक हिस्सा है, हालाँकि, जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अनावश्यक पीड़ा पैदा करते हैं। जब हम स्वीकृति का अभ्यास करते हैं, तो हम खुद को आगे बढ़ने देते हैं, हम स्वतंत्रता के द्वार खोलते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं।

हममें से अधिकांश लोगों को वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन लग सकता है और फिर भी समय और परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार करना पसंद करते हैं, हालांकि ऐसा करते समय, हम भूल जाते हैं कि समय सब कुछ ठीक नहीं करता, लेकिन स्वीकृति सब कुछ ठीक कर देगी।

आप की बात

चिन्ताजनक स्थिति

बांग्लादेश में वर्तमान हालात बेहद चिंताजनक है। हिंदुओं के मंदिरों में आगजनी और हिंदुओ पर जानलेवा हमले कानून व्यवस्था की व्यापक हत्या जैसे लगते है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश की लपटें अन्य देशों को भी सोचने पर विवश कर रही। भारत की नजर इन हालातों पर अनवरत बनी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सदन में कहा कि बांग्लादेश में कई संगठन हिंदुओं की सहायता कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यह कहना कठिन है कि बांग्लादेश के समझदार व पंथनिपरेक्ष नागरिक कब तक हिंदुओं की रक्षा कर सकेंगे। बांग्लादेश में यदि स्थिति जल्दी नहीं सुधरी और वहां बिजनेस व कामकाज बंद रहे तो देश से हिंदुओं के साथ अन्य गरीब लोगों का पलायन भी भारत को हो सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तथा सेना को अविलंब स्थिति सामान्य करने तथा हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के प्रयास करने चाहिए। भारत सरकार को भी राजनयिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नई सरकार से सीधे संपर्क स्थापित कर दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को यथासंभव व जल्दी से जल्दी पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास करना होगा।

– **योगेश जोशी,** बड़वाह

लव जिहाद का विरोध

उत्तर प्रदेश के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने भी घोषणा की है कि उनकी सरकार भी अब शीघ्र ही यूपी सरकार की तरह लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बाबत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। असम सरकार के इस निर्णय की सराहना करनी चाहिए। हमारे देश में आज लव जिहाद के केस काफी अधिक बढ़ रहे हैं अतः इन पर रोक लगाने के लिए आज यूपी एवं असम सरकार के साथ ही सभी राज्यों को ऐसे कानून बनाने और उन पर कठोरता से अमल करने की जरूरत है। कोई भी प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं है परंतु अपनी पहचान छिपा कर हिंदू लड़कियों को धर्मान्तरण के उद्देश्य से धोखा देना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सचेतन रूप से सोच समझ कर अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों को भी किसी धर्म की परंपरा के बजाय विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही विवाह करना चाहिए जो महिलाओं को किसी पर्सनल कानून की तुलना में बेहतर सुरक्षा देता है तथा जिसे अदालतों द्वारा लागू करवाना तुलनात्मक रूप से बहुत आसान है।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

मुहम्मद यूनुस को कमान

बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज़ जमान शायद खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। इसी लिए छात्र नेताओं के अनुरोध पर मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। मुहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के नेता हैं। 84 वर्षीय मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रोक्रेडिट व माइक्रोफाइनेंस अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिना कोई संपत्ति बंधक रखे या गारंटी के बांग्लादेश के आम ग्रामीणों व सबसे गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्होंने पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था को चौंका दिया था। हालांकि, उन पर हसीना सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जेल की लंबी सजा से बचने के लिए मुहम्मद यूनुस विदेश चले गए थे। मुहम्मद यूनुस जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाले व्यक्ति को अंतरिम सरकार की कमान सौंप कर बांग्लादेश दुनिया में अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर सकता है। देखना होगा कि उनको काम करने का कितना मौका मिलता है और वे बांग्लादेश में सामान्य स्थिति बहाल करने में कहां तक सफल होते हैं।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

खुफिया तंत्र की विफलता

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चले छात्र आंदोलन में हिंसा और अंततः सेना द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलटना एक प्रकार से खुफिया तंत्र की विफलता है। यह कोई अचानक होनेवाली घटना नहीं है। ऐसा लगता है कि विदेशी शक्तियों के जरिए बांग्लादेश की सेना के माध्यम से विद्रोह का षड्यंत्र रचा गया था। बांग्लादेश-भारत की निकटता चीन ओर पाकिस्तान को खल रही थी। इन देशों ने चालाकी से दशकों से जारी आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन के नाम पर सुनियोजित षडयंत्र किया। इसमें शेख हसीना की सरकारी गुप्तचर सेवा के साथ भारत की राजनयिक विफलता भी सामने आई है। क्या भारत सरकार का विदेश खुफिया विभाग समय रहते देश की सबसे निकट मित्र सरकार के खिलाफ षडयंत्र का समय रहत पता नहीं लगा पाया? हालांकि, शेख हसीना को अपने पिता की तरह जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन बंग बंधु मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ती भीड़ एक प्रकार से अवामी लीग की राजनीतिक विफलता का प्रतीक बन गई है। भारत को अब और अधिक सजग रहना और ताकतवर बनना होगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

ब्रिटेन में भी हिंसा चिंताजनक

ब्रिटेन में दक्षिणपंथी हिंसा की लहर के बीच आप्रवासियों व मुस्लिमों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंता का विषय है। सोशल मीडिया के जरिये भ्रामक प्रचार से समूह विशेष पर हमले ब्रिटिश समाज में विकट होती स्थिति को दशार्ता है। गत 29 जुलाई को साउथपॉर्ट में टेलर स्विफ्ट की थीम डांस पार्टी में तीन बच्चियों की नृशंस हत्या के बाद ब्रिटेन के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। इस घटना में दो वयस्कों के साथ कई अन्य बच्चे भी घायल हुए थे। इसके बाद पूरे ब्रिटेन में दक्षिणपंथी आंदोलनकारियों ने इस घटना का इस्तेमाल नफरत को बढ़ावा देने और अराजकता भड़काने में किया। कालांतर में हिंसा महज विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रही। दुकानें लूट ली गईं, कारों को आग लगा दी गईं, मस्जिदों और एशियाई स्वामित्व वाले व्यवसायों को निशाना बनाया गया। यह चिंताजनक स्थिति ब्रिटिश समाज में पैर पसारती मानसिक रुग्णता को ही दशार्ती है। ब्रिटिश समाज में आप्रवासियों के प्रति धुर दक्षिणपंथियों की कटुता छिटपुट घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ही नजर नहीं आती, बल्कि ये घटनाक्रम ब्रिटिश समाज में व्यापक सामाजिक चिंताओं और राजनीतिक विफलताओं का भी परिचायक है। दरअसल, कई दक्षिणपंथी राजनेताओं ने आप्रवासन और सांस्कृतिक एकीकरण के बारे में गलत धारणाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने विभाजनकारी एजेंडे के लिए समर्थन जुटाने के लिये खतरनाक ढंग से गलत सूचनाएं फैलायीं। कहा गया कि हमलावर एक आप्रवासी मुस्लिम था। हालांकि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने दंगों को सुनियोजित साजिश बताते हुए घटनाओं की निंदा की है, लेकिन अभी ब्रिटिश समाज में सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह में हिंसक गतिविधियों में शामिल करीब चार सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस से संघर्ष करते नजर आ रहे थे। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति और आप्रवासियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाल के दिनों में देखने में आया है कि कई देशों में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन सूचनाओं को गलत ढंग से प्रसारित व प्रचारित किया गया। वास्तव में भ्रामक सूचनाओं के तंत्र पर अंकुश लगाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की जरूरत है। देखने में आया है कि सुनियोजित ढंग से प्रचारित सूचनाएं लोगों को कट्टरपंथी बनाने और हिंसा को भड़काने के लिये प्रयोग की जाती हैं। सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से दक्षिणपंथियों की हिंसा से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

कितनी बार अपने ही संस्थापक बंगबंधु को मारेगा बांग्लादेश

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

शेख हसीना का इस्तीफा बांग्लादेश के लिए एक दुखद अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उतनी ही दुखद वे तमाम छवियां है, जिन्हें आज सारी दुनिया टेलीविजन पर देख रही है। इनमें सैकड़ों लोग बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान की मूरत पर चढ़कर उसे हथौड़े मारकर तोड़ रहे हैं। जिस बंगबंधु की कुर्बानियों के चलते बांग्लादेश का 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद जन्म हुआ था, उनकी तस्वीरों और मूर्ति को तोड़ा और फाड़ा जा रहा है। और पूरी दुनिया ने इसे देख रही है। मैं तो उन चन्द युद्ध संवाददाताओं में एक था जिसने बांग्लादेश के ₹राष्ट्रपिता₹ कहे जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के नेता शेख मुजीब के पराक्रम, चमत्कार और करिश्माई नेतृत्व को मुक्ति वाहिनी के संघर्ष से लेकर भारत- पाक के युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता तक नजदीकी से देखा है। फिर यह भी देखा है कि 1975 में किस तरह उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों (विदेश में रह रही हसीना बच गई थीं) की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। अब उनकी बेटी और बांग्लादेश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाने वाली शेख हसीना को भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। उन्हें देश छोड़ने के लिये मात्र 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद देश फिर से सेना के पूर्ण नियंत्रण में आ गया है।

सेना प्रमुख, जनरल वाकर-उज-जमान, जो इस साल 23 जून से पद पर हैं, ने एक अंतरिम सरकार का वादा किया है। लेकिन , इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आदेश कौन देगा। उन्होंने विपक्षी दलों से बात की है। उन्होंने शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को रिहा कर दिया है। खालिदा जिया के प्रधानमंत्रित्व काल में बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया था। खालिदा जिया घनघोर भारत विरोधी रहीं हैं । खालिदा जिया की रिहाई से भारत की विदेश नीति को तय करने वाले चिंतित जरूर होंगे। खालिदा जिया जब अपने देश की प्रधानमंत्री थीं तब वहां टाटा ग्रुप की इनवेस्टमेंट करने की योजना का कसकर विरोध हुआ था। उसे हवा खालिदा की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी(बीएनपी) ही दे रही थी। टाटा ग्रुप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा रही थी। टाटा ग्रुप को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बताने वाले भूल गए थे कि टाटा ग्रुप भारत से बाहर दर्जनों देशों में स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शिता पूर्ण कारोबार करता है। वहां पर तो उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगाता।

शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने के साथ ही वहां जमात ए इस्लामी और भारत विरोधी ताकतें हिन्दुओं और प्राचीन हिन्दू मंदिरों पर हमला करने लगी हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले शेख हसीना के दौर में कमोबेश खत्म हो गए थे। वहां पर अब तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए स्पेस जीवन के सभी क्षेत्रों में घट रहा है। बांग्लादेश में कठमुल्ले कट्टर इस्लामिक हिन्दुओं की जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें तो बस मौके भर की तलाश होती है। यह अफसोसजनक बात है कि बांग्लादेश में हिन्दू कतई सुरक्षित नहीं हैं। जबकि बांग्लादेश में सदियों से बसे हिन्दुओं ने बंग बंधु के नेतृत्व में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था ।

राजधानी दिल्ली में निर्वासित जीवन जी रही तस्लीमा नसरीन ने अपने उपन्यास 'लज्जा' में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दर्दनाक स्थिति पर विस्तार से लिखा है । इसलिए ही उनकी जान के भी दुश्मन हो गए थे कठमुल्ले। मुझसे एक- दो बार तस्लीमा मिलने क्या आ गईं कि मुझे भी सलाहपूर्ण धमकियों भरे कॉल आने लगे थे। उसी विरोध के कारण तसलीमा को भी अंततः अपनी मातृभूमि बांग्लादेश सदा के लिये छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास ह्यलज्जाह्न1993 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसमें साम्प्रदायिक उन्माद के नृशंस रूप को दशार्या गया है। लज्जा के आने के बाद कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। जिस कारण से वह अमेरिका चली गईं थीं। अपनी जान बचाने की गरज से तस्लीमा लम्बे अरसे तक स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में भी रहीं । वह 2004 में कोलकाता आ गई थीं। उन पर 2007 में हैदराबाद में भारत के कठमुल्लों ने हमला भी किया पर वे बाल बाल बच गईं।

बांग्लादेश में जेसोर, देबीगंज, राजशाही, शांतिपुर, प्रोधनपारा और आलमनगर में हिन्दुओं पर सर्वाधिक जुल्मों-सितम होते रहे हैं। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में हिन्दू वहां की आबादी के 30 से 35 फीसदी के बीच थे। पर 2011 की जनगणना के बाद वहां हिन्दू देश की कुल आबादी का मात्र 8 फीसदी ही रह गए हैं। शेख हसीना के दौर से पहले बांग्लादेश में शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो, जब किसी हिन्दू महिला के साथ कट्टरवादी बदतमीजी न करते हों। कोई महिला कट्टरवादियों का विरोध करती , तो उसे निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता।

बांग्लादेश में हिन्दू महिलाएं हमेशा ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। राह चलती किसी लड़की को सरेआम उठाकर कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका जबरन निकाह किसी मुस्लिम से कर दिया जाता है। इसलिए दोनों देशों के हिंदू भारत आना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या कुछ साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश हिन्दू-विहीन हो जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिन्दुओं के उत्पीड़न की खबरें उन भारतीय सेक्युलरवादियों तक नहीं पहुंचती हैं, जो हमास के किसी आतंकी को मारे जाने पर इजरायल को पानी पी-पीकर कोसते हैं?

एक बात तो माननी ही होगी कि शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर को सुरक्षित बनाने में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने अपने देश के कठमुल्लों को कभी भारत के पूर्वोत्तर भागों में अपना खेल खेलने की इजाजत नहीं दी। क्या अब यह क्षेत्र फिर से आतंकवादियों का केंद्र बन जाएगा? शेख हसीना, जो 2009 से सत्ता में थीं और दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेता रहीं। लेकिन, वे भी कई कमियों की शिकार रहीं। वह उन चेतावनियों को पढ़ने में विफल रहीं जो एक सामाजिक-आर्थिक और संभावित रूप से भावनात्मक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों के साथ आई थीं। हाल के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित नौकरी कोटे को समाप्त करने की थी, जिसे उनके बच्चों और यहां तक कि पोते-पोतियों तक बढ़ा दिया गया था। नौकरी कोटा उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था , जिन्हें इसका लाभ नहीं हुआ था और आर्थिक संकट के बीच शेख हसीना के विरोधियों के लिए यह काम आया।

शेख हसीना ने पहले उन्हें 'रजाकार' (स्वतंत्रता संग्राम के पाकिस्तान समर्थक विरोधी) कहा, और फिर उन्हें 'आतंकवादी' कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कोटे को न्यूनतम तक कम कर दिया था। इससे यह उम्मीद बनी थी कि अब बंगलादेश फिर से अमन की तरफ लौट जाएगा।लेकिन , यह उम्मीद गलत साबित हुई। पांच हफ्तों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बल के प्रयोग, ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया था। खैर, बांग्लादेश अब तो एक गहरे संकट में जा चुका है। अब इस बात की उम्मीद कम ही है कि वहां पर जिंदगी निकट भविष्य में पटरी पर लौट जाएगी। जो देश अपने संस्थापक का अपमान करता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

न्याय के लिए शुरू हुए आंदोलन का चेहरा इतना क्रूर क्यों?

महेश खरे

1975 में बांग्लादेश के निमार्ता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना मात्र से आज भी कलेजा कांप जाता है। इस बार शेख हसीना के साथ भी 1975 दोहराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि शेख हसीना अगर 15-20 मिनट भी सामान बटोरने में और लगा देतीं तो उनका हस्त्र भी पाकिस्तान के पुराने हुक्मरानों जैसा ही होता। अपदस्थ प्रधानमंत्री के साथ क्या होता इसका अंदाजा उनके अंगवस्त्र लहराते हुए हाथों और कुटिल मुस्कान बिखेरते चेहरों को देख कर लगाया जा सकता है। छात्र बनकर आंदोलन कर रही भीड़ के मंसूबे अब छुपे हुए नहीं हैं। क्या न्याय के लिए आंदोलन का चेहरा इतना विद्रूप भी हो सकता है? पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को इससे कम में घटनाओं को अंजाम देना आता भी नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन कब कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया ...पता ही नहीं चला। वरना बंग बंधु की विरासत से दुश्मनी निकालने में छात्रों को क्या रुचि हो सकती है? 17 करोड़ आबादी वाले इस देश में मात्र पांच लाख की भीड़ का आंदोलन इतना उग्र और हिंसक कैसे और क्यों हो गया? अब यह भी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है।

बांग्लादेश में जो भी हुआ वह केवल दो महीनों का खेल नहीं है। दरअसल इसकी पटकथा 15 साल पहले लिखनी शुरू हो गई थी। सत्ता की आंखों पर लगी तानाशाही की पट्टी ने सामने घट रही घटनाओं का आधा-अधूरा सच ही समझ में आने दिया। जब हुक्मरान के मन में सर्वशक्तिमान का अहं गहरे पैठ जाता है तो फिर उसे सच्चाई भी धुंधली धुंधली सी नजर आने लगती है। विपक्ष की चुनौतियां भी जी हुजूरियों की वाहवाही के बीच गले से उतरने नहीं देती। सत्ता की जड़ों को चाटुकारिता का कीड़ा खोखला करता रहता है। इन परिस्थितियों में सत्ता के तोते कब उड़ गए पता ही चला। तख्तापलट से अंतरिम सरकार बनने तक हिंसा और अराजकता देश को किन हाथों का खिलौना बना देगी यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

इन हालातों में भारत की पहली चिंता वहां फंसे हिंदुओं की सुरक्षा और तटस्थ भाव से सरकार गठन की प्रक्रिया देखने से ज्यादा कुछ नजर नहीं आती। आज की परिस्थिति में इससे अधिक कुछ किया भी नहीं जा सकता। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के चीफ एडवाइजर बनने के बाद वहां धीरे धीरे शांति की बहाली का विश्वास बढ़ने लगा है।

वैसे मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में क्रांति प्रायः रक्तरंजित ही होती है। सच्चाई जानने के लिए पाकिस्तान के इतिहास पर फौरी नजर घुमाना ही काफी है। लगता है पाकिस्तान में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण वहां की आवाम को पसंद नहीं आता। गोली और तलवार से फैसला निर्णायक तो होता है लेकिन इसमें निदोर्षों के खून से जमीन लाल भी होती है। पाकिस्तान में ऐसे दृश्य एक नहीं अनेक बार दोहराए गए। बांग्लादेश में तख्तापलट की कहानी भी खून से सनी हुई है। दो दिन की रक्त क्रांति में ही पांच सौ से अधिक इंसानों की बलि चढ़ा दी गई। हिंसा का सिलसिला इसमें कितना इजाफा करता रहेगा कहा नहीं जा सकता।

1975 में बांग्लादेश के निमार्ता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना मात्र से आज भी कलेजा कांप जाता है। इस बार शेख हसीना के साथ भी 1975 दोहराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि शेख हसीना अगर 15-20 मिनट भी सामान बटोरने में और लगा देतीं तो उनका हस्त्र भी पाकिस्तान के पुराने हुक्मरानों जैसा ही होता। अपदस्थ प्रधानमंत्री के साथ क्या होता इसका अंदाजा उनके अंगवस्त्र लहराते हुए हाथों और कुटिल मुस्कान बिखेरते चेहरों को देख कर लगाया जा सकता है। छात्र बनकर आंदोलन कर रही भीड़ के मंसूबे अब छुपे हुए नहीं हैं। क्या न्याय के लिए आंदोलन का चेहरा इतना विद्रूप भी हो सकता है? पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को इससे कम में घटनाओं को अंजाम देना आता भी नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन कब कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया ...पता ही नहीं चला। वरना बंग बंधु की विरासत से दुश्मनी निकालने में छात्रों को क्या रुचि हो सकती है? 17 करोड़ आबादी वाले इस देश में मात्र पांच लाख की भीड़ का आंदोलन इतना उग्र और हिंसक कैसे और क्यों हो गया? अब यह भी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है।

जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना की हिस्सेदारी हो जाती है तो सत्ता के केन्द्र में सेना ही होती है। जन नेता आंदोलन तो कर सकते हैं। हथियार नहीं उठा सकते। इस आंदोलन में भी सेना इसीलिए तो हावी हुई। सत्ता का स्वाद चख कर सेना नायकों में देश सेवा, वफादारी और त्याग की भावना तिरोहित हो जाती है। अब देखिए बांग्लादेश के जनरल वकार -उज - जमान रिश्ते में तो शेख हसीना के करीबी रिश्तेदार (जीजा) लगते हैं। वफादारों में भी वे उनके सबसे भरोसेमंद रहे। लेकिन, जब मौका आया तो पलटी खाने में भी वो नंबर वन रहे। देश की जड़ों में मट्ठा डालने वाली ताकतों के साथ गोटी फिट करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। क्या पता मिलीभगत पहले से चल रही हो। वरना, जहां शेख हसीना के वफादारों, आवामी लीग के नेताओं और हिन्दुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा हो वहां जनरल वकार का आंदोलन के नेताओं के चहेते बने रहना चौंकाता तो है ही।

शेख हसीना को विपक्ष का दमन भी बहुत भारी पड़ा। उनकी कट्टर दुश्मन मानीं जाने वाली 78 वर्षीय खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख हैं। खालिदा के अलावा 25 हजार से अधिक विपक्षी नेता किसी न किसी आरोप में जेल में ठूंस दिए गए थे। साल 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनके राजनीतिक जीवन का उदय हुआ। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्हें 2018 में जेल भेज दिया गया। अब जेल के दरवाजे विपक्ष के साथ साथ अपराधियों के लिए भी खोल दिए गए हैं। जो प्रतिबंधित थे वे अब सत्ता के गठन में निर्णायक भूमिका में हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का दमन लोकतंत्र में दुश्मनी को ही जन्म देता है।

बांग्लादेश के हाल के घटनाक्रमों से भारत का संकट भी गहरा गया है। अभी तक तो बांग्लादेश भारत का मैत्री देश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेख हसीना से मैत्रीपूर्ण राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। अब बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में कितना रहेगा और किस दिशा में बहेगा यह भविष्य के गर्त में हैं। सीमा से सटे अन्य पड़ोसी देशों में भी अपना कौन है यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। ऐसे हालातों में विपक्ष ने भारत सरकार के प्रति जो एकजुटता दिखाई है वह स्वागत योग्य है। इस समय एकता, संयम और विवेक से ही नए रास्ते निकलेंगे।

नई सोच एक्सप्रेस
हर खबर पर पैनी नजर
(पटना से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

हिंसा को रोकने का आह्वान

यह थोड़ी हैरानी वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन सप्ताह पहले हुई रूस यात्रा के बाद भारत ने यूक्रेन समेत गाजा और म्यांमार में जारी हिंसा को रोकने का आह्वान किया। टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यायसंगत और संतुलित विश्व व्यवस्था बनाए रखने और सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का सम्मान करने की अपील की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने के आह्वान का आशय यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से भी निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का अलगे महीने यूक्रेन की यात्रा पर ही जाने की चर्चा है जहां रूस-यूक्रेन संघर्ष पर विस्तार से वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मोदी की यूक्रेन यात्रा की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। क्वाड की इस बैठक में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की इकतरफा कार्रवाई की भी निंदा की गई। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया लेकिन स्पष्ट रूप से चीन की ओर इशारा था। विदेश मंत्री जयशंकर ने स्वीकार किया कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ मई महीने में रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता विश्व की सबसे बड़ी घटना थी। यह शिखर वार्ता भावी विश्व व्यवस्था के निर्माण में नींव का पत्थर साबित हो सकती है। शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य को रूस और चीन के बीच 'असीमित साझेदारी वाला दस्तावेज बताया गया। यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले वर्ष 2022 में दोनों देशों ने असीमित समझदारी कायम करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई में हुई रूस यात्रा के ठीक पहले पुतिन और जिंगपिंग की कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ता हुई थी। दोनों नेताओं के बीच यह एक वर्ष में दूसरी मुलाकात थी। कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है कि रूस और चीन की मित्रता ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत और चीन के शत्रुतापूर्ण संबंधों पर भविष्य में रूस का रुख क्या होगा यह कहना मुश्किल है। क्या टोक्यो में आयोजित क्वाड की बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुट होकर चीन के प्रति भारत का मुखर होना कुछ विशेष संकेत दे रहा है?

पडोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

आरती कुमारी

भारत के पडोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा? इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है। हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है। भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं। भारत समर्थ है, शक्ति सम्पन्न है, दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिये उसे अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमाओं पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। क्योंकि भारत के सभी पडोसी देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तख्तापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कतई नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

उत्तर प्रदेश उप चुनाव में होगी योगी व अखिलेश दोनों की कड़ी परीक्षा!

अशोक भाटिया , मुंबई

उत्तरप्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने वाले विधायकों से खाली हुई सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक कर सरकार के मंत्रियों की 'स्पेशल टीम' को एक-एक विधानसभा में उतार दिया है। यह सभी इसी हफ्ते से उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है । चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है पर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है। वहीं, सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनावों में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती होगी। इन उपचुनावों में दलित मतदाता की फैक्टर साबित हो सकते हैं। भाजपा और सपा, दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं इनमें कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी जिले की करहल और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त हुई मिल्कीपुर के साथ ही कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर विधानसभा सीट भी शामिल हैं। फूलपुर, मीरापुर, मझवा और सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होने हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से पांच सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे। भाजपा के पास तीन, निषाद पार्टी के पास एक और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक दल के पास एक सीट थी। mविकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनावों में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में 2019 की 62 सीटों के मुकाबले पार्टी के 29 सीटों के नुकसान के साथ 33 पर आने के पीछे भाजपा के नेता भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गढ़े गए नैरेटिव को मुख्य वजह मान रहे हैं। जब चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग में भी दलित और ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था । भाजपा नेताओं ने बीएल संतोष को ये बताया था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का न होना लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के पीछे बड़ी वजह रहा है। दलित समाज इसे आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठा है। विपक्ष संविधान को लेकर भी भाजपा के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल रहा है , पार्टी के नेता ये भी मान रहे हैं। भाजपा के सामने संविधान और आरक्षण के मोर्चे पर विपक्ष के नैरेटिव से निपटने की चुनौती भी होगी। वहीं, मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता है। गाजियाबाद की सीट शहरी है और इसे भाजपा के लिए अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक हैं तो वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट-गुर्जर के साथ मुस्लिम मतदाता नतीजे तय करते हैं। प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर भी उठती रही है और अब उनके लिए इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति हो गई है क्योकि योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू कम हुई है। हालांकि, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में मुख्यमंत्री योगी की सीधी भूमिका नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखने हुए विपक्ष की जीती सीट हासिल कर यह साबित करने का मौका है कि प्रदेश के जनमन पर उनकी छाप मद्धम नहीं पड़ी है। उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी को भी इस बात का अंदाजा हो गया है इस कारण वे खुद मोर्चा संभाल रहे है । प्रदेश में दलित वर्ग मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। सूबे में करीब 20 फीसदी आबादी दलित वर्ग की है और बसपा का वोट शेयर भी 19 फीसदी के आसपास रहता रहा है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, कुछ चुनावों में तस्वीर बदली है। हाल के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो बसपा का वोट शेयर 19 फीसदी से गिरकर 10 फीसदी से भी नीचे चला गया। बसपा को लोकसभा चुनाव में नौ फीसदी वोट मिले थे और पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के भी पीछे रही। बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसके उलट, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे। अब कहा यह जा रहा है कि दलितों का मोह मायावती की पार्टी से भंग हुआ है। नगीना में जहां दलित नेतृत्व का विकल्प था, दलित मतदाताओं ने वहां उसे चुना और बाकी जगह भी मायावती से छिटका यह वोटबैंक सपा और भाजपा में बंट गया। भाजपा के नेताओं ने खुद समीक्षा बैठक में यह कहा कि दलितों ने पार्टी को वोट करने से परहेज किया। ऐसे में देखना होगा कि दलित मतदाताओं का रुख उपचुनाव में किधर रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले पहले भाजपा सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात करती थी। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के नेताओं के बयानों से सबका विश्वास नदारद नजर आ रहा है। राम मंदिर और अयोध्या के जिक्र से भी पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उपचुनाव में पार्टी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपने कोर मुद्दे पर लौटेगी? वरिष्ठ पत्रकार बताते है कि उपचुनाव में वैसे भी सत्ताधारी दल को एज रहता है। ये उपचुनाव प्रदेश से जुड़े हैं जहां सरकार की कमान पहले से ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे लेकिन पार्टी का जोर संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष के नैरेटिव की काट करने पर अधिक होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे से रिक्त हुई है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से संसद पहुंच चुके हैं और इसी सीट में अयोध्या भी है। भाजपा के पास उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने का भी मौका होगा। प्रदेश में दूसरे नंबर पर पहुंचने से ज्यादा भाजपा को अयोध्या की हार सता रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा की कोशिश मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने की होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में नौ बार विधायक रह चुके अवधेश पासी के बेटे अजित प्रसाद के सपा से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें हैं। इसी कारण शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खुद इंटरेस्ट ले रहे है । हाल ही में उन्होंने चुनाव प्रभारियों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा की। चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। बूथ प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर उन्होंने विस्तार से पदाधिकारियों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "हर घर तिरंगा (13 से 15 अगस्त)" अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को प्रत्येक परिवार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बोले कि सरकार हर वर्ग के लिए विकास योजनाएं चला रही हैं। इसका लाभ भी आमजन को मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर हाल में आमजन से जुड़कर विकास के मुद्दे लोगों तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष की गुमराह करने की राजनीति का जवाब दें। इसके लिए पदाधिकारियों को सक्रिय रहना होगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जनता से छलावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की रक्षा भाजपा सरकारों के समय ही की गई। कांग्रेस के समय में अनेक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्षियों के दोहरे रवैये की पोल जनता के सामने खोलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'बूथ जीतो चुनाव जीतो' अभियान को गति देने के लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है । सभी बूथ समितियों को सक्रिय करने के साथ लाभार्थियों से लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे रखा है । चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है । बूथ प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर उन्होंने विस्तार से पदाधिकारियों को जानकारी दी जा रही है । प्रदेश की 10 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से भी अहम है। उपचुनावों को सपा-कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं कम ही हैं लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनावों के बहाने 'प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी' और मजबूत हो, इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज एक सीट ही जीत सकी कांग्रेस हाल के चुनाव में छह सीटें जीतकर उत्साह से लबरेज है।

https://t.me/AINewsPaperPaid

मेष राशिः आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि आज आपको करियर से रिलेटेड कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कॉलेज में आपकी एक्टिविटी से आपके दोस्त खुश होंगे। आज आप शाम का समय किसी व्यक्ति से मिलेंगे जिससे किसी इम्पोर्टेन्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज आपको किसी मामले में समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि यह आपके भविष्य में अड़चनें भी पैदा कर सकता है।

वृष राशिः आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आपको काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी नहीं तो आपका काम अधूरा रह भी सकता है। जो लोग आपको अभी तक ताना दे रहे थे आज उनको कुछ कर दिखाने का दिन है, आप जिस भी काम को करेंगे उसमे आपको सफलता के योग बन रहे हैं। आज आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, आज आपका दिन ज्यादा लाभ कमानें का है। आज आपको जीवन और कार्यक्षेत्र दोनों जगहों पर पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए समान्य रहने वाला है। आज आपको व्यापार में उम्मीद से कुछ कम ही लाभ प्राप्त होगा। आज आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आज आपके घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं, आपको ख़ुशी होगी। आज ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन शाम तक सारा काम अच्छे से निपट जायेगा।

सिंह राशिः आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। आज किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। साथ ही समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा, आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में विचार करेंगे। ऑफिस में आपके अच्छे काम को देखकर जूनियर आपकी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे।

कन्या राशिः आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है।आज का दिन आपके फेवर में रहने से आपको ख़ुशी होगी जिस काम का रिजल्ट अभी तक आपको निराश कर रहा था उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। आज आपकी संतान को खुश देखकर आपको भी ख़ुशी होगी। फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और खरीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा, बचत की ओर खासतौर पर ध्यान देना होगा.

तुला राशिः आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों की बिक्री आज बढ़ेगी, अधिक आमदनी मिलेगी। सरकारी जॉब कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा, प्रमोशन होने के चांस है। बिजनेस के सारे रुके हुए कामों को आज आप पूरा कर लेंगे, आपकी टेंशन कम होगी। घर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों का प्लान आज कामयाब होने का योग बन रहा है।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन सामान्य रहेगा। बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे बड़े व्यापारी से डील फाइनल करेंगे। राजनीति के कामों में आज आप ज्यादा रूचि लेंगे, आपके अच्छे कामों की आज तारीफ़ होगी। सोशल मीडिया से जुड़कर लोग अपनी अलग पहचान बनाएंगे।

धनु राशिः आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं यह ख़ुशी आपके घर में बेटे के करियर को लेकर हो सकती है। आज की शाम परिवार वालों के साथ बितायेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। आपको माता-पिता के साथ किसी समारोह में जा सकते हैं। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नये अवसर मिल सकते हैं।

मकर राशिः आज का दिन आपके लिए नयी उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करके ख़ुशी मिलेगी साथ ही आप कुछ नया भी सीखने को पाएंगे। आज आप कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो और किसी की भावनाओं को भी ठेस न पहुचे। आज आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए किसी की मदद मांगेगे, आपको निराश होने की जरूरत नही होगी आपका काम बन जायेगा।

कुंभ राशिः आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा.. आपका सही मार्गदर्शन घर के सभी सदस्यों के दिल में एक-दुसरे के प्रति प्यार बढ़ा देगा। आज किसी को दिए पैसे आपको मिल जायेंगे इससे आपको आर्थिक सपोर्ट मिलेगा साथ ही आप कुछ नया खरीदने का विचार करेंगे। आज कार्यस्थल पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा लेकिन शाम का समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मीन राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप ऑफिस में किसी काम को आसानी से करेंगे जिससे आपके जूनियर और सीनियर सभी तारीफ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढेगा साथ ही आपकी रेस्पेक्ट में भी इजाफा होगा।

शब्द सामर्थ्य -142

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे

1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।

1		2	■	3	4		5	■
	■	6				■	7	8
9			■		■	10		
	■	11		■	12		■	
■	13	■	■	14			■	■
15		16		■		■	■	17
	■		■	18		19	■	
	■	20			■	21		
■	22		■	23			■	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 141 का हल

ज	ल	■	आ	वा	जा	ही	■	■
मा	■	खू	ब	■	दू	र	स्थ	■
ना	दा	न	■	सा	ग	■	ल	क्ष्य
■	न	ख	■	त	र	ल	■	■
■	वी	रा	न	■	■	च	ट	क
■	र	ब	■	आ	ज	क	ल	■
■	■	■	आ	ग	■	दा	ना	■
■	अ	ग	र	म	ग	र	■	क्रो
भा	भी	■	ती	न	■	■	व	ध

सूडोकु नवताल- 7151

***** कठिनतम

			2					4
			6					1
	5		8			2		3
		7					6	
	3					8		
1		6			3		7	
2					5			
8					4			

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7150 का हल

6	5	4	3	1	9	7	2	8
7	2	3	5	8	4	9	6	1
8	9	1	7	2	6	3	4	5
1	7	2	8	3	2	5	9	4
4	3	8	9	6	5	1	7	6
5	6	9	4	7	1	8	3	2
2	8	7	1	4	3	6	5	9
9	1	6	2	5	7	4	8	3
3	4	5	6	9	8	2	1	7

संपादकीय

जो चाहे कर सो करा ले ऊपर वाले अपनी मर्जी से!

इस आधुनिक काल में ऊपर वाले की मर्जी जो ना चाहे वह कर ले। हर किसी से चाहे वह छोटा हो या बड़ा। ऊपर वाले तो शक्तिशाली होते ही हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और जीने की सारी सुविधाएं लिए नीचे वाला भी यानी धरा पर के लोग ऊपर वाला कहलाता है। जिसके हाथ में सब कुछ होता है, लोकतंत्र में राज्य सत्ता की प्राप्ति और उसके संचालन में राजनीतिक पदधारी के साथ ही उनके इर्द-गिर्द वाले बड़े-बड़े ओहदे पर विराजमान प्रशासनिक महकमे के अधिकारी भी ऊपर वाले ही हो गए हैं, इस इस कलयुगी जमाने में और वर्तमान समय में इस देश में सबकी मनमर्जी चलती रहती है। वैसे ऊपर वाले तो एक ही है जो इस संसार को संचालित करते हैं उन्हें लोग देख नहीं पाते लेकिन भगवान का कर पुकारते हैं। आज हर कोई अपने मन की करने में लगा है। आमजन हो या सरकार सभी लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं, अपनी मनमर्जी करने को और लोग कर रहे हैं। जिनको जैसा करने का मन करता है, वैसा ही करते रहते हैं। किसी की भलाई बुराई से कोई मतलब, किसी को नहीं रहती अपना भला सब चाहते हैं । जनता और सरकार इस देश में सब अपने-अपने मनमर्जी से चलते हैं। सरकार अपनी मनमर्जी से नियम कानून बनाती रहती है और जनता हिस्सो में बट कर इसमें हिस्सा लेती है। कोई कहता है, यह सही है कोई कहता है यह गलत है। सही और गलत का फैसला भी लोग अपने मन मुताविक ही करते है और जो मन मरजी का नहीं होता है, तो बवाल होता है। हर कोई अपने अपने ढंग से तर्क देता नजर आता है। पक्ष में और विपक्ष में, नारेबाजी होती रहती है। हर कोई इस बात के लिए अपने को तैनात रहता है कि वह अपने विचार में बाजी मारेगा और विचार की लड़ाई लडना ही तो स्वतंत्रता का मायने चिन्हीत करता है। आज हर आदमी स्वतंत्रता की दुहाई देते नजर आता है। लोगबाग अब अपने को हर तरह से स्वतंत्रता की मायने को अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर अपने मन मरजी का बोलते, करते हैं, भले ही अच्छा हो या बुरा। आज का युग अर्थ पर टिका है और यह अर्थ का अर्थ हर किसी के लिए अपना होता है। हर कोई अपने मन और कर्म से अर्थ का उपार्जन करने में लगा है। सही गलत की सोच परे हो चुकी है। घर परिवार समाज और देश सारे के सारे इसी मूल मंत्र पर टिक हुए हैं आकर कि दुनियादारी समाज विकास घर परिवार छोडो अपनी मन की करो संस्कार विहीन आधुनिक युग का यह फंडा है योजन कि जो मन में आए वही करो बस अपनी मन की करते रहो इसी फंडे पर सरकार भी चलती रही है। लोग प्रलोभन देकर अपने काम को अंजाम देने में, सफलता की चाहत रखते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। इस जग में अब न्याय अन्याय भी मन से होती है। पंच और परमेश्वर को लोग तिलांजली दे चुके है। लोग अब अपने विचार से हर कुछ तय करते हैं । कोर्ट कचहरी बहियात नजर आती है, जहां से न्याय नहीं परेशानियों का बोझ मिलता हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अदालत से न्याय नहीं मिलती है वहां तो बस आना जाना और कागजात जुटाने के साथ ही ही संबंधित लोगों को चढ़ावा चढ़ाना जरूरी होता है और डेट पर डेट करते हुए मामला ही इतना पुराना हो जाता है कि उसका कोई महत्व ही नहीं रहता और कुछ मामले मे रहता भी है तो वह भी मनमर्जी से ही रहता है। समाज और सरकार सभी की मनमर्जी चलती रहती है और इस जमाने में यानी आधुनिक काल में मनमर्जी का ही बोलबाला है सरकार भी अपनी मनमर्जी से बनती है बस जनता का नाम होता है और सरकार चलती भी अपनी मनमर्जी से ही है।बस संविधान का सहारा होता है। मनमर्जी का भी अपना एक मंत्र होता है और इस मंत्र के सहारे ही तर्कों से मनमर्जी चलती है। सामाजिक व्यवस्था में आज जो कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव परिवार और देश पर भी पड़ रहा है। समाज आज कहीं दिखता ही नहीं, परिवार के लोग भी अब एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, या जा रहे हैं।अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही जीवन जीने की चाह लिए हर आदमी चल रहा है। दूसरे की भलाई और बुराई से कोई मतलब नहीं होता। अपना स्वार्थ, अपनी बात, अपनी चाहत ही सर्वोपरि होती है। हर कोई इस अर्थ युग में बस पाने की चाहत रखता है। देने की काम स्वार्थ मे समाहित हो मुल भाव मे समाप्त हो चुकी है। इस देश के लोग जीवन जी रहे हैं, अपनी मनमर्जी से। जबकि पूरी दुनिया में ही सबकी अपनी अपनी चलती है और सब अपना अपना भला करते हैं। हम ये नहीं ये भी नही कह सकते कि मानव जीवन जीने के लिए ये व्यवस्थाएं जो समाज, सरकार, घर परिवार के जिम्मे होता है। वह अपने से दायित्वों से दूर हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कर ही रहे हैं। लेकिन वह अपनी मनमर्जी से। हम सरकार समाज से कहना चाहते हैं कि हां सब व्यवस्था है। हां व्यवस्था है। प्रशासन है, सरकार है, सब कुछ जो आम आदमी से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसे अलग नहीं है। लेकिन व्यवस्था प्रशासन और सरकार जिस तरह से दिखती है वह तो निश्चित रूप से हित की जगह अहित से ही जुड़ जाता है। सरकार कहती है कि शिकायतों के लिए अलग सेल बना है, यहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के उपरांत जो पीड़ा जो आतंक जो संताप शिकायतकर्ता को खेलना पड़ता है, वह देखने लायक होती है। शिकायत करना अपनी मजबूरियों को उजागर करता है और मजबूरियों में सरकार की जो देखा देखी होती है वह मनमर्जी पर। यानी करने वाले, देखने वाले, जांच करने वाले, समझने वाले प्रशासन के लोग कर्मी सभी तो अपनी मनमर्जी से ही काम करते हैं। शिकायत लफड़े बाजी से बहुत लोग बचना भी चाहते हैं और बचते है, जो नहीं बचते वह परेशानी झलते हैं। जीवन को दुखद स्थिति में लाते हैं। इस जमाने में सबको अपना अधिकार तो याद रहता है, लेकिन दूसरे का अधिकार ही भूल जाते है। आज क्या हो रहा है, इस देश में तब बस इतना ही कहा जा सकता है कि सब काम हो रहा है ऊपर वाले तेरी मर्जी से!

प्रभात वर्मा

कविता

जहन्नुम

जन्नत" को "जहन्नुम" बनाकर "हूर" की चाह रखते हैं लोग....

कभी "आईना" ना देखने वाले दूसरों को "बदशक्ल"बोलते हैं लोग...

राष्ट्रपिता तक की "मजम्मत" कर देते हैं और इसे "जिहाद" बोलते हैं लोग...

देखिये कहां जाकर रुकते हैं, जिस थाली मे खाते हैं उसी थाली मे छेद कर देते हैं लोग...

जिसने अपनी 'तप' से आसमान मे सुराख कर दिया, आसमान की तरफ "मुख" करके उसी पर थूकते हैं लोग... !

दस्तक प्रभात
डॉ. अमरनाथ पाठक

सावन और शिवालय

दर्शन कीजिए गुप्तेश्वरनाथ महादेव जी का

आदि अनादि काल से भारतीय धार्मिक संसार में देवों के देव महादेव के कितने ही भक्तों की कथाएं आज भी जन सामान्य के बीच प्रसिद्ध है।

ऐसा ही एक भक्त था भस्मासुर जिसने अपनी अपवित्र निगाह भोले भंडारी भंडारी पर ही डाल दी और यह कथा जिस स्थान से सूत्र संबंध है वही है गुप्ता स्थान, गुप्ता धाम अथवा गुप्तेश्वर महादेव का पुराण प्रसिद्ध तीर्थ;जो बिहार के शैव तीर्थों में बड़ा ही प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त है। प्राचीन शाहाबाद क्षेत्र में विराजमान शेरशाह सूरी की ऐतिहासिक नगरी सासाराम से गुप्ता धाम तक जाना सहज है जहां आज जाने के अच्छे मार्ग बन गए हैं ।यहां एक विशाल पर्वतीय खंड के गुफा में बाबा विराजते हैं। बाबा के गुप्त रूप में विराजने के कारण ही इस स्थान को गुप्ता धाम कहा जाता है जो शिव भक्तों के बीच में बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में ख्यात है। पुराण प्रसिद्ध कथा कही जाती है कि एक भक्त भस्मासुर हुआ जिसने अपनी सिद्धि से शिव शंकर के मन को जीत लिया। बाबा औघड़ दानी में उसके वर मांगने पर उसे वरदान दिया कि वह जिस पर भी अपना हाथ रख देउसका सितारा अस्त हो जाएगा। अब वरदान पाने के बाद भस्मासुर का आतंक बढ़ने लगा।एक दिन वह माता पार्वती को देख लिया। अपूर्व सुंदरी माता पार्वती को देखते ही उसकी नियत बदल गई और जगत जननी को पाने के उद्देश्य से उसमें शंकर जी को पर ही अपनी गलत निगाह डाल दी कि अगर भोले बाबा को स्वाहा कर दें तो पार्वती सदा सर्वदा के लिए हमारी हो जाएंगी। ऐसा सोच उसने भोले बाबा को देख उनके पीछे हो लिया। बाबा उसकी गलत मंशा को समझ तुरंत अपने अभिन्न विष्णु जी से मदद ली तो

विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को उनके राह से मुक्त किया। लोकविश्रुत चर्चा है कि विष्णु के मोहनी रूप के कारण ही यहां एक पास का नगर मोहनिया है। कहते हैं मोहनी ने अपनी सुंदरता से भस्मासुर की मनसा को भांपते हुए उसे अपने जैसा नृत्य करने की सलाह दी और कहा कि तभी वह उसे वरण करेगी। ऐसा सोच कर वह नृत्य करने लगी और अपने हाथ को स्वयं अपने मस्तक पर जैसे ही रखी यह देखकर भस्मासुर भी रख दिया और उसके परिणाम से भस्मासुर स्वयं स्वाहा हो गया।भस्मासुर के डर से जिस गुफा में भोले भंडारी ने पर्वतीय खंड पर आश्रय ली थी वही उनका रूप महिमामय लिंग के रूप में आज भी विराजमान है और यही गुप्ता धाम है। गुप्ता धाम में नीचे से ऊपर तक पर्वतीय खंड की तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी प्रकृति के सुरम्य वातावरण का स्पष्ट नजारा प्रस्तुत करता है जहां मार्ग में उछलते कुदते हनुमान, बंदर, विभिन्न तरह के पक्षियां और छोटे बड़े जीव मन को मोहते हैं और बोल बम के नारा से मन में नव धार्मिक संस्कार का अभ्युदय होता है। कहते हैं शाहाबाद क्षेत्र का सबसे बड़ा शिवशंकर जी के नाम समर्पित श्रावण का महामेला यहीं लगता है। गुफा में विराजमान यहां का मूल मंदिर में प्राकृतिक शिवलिंग सचमुच दर्शनीय है जहां कोई-कोई भक्त को अंदर में थोड़ी परेशानी भी होती है ऐसे अंदर तक रोशनी की व्यवस्था है। द्वार के बाहर श्री भैरवनाथ बजरंगबली और

बहुत सारे त्रिशूल रखे हुए हैं। यहां पर कुछ प्राचीन महत्व की मूर्तियां भी उपस्थित है जिसमें कामदेव, भैरव और उमा महेश्वर प्रमुख हैं। इधर हाल के दिनों में श्री गुप्ता धाम का

विशेष रूप से विकास हुआ है और भक्तों के सुविधार्थ कितने ही निर्माण कार्य किए गए हैं और संप्रत्ति किया जा रहे हैं। इस पर्वत पर छोटे-छोटे झरने बरसाती नाले और 33 बड़ी नदियों का भी साम्राज्य कायम है जिसे मार्ग में देखा जा सकता है। इतिहास और पुरातत्व के अध्यताओं के लिए यह स्थान बड़ा ही उपयोगी है और बिहार में शैव धर्म से जुडा हुआ यह स्थान पुरातन काल से ही चर्चित रहा है जहां किसी भी शैव पर्व में भीड़ लगी रहती है लेकिन सावन के महीने में यहां भक्तों के आगमन से यहां की रौनकता देखने लायक रहती है । सुविज्ञ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव बताते हैं कि बिहार प्रदेश के चर्चित शैव तीर्थों में गुप्ता धाम का विशिष्ट मान है। यहां एक बार आने वाला भक्त सदा सर्वदा के लिए बाबा का हो जाता है। प्रकृति और धर्म का ऐसा संगम रूप अन्यत्र दुर्लभ है।

दस्तक प्रभात
डॉ.राकेश कुमार सिंह 'रवि'

भारतीय संस्कृति में सन्निहित संस्कार

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति हैआधुनिकतम पुरातत्वीय वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं दुनियां के सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ वेद में इसका उल्लेख है यजुर्वेद ७/१४ का मंत्र है ;'सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा' अर्थात यह विश्व की प्रथम संस्कृति हैवैदिक काल के ऋषियों द्वारा इस संस्कृति का निर्माण किया गया है अतः इसे देवसंस्कृति भी कहा जाता है संस्कृति का अर्थ है - वह कृति या कार्य पद्धति जो संस्कार सम्पन्न होव्यक्ति की उच्छृंखल मनोवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर कैसे उसे संस्कारी बनाया जाये?यह संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति के मूर्धन्य मनीषियों का है`जिन्होंने भारतीय संस्कृति की कुछ मान्यताओं को बड़ी गहराई से आलोकित किया हैप्रत्येक तथ्य का सम्मत विवेचन, विज्ञान की शास्त्रों की सम्मति के साथ प्रस्तुत किया है भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर कही जा सकती हैइसकी परिधि में संपूर्ण विश्वराष्ट्र के विश्वास "वसुधैव कुटुंबकम्"के सारे सूत्र आ जाते हैंहमारी संस्कृति में मनुष्य के जन्म से पूर्व से मृत्यु पश्चात तक मानवीय चेतना को संस्कारित करने का क्रम निर्धारित है`मनुष्य में पशुता के संस्कार उभरने न पायें यह इसका प्रथम उत्तरदायित्व है भारतीय संस्कृति मानव के विकास का आध्यात्मिक आधार बनाती है और मनुष्य में संत, सुधारक और शहीद की मनोभूमि विकसित करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेती है`सदा से ही भारतीय संस्कृति महापुरुषों को जन्म देती आई है और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ धरोहर हैइसे धारण करना और अक्षुण्ण बनाये रखना हम सबका कर्तव्य है हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के जो सूत्र खोजे तथा आचरण पद्धति का निर्माण कर श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना की, वे किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी प्रचलित हैंवेदों के जीवन सूत्रों का ही उपनिषद्, पुराण एवं रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों के रूप में विस्तार हुआ है यह सभी ग्रन्थ प्राचीन काल से अद्यतन हमारे जीवन के लिए प्रेरक एवं आदर्श बने हुए हैंइनमें प्रस्तुत उपासना, यज्ञ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, एवं अन्य अनेक श्रेष्ठतम परंपरायें दृष्टिगोचर होती हैं अत्यंत विस्तारित इतिहास के कारण भारतीय संस्कृति की इन जीवनमूल्यों और संस्कार परंपराओं में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आया है परंतु समय के इतने उतार -चढाव के उपरांत भी अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरायें जीवंत एवं गतिशील हैंसंसार में मिस्र, बेबीलोन, रोम, एवं यूनानी सभ्यताओं जैसी अनेक प्राचीन संस्कृतियों के अब अवशेष ही रह गये हैं किंतु भारतीय सभ्यता-संस्कृति आज भी प्रवाहमान हैइस संस्कृति के जीवित बने रहने का मूल कारण इसकी अध्यात्मिकता हैअध्यात्म तत्व भारतीय संस्कृति की मूल प्राणात्मा हैइसका प्रथम संदेश भी "आत्मानं विजानीहि" अर्थात आत्मा को जानो हैविश्व मानवता एवं प्राणिजगत के लिए "आत्मवत सर्वभूतेषु ", वसुधैव कुटुंबकम् की भावना तथा" अनेकता में एकता"की दृष्टि प्राचीन काल से इस संस्कृति की पहचान एवं विशेषता रही है` इस संस्कृति की जीवन दृष्टि अध्यात्म एवं चिंतन प्रधान है तथा जीवन पद्धति में तप-त्याग एवं आदर्श की प्रधानता रही है ऋषियों का सनातन संदेश है - "त्येन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्' (ईशावास्योपनिषद्) अर्थात त्याग पूर्ण भोग करना तथा अन्य की वस्तु पर लालच न करनोइसकी आदर्शमय जीवन पद्धति का मूल स्वरूप वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में प्रकट हुआ हैवर्णाश्रम का चिंतन भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं श्रेष्ठ जीवनादर्शों से सुसज्जित हैज्ञानार्जन के क्रम में स्वाध्याय, तप, उपासना, अपरिग्रही जीवन जीता है तथा सद्कार्यों को करते हुए समाज को सही दिशा प्रदान करता हैउपर्युक्त विशेषताओं के साथ ही साथ "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" मातृरूपेण संस्थिता, वसुंधरा कुटुंबकम्, अद्वैत, वेदांत, दर्शन, कर्म एवं सिद्धिमंत्रःआदि ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो भारतीय संस्कृति को विश्व की प्रथम एवं चिर महान संस्कृति बनाती है जिसके दिव्यता की दीप्ति सतत देदीप्यमान है

दस्तक प्रभात/डा. स्नेहसुधा

शिवत्व भाव और शिव की महिमा

हमारी संस्कृति में पर्व- त्योहार का विशेष महत्त्व है। प्रायः प्रत्येक मास कोई न कोई पर्व आ ही जाता है। भक्तगण अपने भक्तिभाव से देवी देवता को प्रसन्न करते हैं तथा उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उन्हीं त्योहारों में श्रावण मास का त्योहार विशेष उल्लेखनीय है। श्रावण का पावन मास शिव का पावन मास है। इस मास में शिव की पूजा व आराधना की जाती है। अजगैबीनाथ धाम सुलतानगंज से लेकर वैद्यनाथ धाम देवघर तक 'बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है।' बोलबम, बोलबम के नारे से सम्पूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठता है। अपने काँधे पर काँवर रखकर काँवरिए मन में देवाधिदेव महादेव का सुमिरन तथा उनके नाम को जपते हुए बाबा धाम जाते हैं। जो भक्त निश्छल मन से उनका दरबार जाते हैं उनकी हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंदपुराण में कहा गया है - 'अपने काँधे पर काँवर रखकर जो शिव भक्त बम बम का उच्चारण करते हुए बाबाधाम जाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति के साथ-साथ शिवलोक भी प्राप्त होता है।' अतः हमें निर्मल मन से शिवधाम जाना चाहिए। काँवर की पवित्रता के साथ हमारा अंतर भी पवित्र होना चाहिए तभी जीवन में शिव की कृपा का प्रसाद मिलता है। शिव का अर्थ व उत्पत्तिः सनातन धर्म के आदि पंच देवों में शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के स्रोत हैं। वे सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी होता है परन्तु लय एवं प्रलय दोनों उनके वश में रहते हैं। एक बात दीगर है कि यहाँ शिव में 'इ' मात्रा का यानि पराशक्ति

का विशेष महत्त्व है। इसके बिना वह शव बन जाता है। इसलिए तो शिव पुराण में वर्णित हैः भगवान सदाशिव और पराशक्ति अम्बिका से ही शिव की उत्पत्ति हुई है। उस अम्बिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। शिव को शंकर (शं करोति इति शंकरः), भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने के कारण आशुतोष, शिखर पर चन्द्र होने के कारण चन्द्रशेखर, विषपान करने के कारण नीलकंठ, कैलाश का स्वामी होने के कारण कैलाशपति, गिरिजा (उमा) के स्वामी होने के कारण गिरिजापति इत्यादि अनेक नाम से जाना जाता है। इस सृष्टि में सृजन के साथ संहार का कार्य होता है। हर संहार के पश्चात पुनः सृजन का श्रीगणेश होता है। यानि दोनों प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। शिव संहार के अधिपति होने के बावजूद सृजन के प्रतीक हैं। वे सृजन का संदेश देते हैं। शिव के रूपः शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे दो रूप हैंः 'सकल' और ' निष्कल'। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। मैं सबसे वृहत तथा जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण 'ब्रह्म' कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। जगत - सम्बन्धी पाँच कृत्य जैसे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपता का बोध कराने के लिए 'निष्कल' लिंग प्रकट हुआ था। पुनः अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही 'सकल' रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझमें जो ईशत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्कल स्तम्भ है, वह मेरे ब्रह्मस्वरूप का बोध कराने वाला है। वस्तुतः सावन मास में शिव की आराधना, उनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। उन्हें बेलपत्र, धतूरा का फूल तथा जल प्रिय हैं। परन्तु जल उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। इसलिए तो भक्तगण जलाभिषेक करते हैं। हम चाहें जिस रूप में देवाधिदेव महादेव की पूजा करें, हमारा मन निश्छल और पावन होना चाहिए। इसके साथ हमें अपने जीवन में दूसरों का कल्याण करना चाहिए। नकारात्मक विचारों का परित्याग तथा घोर अन्याय करने वालों का मिलकर संहार करना चाहिए तभी हमारा जीवन सुखद रहेगा तथा हम अपने समाज, प्रांत और राष्ट्र को स्वस्थ व समृद्ध बना पाएँगे। रख शिव भाव शिवत्व का, चलिए शिव का धाम। शिव के आशीर्वाद से, सभी बनेंगे काम।।

दस्तक प्रभात
देव कांत मिश्र 'दिव्य'

गुरु रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित:शान्तिनिकेतन

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना बोलपुर के पास की। बाद में इसका नाम उन्होंने शान्तिनिकेतन रखा। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि जिस समय ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना की गई उस समय टैगोर नेवैद्य नामक कवितांए लिख रहे थे। जिस पर उपनिषद् के आर्दशों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उसी समय ब्रह्मबांधव उपाध्याय ने टैगोर को 'गुरूदेव' कहा और वे अंत तक गुरूदेव बने रहे। टैगोर विद्यालयों के नियमों को संहिता पर आधारित करना चाहते थे ताकि भारतीय परम्परा के अनुसार विद्यालय का संचालन किया जा सके।प्रारंभ में शान्तिनिकेतन को रवीन्द्रनाथ टैगोर के दो पुत्रों रतिन्द्रनाथ तथा समिन्द्रनाथ के साथ प्रारंभ किया गया। बाद में छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या बढ़ती गई। 1913 तक गुरूदेव ने स्वंय ही इस संस्था का व्यय वहन किया। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलने के उपरांत आर्थिक संकट कम हुआ।अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान आदि देशों के भ्रमण करने से गुरूदेव के शैक्षिक विचारों में परिपक्वता आई । शान्तिनिकेतन विश्वभर की संस्कृतियों का मिलन स्थल बन गया जहाँ कोई भी बिना धर्म, देश या संस्कृति के भेदभाव के

सम्मानपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकता था।टैगोर शान्तिनिकेतन से कुछ हद तक निराश हुए। उन्हें लगा कि उसमें उनके विचारो पर अमल नहीं किया जा रहा है। वे कहते हैं "अभिभावकों की अवसरवादिता परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए जिम्मेवार है। इसने एक प्रकार से आजादी और स्वतः स्फूर्तता का वातावरण कमजोर किया।"अपना प्रयोग जारी रखने के लिए टैगोर ने 1924 में शिक्षा सत्र के नाम से एक और स्कूल प्रारम्भ किया। इसमें ऐसे बच्चे शामिल किए गये जो अनाथ थे या जिनके माता-पिता इतने गरीब थे कि वे उन्हें किसी भी स्कूल में नही भेज सकते थे। उन्हें इस स्कूल से बड़ी आशाएं थी। वस्तुतः उन्हें उम्मीद थी कि शान्तिनिकेतन की कमियां इस विद्यालय में नही आयेंगी और यह विद्यालय उनके विचारों का सही अर्थों मे मूर्तरूप होगा। लेकिन 'शिक्षा सत्र' के महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रयोगों को टैगोर के उपरांत विस्मृत कर दिया गया और वह एक सामान्य विद्यालय बन गया।गुरूदेव भारतीय ग्राम्य जीवन को पुनः उसकी गौरवशाली परम्पराओं के आधार पर पुनर्जीवित करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने स्वदेश समाज नामक निबन्ध में कृषि, शिल्प, ग्रामोद्योग को पुनः विकसित करने पर जोर दिया। इन्हीं सपनों को वास्तविक रूप देने के लिए शान्तिनिकेतन के एक मील की दूरी पर, ह्यसुरूल' नामक स्थान में ग्रामीण पुनर्रचना के लिए उन्होंने श्रीनिकेतन की स्थापना की। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि 1920 के दशक के मध्य उन्होंने दो प्रसिद्ध नाटक उस समय लिखे जब श्रीनिकेतन का प्रयोग चल रहा था। ये थे 1922 में लिखी गई मुक्तोधारा और 1924 में लिखी गई रक्तकरबी। दोनों में ही मशीनी सभ्यता के प्रति विरोध का भाव है। वे प्रकृति पर मशीनी टेक्नोलॉजी के प्रभुत्व से चितिंत थे। तकनीकी प्रभुत्व वाले समाज के शोषण के चरित्र के प्रति तिरस्कार की भावना स्पष्ट है। श्रीनिकेतन का प्रयोग आरम्भ करने के लिए उन्हें विदेश से एमहर्ट द्वारा लाई गई वित्तीय सहायता पर निर्भर होना पड़ा था। श्रीनिकेतन प्रयोग के दौरान ग्रामीण समाज की विशेष जरूरत के आधार पर विकसित आत्म सहायता और सहयोग के जरिए सामुदायिक विकास पर ध्यान दिया गया।

दस्तक प्रभात/

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Machine Translated by Google

अधिपतियों के अधीन

एल्डरमेन पर अदालत का फैसला केंद्र के प्रभुत्व के सामने दिल्ली की कमजोरी को दर्शाता है

टी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली नगर निगम के लिए पार्षदों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्र प्राधिकार का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार की केंद्रीय प्रभुत्व के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय केन्द्र-दिल्ली सरकार संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून के साथ-साथ पहले के निर्णयों पर भी आधारित है, जिनमें निर्वाचित शासन और नियुक्त प्रशासक के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया था।

मुकदमे के नवीनतम दौर का अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है, यह देखते हुए कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह दिल्ली के लिए एक निर्वाचित विधानसभा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है। न्यायालय ने कहा कि नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने की उपराज्यपाल की शक्ति उनका वैधानिक कर्तव्य है, और यह ऐसा कर्तव्य नहीं है जिसका प्रयोग उन्हें दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करना चाहिए। यह शक्ति संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है, जो कहता है कि उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषयों को छोड़कर, राज्य और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं। न्यायालय ने दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है कि नगर प्रशासन राज्य का विषय होने के नाते, उपराज्यपाल अपने दम पर काम नहीं कर सकते थे।

संसद द्वारा पारित 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में नियुक्ति शक्ति की प्रकृति का पता लगाते हुए, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम अलग-अलग प्राधिकारियों की पहचान करता है, जिनमें से प्रत्येक की अलग भूमिकाएं हैं। जबकि प्रशासक को विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार था, अध्यक्ष कुछ विधायकों को रोटेशन द्वारा निगम में सेवा देने के लिए नामित कर सकते थे। और इससे पता चलता है कि यह एक स्वतंत्र वैधानिक शक्ति थी। संविधान पीठ ने 2018 में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को बढ़ने से रोकने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की मांग की थी। इस तरह के मतभेद, साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक कटुता, दिल्ली पर शासन करने को लेकर कई संघर्षों और कानूनी झगड़ों के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति रही है। जैसा कि एल्डरमेन पर हाल ही में दिए गए फैसले से पता चलता है, संविधान संसद को किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, जिस पर दिल्ली विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है, अन्य राज्यों के विपरीत जिनके पास विशेष विधायी क्षेत्र है। संसद दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संशोधन या उसे रद्द भी कर सकती है। चूंकि विधायी और कार्यकारी शक्तियां एक समान हैं, इसका प्रभावी अर्थ यह है कि दिल्ली सरकार को केंद्र किसी भी तरह से कमजोर कर सकता है।

वह नेता जिसका बांग्लादेश से संपर्क टूट गया

बी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का सदन से अप्रत्याशित ढंग से बाहर निकलना सत्ता और देश में अचानक और तेजी से बदलाव हुए हैं। कई लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं यह समझना मुश्किल है कि कैसे "आयरन लेडी", जो छात्र आंदोलन के तेज होने तक पूरी तरह नियंत्रण में थी, को पद छोड़ने और यहां तक कि बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके देश छोड़ने से गुस्सा शांत हो गया है। ऐसा बिलकुल नहीं है।

बांग्लादेश में अराजकता और बिना सोचे-समझे खून-खराबे की स्थिति पैदा हो गई है, जो बदले की भावना से प्रेरित है। सुश्री हसीना की पार्टी के लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, पुलिसकर्मियों और सीमा रक्षकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, संपत्ति के भारी नुकसान की तो बात ही छोड़िए।

सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि धार्मिक कट्टरपंथी माने जाने वाले तत्वों द्वारा पुलिस स्टेशनों पर व्यवस्थित हमले किए जा रहे हैं तथा हथियारों की लूट की जा रही है।

शेख के लिए इतिहास की एक अजीब पुनरावृत्ति है अगस्त 1975 में, जब उनके महान पिता शेख मुजीबुर रहमान सहित लगभग पूरा परिवार एक खूनी तख्तापलट में मारा गया, तो शेख हसीना और बहन रेहाना को भारत में शरण लेनी पड़ी।

यह तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से संभव हुआ, जिनका शेख मुजीबुर रहमान के साथ बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध था। एकमात्र अंतर यह है कि 1975 में सुश्री हसीना एक गृहिणी थीं और एक महान नेता की बेटी थीं, जिन्होंने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाई थी। लेकिन अब, सुश्री हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में चार पूर्ण पंचवर्षीय कार्यकाल पूरे किए हैं।

कोई भी आसानी से उनकी दुर्दशा के लिए सितारों को दोष दे सकता है और ज्योतिषीय गणनाओं पर विचार कर सकता है, लेकिन सुश्री.

हसीना का पतन जनता से बढ़ते अलगाव के कारण हुआ है - कई नेताओं का पतन जो सत्तावादी शासन की ओर झुके हुए हैं। सुश्री हसीना ने बांग्लादेश के लिए एक दशक से अधिक समय तक असाधारण आर्थिक बदलाव की अध्यक्षता की है, जब देश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गई और बुनियादी ढांचे में भारी वृद्धि हुई - बंदरगाह, सड़कें, रेलवे विस्तार और बिजली उत्पादन। देश के मानव विकास संकेतकों ने भी उल्लेखनीय सुधार दिखाया, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में। बांग्लादेश दुनिया का शीर्ष परिधान निर्यातक बनने के करीब था और देश के भविष्य के प्रति आशावान प्रवासी लोगों द्वारा अपने घर अधिक धन भेजे जाने के कारण धन प्रेषण आय में वृद्धि हुई।

शक्तिशाली नदी पर बना 6.15 किलोमीटर लम्बा प्रतिष्ठित पुल पद्मा नदी, जिसे सुश्री हसीना ने आगे बढ़ाया

सुबीर भौमिक

एक वरिष्ठ बीबीसी पत्रकार और लेखक। उन्होंने ढाका स्थित bdnews24.com में वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य किया है।)

शेख हसीना ने देश के असाधारण आर्थिक बदलाव की अध्यक्षता की, लेकिन उस जन संपर्क को खोने की भारी कीमत चुकाई जिसने उन्हें एक बार उच्च पदों पर पहुंचा दिया था।

बांग्लादेश के अपने धन से निर्मित यह परियोजना उनके कार्यकाल में ही पूरी हुई, जिससे 21 जिलों के साथ बेहतर सम्पर्क की उम्मीद जगी तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिला। एक समय तो ऐसा आया जब सुश्री हसीना को यह विश्वास हो गया कि यदि वे विकास के मामले में आगे बढ़ेंगी तो वे देश में बढ़ते लोकतंत्र के मुद्दे से बच सकेंगी।

उनके आलोचक उन्हें तीन बार निष्पक्ष नहीं हुए चुनावों के लिए दोषी ठहराते हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, तथा जो बांग्लादेश की जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते।

उन पर बांग्लादेश को होस्नी मुबारक के मिस्र की तरह एकदलीय पुलिस राज्य में बदलने का भी आरोप लगाया गया, जहां न्यायेतर हत्याएं, जबरन गायब कर दिया जाना और अक्सर झूठे आरोपों पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करके विपक्ष का मुंह बंद करना आम बात हो गई थी।

एक तरह से, इस लोकतंत्र ने विपक्ष से ज़्यादा अवामी लीग को प्रभावित किया। चुनावों में जीत निश्चित होने के कारण, अवामी लीग ने ऐसे लोकप्रिय नेताओं को खोजने और बढ़ावा देने की इच्छा खो दी थी, जिनका जन-सम्पर्क मज़बूत था, जो किसी भी संकट जैसे कि हाल ही में हुए आरक्षण विरोधी छात्र विरोध प्रदर्शनों में ज़मीन पर टिके रहने में सक्षम थे।

अवामी लीग का परिवर्तन, राजनीति दरअसल, पिछले दशक के दौरान अवामी लीग के नेतृत्व के चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कभी गरीबों और मध्यम वर्ग की पार्टी रही अवामी लीग का नेतृत्व विचारधारा से प्रेरित मध्यम वर्ग के नेताओं द्वारा किया जाता था, जिनका जमीनी स्तर पर सम्मान किया जाता था - शिक्षक, पेशेवर और वकील। लेकिन पिछले दशक में, व्यापारियों ने पार्टी नेतृत्व में अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी थी, संसद की सीटों के लिए नामांकन सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देना। पार्टी के अपने संगठन की तो बात ही छोड़िए, जमीनी स्तर से उनका बहुत कम जुड़ाव था। संदिग्ध तरीकों से नामांकन हासिल करने के बाद वे चुनाव जीत सकते थे, जिसका एकमात्र तरीका पुलिस और सिविल नौकरशाही की हथेलियों को चिकना करना और चुनावों में धांधली करने में मदद करने के लिए बाहुबलियों को काम पर रखना था।

इनमें से कई व्यवसायी-राजनेता भी संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से अपने गठजोड़ के कारण पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

इस दौरान, शेख हसीना ने पार्टी के पुराने नेताओं पर कम भरोसा जताया और इनमें से कुछ कारोबारी दिग्गजों की ओर अधिक झुकाव दिखाया। देश के सबसे खराब बैंक डिफॉल्टरों में से एक, जिस पर बड़े पैमाने पर मनी-लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, को प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। वह इतना स्वतंत्र सत्ता केंद्र बन गया कि कई लोग उसे 'उप प्रधानमंत्री' कहने लगे।

बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इस बढ़ते भ्रष्टाचार से प्रभावित और कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित।

बेरोजगारी खतरनाक रूप से बढ़ गई है, 170 मिलियन की आबादी में अब 30 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। पिछले तीन सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में 44% की गिरावट आई है, जिससे बहुपक्षीय संगठनों से लिए गए ऋणों को चुकाने की बांग्लादेश की क्षमता पर संदेह बढ़ गया है। इस साल बांग्लादेशी टका का मूल्य 28% गिरा है।

मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि, जिसे अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी समर्थित जबरन वसूली करने वाले सिंडिकेटों के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो व्यवसायों को लूटते हैं, ने देश को एक उबलते हुए कढ़ाई में बदल दिया है जो आग लगाने के लिए इंतजार कर रही है।

आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई इस तरह की गलत कार्यवाही और सुश्री हसीना तथा उनके आंतरिक समूह द्वारा की गई इस गलत कार्यवाही के बाद 5 जून को उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बरकरार रखा, जिसके बाद उग्र छात्र प्रदर्शन शुरू हो गए, जो चाहते थे कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, ताकि योग्यता आधारित व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके।

हसीना की सरकार ने 2018 के छात्र आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों में कोटा खत्म करने पर सहमति जताई थी (कुल 56%, 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30%) लेकिन सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए एक मामला दायर किया गया था। सुश्री हसीना को बस इतना करना था कि छात्र नेताओं को बातचीत की मेज पर लाना था और उन्हें उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का आश्वासन देना था, जो उनकी सरकार ने आखिरकार किया।

इसके बजाय, उन्होंने शुरू में विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज कर दिया। फिर, उनकी एक टिप्पणी ने छात्रों को परेशान कर दिया जब उन्होंने कहा: "यदि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए नहीं, तो क्या हमें रजाकारों के लिए कोटा बनाना चाहिए"। रजाकार बांग्लादेश में एक अपमानजनक शब्द है, जो उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के दमन अभियान का समर्थन किया था। जैसे-जैसे आंदोलन तेज हुआ, सुश्री हसीना ने पुलिस और अपनी स्वयं की छात्र शाखा, छात्र लीग द्वारा क्रूर दमन का सहारा लिया। यह उल्टा साबित हुआ और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अंत में, सुश्री हसीना को सत्ता के अपने अहंकार के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, उस जन संपर्क को खोने के लिए जिसने कभी उन्हें उच्च पद पर पहुँचाया था। एक पारंपरिक गृहिणी के लिए अपने पिता की विरासत को अपने पूरे परिवार की हत्या के बाद संभालना और एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना कोई मामूली बात नहीं है जो 1975 के खूनी तख्तापलट से बुरी तरह से हतोत्साहित हो चुकी थी। लेकिन, अंत में, उस जन संपर्क का नुकसान उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जम्मू के आतंकवाद रोधी ग्रिड पर एक करीबी नजर

ज्यादतियों का मामला

पूजा खेडकर का सिविल सेवा में प्रवेश भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाता है

नियम का एक भी गंभीर उल्लंघन

पूजा खेडकर की विचित्र कहानी के रूप में सामने आई है, कानून से बाहर निकलने के लिए उसने जिन कई तरीकों का इस्तेमाल किया, वे शानदार होते, अगर वे सच साबित न होते। हालांकि, पूरे संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती संरचना की आंखों में धूल झोंकने के बाद, सांठगांठ और षडयंत्र करके, यह एक ऐसा दृश्य है जो सहजता के लिए बहुत डरावना है। उसने मानसिक बीमारी और दृष्टि दोष का दावा किया, एक फर्जी सामुदायिक प्रमाण पत्र बनाया, चयनित होने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, उसे ऐसी रैंक मिली जो अन्यथा उसे गणना से बाहर कर देती। इस बीच, पुणे के जिस अस्पताल ने उसे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया था, उसने कहा कि उसने 7% लोकोमोटर विकलांगता प्रमाणित की थी और यह रियायतें प्राप्त करने में व्यावहारिक रूप से बेकार होता, क्योंकि लाभ के लिए उच्च स्तर की विकलांगता की आवश्यकता थी। यह देखते हुए कि वास्तविक विकलांगता वाले लोगों को विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है, विकलांगता का नाटक करते हुए प्रमाणपत्र प्राप्त करने में उनकी आसानी से क्या भूमिका है, यह सवाल उठता है: क्या कुछ लोग दूसरों से अधिक समान हैं? उन्होंने सिविल सेवाओं में अपने पिता के पद से प्राप्त विशेषाधिकार का लाभ उठाकर कई ऐसे लाभ प्राप्त किए, जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल पाते। उनकी बदनामी में योगदान उनके फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्र ने दिया है; उन्होंने परीक्षा देने के लिए कई पहचानों का इस्तेमाल किया, यह झूठा दावा किया कि क्रीमी लेयर के बहिष्कार के मानदंडों को पार करने के लिए उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। सबसे भयावह तथ्य यह है कि अगर खेडकर ने प्रोबेशनर के रूप में अपने पद के अलावा अन्य सुविधाओं का दुरुपयोग न किया होता, तो यह सब सामने नहीं आता - उन्होंने अपनी निजी लक्जरी सेडान पर एक लालटेन लगाई और उस पर अवैध रूप से महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर चिपका दिया। उन्हें जल्द ही उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश मिल जाएगा।

यह सच है कि देश में योग्यता परीक्षाओं के लिए यह एक अच्छा साल नहीं रहा है, जिसमें NEET UG, NEET PG और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के साथ मेडिकल प्रवेश को लेकर विवाद हैं। यह तर्क देने में कोई दम नहीं है कि वह सिर्फ़ एक अपवाद हो सकती है, क्योंकि उसके और उसके माता-पिता के साथ ऐसा हुआ है क्योंकि UPSC पूरी तरह से बेखबर रहा और धोखाधड़ी का पता लगाने में असमर्थ रहा। यह क्षम्य नहीं है। सरकार को अब यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि पूरी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव हो। प्रशासकों और प्रणालियों को प्रतियोगियों और उभरती हुई तकनीक द्वारा पेश की गई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भोला या अक्षम नहीं होना चाहिए। इस बीच, इस घटना को आधार बनाकर, सरकार को विकलांगता प्रमाणन प्रक्रिया पर अपनी नज़र रखनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक आवेदकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।

पिछले कुछ वर्षों से जम्मू

[illegible] कारणों से खबरों में रहा है।

पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने सक्रिय आतंकवादियों की तलाश में अपूरणीय क्षति का सामना किया है - इसमें हाल ही में घुसपैठ करने वाले कैडर भी शामिल हैं - और हमेशा की तरह पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं। एक प्रमुख कारक जो इस विशेषता के रूप में उभरा, वह जून 2020 की गलवान घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जम्मू क्षेत्र से सैनिकों को फिर से तैनात किए जाने के परिणामस्वरूप कमजोर आतंकवाद विरोधी ग्रिड था। इस विशेष चुनौती से निपटने के लिए, अतिरिक्त सैनिकों, जिसमें विशेष बल दल शामिल हैं, को क्षेत्र में खाली जगह को भरने के लिए शामिल किया गया है। इस दैनिक ने इस पर एक रिपोर्ट की थी, जिसका शीर्षक था "जम्मू क्षेत्र में लगभग 3,000 सेना के जवान, 500 विशेष बल शामिल किए गए", 19 जुलाई, 2024)।

हाल ही में, जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए असम रीज के सैनिकों को शामिल किए जाने की खबर विभिन्न समाचार एजेंसियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट द्वारा दी गई है। इस दैनिक ने भी इस पर एक रिपोर्ट दी थी - "मणिपुर में असम रीज की दो बटालियनों की जगह सीआरपीएफ; कुकी-जो समूह इस कदम का विरोध करते हैं", 1 अगस्त, 2024)। ये रिपोर्टें, जाहिर तौर पर और सही ढंग से, पूरे जम्मू क्षेत्र में कठुआ से पुंछ तक और डोडा और आसपास के उप-क्षेत्रों वाली चिनाब घाटी में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के प्रति सरकार की गंभीरता को उजागर करती हैं। हालांकि, आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए क्षेत्र के बाहर से सैनिकों को शामिल करने के कई संकेत हैं।

एक ग्रिड की स्थापना एक आतंकवाद विरोधी तैनाती ग्रिड में इकाइयों और उप-इकाइयों को इस तरह से तैनात किया जाता है कि वे संभावित कमजोर क्षेत्रों पर हावी हो सकें, जो आतंकवादियों को स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ग्रिड की स्थापना सेना द्वारा किए गए खतरे की धारणाओं पर आधारित है, जो भूभाग, कमजोर क्षेत्रों और जैसे कारकों पर आधारित है।

कर्नल शशांक रंजन

एक सेवानिवृत्त पैदल सेना जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने का पर्याप्त अनुभव रखने वाले अधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान भी शामिल है। वे हरियाणा के सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं।

क्षेत्र के बाहर से सैनिकों को शामिल करने के कई निहितार्थ हैं, लेकिन संदेश स्पष्ट है - सुरक्षा परिदृश्य को संभालने के प्रति गंभीरता है

स्थानीय आबादी का झुकाव भी समान होता है, यानी, आबादी सहायक है या नहीं। ग्रिड के हिस्से के रूप में तैनात की गई उप-इकाइयाँ, लोगों की मित्रता जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर सामरिक ऑपरेशन करके आतंकवादियों की तलाश के मिशन पर निकलती हैं।

इलाके का ज्ञान और लोगों का दिल और दिमाग जीतना ऊपर बताए गए ऑपरेशन का आधार है। हाथ में लिए गए कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से सोची-समझी, जानबूझकर और समय लेने वाली है।

उप-इकाई कमांडर अपने परिचालन आचरण से लोगों का विश्वास प्राप्त करते हैं, ताकि स्थानीय आबादी को अपने पक्ष में कर सकें, जिसका अंतिम उद्देश्य क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है।

चुनौतियाँ उग्रवाद/आतंकवाद-विरोध की शास्त्रीय शिक्षा के अनुसार, स्थानीय आबादी को तीन उप-समूहों में विभाजित किया जाता है।

एक अल्पसंख्यक उप-समूह जो क्रमशः राज्य और आतंकवादियों का समर्थन करता है, और एक बहुसंख्यक जो कुल मिलाकर तटस्थ है। सुरक्षा बलों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे पहले से मौजूद अल्पसंख्यकों के समर्थन को बनाए रखें और तटस्थ बहुसंख्यकों को जीतें, जिससे स्थानीय आबादी का दो-तिहाई हिस्सा जीत सकें।

भारतीय सेना एक ग्रिड में तैनात पैदल सेना या राष्ट्रीय सेना इकाइयों द्वारा किए गए अभियानों के आधार पर उग्रवाद/आतंकवाद का मुकाबला कर रही है। आंतरिक क्षेत्र में तैनात ग्रिड नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी तैनाती का समर्थन करता है, जिससे बहु-स्तरीय व्यवस्था बनती है।

अतिरिक्त सैनिकों को शामिल किए जाने के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि नए शामिल किए गए सैनिकों के पास खुद को उन्मुख करने और जिम्मेदारी के संबंधित क्षेत्र में बसने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ऐसा करने के लिए, क्षेत्र को जानने, स्थानीय आबादी को जानने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें जीतने की अपरिहार्य आवश्यकता होती है। यह बहुत अधिक है केवल वृद्धि के गणित से अधिक। इन चुनौतियों को, एक हद तक, कम किया जा सकता है यदि नए शामिल किए गए सैनिकों को स्वतंत्र तरीके से तैनात करने के बजाय पहले से तैनात इकाइयों और उप-इकाइयों पर आरोपित किया जाए। जहाँ तक संभव हो, किसी क्षेत्र में सैनिकों के नए समूह को संबंधित नेताओं के अधीन उप-इकाइयों के रूप में तैनात किया जाना चाहिए, न कि संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से टुकड़ों में।

अंत में, असम रीज इकाई की तैनाती की संभावना के संबंध में , जैसा कि हालिया मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है, यह पहली बार नहीं है कि असम रीज इकाइयों को जम्मू और कश्मीर में शामिल किया जा रहा है।

1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में, असम रीज की इकाइयों को घाटी में तैनात किया गया था और उन्होंने अभिन्न इकाइयों के रूप में वीरतापूर्ण प्रदर्शन किया था। मई 1991 में चौकीबल के सामान्य क्षेत्र में 7 असम रीज द्वारा सफल ऑपरेशन दुधी को आज भी सबसे सफल ऑपरेशनों में से एक के रूप में याद किया जाता है।

ऑपरेशन दूधी की विशेषता यह थी कि मुख्य रूप से बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के अधीन काम किया जाता था, जिसमें उनकी सब-यूनिट्स प्रमुख भूमिका निभाती थीं। इससे जो मुख्य सबक सामने आते हैं, वे हैं कि कमांडिंग ऑफिसर्स पर भरोसा किया जाना चाहिए और उन्हें ऑपरेशन को नियंत्रित करने और संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, हाल ही में, ऑपरेशनों की तीव्रता में अपेक्षाकृत कमी आने के कारण, इन दिनों कोई भी विकासशील ऑपरेशन बटालियन स्तर से परे कमांड के नियंत्रण में चला जाता है, जिससे निर्बाध नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

संक्षेप में, शामिल की गई अतिरिक्त इकाई को सैनिकों के एक अभिन्न अंग के रूप में तैनात और कार्य करने की आवश्यकता है और नए क्षेत्र में नियंत्रण हासिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ब्रिगेड/सेक्टरों की मौजूदा कमान संरचना द्वारा समर्थित - गणितीय वितरण और तैनाती के विरुद्ध जो निश्चित रूप से प्रतिकूल परिणाम देने वाला है। यह समझना होगा कि सुरक्षा बल लंबे समय तक इस काम में लगे रहेंगे, और त्वरित परिणामों की अपेक्षा करना सभी मामलों में हानिकारक होगा।

संपादक के नाम चिठी

बांग्लादेश, सबक वर्तमान शासन को दोष दिए बिना, बांग्लादेश में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से कई सबक सीखे जाने चाहिए।

लोकतंत्र चुनावों से खत्म नहीं होता; इसकी शुरुआत यहीं से होती है। किसी के कामकाज में समावेशिता का तत्व होना चाहिए।

समाज के एक वर्ग को वंचित करना लोकतंत्र नहीं है। बांग्लादेश में, जब छात्र बेरोजगार थे, तो उनके एक वर्ग को बाहर रखा गया, जिससे असहिष्णुता पैदा हुई।

विपक्ष सहित समाज के सभी वर्ग पार्टियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कठोर कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। वे कालबाह्य हैं और उनका कोई महत्व नहीं है

एक कार्यशील लोकतंत्र में असहमति के लिए एक बड़ा स्थान होना चाहिए।

बांग्लादेश में हुई घटनाएं हमारी सोच के लिए प्रासंगिक हैं। ये सभी गंभीर सबक हैं जो बेहतर लोकतंत्र की ओर ले जाएंगे। ये केवल विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की चिंता नहीं होनी चाहिए।

एनजीआर प्रसाद, चेन्नई

यातनापूर्ण रास्ता भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगट को इस समय किस तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ रहा होगा, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यह जानकर हैरान रह गया कि जीत की चाह में एथलीट्स को किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जिसका आयोजन उनके साथ की टीम करती है।

आर. रमानी, चेन्नई

बैंक का मोबाइल ऐप मैं यह पत्र इस प्रकार लिख रहा हूँ सहायक महाप्रबंधक, सामूहिक संवाद विभाग, इंडियन बैंक, चेन्नई में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में। बैंक के ऐप, 'इंडस्मार्ट' और 'इंडओएसआईएस' ('संपादक को पत्र', द हिंदू, 5 अगस्त) पर एक पाठक द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में, इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को आश्वस्त करना चाहता है कि वह उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेता है - जैसा कि पत्र में व्यक्त किया गया है। नया मोबाइल ऐप, 'इंडस्मार्ट', 'इंडओएसआईएस' ऐप का एक उन्नत संस्करण है। ग्राहकों को एसएमएस, व्हाट्सएप और बैंक के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है, जिसमें उनसे स्विच करने का अनुरोध किया जा रहा है ऐप में मौजूद सुविधाओं को जानने और समझने के लिए 'इंडओएसआईएस' ऐप में एक पॉप अप मैसेज रखा गया है, जिससे प्लेस्टोर/ऐप स्टोर से 'इंडस्मार्ट' ऐप डाउनलोड करके उसे अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया जा सके। बैंक की कॉल सेंटर टीम ग्राहकों से संपर्क कर रही है और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

'इंडओएसआईएस' ऐप सक्रिय है। 'इंडस्मार्ट' के साथ पंजीकरण की सुविधा सीआईएफ के माध्यम से उपलब्ध है और बैंक की शाखाओं में सक्षम है, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होती है। ग्राहकों के लिए स्व-पंजीकरण का विकल्प भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा।

बैंक को फीडबैक का इंतजार है। बैंक अपने ग्राहकों को यह भी आश्वस्त करना चाहता है कि वह उन्हें ऐप में किए गए नए फंक्शन या सुधारों के बारे में सूचित करता रहेगा, जिससे उनका बैंकिंग अनुभव बेहतर होगा।

पवन कुमार सक्सेना, चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में पूरा डाक पता अवश्य होना चाहिए।

सेमी
वाईके

...धिक जानकारी के लिए जुड़ें-https://telegram.me/DailyPressNation

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 8 अगस्त 2024

बेमिसाल विनेश

विमिन रेसलर विनेश फोगाट ने जिस तरह से पैरिस ओलिंपिक्स के 12वें दिन फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा और फिर डिस्क्वॉलिफाई कर दी गईं, वह किसी सदमे से कम नहीं।

असाधारण संघर्ष | इस तरह का घटनाक्रम किसी भी स्पोर्ट्सपर्सन के लिए दुखद होता, लेकिन विनेश फोगाट जिस तरह का जज्बा दिखाते हुए यहां तक पहुंची थीं, उसमें देश ही नहीं दुनिया भर के खेल प्रेमियों की भावनाओं का उनके साथ जुड़ जाना बिल्कुल स्वाभाविक था।

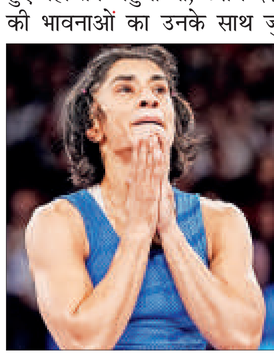

अपात्र घोषित हुईं फोगाट

खासकर इसलिए कि मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि से वंचित किया जाना किसी के लिए भी आसानी से हजम होना मुश्किल है।

कुश्ती महासंघ को चुनौती | इससे पहले विनेश ने साथी पहलवानों के साथ कुश्ती के क्षेत्र में चल रही कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाने का मतलब था करियर दांव पर लगाना। हालांकि उस मामले में कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं और अदालत के फैसले का इंतजार है।

प्रतिकूल माहौल | यह भी तय है कि कुश्ती महासंघ के खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने इसके तत्कालीन कर्ता-धर्ताओं की नाराजगी मोल ली थी। इससे यह भी समझा जा सकता है कि खेल ढांचे का एक हिस्सा विनेश के साथ सहज नहीं महसूस कर रहा होगा और उन्हें पैरिस ओलिंपिक्स की अपनी पूरी यात्रा प्रतिकूल माहौल में तय करनी पड़ी होगी। यह संघर्ष का उनका जज्बा ही था जिसमें उन्होंने 50 किलोग्राम कैटिगरी की वर्ल्ड और ओलिंपिक्स चैंपियन युई सुसाकी तक को पराजित कर दिया, जो 82 मैचों से अजेय थीं।

जांच के आदेश | यह बात कई कोनों से उठ रही है कि 100 ग्राम ज्यादा वजन निकलना खुद रेसलर की नहीं बल्कि सपोर्ट स्टाफ की कमी का नतीजा कहा जाएगा। कुश्ती महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा भी है कि सपोर्ट स्टाफ द्वारा अपना काम ठीक से न करने संबंधी शिकायतों की जांच की जाएगी।

सबका दिल जीता | तात्कालिक आरोप-प्रत्यारोपों के जरिए इन सवालों के सही जवाब नहीं मिल सकते। जो कुछ हुआ है, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि खेल ढांचों से लेकर राजनीतिक संस्कृति तक तमाम पहलुओं की गहराई से पड़ताल की मांग करता है। जहां तक विनेश की बात है तो तकनीकी आधार पर मेडल चाहे जिसके भी नाम कर दिया गया हो, दुनिया भर के खेल प्रेमियों के दिलों में उनकी उपलब्धि हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है।

साड्डी दिल्ली

क्या बेचते पनवाड़ी

विवेक शुक्ला

क्या आपको कनॉट प्लेस, करोल बाग या सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में लजीज लंच या डिनर करने के बाद मन-माफिक पान खाने की चाहत है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। आपको इन जगहों पर मुश्किल से ही पान बनाने वाला कोई पनवाड़ी मिलेगा। यह स्थिति अधिकतर बाजारों की है। यह बात भी नहीं है कि पनवाड़ी गायब हो गए हैं। इधर पनवाड़ी मौजूद हैं, पर वे पान नहीं बना रहे। तो ये पनवाड़ी क्या कर रहे हैं? अब ये मुख्य रूप से सिगरेट और पान मसाला ही बेच रहे हैं। इन्होंने पान बेचना बंद कर दिया है। रीगल के पास एक भूतपूर्व पनवाड़ी का कहना है, 'पान बेचने के लिए बहुत कुछ रखना और करना पड़ता है। सिगरेट और मसाला बेचने में झंझट नहीं है। अब पहले वाले पान खाने के शौकीन भी नहीं रहे।' आपको राजधानी के अधिकतर, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, सरकारी दफ्तरों वगैरह के आसपास भी बहुत सारे पनवाड़ी तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, हुक्का, चूरुट आदि खुलेआम बेचते नजर आ जाएंगे। सर गंगा राम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहसिन वली कहते हैं, 'अफसोस होता है कि कई अस्पतालों के आसपास भी नशा बिक रहा है। सरकार चाहे तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरपी (एनआरटी) और स्नस (धुआं रहित तंबाकू) जैसे वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित विकल्पों के जरिए नशे पर रोक लगा सकती है।' निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरपी लोगों को धूम्रपान छोड़ने में मदद करने के लिए एक उपचार है।

Subrata Dhar

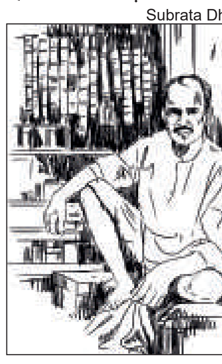

कभी वक्त मिले तो दिल्ली नगर निगम के हेड ऑफिस सिविक सेंटर के मेन गेट के पास टैगोर रोड हॉस्टल के बाहर खड़े हो जाएं। वहां कई नशेड़ी सामूहिक रूप से दिन के उजाले में नशा कर रहे होते हैं। वहीं उन्हें नशा मिलता है। इस जगह से पांच मिनट की दूरी पर कमला मार्केट थाना है, पर कौन नशे की बढ़ती लत के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। दरअसल नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता ने नशे के कारोबार को गति देने में अहम भूमिका निभाई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क और पालिका बाजार के ऊपर बने पार्क में ही शाम को नशे के सौदागर किसी कोने में बैठे हुए मिल जाते हैं। इधर ही कभी-कभी घुमंतू पनवाड़ी पान बेचते हुए मिलते हैं।

एकदा

लीडरशिप की मिसाल

10 अगस्त 1979 की घटना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्री हरि कोटा रेंज) के एक सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दुनिया भर के पत्रकारों का जमावड़ा था। सतीश धवन इसे संबोधित करने वाले थे। उसी दिन SLV-3 का प्रक्षेपण असफल हुआ था। खबर प्रसारित हो गई थी कि भारत के 20 करोड़ रुपये बंगाल की खाड़ी में डूब गए। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रक्षेपण की असफलता पर पूछे जाने वाले सवालों और ISRO चेयरमैन सतीश धवन के जवाब को सुनने के लिए पूरा देश उत्सुक था। वहीं, प्रॉजेक्ट के डायरेक्टर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सहित सभी वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि असफलता के लिए मूल रूप से वही जिम्मेदार थे। सतीश धवन के सामने आते ही सवालों की बौछार होने लगी। 'कहां गलती हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चेयरमैन होने के कारण आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं?' सतीश धवन ने कहा, 'गलती मेरी है। मैंने ही वैज्ञानिकों को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। चेयरमैन होने के नाते मैं असफल हुआ हूं।' वैज्ञानिकों का मन भावुकता से भर गया। कई की आंखें छलछला आईं। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम सहित सभी वैज्ञानिकों ने दिन-रात मेहनत कर 11 महीने के रेकॉर्ड समय में 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रक्षेपण करके भारत का नाम अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी छह देशों की सूची में दर्ज करा दिया। इस सफलता के बाद सतीश धवन प्रेसवार्ता के लिए खुद नहीं गए, बल्कि प्रॉजेक्ट डायरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भेजकर लीडरशिप की बड़ी मिसाल कायम की। नेतृत्व नहीं, काम महत्वपूर्ण होता है।

Subrata Dhar

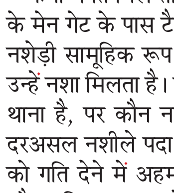

संकलन : **हरिप्रसाद राय**

पड़ोसी देश से संबंध इस पर निर्भर करेंगे कि अंतरिम सरकार का नियंत्रण किसके हाथों में रहता है

रिश्ते और हों मज़बूत, यही चाहता है भारत

हर्षवर्धन श्रृंगला

शेख हसीना की अचानक विदाई के बाद बांग्लादेश में उथलपुथल मची हुई है। इसी को लेकर यह विश्लेषण है, जिसमें मैं तीन बातों की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली, हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने किन चीजों में तरक्की की। दूसरी, आने वाले वक्त में बांग्लादेश की राजनीति क्या शक्ल अख्तियार कर सकती है। तीसरी, बांग्लादेश को लेकर भारत का रवैया कैसा होना चाहिए।

हसीना की उपलब्धियां | शेख हसीना को आर्थिक रूप से मजबूत बांग्लादेश का कर्ता-धर्ता माना जाता है। हसीना सरकार ने 2009 के बाद से देश को जो स्थायित्व दिया, उससे वहां निवेश बढ़ा। इसी की बदौलत बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की बड़ी ताकत बन सका।

आर्थिक मजबूती | मैं ढाका में 2016-2019 के बीच हाई-कमिश्नर था। उस दौर में वहां की इकॉनमी में जो बड़े बदलाव हुए, उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने देखा कि किस तरह से हसीना ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मजबूत मुल्क बनाया।

अदालत का फैसला | जिस आरक्षण वाले मामले की वजह से उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, विडंबना है कि उसे बहाल करने का आदेश वहां की अदालतों ने दिया था। हसीना सरकार ने तो 2018 में मुक्तियोद्धाओं के लिए सारी सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण को रद्द कर दिया था।

खुद कुर्सी छोड़ी | हसीना की इस बात के लिए भी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने खुद से कुर्सी छोड़ने की सलाह मान ली। अगर वह इस सलाह को नहीं मानतीं और प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़तीं तो बांग्लादेश की स्थिति आज और भी खराब हो सकती थी। उनके पद छोड़ने से अब वहां सहज ढंग से नई सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ है।

बदली हवा
- हसीना ने खुद पद छोड़ा, अच्छा फैसला
- मो. यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया
- जमात-ए-इस्लामी को न मिले जगह

जमात की कारगुजारी | ध्यान रहे, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व छात्र कर रहे थे, लेकिन बाद में इसमें जमात-ए-इस्लामी की घुसपैठ हुई। जमात की स्टूडेंट विंग छात्र शिबिर ही बांग्लादेश में हो रही ज्यादातर हिंसा के लिए दोषी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश में मेट्रो स्टेशनों जैसे आम लोगों के काम आने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर को जलाया नहीं जाता। इन्हीं लोगों की वजह से बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति और उनसे जुड़े म्यूजियम को निशाना बनाया गया।

ढाका में BNP मुख्यालय के सामने बुधवार को उमड़े प्रदर्शनकारी

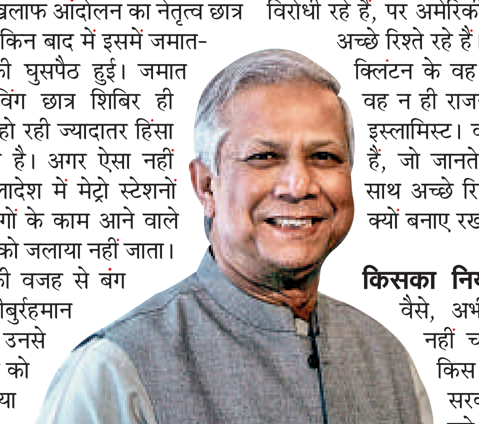

यूनुस से आस | नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए हैं। वह शेख हसीना के विरोधी रहे हैं, पर अमेरिकी लीडर्स से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। बिल और हिलेरी क्लिंटन के वह काफी करीब हैं। वह न ही राजनेता हैं और न ही इस्लामिस्ट। वह एक टेक्नॉक्रेट हैं, जो जानते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बांग्लादेश को क्यों बनाए रखना चाहिए।

किसका नियंत्रण रहेगा | वैसे, अभी तक यह पता नहीं चला है कि यूनुस किस तरह की अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं? अलग-अलग पक्षों के दखल की वजह से सरकार बनने में कुछ वक्त लगेगा। देश में स्थिरता के लिए मार्शल लॉ लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार का असल नियंत्रण किसके हाथों में रहता है? क्या यह सेना प्रमुख, दूसरे प्रभावशाली फौजी अफसरों, राष्ट्रपति, जमात या विपक्षी दल BNP से निर्वासित नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में पार्टी के हाथों में बना रहेगा या फिर सरकार की कमान इन सबके हाथों में संयुक्त रूप से रहेगी?

भारत क्या करे | अगर वहां ऐसी सरकार बनती है, जो भारत विरोधी न हो तो यह अच्छा होगा। इससे भारत को शरणार्थियों की समस्या का सामना नहीं करना होगा। साथ ही, पिछले 15 वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में जो प्रगति हुई है, वह बाधित नहीं होगी। बांग्लादेशी प्रशासन अल्पसंख्यकों के हितों की किस तरह से रक्षा करता है, भारत के लिए यह बात भी काफी अहमियत रखती है। भारत यह भी नहीं चाहेगा कि अंतरिम सरकार में जमात को जगह मिले। अतीत में हम देख चुके हैं कि उसने किसी तरह से भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ काम किया था।

क्या है नजरिया | जब वहां नई सरकार बनेगी तो भारत उसके साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए जरूर बातचीत करेगा। पिछले 15 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत करने के जो प्रयास किए हैं, उसके फायदे स्पष्ट हैं। इनमें पूर्वोत्तर भारत में हुआ विकास भी शामिल है। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मजबूत स्तंभ रहा है। लोकतांत्रिक और सेकुलर बांग्लादेश भारत के हितों के लिए अच्छा होगा।

लंबा बॉर्डर | दोनों देश 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह भारत के लिए दूसरे किसी पड़ोसी मुल्क की तुलना में सर्वाधिक है। एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक पॉलिसीज के लिहाज से भी भारत के लिए बांग्लादेश की काफी अहमियत है। व्यापार-निवेश के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार हुआ है। सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग से उसके साथ संपर्क और बढ़ा है। इससे दोनों ही देशों को फायदा हुआ है। दोनों देशों के संबंधों का बेहतर भविष्य इसी में छिपा है।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं)

ब्रिटेन से बांग्लादेश तक, डीपफेक की आग

शैलेंद्र पांडेय

बांग्लादेश में जिस समय हजारों की भीड़ शेख हसीना के आवास में घुसकर लूटपाट करने और सेल्फी लेने में बिजी थी, उसी समय सोशल मीडिया पर लाखों विडियो और मेसेज भी घूम रहे थे। इनमें से कुछ मेसेज एक खास नैरेटिव को बढ़ाने वाले थे, भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले। इनकी वजह से एक छात्र आंदोलन तख्तापलट की साजिश, राजनीतिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत में तब्दील हो गया।

ब्रिटेन में संकट | डीपफेक विडियो और गलत सूचनाओं ने जो तबाही फैलाई है, उसे झेलने वाला बांग्लादेश इकलौता देश नहीं। इसी समय ब्रिटेन भी इसी तरह के संकट से जूझ रहा है। ब्रिटेन के साउथपोर्ट में तीन बच्चियों की हत्या के बाद मिस-इंफॉर्मेशन की ऐसी लहर उठी कि कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। अब जबकि साबित हो चुका है कि बच्चियों का हत्यारा कोई मुस्लिम नहीं, बल्कि ब्रिटेन का ही रहने वाला है, तब भी तनाव कम नहीं हो रहा।

झूठ की रफ्तार | डीपफेक से लड़ने में मुश्किल यही है कि इसे गलत साबित कैसे किया जाए? लोगों को भड़काने वाली जानकारी सोशल मीडिया पर जिस रफ्तार से फैलती है, उस गति से सच नहीं पहुंच पाता। फिर आम लोगों के पास कोई जरिया भी नहीं होता कि वे अपने पास पहुंची सूचना को क्रॉस चेक कर सकें। कई बार वे इस मनोदशा में भी नहीं होते। अब बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल कोई युवा किसी सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई करने की जहमत क्यों उठाएगा और वह भी तब, जब सूचना उसके हक में लग रही हो!

दूर बैठकर साजिश | टेक्नॉलजी का सहारा लेकर झूठ फैलाने वाले इसी का फायदा उठाते हैं। जब तक किसी सूचना की सचाई से पर्दा उठता है, तब तक दो और झूठ गढ़ लिए जाते हैं। साजिश रचने वाले जानते हैं कि किसी घटनाक्रम का जितना भयावह पहलू वह पेश करेंगे, उसकी याद उतनी ही देर तक बनी रहेगी। डीपफेक जैसी तकनीक ने उन्हें अब इतनी ताकत दे दी है कि वे किसी घटना को मनचाहा मोड़ दे सकें। बांग्लादेश के मामले में धीरे-धीरे खुलासा हो रहा है कि लोगों को भड़काने वाले तमाम पोस्ट चीन और पाकिस्तान से भी किए गए। खासकर, भारत विरोधी पोस्ट्स को पाकिस्तान में बैठकर रचा गया।

AI Image

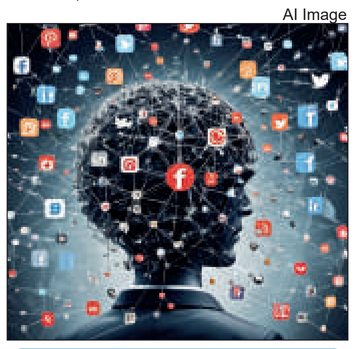

कॉमन रूम

मॉनिटरिंग मुश्किल | कम से कम डीपफेक के मामले में सस्ती टेक्नॉलजी ने मुसीबत और बढ़ाई है। 25 से 30 डॉलर यानी दो से तीन हजार रुपये में कोई भी इन ऐप्स का एक्सेस हासिल कर सकता है। इनको प्रमोट किया जाता है फन टूल के रूप में, लेकिन यह मॉनिटर करने का कोई जरिया नहीं कि इनका इस्तेमाल फन के लिए हो रहा है या किसी और काम के लिए।

कंपनियों की मनमानी | यह भी संकट है कि जायंट टेक कंपनियां अपने नियम कायदों से चलती हैं और जो मार्केट उनकी नजर में छोटे हैं, वहां की चिंताओं पर ध्यान नहीं देतीं। इस साल जनवरी की बात है, जब बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी चल रही थी। उसी वक्त मेटा पर विपक्षी बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (BNP) के निर्वासित नेता तारिक रहमान का एक विडियो वायरल हुआ। इसमें तारिक यह सुझाव देते दिख रहे थे कि गाजा मसले पर बांग्लादेश को चुप रहना चाहिए वरना अमेरिका नाराज हो सकता है। यह ऐसा विडियो था, जो एक इस्लामिक देश के किसी राजनीतिक दल को तबाह कर सकता है। BNP का आरोप है कि उसके कई बार आग्रह के बावजूद मेटा ने इस डीपफेक विडियो को नहीं हटाया।

AI से सामना | पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ताइवान के चुनावों में डीपफेक का जमकर इस्तेमाल हुआ। अभी अमेरिका में वायरल एक विडियो ने यह सनसनीखेज जानकारी दी कि बाइडन सरकार ने चुपके से हमास को 6 बिलियन डॉलर की मदद भेजी है। जाहिर है कि विडियो फर्जी था। तो क्या इस दुष्प्रचार से लड़ने का कोई उपाय नहीं? या शायद है। ताइवान में Cofacts और Taiwan AILabs जैसे फैक्ट चेकिंग ऑर्गनाइजेशन हैं। ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से फैलाए गए झूठ का AI की मदद से ही खुलासा करते हैं। कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, तो टेक्नॉलजी का सामना टेक्नॉलजी से क्यों नहीं?

सिक्कों ने खोलीं इतिहास की परतें

सुविज्ञा जैन

आज भले ही एरण के इतिहास को ज्यादा न दोहराया जाता हो, लेकिन इसका वैभव दुनिया के किसी भी प्राचीन नगर से कम नहीं रहा। आज से डेढ़ हजार साल पहले यानी चौथी से छठी सदी तक एरण गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। गुप्त राजवंश के कालखंड को क्रमवार लगाने के लिए इतिहासकारों को इसी नगर से मिले अभिलेखों और सिक्कों से अहम जानकारी मिली।

सबसे पुरानी टकसाल | अभिलेखों से पता चलता है कि 1700 साल पहले गुप्त शासनकाल में यह नगर उस समय का एक मुख्य प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। प्राचीन भारत की मुख्य टकसालों में एक प्रमुख टकसाल थी एरण में। इसमें कई शासनकालों में सिक्कों को ढाला गया। एरण में पुरातात्विक उत्खननों में सिक्के बनाने के सांचों का मिलना इस बात की तस्दीक करता है।

AI Image

टाइम मशीन

कनिंघम की भूमिका | ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता एलेग्जेंडर कनिंघम ने अपने दस्तावेजों में लिखा कि उन्हें पूरे भारत में जगह-जगह खुदाई में जितने भी सिक्के मिले, उनमें एरण के सिक्के सबसे बेहतरीन कहे जा सकते हैं। कनिंघम के नेतृत्व में ही 1870 के दशक में एरण में खुदाई की गई थी।

दुर्लभ सिक्के | एरण में मिले हजारों सिक्कों में सबसे बड़ा 28 मिलीमीटर का है और सबसे छोटा सिर्फ 5 मिलीमीटर का। चौकोर आकार के सिक्के एरण की खास पहचान थे। यहां की टकसाल में बने चांदी और तांबे के कई नायाब सिक्के लंदन म्यूजियम में संरक्षित हैं। इनमें वह दुर्लभ सिक्का भी शामिल है, जिसे भारतीय इतिहास का प्राचीनतम अभिलिखित सिक्का माना गया है। 300 ईसा पूर्व के इस सिक्के पर राजा धर्मपाल का नाम लिखा है।

पहली टकसाल | कनिंघम ने पाया कि एरण प्राचीन भारत की ऐसी पहली टकसाल थी, जिसमें पंच मार्क सिक्कों के अलावा डाई बेस्ड सिक्के भी बनने शुरू हो गए थे। इनका आज के लिए सबसे बड़ा महत्व यह है कि कई सिक्कों पर अंकित तब के राजाओं के नाम से ही इतिहासकारों को गुप्त राजवंश के लंबे दौर का पता चला।

कला-सभ्यता | एरण की टकसाल में बने इन्हीं सिक्कों के जरिए तब की कला और संस्कृति के बारे में भी जाना-समझा गया। सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लिखे शब्दों से अंग्रेज पुरातत्ववेत्ताओं ने काफी कुछ जाना। कुछ सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और दो हाथी अंकित पाए गए।

सती प्रथा का साक्ष्य | एरण में पुरातात्विक खुदाई में मिले अभिलेखों और स्तंभों से प्राचीन भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप देने में बड़ी मदद मिली। इन्हीं साक्ष्यों से गुप्त साम्राज्य में सामाजिक परिवेश का भी पता चला। भारतीय समाज में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य एरण में ही पाया गया है। राजा भानुगुप्त के शासनकाल यानी सन 510 के एक स्तंभ पर उनके सेनापति और प्रिय मित्र गोपराज की युद्ध में मौत के बाद उनकी पत्नी के आत्मदाह का वर्णन है। इतिहास में इस चलन की शुरुआत का यह सबसे पहला अभिलिखित और तिथि युक्त साक्ष्य कहा जाता है।

घास पर नाम | सम्राट समुद्रगुप्त के एक अभिलेख में एरण को एरिकिण कहा गया है। अनुमान है कि इस क्षेत्र का एरिकिण नाम इस इलाके में उगने वाली एक खास किस्म की घास 'एरक' के नाम पर पड़ा, जो आगे चल कर एरण हो गया।

ब्रेक के बाद...

प्रणव प्रियदर्शी

मुंबई यूनिवर्सिटी से बीई करने के ठीक बाद ही दीना सवलानी का करियर उड़ान भरता नजर आने लगा। कैपिटल मार्केट में अपनी दक्षता की बदौलत उन्होंने लीमैन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियों की भारतीय शाखाओं में टेक्नॉलजिस्ट की भूमिका निभाई। मगर 11 साल लगातार काम करने के बाद वह थकान महसूस करे लगीं। लिहाजा 2016 में उन्होंने मोटी सैलरी वाला यह काम छोड़ दिया और फैशन जूलरी का अपना बिजनेस शुरू किया। यह बिजनेस संभालने के दौरान ही वह मां बनीं और फिर बच्चा उनकी प्राथमिकता बन गया। इसके बाद उन्होंने वह बिजनेस बंद कर दिया। बच्चे के छह महीने का होते-होते उनके मन में दोबारा काम करने की इच्छा जोर मारने लगी। लेकिन वह ऐसी कंपनी चाहती थीं जिसमें करियर ब्रेक के बाद वापसी करने वाली महिलाओं के लिए प्रोग्राम हो। सोच यह थी कि टीम के साथ ग्रुप में सीखना आसान होगा और अलग-थलग पड़ने का डर भी नहीं रहेगा। वेल्स फारगो में उन्हें ऐसा प्रोग्राम मिला तो उन्होंने अप्लाई किया और चुन ली गईं। यहां भी दीना ने पहले महीने रोज 3 घंटे ही काम किया, दूसरे महीने यह 4 घंटे हुआ और फिर धीरे-धीरे 8 घंटे रोजाना का क्रम शुरू हुआ। इस सहूलियत का फायदा यह हुआ कि दीना और उनके बेटे दोनों के लिए नई रूटीन में ढलना आसान हो गया। इस बिंदु पर यह समझना अहम है कि कई मौके दीना को इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि वे उनके हालात को सूट नहीं कर रहे थे। मसलन, एक पूर्व एम्प्लॉयर ने उन्हें अच्छी पोजिशन ऑफर की थी, लेकिन वहां वर्कप्लेस से दूरी के चलते आने जाने में ज्यादा टाइम लगता। वेल्स फारगो के इस प्रोग्राम की जानकारी उन्हें एक पूर्व सहकर्मी से मिली। दीना गलत नहीं कहती हैं कि पूर्व सहकर्मियों से संपर्क बनाए रखना और लिंक्डइन व अन्य तमाम माध्यमों से कार्यक्षेत्र में हो रहे बदलावों पर नजर बनाए रखना खासा उपयोगी होता है।

दीना सवलानी

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

अकेलेपन से भागें नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करके देखें

जे. कृष्णमूर्ति

मनुष्य स्वाभाविक रूप से अकेला नहीं रहना चाहता। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब सब अपने-अपने काम में व्यस्त हैं और किसी के पास समय नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद अकेलापन और बढ़ जाता है। क्योंकि घर में हर कोई अपनी रफ्तार में चल रहा होता है। ऐसे में, अकेलेपन को एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय, इसे आत्म-खोज का अवसर मानना चाहिए। अकेलेपन को अपने अंदर समेटें, उसे समझें और उसके साथ दोस्ती करें। यह आत्मावलोकन का समय होता है, जो हमें खुद को बेहतर समझने और जीवन के सच्चे मूल्य को पहचानने का अवसर देता है।

अकेलापन को अक्सर संग-साथ न होने के दुख और अलग-थलग पड़ने की अवस्था के रूप में समझा जाता है। लेकिन यह एक गहरा और बहुआयामी अनुभव भी है। यह एक ऐसी स्थिति है, जब व्यक्ति खुद को किसी भी समूह, परिवार या समाज से अलग महसूस करने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी इस अकेलेपन को विस्तार से देखा है और इसे समझने का प्रयास किया है?

अकेलेपन का अनुभव केवल एकाकी होने की स्थिति का संकेत नहीं, बल्कि यह आत्म-विश्लेषण और आत्म-खोज का भी अवसर प्रदान करता है। जब आप अकेले होते हैं, तो यह अवसर मिलता है कि आप अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकें। यह समय आत्म-विश्लेषण के लिए होता है, जिसमें आप खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अकेलेपन की समझ केवल तभी प्राप्त होती है जब आप इसके साथ खुलकर और निर्भीक रूप से रहना सीखते हैं। इसे समझने के लिए आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है और न ही यह मान लेना चाहिए कि आप इसके कारणों को पहले से जानते हैं।

अकेलेपन का सही अनुभव तभी संभव है जब आप बिना किसी पूर्वधारणा या बाहरी प्रभावों के इसका सामना करें। हम अक्सर अकेलेपन से बचने का प्रयास करते हैं, जैसे रेडियो सुनना, पूजा करना, या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। ये पलायन के तरीके होते हैं, जो हमें खुद से दूर करने का काम करते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तो आप इन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे आप अकेलेपन की वास्तविकता से भाग जाते हैं। ये पलायन अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन वे अकेलेपन की गहराई को नहीं समझाते।

अकेलेपन को समझने के लिए, आपको सभी प्रकार के पलायनों को छोड़ना होगा और इस बात को गहराई से देखना होगा कि ये पलायन कितने व्यर्थ और निरर्थक हो सकते हैं। अकेलेपन का सामना करने और समझने के लिए, आपको अपनी आंतरिक दुनिया के साथ एक ईमानदार और निर्भीक संवाद करना होगा। इससे आप अकेलेपन के वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं और इस अनुभव को आत्म-खोज और व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देख सकते हैं।

जब आप अकेलेपन का सही अनुभव करेंगे, तो आप इसे एक नई दृष्टि से देख सकेंगे, जो आपको आत्म-ज्ञान और व्यक्तिगत वृद्धि के पथ पर ले जाएगा।

(साभार : 'प्रेम क्या है' पुस्तक से)

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ कायम रहें रिश्ते

7 अगस्त के संपादकीय 'भारत की चुनौतियां बढ़ीं' में बिलकुल सही कहा गया है कि बांग्लादेश में चाहे किसी की सरकार बने, लेकिन भारत से उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने सत्ता परिवर्तन का माहौल बना दिया है। कुटिल चालों के चलते पहले मालदीव, फिर नेपाल, श्रीलंका और अब बांग्लादेश में चीन ने अपने मोहरे फिट कर लिए हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। शायद व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में पहले जैसी घनिष्ठता नहीं रहेगी। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार सजगता पूर्वक प्रयास कर रही है। बांग्लादेश की घटना से इंटेलिजेंस का फेल्योर सामने आया है।

मधु बुड़ावन वाला, ईमेल से

■ लोकतंत्र का सम्मान

यह पत्र 1 अगस्त के संपादकीय 'स्वस्थ हो बहस' से संबंधित है। संसद में किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी उचित नहीं है। चाहे वह सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से की गई हो या प्रतिपक्ष के नेताओं की ओर से। इससे संसद की गरिमा भंग होती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। संसद में शालीनता के साथ बहस हो। संसद को रणभूमि में तब्दील करने को समझदारी नहीं कह सकते हैं। हमने अपने नेताओं को संसद में इसलिए भेजा है कि वे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाएं।

वारिस अली खान, ईमेल से

■ खेल में भेदभाव न हो

पेरिस ओलिंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन खराब अंपायरिंग के चलते भारत को हॉकी में गोल्ड की रेस से बाहर होना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में अमित रोहित दास को रेड कार्ड दिखाकर पूरे मैच में उन्हें खेलने से वंचित रखा गया। फिर सेमीफाइनल में भी निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए, जबकि अमित ने जानबूझ कर ब्रिटेन के खिलाड़ी को चोट नहीं पहुंचाई थी। वहीं सेमीफाइनल में भी अंपायरिंग उच्चस्तरीय नहीं रही। भले ही पैरिस ओलिंपिक्स में हॉकी सेमीफाइनल जर्मनी ने जीता, पर भारतीय टीम ने दिल जीता।

योगराज धूपड़, द्वारका मोड़

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

उद्धव सीएम के चेहरे पर कांग्रेस नेताओं से करेंगे बात - एक खबर
- बात करेंगे या अपना ही चेहरा पास कराएंगे!

प्रीति अग्रवाल

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए, राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 8 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जय उसी की होती है जो अपने को संकट में डाल कर कार्य संपन्न करते हैं। जय कायरों की कभी नहीं होती।
-जवाहरलाल नेहरू

पड़ोसियों के संकट

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद संसद भंग कर दी है। सेना प्रमुख जनरल वकार ने कहा कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हसीना अपनी बहन के साथ अस्थायी शरण के लिए भारत में हैं परंतु उनकी लंदन जाने की योजना अटक गई प्रतीत हो रही है। ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिए हैं कि उनके देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के कारण कानूनी सुरक्षा मिलने में अड़चनें आ सकती हैं। दूसरा, अभी यह भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना अस्वस्थ हैं, और इस सूरत में यात्रा करने में परेशानी का सामना कर सकती हैं। इसलिए उनका भारत में कुछ रोज और रुकना हो सकता है। हसीना के परिवार के कुछ सदस्य फिनलैंड में भी हैं। उनकी बहन की बेटी ब्रिटिश

संसद की सदस्य हैं। भारत सरकार मामले पर पैनी नजर रखे हुए है। वहां मौजूद भारतीयों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है। भारत और बांग्लादेश के दरम्यान त्रेपन सालों से द्विपक्षीय संबंध हैं परंतु हसीना का सत्ता में न रह पाना मुश्किलें पैदा कर सकता है। लंबे समय से जेल में बन्द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। खालिदा का झुकाव हमेशा इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है जिसका लाभ उठाने में चीन और पाकिस्तान चूकने वाले नहीं। चूंकि भारत-बांग्लादेश के दरम्यान हजारों किलोमीटर की सीमा है। लिहाजा, शांति योजनाओं को झटका लगने का अंदेशा खासा बढ़ गया है। इस सारे संकट में विदेशी सरकारों का हाथ होने से भी इंकार नहीं किया जा रहा है जिसकी बुनियाद को समझना बेहद जरूरी है। वहां नये चुनाव होंगे, शेख हसीना को उसमें शामिल किया जाएगा या सत्ता को सेना अपने हाथ में ही रखेगी, यह कुछ अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि वहां सैन्य शासन नई बात नहीं है। मगर इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खासी ठेस पहुंचती है। हसीना को भारत सरकार पहले भी राजनीतिक शरण दे चुकी है। इसलिए हम उनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इस मुस्लिम देश में यदि अधिक वक्त तक अस्थिरता रहती है तो यह भारत के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि कट्टरपंथियों, आतंकवादी संगठनों के हौंसले बढ़ेंगे और कानून-व्यवस्था ढुलमुला सकती है जो शेख हसीना के राज में बांग्लादेश की संभली अर्थव्यवस्था के अनुकूल तो कतई नहीं कही जा सकती। पड़ोसी देशों में होने वाली राजनीतिक अस्थिरता हमारे लिए संकट का सबब हो सकती है।

व्यापार पर असर

पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैली व्यापक अशांति और अस्थिरता की वजह से पश्चिम बंगाल के रास्ते होने वाला सीमापार व्यापार मंगलवार को पूरी तरह ठप हो गया। देश में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को इस्तीफा देकर देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कारोबारी स्थितियों की बेहतरी के लिए माना जाता है कि हालात सहज और शांतिपूर्ण होने चाहिए। और बांग्लादेश यह शर्त अब बाकी रह नहीं गई है, इसलिए बांग्लादेश में कारोबार चौपट हुआ जा रहा है। पश्चिम बंगाल निर्यातक समन्वय समिति के सचिव उज्ज्वल साहा के मुताबिक, राज्य में भूमि बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार बांग्लादेश के सीमा शुल्क विभाग द्वारा माल की निकासी नहीं होने से रुका हुआ है। इसकी वजह से सैकड़ों ट्रक पार्किंग स्थल पर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल, गोजाडांगा, महादीपुर और फुलवारी में स्थित भूमि बंदरगाहों के जरिए होने वाला भारत-बांग्लादेश व्यापार प्रभावित हुआ है।

बांग्लादेश की तरफ की सीमा शुल्क चौकी पर काम ठन होने से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंदरगाहों पर व्यापार ठप हो गया है। बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। दोनों देशों के बीच 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। इसलिए चिंता इस बात की जताई जा रही है कि दोनों देशों के व्यापार पर बांग्लादेश के हालात का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। चिंता इसलिए भी है कि भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उसने भारत को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था। हालांकि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक, बांग्लादेश की उथल-पुथल का दोनों देशों के व्यापार कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता, उसका यह भी कहना है कि भारतीय निर्यात को बांग्लादेश में घरेलू मांग में कमी का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठित होते ही संभवतः दोनों देशों के बीच व्यापार पटरी पर लौटे। भारत बांग्लादेश से मछली, प्लास्टिक, चर्म उत्पाद, परिधान आदि का आयात करता है, जबकि बांग्लादेश को सब्जियों, काफी, चाय, मसालों, चीनी, कन्फैक्शनरी, परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों, रसायन, कपास, लोहे और स्टील तथा वाहनों आदि का निर्यात करता है। स्थिति दो-एक दिन में साफ हो जाएगी।

कटाक्ष/ सहीराम

खुराक नहीं लग रही

नहीं यह वो वाली शिकायत नहीं है जी, जो अक्सर मां-बाप खास तौर लड़कों को लेकर रहती है कि पता नहीं क्यों इसे खुराक लग ही नहीं रही। नहीं, हम वो इश्तहारों वाली कमजोरी की बात नहीं कर रहे। नौजवानों को तो खुराक बेरोजगारी की चिंता में भी नहीं लग रही होगी। पर जी लगता है, खुराक तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं लग रही। वो जो एक सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने उनमें फिट कर रखा था, जो गालियों को न्यूट्रिशन में बदल देता था, लगता है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। ऊपर वाले को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। अयोध्या में तो करी सो करी, बद्रीनाथ में भी कर गया। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह हो रही है जी कि अब तो वह गालियों वाली खुराक भी नहीं लग रही। अभी देखो उन्होंने कितनी मार्मिक अपील की कि विपक्ष ने ढ़ाई घंटे तक प्रधानमंत्री का गला दबाए रखा, उन्हें बोलने नहीं दिया। लेकिन किसी ने उनकी करुण पुकार सुनी ही नहीं।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस मसले पर अपने विश्वस्तों से चर्चा की कि आखिर, गालियों की खुराक लग क्यों नहीं। उन्होंने कहा, देखो गुजरात में तो मुझे यह खुराक खूब लगती थी, अब क्यों नहीं लग रही। मुझे एक बार मौत का सौदागर कहा गया और वह खुराक ऐसी लगी कि चुनाव जीतने के लिए और कुछ करना ही नहीं पड़ा। पर अब यह खुराक क्यों नहीं लग रही। विश्वस्तों ने हिम्मत जुटा कर कहा कि सर, ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली में भी यह खुराक आपको खूब लगी है। अपनी दलील के पक्ष में सबूत देते हुए उन्होंने कहा-वो नीच वाली बात सर...याद है न आपको। प्रधानमंत्री को फौरन याद आ गया और उन्होंने दोहराया-इन लोगों ने मुझे नीच कहा, मेरी जाति को गाली दी। लेकिन फिर अफसोस करते हुए कहा-पर अब यह खुराक क्यों नहीं लग रही। बल्कि मैंने तो गिन कर बताया कि मुझे कितनी गालियां दी गईं। लेकिन उनकी हिम्मत देखो कह दिया हमें तो इतनी गालियां दी हैं कि पूरी किताब बन सकती है। एक विश्वस्त ने कहा कि अगर उन्होंने किताब छपवाई तो हम उसके कॉपीराइट पर दावा कर देंगे सर। लेकिन प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे कि कहीं सचमुच सॉफ्टवेयर में ही तो कोई गड़बड़ी नहीं आ गई है। देखना चाहिए। नहीं क्या?

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

हथकरघा

गिरिराज सिंह

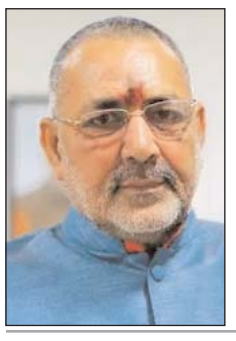

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त, 1905 को टाउन हॉल, कलकत्ता (अब कोलकाता) में आयोजित एक बैठक में हुई थी। इस ऐतिहासिक अवसर को याद करने और हमारी हथकरघा परंपरा का जश्न मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इनमें से 25 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय ने देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं।

मैं आपका ध्यान 28 जुलाई, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में हथकरघा क्षेत्र के महत्त्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने नये स्टार्टअप उद्यमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था, जो हथकरघा उत्पादों और सस्टेनबल फैशन को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का भी आग्रह किया था।

पिछले कुछ वर्षों में भारत का हथकरघा क्षेत्र निरंतरता और स्लो फैशन के प्रतीक के रूप में उभरा है। आज, मैं मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के महत्त्व पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि हम हथकरघा के पुनरुत्थान का जश्न मना रहे हैं, अतः इस अवसर पर मैं भारत के लोगों से हथकरघा क्षेत्र में सतत गति बनाए रखने की अपील करता हूं। हथकरघा बुनाई एक विरासत वाली शिल्पकला है, जो स्लो, निरंतर और नैतिक फैशन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। पिछले दशक में लगातार सरकारी प्रयासों से फास्ट फैशन से लेकर स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी गर्व से भारतीय हथकरघा पर बुने हुए कपड़े पहनते हैं, और विश्व स्तर पर उनको बढ़ावा भी देते हैं तथा हथकरघा क्षेत्र की सफलता में काफी हद तक उनका योगदान रहा है। समय आ गया है कि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल हों। मैं इस क्षेत्र के उत्थान में कताई, रंगाई और बुनकर के रूप में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता हूं तथा उनके अमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। मैं देश भर के पारंपरिक समुदायों विशेषकर महिलाओं के योगदान को पूरी तरह से मान्यता और सम्मान देता हूं, जिनके बिना हथकरघा क्षेत्र

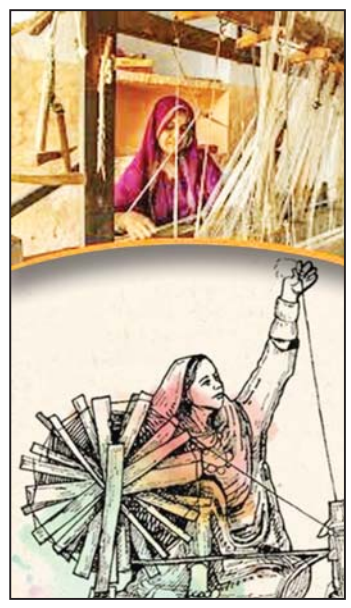

के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके योगदान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए उनके साथ गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करना जरूरी है।

बुनाई कौशल, डिजाइन नवाचार और एंटरप्रेन्योर क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रम और पहल महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाती हैं। नई तकनीकों में निपुणता प्राप्त करके और आधुनिक डिजाइनों को एक्सप्लोर करके महिला बुनकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना कर समकालीन बाजारों को आकर्षित कर सकती हैं, जो उनके शिल्प की सस्टेनिबलिटी को सुनिश्चित करेगी। एम्ब्रॉइडरी और प्रिंटिंग द्वारा मूल्य संवर्धन के माध्यम से हथकरघा को बढ़ावा देने से पारंपरिक वस्त्रों में नई जान आती है, तथा अद्वितीय और अत्यधिक वांछनीय उत्पाद तैयार होते हैं। एम्ब्रॉइडरी, सुई के काम से जुड़ी एक जटिल कला, जो हथकरघा कपड़ों में गहराई और विशेषता पैदा करती है। जरदोजी, कांथा या चिकनकारी जैसी विभिन्न तकनीकों को शामिल करके कारीगर साधारण हथकरघा वस्त्रों को विस्तृत, अद्वितीय टुकड़ों में बदल देते हैं। इससे न केवल सौंदर्य अपील बढ़ती है, बल्कि उत्पादों का बाजार मूल्य भी बढ़ता है, जिससे कारीगरों को बेहतर आर्थिक अवसर मिलते हैं।

हथकरघा उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवाचार का एकीकरण बुनकरों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और इस पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। आधुनिक प्रगति ने हथकरघा बुनाई से जुड़े शारीरिक श्रम को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक एफिशएंट और अपेक्षाकृत कम श्रम वाली हो गई है। कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (सीएडी) सॉफ्टवेयर बुनकरों को बुनाई शुरू करने से पहले उन्हें जटिल पैटर्न और रंग संयोजनों के सुव्यवस्थित प्रयोग हेतु सक्षम बनाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि त्रुटियों का जोखिम भी कम हो जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के उपलक्ष्य में इस वर्ष मैं सभी से दो प्रतिज्ञाएं लेने का आग्रह करता हूं; पहली, हम सभी हथकरघा उत्पादों के साथ सेल्फी लेंगे और उसे सोशल मीडिया पर साझा करेंगे; दूसरी, हथकरघा को अपने परिधानों एवं दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। प्रत्येक हथकरघा वस्तु अद्वितीय है, जिसे सावधानी एवं बारीकी से बुना जाता है, जो इसके बनाने वाले के समर्पण के साथ-साथ उसके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। हथकरघा उत्पादों का चयन करके हम न केवल पारंपरिक वस्त्रों की सुंदरता और विविधता को सम्मानित करते हैं, बल्कि कारीगरों की आजीविका में भी महती योगदान देते हैं।

हथकरघा उद्योग में गुणवत्ता, निरंतरता और तकनीक को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है। हर किसी को क्षेत्रीय शिल्पकारों और पारंपरिक बुनाई समुदायों का समर्थन करना चाहिए और उनके कपड़ों की खरीदारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए जिससे इन्हें बनाने वाले लोग और यह क्षेत्र लाभान्वित होता है। हथकरघा वस्तुओं के निष्पक्ष व्यापार, रीजनल मैन्यूफैक्चरिंग, सस्टेनिबलिटी और शिल्प कौशल पर ध्यान देने से इस आंदोलन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और हथकरघा बुनकरों को उनका हक मिलेगा। हथकरघा उद्योग का समर्थन करके हम न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए भी प्रयास करते हैं, और साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को भी प्राप्त करते हैं।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं)

मैं आपका ध्यान 28 जुलाई, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में हथकरघा क्षेत्र के महत्त्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने नागरिकों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का भी आग्रह किया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत का हथकरघा क्षेत्र निरंतरता और स्लो फैशन के प्रतीक के रूप में उभरा है

बांग्लादेश के सत्ता प्रतिष्ठान में खतरनाक शून्यता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने सेना द्वारा मनोनीत होने वाली अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की हामी भर दी है। लेकिन अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिन्दुओं की हत्याएं कानून-व्यवस्था की बहाली की जरूरत पर गहरा आघात कर रही हैं।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

भारत छोड़ो आंदोलन | अखिलेश आर्येन्दु

सीखने की है जरूरत

भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिकता और उसके असर को जानने के पहले उस दौर की अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाओं को जानना इसलिए जरूरी है कि सभी घटनाएं भारत की आजादी की सफलता का आधार तैयार करने का कार्य कर रही थीं। एक सितम्बर, 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ब्रिटेन इस युद्ध से अलग नहीं रह सकता था। इसलिए तथाकथित लोकतंत्र और आजादी के नाम पर ब्रिटेन ने 3 सितम्बर, 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ और समर्थन, दोनों दिया। सैकड़ों की तादाद में भारतीयों ने ब्रिटेन की सेना में सैनिक बनकर जर्मनी और जापान की सेनाओं से युद्ध किया। जिस अलोकतंत्रीय ढंग से भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, उसका विरोध कांग्रेस ने किया जरूर, लेकिन जनता के दबाव की वजह से किया। विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंकने का यह भी मकसद था कि जो जान-माल का नुकसान हो वे भारतीयों का ही हो, अंग्रेज सिपाहियों का कम से कम हो। वायसराय ने मनमाने ढंग से युद्ध की घोषणा ही नहीं की, बल्कि भारतीयों को आजाद करने का कोई आश्वासन भी नहीं दिया। इससे कांग्रेस नेताओं को घोर निराशा हुई जिसका विरोध प्रकट करने के लिए गांधी, नेहरू और स्वामी श्रद्धानंद सहित 52 कांग्रेसी नेताओं ने वायसराय से मुलाकात की। वायसराय ने भारतीय नेताओं की बातें सुनीं और 17 अक्टूबर, 1939 को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि कांग्रेस की मांग अव्यावहारिक है कि तुरंत भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। दूसरी महत्त्वपूर्ण घोषणा यह की कि सारी संवैधानिक योजना पर युद्ध के बाद ही विचार किया जाएगा। वायसराय ने तीसरी बात कही कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो उन्हें युद्ध संचालन से ताल्लुक रखने वाले विषयों पर राय देगी।

वायसराय की तीनों घोषणाओं को सभी भारतीय दलों और नेताओं ने मानने से साफ मना कर दिया। गौरतलब है कि तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और आठ राज्यों में

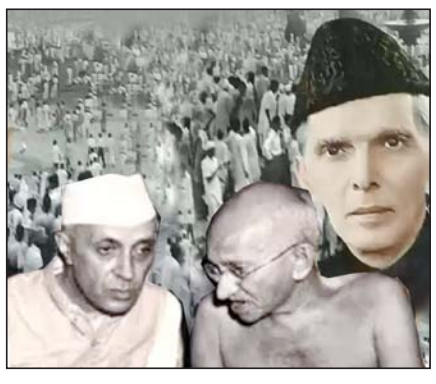

कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें अंगेजों की देख-रेख में शासन कर रही थीं। आठों प्रांतों की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और उधर प्रांतों का शासन गवर्नरों ने संभाल लिया। लेकिन इससे जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग को अपार खुशी हुई और उसने इसे 'मुक्ति दिवस' के रूप में जोर-खरोश के साथ मनाया। इससे हिन्दू-मुस्लिम नफरत का नया दौर शुरू हुआ जो लगातार पाकिस्तान के विभाजन तक लगातार दुश्मनी के रूप में जारी रहा है। अंग्रेज यही चाहते थे कि हिन्दू-मुसलमानों में ऐसी दरार पैदा कर दी जाए जो उनकी हुकूमत और नीतियों के लिए मील का पत्थर साबित हो। इतिहास बताता है कि अंग्रेज अपनी इस नीति में पूरी तरह इसलिए सफल रहे क्योंकि जिन्ना जैसा देशद्रोही और पदलोलुप राजनेता उनके मन मुताबिक कार्य करने लगा था। 1939 में वायसराय से कांग्रेस ने जो मांग भारत की आजादी के संदर्भ में रखी थी उसे वायसराय ने मानने से मना कर दिया था जिसके खिलाफ कांग्रेस की आठ प्रांतों में गठित सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और अंग्रेजों ने अपनी शर्त के मुताबिक कांग्रेस नेताओं को झुकाने का षड्यंत्र रचा था, उसमें वे पूरी तरह कामयाब रहे, लेकिन अंग्रेजों की शर्तों को उसी का कांग्रेस ने 7 जुलाई, 1940 को कार्यसमिति की बैठक, जो पूना में हुई थी (इतिहस में पूना प्रस्ताव के रूप में दर्ज) में स्वीकार करते हुए कहा गया कि ब्रिटिशा राज सत्ता को कांग्रेस मदद देने के लिए तैयार है लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत को पूरी तरह आजाद करना होगा। कांग्रेस की इस मांग को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने नहीं माना। युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय हालात अति गंभीर होते जा रहे थे। ब्रिटिश शासन को लगा कि भारतीयों को लगातार दरकिनार किया जाता रहेगा तो हालात और भी नाजुक हो सकते हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के नाम पर एक नया दिखावा किया। सर स्टैफन क्रिप्स को भारत भेजा। 22 मार्च, 1942 को क्रिप्स भारत पहुंचे। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पांच प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे गए। ये प्रस्ताव 1940 के प्रस्तावों से अच्छे थे लकिन इतने अच्छे नहीं थे कि भारतीय नेताओं को संतुष्ट कर पाते। गांधी ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया और 5 जूलाई 1942 को-'अंग्रेजों भारत छोड़ो' की घोषणा कर दी। इस आंदोलन ने भारतीयों को सीख दी कि भारत का हित जिसमें हो उसके लिए आपसी मतभेद और मनभेद भुला कर एक स्वर में आवाज बुलंद करनी चाहिए। दूसरी बात, आजाद देश से ही अवाम की प्रगति, विकास और खुशहाली का राह खुलती है। तीसरी सीख यह लेने की जरूरत है कि वतन के लिए कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

कटु औषध | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

एक गुरु मूर्तिकला में बड़े निपुण थे। उनका एक शिष्य भी उनके जैसा कुशल बनने के लिए तत्पर था। वह एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियों को बनाता और गुरु को दिखाता परन्तु गुरु ने कभी उसकी कला की प्रशंसा नहीं की, ऊपर से हमेशा उसकी कमियां निकाल कर सुधार करने की शिक्षा देते। एक दिन शिष्य ने एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसे जमीन में गाड़ दिया! जब गुरु को शिष्य की युक्ति के अनुसार यह मूर्ति जमीन से निकली हुई मिली तो गुरु ने सामने से शिष्य से कहा, 'कितनी सुंदर, आकर्षक और सौम्य मूर्ति है! तुम्हें भी ऐसी बनानी सीखनी चाहिए।' 'मैंने ही इसे बना कर यहां रखा था' शिष्य ने अपनी जीत के गुमान में सब कह दिया। अपने कड़वे शिक्षा के शब्दों की इस प्रतिक्रिया को गुरु समझ गए। गुरु ने कहा-'अब तुम्हारी प्रगति पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक तुम मेरे कड़वे शिक्षा वचनों से प्रेरित होकर निरंतर सुधार करते जा रहे थे, किंतु अब वह प्रक्रिया ठहर जाएगी।' इस प्रकार, दयालु गुरु हमें कड़वी सच्चाई बता कर हमारी गलतियों को सुधारते हैं, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे मुमुक्षु का भ्रम दूर हो जाता है, और वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण दुःखी शरणागत शिष्य अर्जुन को पहले कायर और अयोग्य कहकर डांटते हैं। उसकी सारी तर्क भरी बातों को प्रज्ञावाद (दिखावा) घोषित कर देते हैं। उसकी दया को अधर्म में स्थान देते हैं। यहां अमृत के समान मीठा फल देने वाली गीता के उपदेश का आरंभ कड़वाहट भरा जरूर लगेगा। भगवान के ये शब्द कटु औषधि के समान थे, जो अर्जुन के कर्त्तव्यहीनता रूपी गंभीर रोग के निराकरण के लिए थे। हम भी अर्जुन की तरह रोगी हैं, किंतु उस रोग को मिटाने के लिए हम औषधि भी सरल, सीधी और मीठी मांगते हैं, लेकिन महंतस्वामी महाराज कहते हैं कि जीवन के तूफानों से जूझने के लिए विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता के लिए केवल लाड़-प्यार नहीं चलता। अपने शिष्य को जीवन के कठोर सत्य का सामना करने के लिए वज्र बनाना आवश्यक है। जी हां, पैरों में चुभे कांटे को फूंक मार कर नहीं निकाल सकते, उसे निकालने के लिए तीक्ष्ण सूई जरूरी है।

रीडर्स मेल

हथकरघा को प्रोत्साहन जरूरी

हथकरघा उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा रहा है। हाथ या पैर की मदद से निर्मित सामग्री को हथकरघा की श्रेणी में रखा जाता है। देश के हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने एवं दुनिया भर में इसे ब्रांड के रूप में पेश करने के लिए प्रति वर्ष सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। हथकरघा उद्योग सीधे तौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करता है। आज फैशन के दौर में विदेशी वस्त्रों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। हम सभी को हथकरघा उद्योग से निर्मित वस्त्रों को पहनावे में शामिल करना चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।

हिमांशु शेखर, गया

भारत पर नस्लभेदी निशाना

भारतीय उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मैच के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब वह मैच नहीं खेल पाएंगी। रिपोर्ट्स में खबर आई है कि वह वेट के दौरान 50 किलोग्राम से लगभग 100 ग्राम अधिक निकलीं। एक भारतीय कोच ने कहा-आज सुबह उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। पहले हॉकी टीम के एक खिलाड़ी को क्वार्टरफाइनल की रेस में रेड कार्ड दिखा कर बाहर किया और भारत को 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। फोगाट को मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर कर दिया गया। 100 ग्राम वजन तो बाथरूम करने से ही कम हो सकता है। अंडर गारमेंट्स का वजन ही 100 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए लगता है कि ओलंपिक में भी नस्लभेद की गहरी साजिश चल रही है और भारत को इसका निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय टीम मैनेजर को इस पर आपत्ति उठाना चाहिए। एक खिलाड़ी के वर्षों के कठोर परिश्रम को यूं लात मार कर बाहर नहीं किया जा सकता!

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम, मप्र
letter.editorsahara@gmail.com

भूल सुधार

राष्ट्रीय सहारा के दिनांक 5 अगस्त, 2024 के अंक के संपादकीय 'मुकदमेबाजी में समझौता' की प्रथम पंक्ति में भूलवश भारत के प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री जस्टिस चला गया है। इसके लिए हमें खेद हैं, और इस भूल के लिए क्षमाप्रार्थी हैं। इस पंक्ति को 'भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दो टूक कहा है कि लोग अदालतों से 'इतने तंग' आ गए हैं कि वे बस समझौता चाहते हैं' पढ़ा जाए।

समूह संपादक

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-33, अंक 356
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

शेख हसीना को भारत में शरण

बंगलादेश ऐसा राष्ट्र है जिसके अस्तित्व का आंशिक श्रेय भारत को भी दिया जा सकता है क्योंकि 1971 में इसका वजूद कायम करने के लिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं से युद्ध लड़ा था। यह दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बंगलादेश के अस्तित्व के लिए सम्पूर्ण भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी और अमेरिका जैसी महाशक्ति से बिना डरे सैनिक व कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर यह युद्ध जीता था। हम सभी जानते हैं कि बंगलादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महान जन नायक शेख मुजीबुर्रहमान का जब दिल्ली में नागरिक सम्मान किया गया था तो उन्होंने 'आमार सोनार बांग्ला' का उद्घोष करते हुए संदेश दे दिया था कि 1947 में जिस हिन्दू-मुस्लिम द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त पर मुहम्मद अली जिन्ना ने भारत के दो टुकड़े किये थे उसी सिद्धान्त को उनके देश के लोगों ने कब्र में गाड़ कर पूर्वी पाकिस्तान को बंगलादेश बना दिया है। बंगलादेश का निर्माण पिछली सदी के इतिहास की ऐसी अपूर्व घटना थी जिसने दो सौ साल तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों की मजहबी हिन्दू-मुस्लिम विद्वेश की साजिश को भी तार-तार कर दिया था।

1857 के प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हिन्दू- मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए बहुत ताबड़तोड़ मेहनत और साजिशें रची थीं। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक बारगी न केवल इतिहास को उलट दिया था बल्कि भारतीय उप महाद्वीप की बांग्ला संस्कृति की ताकत का अन्दाजा भी दुनिया को कराया था। आज उन्हीं की पुत्री शेख हसीना वाजेद को मजबूरी में भारत में शरण तब लेनी पड़ रही है जबकि विगत 5 अगस्त तक वह अपने देश की चुनी हुई प्रधानमन्त्री थीं। बंगलादेश में जिस तरह उनका तख्ता पलट किया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया उसी से पता लगता है कि बंगलादेश में कुछ विदेशी बाहरी शक्तियां सक्रिय हैं जो अपने मनमाफिक शासन व्यवस्था चाहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत शुरू से ही बंगलादेश के शेख परिवार के लिए दूसरा घर है। खासकर शेख हसीना के लिए तो यह उनका दूसरा घर ही रहा है। भारत में आकर वह स्वयं को चारों तरफ से सुरक्षित अनुभव करती हैं। पहले भी 1975 से 1981 तक वह भारत में ही तब रहीं जब उनके माता- पिता समेत उनके परिवार के सात लोगों का कत्ल सैनिक अफसरों ने कर दिया था। मगर बंगलादेश के लोग शेख मुजीबुर्रहमान को न केवल राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं बल्कि उन्हें अपने देश का महा जननायक भी समझते हैं लेकिन शेख हसीना के बंगलादेश से दिल्ली आने के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने उनकी मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया। यह कार्य निश्चित रूप से वे लोग ही कर सकते हैं जिन्हें अपने देश की महान विरासत से प्यार न हो। बंगलादेश की प्रधानमन्त्री के रूप में शेख हसीना ने पूरे 20 वर्ष तक शासन किया है और इस दौरान उन्होंने अपने देश में सक्रिय पाकिस्तान परस्त ताकतों को कभी उभरने नहीं दिया और इस्लामी जेहादियों को प्रभावी नहीं होने दिया। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई की शह पर बंगलादेश की धरती से क्रियाशील इंडियन मुजाहीदीन जैसी संस्था के उन्होंने पर कतरने में जरा भी संकोच नहीं किया। बंगलादेश की धरती से जो भी भारत विरोधी कार्य जमाते इस्लामी जैसी संस्था की ओर से किये जाते थे उसे उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया और भारत के साथ सर्वदा मधुर सम्बन्ध रखे और भारत से लगी चार हजार कि.मी. से अधिक की सीमा पर सर्वदा शान्ति व सद्भाव बनाये रखा। अब कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से राजनीतिक शरण मांगी थी जिसे ब्रिटेन के नियम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पहले से वैध वीजा के साथ ब्रिटेन में होना जरूरी है।

ब्रिटेन अपने देश में पहले से आये हुए व्यक्तियों को ही राजनीतिक शरण देता है। बंगलादेश के सम्बन्ध में अमेरिका के रुख को सभी भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे उसके सैनिक व कूटनीतिक विरोध के बावजूद 1971 में बंगलादेश का निर्माण हुआ था। अत: बेशक अमेरिका स्वयं को दुनिया को सबसे पुराना लोकतन्त्र कहता हो मगर वह शेख हसीना को शरण नहीं देगा। अन्य यूरोपीय देशों के नियम भी ब्रिटेन से मिलते-जुलते हैं। अत: भारत ही ऐसा देश बचता है जो शेख हसीना को ससम्मान शरण पहले की भांति दे सकता है परन्तु भारत को बंगलादेश से भी अपने सम्बन्ध अच्छे रखने हैं।

ब्रिटेन अपने देश में पहले से आये हुए व्यक्तियों को ही राजनीतिक शरण देता है। बंगलादेश के सम्बन्ध में अमेरिका के रुख को सभी भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे उसके सैनिक व कूटनीतिक विरोध के बावजूद 1971 में बंगलादेश का निर्माण हुआ था। अत: बेशक अमेरिका स्वयं को दुनिया को सबसे पुराना लोकतन्त्र कहता हो मगर वह शेख हसीना को शरण नहीं देगा। अन्य यूरोपीय देशों के नियम भी ब्रिटेन से मिलते-जुलते हैं। अत: भारत ही ऐसा देश बचता है जो शेख हसीना को ससम्मान शरण पहले की भांति दे सकता है परन्तु भारत को बंगलादेश से भी अपने सम्बन्ध अच्छे रखने हैं। बेशक अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि बंगलादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी क्योंकि राजनैतिक परिस्थितियां बहुत अस्थिर हैं परन्तु जो खबरें मिल रही हैं उनके अनुसार एक अन्तरिम सरकार का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व नौबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं परन्तु पीछे से सेना ही इस प्रशासन की बागडोर पकड़े रहेगी और कहा नहीं जा सकता कि चुनाव कब तक होंगे जबकि बंगलादेश की मौजूदा संसद को राष्ट्रपति से भंग करा दिया गया है। बंगलादेश में पहले भी आधा दर्जन बार सेना का शासन रहा है जिसे समाप्त कर लोकतन्त्र स्थापित करने में शेख हसीना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है परन्तु वक्त ने ऐसी करवट ली कि लोकतन्त्र के नाम पर ही उनके विरुद्ध छात्र आन्दोलन चलवा कर उनका ही तख्ता पलट करवा दिया गया जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अत: स्वाभविक रूप से उन्हें भारत ही सबसे सुरक्षित शरण स्थल लगा और वह दिल्ली आ गईं। प्रकट रूप से यह भारत की सरकार की मर्जी से ही हुआ है। बंगलादेश के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और चाहता है कि इस मामले में पूरा भारत एक स्वर से बोले। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

NewsPaperPaid

कामयाबी के द्वार को

गीता पाढा

"वो पुराने पेड़ ही जानते हैं धूप की मार को,
पूरे वर्ष में आती जाती पतझड़ और बसंत की फुहार को,,
बूढ़े बरगद के अनुभव से सीख सकते हैं
राहगीर के आदर सत्कार को,
और अक्सर असफलता के दौर से गुजरे लोग ही
खोलते हैं सैकड़ों के लिए कामयाबी के द्वार को...।"

मर्यादाएं

चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

लीक होता इंफ्रास्ट्रक्चर

यह वीडियो देखना बहुत कष्टदायक था। हमारी नई ख़ूबसूरत संसद की छत से पानी टपक रहा था। पानी गिर कर संसद के मकर द्वार तक पहुंच गया था। टपकते पानी के नीचे नीली बाल्टी रखी गई थी पर पानी बाल्टी भरने के बाद फ़र्श पर फैल गया था। पानी के नीचे बाल्टी रखना भारतीय घरों में सामान्य बात है। हमारी छतें बरसात में टपकती हैं। पर यह तो हमारी नई संसद है, आजाद भारत की आकांक्षाओं की प्रतीक है। इसकी भी छत टपकने लगी। लोकसभा के सचिवालय ने सफ़ाई दी कि भारी बारिश के कारण संसद की लॉबी के उपर लगे शीशे के गुंबद को फ़िक्स करने वाले एडहेसिव (चिपकाने वाले पदार्थ) के हट जाने से लॉबी में 'पानी का मामूली रिसाव' हो गया था जिसका इलाज कर लिया गया है और अब वह रुक गया है। यह तो सही है पर सवाल तो है कि एडहेसिव खिसका क्यों? 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने संसद भवन, जिसका उद्घाटन एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धूमधाम से किया था, में ऐसी लापरवाही क्यों हो कि सोशल मीडिया पर संसद भवन के अंदर पानी सैर करता नज़र आए? इसके बग़ल में पुराना संसद भवन है, कृषि भवन है, रेल भवन है। सब ठीक ठीक हैं।

यह मामला गम्भीर इसलिए है कि हाल ही में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिससे पता चलता है कि जिसे वर्क कल्चर अर्थात कार्य संस्कृति कहा जाता है, उसकी देश में कितनी शोचनीय हालत है। बिहार में पन्द्रह दिनों में 12 पुल बह गए। सरकार ने 15 इंजीनियर निलंबित कर दिए पर सवाल है कि ऐसे हादसे हो ही क्यों? पहले क्यों नहीं देखा गया कि यह पुल खतरे में है? निश्चित तौर या तो घटिया मटीरियल लगाया गया होगा या नीचे खदान के कारण नींव कमजोर हो गई थी। दोनों में ही उच्च स्तर की मिलीभगत लगती है और निलम्बन से भी क्या होगा? जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो चुपचाप उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। आख़िर इस हमाम में सब नंगे हैं, कौन किस पर सख्त एक्शन लेगा? ज़रूरत तो थी कि अरबों रुपए बर्बाद करने वालों को जेल भेजा जाता पर जैसे बाइबल में कहा गया है, पहला पत्थर वह उठाए जो खुद पाक साफ़ हो !

जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, उस पर हमारे देश में बहुत काम किया गया पर जिसे क्वालिटी कहा जाता है उससे समझौते के भी समाचार मिलते रहते हैं। मार्च 2016 में कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानन्द फ्लाइओवर का 150 मीटर का स्टील-स्पैन गिर गया। 27 मारे गए और 80 घायल हो गए। हाल ही में दिल्ली के प्रसिद्ध इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट के टी-1 की छत का एक हिस्सा बरसात के पहले दिन टूट कर गिर गया और एक व्यक्ति मारा गया। इस एयरपोर्ट को एक प्रतिष्ठित कम्पनी बना रही है। उसके बाद जबलपुर, रायकोट के एयरपोर्ट की भी छत गिर गई। यह सब तीन दिन में हुआ। पहले गुआहाटी और पोर्ट ब्लेयरएयरपोर्ट में भी छत ढह चुकी है। इस सरकार ने बहुत एयरपोर्ट बनाए और देश के कोने कोने तक उड़ानें पहुंचाई पर कुछ एयरपोर्ट की छतें गिरना तो अविश्वास पैदा करता है। यह एयरपोर्ट तो कम से कम 75 वर्ष के लिए सुरक्षित होने चाहिए।

अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ में बरसात में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। कई जगह से मार्ग धंस गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि पहली बरसात में मंदिर में जल भराव हो गया। यह कैसी लापरवाही है कि इतने उत्साह और श्रद्धा के साथ जो निर्माण हुआ है वहां भी कमी रह गई? जिस भव्य 'भारत मंडपम' में जी-20 सम्मेलन हुआ वहां पानी भर गया और कुछ समय के लिए वह बंद करना पड़ा। बरसात हर साल आती है पर हम बेतैयार क्यों पाए जाते हैं? हमारा हर महानगर पानी में डूब जाता है। मुम्बई, बैंगलोर, दिल्ली तो कुख्यात है। मुम्बई में हर साल दो तीन बड़ी इमारतें गिरती हैं। बैंगलोर में हम देख चुके हैं कि जिनके घरों में करोड़ों रुपए की कारें खड़ी थी उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा कर बाढ़ से निकाला गया। दिल्ली में सड़कों पर बाढ़ के पानी के कारण चार होनहार जाने चली गई हैं। नीलेश राय जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपने कोचिंग सैंटर के पास पानी से गुजरते वक्त इलैक्ट्रोक्यूट हो गया। फिर एक कोचिंग सैंटर की बेसमेंट में पानी भरने से तीन और छात्र डूब गए। यह भी सामान्य है कि जो बेसमेंट पार्किंग या किसी और काम के लिए बनाई जाती है उसका दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बेसमेंट में लाईब्रेरी बननी थी, पर रिहायश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब सड़क से बह कर पानी एक दम दाखिल हो गया तो बच्चे बाहर नहीं निकल सके। और व्यवस्था का हाल देखिए कि इस हादसे के लिए एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया कि उसने वाहन इतनी तेज़ी से चलाया कि पानी उछल कर अंदर घुस गया! उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं जिन्होंने सड़कों पर पानी इकट्ठा होने दिया या बिजली की नंगी तारें छोड़ दी। इस चालक को तो रिहा कर दिया गया है पर सरकारी तंत्र केअपराधियों से ध्यान हटाने के प्रयास पर अदालत ने भी कटाक्ष किया, अब आप पानी का चलान करोगे?

हमारा जर्जर होता बुनियादी ढांचा चिन्ता का विषय है। मुम्बई और दिल्ली जैसे शहर और दबाव सहन नहीं कर सकते। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग वही है जो आज़ादी के समय था।हर शहर में ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है जबकि इतिहास बताता है कि प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्था में भी पानी की निकासी का विशेष प्रबंध किया जाता था। मुम्बई में हर बरसात में उसकी लाइफ़लाइन, स्थानीय रेल व्यवस्था, ठप्प हो जाती है। बेंगलोर ने तो सुसाइड कर लिया है। एक समय यह शहर उभर रहे भारत का प्रतीक था। दुनिया की सब बड़ी आईटी कम्पनियों के दफ्तर यहां हैं पर अत्याधिक निर्माण के कारण शहर ने खुद को तबाह कर लिया। पानी के निकास की जगह नहीं रही। बहुत से तालाब हुआ करते थे अधिकतर पर निर्माण हो चुका है। परिणाम है कि जहां बरसात में बैंगलोर पानी में डूब जाता है वहां गर्मियों में प्यासा रह जाता है और पानी टैंकरों से सप्लाई करना पड़ता है। दिल्ली तो मृत्यु शय्या पर लगता है। या लोग गर्मी में झुलस रहे हैं, या प्रदूषण से दम घुट रहा है, या पानी में डूब रहें है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि ऊंची इमारतों की तो इजाज़त दी जारही है पर सही नाली नहीं बनती। उपर से एलजी और सीएम के राजनीतिक द्वन्द्व के कारण प्रशासन अनिश्चित है। सीएम जेल में हैं, पर ऐसे तो प्रशासन नहीं चल सकता।

उपर से जलवायु परिवर्तन अपनी तबाही ला रहा है। वायनाड में भूस्खलन से पूरा गांव मलबे में दब गया। लोग सो रहे थे कि आफ़त आगई। बहुत समय से केरल को चेतावनी दी जा रही है कि उसका पर्यावरण और परिस्थिति नाज़ुक है इसलिए निर्माण पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लगभग आधे केरल में पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र है जहां नाज़ुक ढलान है लेकिन इसके बावजूद अनियंत्रित निर्माण किया जा रहा है। गृहमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई थी कि वायनाड जैसी घटना हो सकती हैं पर मुख्यमंत्री इसका प्रतिवाद करते हैं। यह हमारी एक और कमजोरी है कि हर बात पर राजनीति होती है, हादसों पर भी। हमारे ढहते शहर तुच्छ राजनीति का मामला नहीं। दो और प्रदेश हैं जहां बहुत प्राकृतिक मार पड़ रही है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में फिर भूस्खलन से जाने गईं है। गांव बह गया। पार्वती नदी में बड़ी इमारत को गिरते देखा गया। निर्माण करते वक्त लोग भी ध्यान नहीं रखते। विकास और सड़कों के लिए जो तोड़ फोड़ की जा रही है वह कई बार महंगी साबित होती है। जिन पगडंडियों पर कभी खच्चर चलते थे वहां अब कारें दौड़ती हैं। तबाही तो होगी ही।

2024 में जितने पेपर लीक हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल टेस्टिंग एजंसी (एनटीए) को बड़ी फटकार लगाई है। नीट-यूजीसी परीक्षा में 24 लाख बच्चे बैठे थे पर कई जगह से पेपर लीक हो गया। यह एक नया रैकेट है जहां भ्रष्ट अधिकारी और अध्यापक, कोचिंग सैंटर वालों से मिल कर बच्चों की सफल होने की बेताबी का फ़ायदा उठातें हैं। कोचिंग सैंटर ही कोई सौ करोड़ का धंधा बन चुके हैं। कोटा में लगातार हो रही आत्महत्या के बावजूद इन्हें नियंत्रित करने का कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जाता। हमारी शिक्षा व्यवस्था का पतन हो रहा है। विकेंद्रीकरण की बहुत ज़रूरत है। वन नेशन-वन एवरीथिंग नहीं होने वाला। अगर देश ने तरक्की करनी है तो इस तरफ़ बहुत सोच की ज़रूरत है।

असली समस्या है कि समाज में पतन आ गया है जिसके चारों तरफ़ दुष्परिणाम निकल रहे हैं। हमारे नगर निगम और पालिकाएं भ्रष्टाचार और अकुशलता के गढ़ बन चुके हैं। अनियंत्रित और अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। सरकारी अफ़सर भी पुराने जैसे समर्पित नहीं रहे। जिस तरह फ़र्ज़ी और झूठे दस्तावेज से पूजा खेडकर आईएएस में प्रवेश पाने में सफल रही, से भी पता चलता है कि व्यवस्था का दुरुपयोग कितना आसान है। सवाल यह भी है कि पूजा खेडकर जैसे और फ्राड हमारी सिविल सर्विस में कितने हैं? और वह इतनी आसानी से धूल झोंकने में कैसे सफल रही? क्या कोई इलाज है? कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने पोस्ट डाली है, 'पेपर लीक बाहर और पानी लीक अंदर'। यह अतिशयोक्ति हो सकती है पर यह भी सही है कि लीक होती व्यवस्था के कारण इसकी कार्यकुशलता और शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। इन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए। जवाबदेही सख्ती से तय होनी चाहिए। यह न हो कि बरसात के ख़त्म होने पर सब कुछ भुला दिया जाए और अगले साल फिर देश को नए हादसों का गवाह बनना पड़े। या नई नीली बाल्टी देखनी पड़े।

शहीद उधम सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नही?

सिख सियासत

सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बाद अगर किसी को शहीद-ए-आजम का खिताब मिलना चाहिए तो वह शहीद उधम सिंह हैं, जिन्हें 13 मार्च 1940 को भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओशडायर की हत्या के लिए जाना जाता है। यह हत्या 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसके लिए सीधे तौर पर ओश्डायर जिम्मेदार था। इसमें सजा के तौर पर उधम सिंह पर हत्या का मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया और जुलाई 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। मगर सरकारी तौर पर आज तक ना तो भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिला और ना ही उधम सिंह को। उ.प्र. में जब मायावती की सरकार आई तो उनके द्वारा शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में एक जिले का नाम उनके नाम पर रखा गया था जिसे आज उधम सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। शहीद उधम सिंह जैसे वीरों की बदौलत ही भारत को आजादी मिली थी मगर बदकिस्मती से सत्ता पर काबिज वह लोग हो गये जिनका दूर-दूर तक आजादी की लड़ाई से कोई वास्ता नहीं था उल्टा उन्होंने आजादी के परवानों का हमेशा मजाक ही उड़ाया था। शहीद उधम सिंह को देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनके इस कार्य की निंदा करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण बताया गया था। हालांकि, 1962 में, पंडित नेहरू ने अपना रुख बदल लिया और अपने नए बयान के साथ उधम सिंह की सराहना की और कहा था कि मैं शहीद-ए-आजम उधम सिंह को श्रद्धा के साथ सलाम करता हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूमा।

देश को आजाद हुए भले ही 77 वर्ष बीत चुके हैं मगर आज भी ऐसी सोच वाले लोग इस देश में हैं जो कि आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों को शहीद मानने को भी तैयार नहीं हैं मगर वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध समाजसेवी एम एम पाल सिंह गोल्डी जैसे लोग भी हैं जो कि स्वयं स्वतंत्रता सैनानी परिवार से सम्बन्ध रखते हैं, उन्होंने शहीद उधम सिंह की शहादत को सलाम करते हुए उनके श्रद्धांजलि दिवस पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में अपनी कमाई से विज्ञापन दिया ताकि देश की युवा पीढ़ी को शहीद उधम सिंह की शहादत और उनकी वीरगाथा की जानकारी मिल सके।

शिरोमणि कमेटी वोटरों की कम होती संख्या

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव बीते कई वर्षों से लम्बित है जिसे करवाने के लिए सरकार पर निरन्तर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा नए चुनावों के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया कुछ माह पूर्व शुरू की गई थी जिसके लिए बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई थी जिन्होंने घर-घर जाकर वोट बनाने का कार्य करना था। मगर देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं किया जा रहा। अब इसके पीछे क्या सोच काम कर रही है यह चिन्तन का विषय है। पिछले चुनावों के दौरान सिख वोटरों की संख्या 56 लाख के करीब थी जो कि इतने वर्ष बीतने के बाद कम से कम दुगनी तो होनी ही चाहिए थी मगर गिनती घटकर आधी रह गई है। यहां सवाल यह बनता है कि कहीं किसी साजिश के तहत तो सिख वोटरों की गिनती कम नहीं दिखाई जा रही हो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह बाठ जो कि पिछले कुछ समय से पंजाब की सिख राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं उनकी मानें तो वह सरकारी तंत्र को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन अधिकारियों को सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी है वह घर-घर जाने के बजाए अपने कार्यालयों में बैठकर वोट बनाने का कार्य करते हैं यां फिर कुछ ऐसे अधिकारी इस कार्य में लगाए गये हैं जो घरों में पहुंच तो रहे हैं मगर उनके पास वोटरों की फोटो खींचने या अन्य दस्तावेज बनाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं रहते, अब गांवों में भोले भाले लोग अपने पास पुख्ता दस्तावेज तो रखते नहीं ऐसे में उनके वोट नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा कारण इसमें यह भी हो सकता है कि आज की तारीख में ज्यादातर लोगों की वोट बनाने के प्रति कोई रुचि ही नहीं रह गई। सिख युवाओं का पतित होना यां फिर विदेशों को पलायन कर जाना भी सिख वोटरों की कमी का एक बड़ा कारण हो सकता है। जो भी हो अगर इसका सही आंकलन नहीं किया गया तो आने वाले समय में सिख समुदाय पंजाब में ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ सकता है। सिख राजनीति के माहिरों की मानें तो अभी तक जो वोटर लिस्ट तैयार हुई है उसमें ज्यादातर वोट अकाली दल के नुमाईंदों ने ही बनवाए हैं अगर इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव हो जाएं तो उसका पूरा फायदा अकाली दल को मिलने वाला है। इससे पहले भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के गठन से लेकर आज तक शिरोमणि अकाली दल का ही कब्जा कमेटी पर रहा है मगर इस बार कई पार्टियां और सरकारें भी अपने नुमाईंदे खड़े करने की सोच रखे हुए हैं, अकाली दल से बागी हो चुके नेता भी अकाली दल को टक्कर देने का मन बनाए हुए हैं जिससे अकाली दल की राह भी हालांकि आसान नहीं होगी। मगर सिख समुदाय की बेहतरी के लिए सभी पार्टियों और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को चाहिए कि इसे गंभीरता से लेते हुए अपने क्षेत्र के लोगों को वोट बनवाने के लिए जागरुक अवश्य करना चाहिए जिससे कि समय रहते सभी सिखों की वोट अवश्य बन सकें।

सिख मार्शल आर्ट ''गतका''

गतका जिसे अब सिख मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है यह सिखों का पारंपरिक खेल भी है और युद्ध के मैदान में दुश्मनों से लड़ने के लिए भी इसकी जानकारी दी जाती थी। वैसे तो इसकी शुरुआत गुरु साहिबान के समय से ही हो गई थी। गुरु गोबिन्द सिंह जी तो महल्ला करवाकर भाव गतका की अलग अलग टीमें बनाकर उनमें मुकाबले भी करवाया करते। देखा जाए तो आज के समय में भी गतका सीखने वाले अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकते हैं और खासकर महिलाओं को इसकी शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। कुछ समय पूर्व तक गतका केवल गुरुपर्व के मौके पर निकलने वाले नगर कीर्तनों में ही खेला जाता था। कई संस्थाएं हैं जो गतका सीखने के इच्छुक युवाओं को गतका की सिखलाई देते हैं जिनमें बुड्ढा दल गतका अकादमी और शिरोमणि गतका फैडरेशन मुख्य भूमिका में है। हाल ही में इन संस्थाओं के द्वारा 96 करोड़ी गतका कप करवाया गया। इससे पूर्व पूर्वी दिल्ली में भाजपा के सिख नेता गुरमीत सिंह सूरा के द्वारा भी इन संस्थाओं के साथ मिलकर पूर्वी दिल्ली गतका

कप का आयोजन किया गया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अधीन चलने वाले स्कूलों में भी बच्चों को गतका की सिखलाई दी जाती है। अब हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को गतका की सिखलाई अवश्य दें।

सिख विधायक का अमरीका में सम्मान

दिल्ली के तिलक नगर से तीसरी बार के विधायक जरनैल सिंह जिन्हें अमरीका में होने वाले लैजिस्लेटिव समिट 2024 के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बेहतर विधायक के तौर पर भेजा गया और उनका अमरीका में भरपूर सम्मान भी हुआ। जरनैल सिंह का इस कांफ्रेंस में जाना समूचे सिखों के लिए गर्व की बात है। हालांकि उनके साथ 2 और विधायक इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं जो कि संसार के अलग अलग देशों से आए विधायकों के साथ विचार विमर्श करते हुए अपने क्षेत्र में और बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम होंगे। जरनैल सिंह का अमरीका में रहने वाले और खासतौर पर भारत से वहां पहुंचे सिखों के द्वारा भी सम्मान किया जा रहा है। जरनैल सिंह केजरीवाल सरकार में बतौर सिख तीसरी बार विधायक चुनकर आए मगर अफसोस कि आज तक उन्हें मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया गया जबकि इससे पहले भाजपा यां कांग्रेस की सरकारें जब भी रही एक ना एक सिख को मंत्रिमण्डल में जगह अवश्य दी जाती थी।

गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 831 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद

- **यह कार्रवाई सूरत में ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद की गई है, आरोपियों में मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल शामिल हैं**

मुंबई, (पंजाब केसरी): गुजरात एटीएस ने बुधवार को महाराष्ट्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एटीएस ने 831 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग बरामद की है। यह कार्रवाई सूरत में ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद की गई है। गुजरात एटीएस की टीम ने मुंबई के भिवंडी में एक फ्लैट से 792 किलो लिक्विड एमडी ड्रग्स बरामद की है। ड्रग्स की कीमत 831 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोपियों में मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल शामिल हैं, जो पहले स्मगलिंग में भी शामिल थे। इन दोनों आरोपियों का संपर्क सुनील यादव से है, जो सूरत केस में आरोपी है। दुबई के स्थानीय पेडलर के साथ मिलकर ये लोग एमडी ड्रग बना रहे थे। तीन भाई मिलकर ड्रग बनाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा, एटीएस ने भरूच से ट्रामाडोल नामक दवाई का उत्पादन करने वाले पंकज राजपूत और निखिल कपूरिया को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 31 करोड़ रुपये का माल बरामद किया गया है। यह दवाई आतंकी संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाती है। मुख्य आरोपी केवल गोंडलिया और हर्षित की तलाश अभी भी जारी है। ये लोग इस ड्रग को अफ्रीका में भेजते थे। गुजरात एटीएस के एसपी सुनील जोशी ने बताया कि जांच के क्रम में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी लोकल पेडलर के संपर्क में थे और उन्हें ड्रग सप्लाई करते थे। जो कंटेनर जब्त की गई है उसे अफ्रीका भेजा जाना था। बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को गुजरात एटीएस की एक टीम ने सूरत के पलसाना में एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में ड्रग्स और नशीले पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया था। एटीएस की टीम को पलसाना के कारेली में स्थित फैक्ट्री में ड्रग्स की सूचना मिली थी। एटीएस को पता चला था कि ड्रग्स का गोरखधंधा रिहायशी इलाकों के बीच एक फैक्ट्री में चल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। इस दौरान तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

आपदाओं का कहर

भारत उन देशों में है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. हमारे देश में अत्यधिक लू वाले दिनों की संख्या 30 वर्षों में 15 गुना बढ़ चुकी है. बीते दशक में ही यह बढ़ोतरी 19 गुना रही है. मानसून के मौसम में गर्मी जैसी स्थिति में भी वृद्धि हो रही है. आइपीइ ग्लोबल एवं एसरी इंडिया द्वारा किये गये नये अध्ययन में बताया गया है कि देश के 84 प्रतिशत से अधिक जिले अत्यधिक लू से प्रभावित हो सकते हैं तथा इनमें से 70 प्रतिशत जिलों में बहुत अधिक बरसात की तीव्रता और आवृत्ति भी बढ़ रही है. प्रकृति के ऐसे कहर का कारण बीती सदी में तापमान में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि है. अत्यधिक बरसात से एक ओर शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या आम होती जा रही है, तो दूसरी ओर भूस्खलन जैसी खतरनाक आपदाएं बढ़ रही हैं. कुछ दिन पहले केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई तथा अनेक इलाकों का पूरी तरह विनाश हो गया. दिल्ली और आसपास के शहरों में बहुत अधिक बारिश से आयी बाढ़ जानलेवा साबित हुई. हमारे देश में अच्छे मानसून की बड़ी अहमियत है क्योंकि यह पानी का प्रमुख स्रोत है. लेकिन बरसात के मौसम में गर्मी का बढ़ता प्रकोप एक गंभीर चिंता की वजह बनता जा रहा है. इससे खेती के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है. कुछ वर्षों से जाड़े के मौसम में औसत तापमान बढ़ने से रबी फसलों के उत्पादन में कमी आयी है. औचक बारिश और अधिक तापमान खरीफ फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं. हीटवेव से भी लोग मर रहे हैं और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. इससे कार्यक्षमता में भी कमी आ रही है तथा स्वास्थ्य सेवा पर दबाव बढ़ रहा है. स्थिति की गंभीरता का अनुमान अध्ययन के इस निष्कर्ष से लगाया जा सकता है कि 2036 तक हर 10 में से आठ भारतीय प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में होगा. एक अन्य अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि पिछले साल ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा, जब देश के किसी न किसी हिस्से में कोई आपदा नहीं आयी. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति के अनुसार, धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रोकने के लिए 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसदी तक कटौती करनी होगी. धरती के गर्म होने की गति पहले के आकलनों से कहीं अधिक है. आज धरती 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है. इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के हिसाब से हमें अपने को ढालने के उपाय करने चाहिए. विभिन्न आंकड़ों और अध्ययनों की सहायता से ऐसा किया जा सकता है.

बरसात के मौसम में गर्मी का बढ़ता प्रकोप एक गंभीर चिंता की वजह बनता जा रहा है.

रुक नहीं रहे ब्रिटेन में दंगे

शिवकांत
पूर्व संपादक, बीबीसी हिंदी
shivkant.sharma@gmail.com

लंदन से विशेष

गनीमत इस बात की रही कि अपने अतिवाद के लिए कुख्यात एक-दो नेताओं को छोड़कर किसी ब्रिटिश नेता ने या मुख्यधारा के मीडिया ने अपराधी और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर राजनीति या अटकलबाजी करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि भारत में होता रहता है. सरकार और विपक्ष ने न केवल सारी जिम्मेदारी पुलिस पर छोड़ी, बल्कि उसका सार्वजनिक रूप से पूरा समर्थन भी किया. भारत के सभी पक्षों को इससे सीख लेनी चाहिए.

अवैध आप्रवासियों और शरणार्थियों का विरोध करने वाले दक्षिणपंथी गुटों ने गत सप्ताह लंदन और मैनचेस्टर समेत ब्रिटेन के 20 से अधिक शहरों में उग्र प्रदर्शन किये, जिनमें कई जगह दंगे हुए और 50 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हो गये. प्रधानमंत्री सर किएर स्टामर को आपातकालीन कोबरा समिति की बैठक बुलानी पड़ी. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा और ऑनलाइन अफवाहबाजी और मिथ्या प्रचार को भी अपराध की श्रेणी में रखकर सजाएं दी जायेंगी. दंगे होना ब्रिटेन में कोई नयी बात नहीं है. दो सप्ताह पहले लीड्स और पूर्वी लंदन में दंगे हुए थे. दो साल पहले लेस्टर में दंगा हुआ था, जो सोशल मीडिया पर फैली अफवाह से शुरू होने वाला पहला दंगा था. गत सप्ताह के दंगे भी सोशल मीडिया पर फैलायी गयी अफवाह से ही भड़के हैं. पश्चिमोत्तरी इंग्लैंड के तटवर्ती शहर साउथपोर्ट में 29 जुलाई को अफ्रीकी मूल के एक 17 वर्षीय किशोर ने बच्चियों की नृत्य और योग शिक्षा की क्लास में घुसकर तीन बच्चियों को चाकू गोदकर मार डाला तथा पांच अन्य बच्चियों और उन्हें बचाने वाले दो लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था. उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर पुलिस उसका नाम और पहचान नहीं बता सकी क्योंकि ब्रिटिश कानून किशोर अपराधी का नाम और पहचान सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं देता. इस बर्बर हमले से फैले गुस्से और संताप के माहौल में कुछ यूट्यूबरों और अफवाहबाजों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि हमलावर मुस्लिम है, अवैध रूप से आया शरणार्थी है और जासूसी एजेंसियों की निगाह में रहा है. पुलिस द्वारा इसका खंडन करने पर भी अफवाह फैलती चली गयी. दंगाइयों को पुलिस के भेदभावपूर्ण बर्ताव से भी शिकायत थी.

अगली शाम को साउथपोर्ट के आसपास के दक्षिणपंथी गुटों ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों को शहर की मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जमा कर लिया. वहां शरणार्थी, आप्रवासी और इस्लाम विरोधी नारे लगे. लोगों ने पुलिस पर पथराव करना, बीयर की बोतलें और कूड़ेदान फेंकना शुरू कर दिया. अगले दिन दंगाइयों ने मैनचैस्टर के उस होटल को घेर लिया, जिसमें शरणार्थी आप्रवासियों को रखा जा रहा था. सबसे गंभीर हमला रोदरम शहर के एक होटल पर हुआ, जहां शरणार्थियों को रखा गया है. लंदन में प्रधानमंत्री आवास के सामने दंगाइयों ने पुलिस पर फ्लेयर चलाये. इसी तरह बेलफास्ट, ब्लैकपूल, ब्लैकबर्न, लिवरपूल, लीड्स, हल, लेस्टर, ब्रिस्टल और हार्टलीपूल में उग्र प्रदर्शन हुए और कहीं-कहीं एशियाई ड्राइवरों को भी निशाना बनाया गया. हमलावर किशोर को पहली अगस्त को अदालत में पेश किया गया और जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे सजा सुनाने के साथ-साथ उसका नाम सार्वजनिक करने पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया. लेकिन तब तक पूर्वाग्रहों पर आधारित शक से उपजी अफवाहें अपना काम कर चुकी थीं.

इसी तरह दो साल पहले मध्य इंग्लैंड के शहर लेस्टर में पाकिस्तान पर भारत की एशिया कप विजय के जुलूस को लेकर कुछ जिहादियों ने सोशल मीडिया पर मस्जिद पर हमले की अफवाह फैला दी थी, जिसके कारण बर्मिंघम और लंदन से उग्र प्रदर्शनकारियों से भरी बसें लेस्टर गयीं और वहां हिंदू विरोधी दंगे किये. सोशल मीडिया के बहकावे में आकर लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण छह जनवरी को अमेरिका की संसद पर हुए हमले में देखने को मिला था. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिंसक अतिवाद संबंधी प्रयोगशाला में शोध करने वाली प्रो जूलिया एबनर का कहना है कि सोशल मीडिया के विविध मंचों की अलगोरिद्म सबसे विवादास्पद और उकसाने वाली बातों को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा कर उन्हें उलझाने के लिए ही बनायी गयी हैं. इसलिए इन मंचों पर झूठ की खुली छूट के होते हुए ब्रिटेन में इस तरह के दंगे होना स्वाभाविक था. गनीमत इस बात की रही कि अपने अतिवाद के लिए कुख्यात एक-दो नेताओं को छोड़कर किसी ब्रिटिश नेता ने या मुख्यधारा के मीडिया ने अपराधी और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर राजनीति या अटकलबाजी करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि भारत में होता रहता है. सरकार और विपक्ष ने न केवल सारी जिम्मेदारी पुलिस पर छोड़ी, बल्कि उसका सार्वजनिक रूप से पूरा समर्थन भी किया. भारत के सभी पक्षों को इससे सीख लेनी चाहिए.

दक्षिणपंथी नाइजल फराज और उनकी रिफॉर्म पार्टी के नेताओं ने जरूर प्रदर्शनों को आप्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ तथा उससे अंग्रेजी समाज की पहचान को मिलती चुनौती से जोड़ने की चेष्टा की, जिसकी हर तरफ से निंदा हुई. परंतु, इस चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आप्रवासियों के नाम पर दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों का मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना संकेत देता है कि वे उन समुदायों को लेकर अधिक चिंतित हैं, जो यहां के समाज में समाकर चलने के बजाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करने पर आमादा रहते हैं. गत सप्ताह के प्रदर्शन और दंगे अधिकतर उन्हीं शहरों में हुए हैं, जहां 2011 में मुख्य रूप से एशियाई मुस्लिम समुदाय ने पुलिस के भेदभावपूर्ण बर्ताव के खिलाफ प्रदर्शन और दंगे किये थे.

ब्रितानी समाज में लोग भूलों से सबक सीखते रहे हैं. वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड के शहर डनब्लेन में टॉमस हैमिल्टन ने प्राथमिक स्कूल में जाकर 16 छात्रों और अध्यापिका को हैंडगन से गोली मार दी थी और बाद में आत्महत्या कर ली थी. इस घटना ने हैंडगनों को लेकर ब्रिटिश समाज में ऐसी घृणा पैदा की कि डेढ़ साल के भीतर सरकार को हैंडगनों पर पाबंदी लगाने वाला विधेयक पारित करना पड़ा. पिछले सप्ताह भड़के दंगे सिद्ध करते हैं कि सोशल मीडिया में संवेदनशील मामलों पर झूठ की छूट और अफवाहबाजी हैंडगनों से कम खतरनाक नहीं है. प्रधानमंत्री स्टामर ने कहा भी है कि उसे अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा. लेकिन क्या सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचने और इस पर कोई कानून बनाने का साहस कर पायेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसका संतुलन कैसे बैठाया जा सकेगा? पूर्व सोवियत नेता यूरी आंद्रोपोव ने कहा था कि मिथ्या प्रचार कोकीन की तरह है. एक-दो बार सेवन करना तो चलता है, पर यदि आप उसे हर समय लेने लगेंगे, तो लती बनकर पूरी तरह बदल सकते हैं. सोशल मीडिया पर हो रहा मिथ्या प्रचार लोगों में इसी तरह के बदलाव ला रहा है, जिसके संभावित प्रभावों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

गाली देने की दुर्योधनी कला

डॉ सुरेश पंत
भाषाविद
drsureshpant@gmail.com

भाषा-संस्कृति

समाज विज्ञानी गाली के शास्त्र को समाज के मनोविज्ञान से भी जोड़ते हैं. कुछ लोग गाली देने के स्वभाव को अशिक्षित और पिछड़े होने से जोड़ते हैं. एक सीमा तक यह सही हो सकता है, परंतु यदि पूर्ण सही होता, तो शिक्षित, शिष्ट और आदर्श समाज में गाली के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि ऐसा केवल कल्पनाओं में होता है.

भर्तृहरि की एक सूक्ति है: ददतु ददतु गालीं गालिमन्तो भवन्तः/ वयमपि तदभावाद् गालिदानेऽसमर्थाः।/ जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानम्/ न हि शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति॥ (वैराग्य शतक) किसी ने किसी को भरपेट गालियां दीं. गाली खाने वाला गाली देना नहीं जानता, वह अपनी झुंझलाहट इस प्रकार व्यक्त करता है, 'दीजिए-दीजिए, गालियां दीजिए. आप तो गाली वाले हैं, गालियों का भंडार हैं. आप गालियां नहीं देंगे तो क्या देंगे और क्या करेंगे. अपने पास गालियां न होने से हम तो गालियों का दान देने में सर्वथा असमर्थ हैं. यह बात तो जगजाहिर है कि जिसके पास जो है, वही तो दिया जाता है. जैसे कोई भी किसी को खरगोश के सींग नहीं दे सकता क्योंकि खरगोश के सींग किसी के पास होते ही नहीं.' महाभारत, कर्ण पर्व के अध्याय 39-41 के बीच कर्ण और उसके सारथि शल्य में विवाद वर्णित है. शल्य ने कर्ण को अर्जुन रूपी सिंह के सामने अपशब्द कहे, तो कर्ण ने शल्य तथा उसके मद्र देश के लोगों तथा उनकी स्त्रियों के दुश्चरित्र का वर्णन किया, जिसे जातीय गाली कहा जा सकता है.

सच तो यह है कि गालियां शब्द में ही नहीं, भाव में भी होती हैं. भाव प्रधान गालियां बड़ी कलात्मकता से दी जाती हैं और अधिक गहरी चोट पहुंचाने के लिए दी जाती हैं. ऐसी स्थितियों में गाली दाता के मुखारविंद से जो शब्द बाहर निकल रहे होते हैं, वे अपशब्द नहीं कहे जा सकते, किंतु उनका एकमात्र मंतव्य चोट पहुंचाना और स्वयं दूध का धुला बना रहना होता है. महाकवि भास की नाटिका 'दूतवाक्यम्' में शिष्ट भाषा में गहरा घाव करने वाली विषैली गालियों का एक रोचक प्रसंग है. श्रीकृष्ण विनाशकारी महाभारत युद्ध को टालकर संधि कराने के लिए पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गये थे. दुर्योधन उनसे कुशल क्षेम कुछ इस प्रकार पूछता है: 'हे दूत! धर्मराज का पुत्र (युधिष्ठिर), वायु पुत्र (भीम), इंद्र का पुत्र (अर्जुन), अश्विनीकुमारों के विनम्र जुड़वां पुत्र (नकुल-सहदेव) नौकर-चाकरों के साथ कुशल से तो हैं?' दुर्योधन ने किसी पांडव का नाम नहीं लिया (नाम लेने योग्य नहीं समझा), किंतु भद्दी गाली दे डाली, शिष्ट शब्दों में, बड़ी कलात्मकता से. चाकरों के साथ पांडवों का उल्लेख कर जता दिया कि दुर्योधन की दृष्टि में वे 'भृत्य' के ही समकक्ष हैं. जब श्रीकृष्ण पांच ग्राम देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखते हैं, तो दुर्योधन कह देता है, 'वे देवताओं के पुत्र (पांडव) भला हम मनुष्य-पुत्रों (धृतराष्ट्र के पुत्रों) के बांधव कैसे हो सकते हैं कि उन्हें उत्तराधिकार दिया जाए.'

पूरी दुनिया की भाषाई संस्कृति में गालियों की अपनी जगह होती है. अंग्रेजी की चौ-आखरी गाली किसी जमाने में अछूत थी. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के पहले संस्करण में यह शब्द मिलता ही नहीं क्योंकि वे इसे बहुत बुरा शब्द मानते थे. लिखित अंग्रेजी साहित्य में पहली बार इस शब्द का खुला इस्तेमाल सर डेविड लिंडेसी ने 1535 में किया. दूसरे पॉपुलर गाली शब्दों का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है, जो बताता है कि गालियों के साम्राज्यवाद के लिए भी कुछ नियम काम करते हैं. जैसे पिछली सदी के प्रारंभ तक ब्रिटेन के कुलीनों में 'ब्लडी' बहुत बुरा शब्द माना जाता था. आज वह स्वीकृत स्लैंग है. भारत में एक वर्ग ऐसा भी मिल जायेगा, जो अंग्रेजी में गाली देना अपनी शान समझता है. कुछ समाजों में गाली देना खुलेपन की पहचान माना जाता है. हमारे मीडिया, सोशल मीडिया में भी यह खुलापन खुल चुका है और भाषा प्रयोग के नये आयाम स्थापित कर रहा है. गालियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं. मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये मानसिक तनाव कम कर सकती हैं. गुस्से में मनुष्य आजकल हत्या तक कर देते हैं. मारने की अपेक्षा गाली से काम चलाया जा सकता है. मनश्चिकित्सा में व्यक्ति चिकित्सक की उपस्थिति में गाली देकर अपने मन की भड़ास निकाल लेता है. यह बात और है कि वहां गालियां देने के लिए फीस चुकानी पड़ती है. सार्वजनिक मंचों से गालियां देने पर एक पक्ष आपकी निंदा करता है, तो दूसरा पक्ष हीरो ठहरा सकता है.

समाज विज्ञानी गाली के शास्त्र को समाज के मनोविज्ञान से भी जोड़ते हैं. कुछ लोग गाली देने के स्वभाव को अशिक्षित और पिछड़े होने से जोड़ते हैं. एक सीमा तक यह सही हो सकता है, परंतु यदि पूर्ण सही होता, तो शिक्षित, शिष्ट और आदर्श समाज में गाली के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि ऐसा केवल कल्पनाओं में होता है. सब जानते हैं कि संसद में असंसदीय भाषा वर्जित होती है और यह ठीक भी है. संसद का अर्थ ही है भले लोगों की मिल-बैठने की सभा, समिति. भले लोगों के बीच अशिष्ट, असंसदीय भाषा का क्या काम! सदस्यों की जानकारी के लिए संसद में प्रयोग से वर्जित, असंसदीय शब्दों की एक आधिकारिक सूची भी बनी हुई है. उदाहरण के लिए, उस सूची में 'झूठा' शब्द को भी असंसदीय माना गया है, तो समझा जा सकता है कि गाली-गलौज में प्रयुक्त होने वाले अपशब्द कैसे संसदीय हो सकते हैं. फिर भी गाली कला में निपुण लोग दुर्योधन वाला कौशल दिखा जाते हैं और ऐसी कला के लिए वे निंदा के नहीं, बल्कि प्रशंसा के पात्र बनते हैं, जबकि फूहड़ गालियां निकालने वाला कितना ही सृजनशील हो, गरियाया जाता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश दुनिया

केन्या में हो रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन के कारणों की पड़ताल

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो, जिन्होंने 100 दिनों के भीतर जीवन यापन की लागत कम करने के वादे के साथ अगस्त 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था, केन्या की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में विफल रहे हैं. इस कारण लोगों में नाराजगी है. विदित हो कि 18 जून को हजारों केन्याई युवा एक विवादास्पद कर बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आये, क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका थी. हालांकि रुटो ने तत्काल छोटी रियायत देने का प्रयास किया, परंतु प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया. हर दिन अधिक से अधिक लोग विद्रोह में शामिल होने लगे, विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने संसद पर भी धावा बोल दिया. अंततः 26 जून को रुटो ने वित्त विधेयक को वापस लेने की घोषणा की. परंतु जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ. इसलिए विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए 11 जून को राष्ट्रपति ने एक और बड़ी रियायत दी, अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया, और इसके स्थान पर एक नया मंत्रिमंडल बनाने का वादा किया. परंतु मंत्रिमंडल में फेरबदल भी केन्या के प्रदर्शनकारियों को शांत करने में विफल रहा है. लोग अब भी सड़कों पर हैं और रुटो के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विधेयक को वापस लेने के बावजूद केन्या में प्रदर्शनों का जारी रहना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस विरोध का कारण महज एक विधेयक पर बिना सोचे-समझे नीति तैयार करना भर नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है. वास्तव में लोग स्थानिक भ्रष्टाचार, शासन की विफलताएं, आगे बढ़ने के लिए सामाजिक-आर्थिक समर्थन और अवसरों की कमी से ऊब चुके हैं. उन्हें अपना भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. यहां काफी असमानता और गरीबी है. इसी कारण लोग व्यवस्थागत परिवर्तन चाहते हैं और वह भी तुरंत.

-ताफी म्हाका

बोधि वृक्ष

कीर्तन की महिमा

खोजी को परम चेतना के निकट लाने का एक बहुमूल्य साधन कीर्तन है. हृदयस्पर्शी सच्चाई और भक्ति पूर्ण गीतों का उद्देश्यपूर्वक गान तथा रचनात्मक तरीके से जाप करना कीर्तन है. कीर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है. कीर्तन के समय अनेक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनके उद्देश्य एक होते हैं. इसलिए उनकी सामूहिक शारीरिक ऊर्जाएं एक साथ काम करती हैं. उनकी सामूहिक आंतरिक शक्तियां परमपुरुष से प्रेरित एक धारा में प्रवाहित होती हैं. कीर्तन स्थल पर न केवल शारीरिक ऊर्जाओं का एक विशाल केंद्रीकरण होता है, मानसिक ऊर्जा का भी एक शक्तिशाली केंद्रीकरण होता है जो भौतिक संसार के सभी सामूहिक, संचित कष्टों को दूर कर देता है. कीर्तन आंतरिक परम चेतना को प्रकट करने के लिये ईश्वर से की गयी प्रार्थना है. परमपुरुष से मिली प्रेरणा द्वारा कीर्तन करने वाले महान शक्ति अर्जित करते हैं. कोई भी लौकिक बाधा उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सकती है. अतः कीर्तन न केवल आध्यात्मिक साधना में सहायक है, लौकिक कठिनाइयों पर काबू पाने में भी सहायक है. शारीरिक कष्ट आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से स्वयं हमारे विचारों तथा कर्मों की उपज हैं. शारीरिक कष्ट चाहे जैसे भी हों- प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित- यदि लोग सामूहिक रूप से कीर्तन करें, तो आपदाओं से निपटना आसान हो जायेगा. हृदयस्पर्शी कीर्तन से बाढ़, अकाल, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं, या मनुष्य निर्मित आपदा, कष्ट और अत्याचार से शीघ्र राहत मिल जाती है. संकीर्तन और परमपुरुष से कृपा की प्रार्थना राहत प्रदान करने में असफल नहीं हो सकती, बल्कि वह उच्चतर चेतना की ओर बढ़ने के लिए एक विशेष गति प्रदान करती है. कीर्तन पहले से मौजूद या जिनका अभी आगमन नहीं हुआ है, पर जिनका पूर्वाभास हमें है, उन व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने में सहायक होने के साथ-साथ सामूहिक मानसिक कष्टों को समाप्त करने में आयी बाधाओं को भी कम कर देती है.

-आनंदमूर्ति गुरु मां

कुछ अलग

गांव की यात्रा और वास्तविकता

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

पिछले दिनों मेरी एक परिचित महिला की बेटी अमेरिका से भारत आयी हुई थी. बहुत दिनों तक वह अपने बच्चों के साथ भारत में जगह-जगह घूमती रही, फिर एक दिन मेरे यहां भी आयी. बातों-बातों में बताया कि वह अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना चाहती थी, इसलिए हरिद्वार, वृंदावन गयी. कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा. तिरुपति में भी भगवान के दर्शन किये. असम में गैंडा अभयारण्य भी दिखाया.

अरे वाह, तुम तो बहुत सारी जगहें घूम आयी. आंटी आपको असली बात तो बतायी ही नहीं. मैंने बच्चों को असली वाला गांव दिखाया. आनंद ही आ गया. असली वाला मतलब? वहां हमने महिलाओं को चक्की पीसते देखा. कच्चे घरों को देखा. उन पर बनी तरह-तरह की डिजाइनें देखीं. कई औरतें कढ़ाई भी कर रही थीं. भैंस, गाय का दूध दुहते देखा. चूल्हे पर पकी रोटी खायी. सचमुच ऐसी स्वादिष्ट रोटी तो आज तक नहीं खायी थी. कच्चे घर कितने सुंदर थे. पता नहीं लोगों ने पक्के घर क्यों बना लिये. मेरे बच्चों ने तो इतना एंज्वॉय किया. वे तो वापस भी नहीं आना चाहते थे. उसकी बात सुन हंसी आ गयी. उसे गांव एक स्वर्ग दिख रहा था, क्योंकि अमेरिका या यूरोप में गांव और शहर लगभग बराबर हैं. फिर अपने यहां जिन गांवों को यात्री देखने जाते हैं, वहां जान-बूझकर ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, जो प्रायः अब गांवों में भी नहीं दिखतीं. कच्चे छप्पर पड़े घर अब लगभग बनना बंद हो गये हैं. इसी तरह, जिस अनुपात में स्त्रियां पढ़ती जा रही हैं, कढ़ाई-सिलाई, बुनाई जैसी पारंपरिक कलाओं से दूर होती जा रही हैं. चूल्हे पर खाना पकाने की बात कौन कहे, घरों में गैस पर ही खाना पकाना कम हो रहा है. जितना ऐसा हो रहा है, गांव देखने की ललक बढ़ रही है. अपने माता-पिता से या दादा-दादी से जिन गांवों के रहन-सहन और कामकाज के किस्से सुने हैं, उन्हें देखने की लालसा रह-रहकर मन में उठती है. ऐसे गांवों को देखने सिर्फ विदेशी ही नहीं जाते, अपने देश के बहुत से युवा भी जाते हैं.

वह पीढ़ी जो शहरों में पली-बढ़ी है, उसे गांव बहुत आकर्षक लगते हैं, परंतु यदि उनसे कोई पूछे कि तुम यहां रहना चाहोगे, तो वे शायद ही हां कहें. ऐसे कई लोगों के बारे में पता है कि वे सब कुछ शहर में छोड़कर, गांव में रहने गये पर उन्हें कुछ ही दिनों में वापस आना पड़ा. क्योंकि जिस बचपन की यादों को खोजने वहां गये थे, वह दूर-दूर तक कहीं नहीं मिलीं. संगी-साथी भी इधर-उधर जा चुके थे. जो बचे थे, अपने नाती-पोतों को पालने में व्यस्त थे. लेकिन कंपनियों ने पैसा कमाने के लिए विलेज टूरिज्म युवाओं को सौंप दिया है.

आपके पत्र

एनटीए की कार्यशैली में सुधार जरूरी

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिहार और झारखंड में हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. इस घटना ने परीक्षार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली और प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठने लगे हैं. एनटीए का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करना था, लेकिन इन राज्यों में हुई घटनाओं ने इस संस्थान की साख पर सवाल खड़े कर दिये हैं. इसलिए यह साफ है कि एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है. क्योंकि, एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं.

पवन कुमार, गया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागतयोग्य

सुप्रीम कोर्ट का एससी-एसटी आरक्षण पर निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस पर बहस करें और इसके प्रभावों को समझें. आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना है, लेकिन आज यह प्रणाली कुछ चुनौतियों का सामना कर रही हैं. आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. यह देखा गया है कि शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं. इसलिए आरक्षण समय और इससे जुड़े लोगों के बारे में समीक्षा अनिवार्य है.

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

विरल अयोग्यता

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक में स्वर्ण की दावेदार थीं, पर उन्हें महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य करार देना दुखद और अफसोसनाक है। मंगलवार को एक के बाद एक तीन मुकाबले जीतने और फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश ने अपनी मां से कहा था, 'सोना लाना है।' दुर्भाग्य, विनेश ही नहीं, देश का एक सपना अधूरा रह गया। ओलंपिक में पहली बार कोई भारतीय महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी। उसे मंगलवार तक 50 किलोग्राम वर्ग में दुनिया का योग्यतम पहलवान माना जा रहा था, पर न जाने एक दिन या एक रात में क्या हो गया कि उनका वजन कुछ ग्राम बढ़ गया और वह अयोग्य करार दे दी गईं? बेशक, अब यह विवाद लंबे समय तक बहस का विषय रहेगा। ओलंपिक के नियम अमानवीय ही नहीं, अन्यायपूर्ण भी हैं। कल अगर विनेश का वजन ठीक था, तब कल तक की उनकी जीत को तो मान्यता मिलनी चाहिए थी? अगर किसी दिन खिलाड़ी का वजन कुछ बढ़ जाए, तो उसकी पिछली उपलब्धियों को क्या शून्य मान लिया जाए? यह शायद हमेशा कहा जाएगा कि विनेश अगर फाइनल खेलने योग्य नहीं थीं, तो उन्हें कम से कम रजत पदक मिलना चाहिए था।

कहना न होगा, भारतीय ओलंपिक के इतिहास में एक स्याह अध्याय जुड़ गया है। भारत को अपना विरोध अवश्य दर्ज कराना चाहिए और विनेश के पदक के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए। क्या भारत के साथ कोई तकनीकी खिलवाड़ किया गया है? वजन बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा सच सामने आना चाहिए। ऐसे लोगों की खेलों की दुनिया में कोई जगह नहीं, जिनकी खिलाड़ियों और देश में निष्ठा नहीं है। विनेश की तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से विनेश का समर्थन किया है, उससे भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री का यह कहना बहुत मायने रखता है कि 'विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हो! आप भारत का गौरव हो और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हो।' आज विनेश के साथ खड़े होने की जरूरत है। उनकी शंकाओं का समाधान करने की जरूरत है। अगर कोई विनेश की राह में रोड़ा बना है, तो उसकी जरूर पहचान होनी चाहिए। जो देश अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसका किसी भी पदक पर हक नहीं है। हम क्रिकेट जैसे कुछ ही खेलों में खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, तो जाहिर है, कुछ ही पदक हमारी झोली में आते हैं। आज ओलंपिक पदक तालिका में हमें अपना स्थान खोजने में परेशानी हो रही है, तो हमें खेलों और खिलाड़ियों के प्रति अपना रवैया सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

विनेश फोगाट को अपने वजन-वर्ग में योग्यतम पहलवान माना जा रहा था, पर क्या हो गया कि उनका वजन कुछ ग्राम बढ़ा और वह अयोग्य करार दी गईं?

बेहद सक्षम पहलवान विनेश फोगाट का अयोग्य घोषित होना तमाम खिलाड़ियों के लिए एक सबक बने। अगर किसी स्तर पर साजिश या गड़बड़ी हुई है, तो खिलाड़ियों को मिलकर खामियों पर सख्ती से उंगली रखनी चाहिए। आज जो कमी रह गई है, वह दोबारा कभी किसी भारतीय के आड़े न आए, यह प्रबंध स्वयं खिलाड़ियों को आगे बढ़कर करना होगा। दोयम दर्जे की खेल-समझ वाले नेताओं के पीछे खड़े होने के बजाय आगे आकर फैसले लेने पड़ेंगे। पदक बेहतर खेल से मिलेंगे, राजनीति से नहीं। अब खिलाड़ियों की योग्यता ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी स्टाफ की योग्यता भी गंभीर विषय बने, तो ही हमारी कामयाबी का कारवां आगे बढ़ेगा।

दक्षिण एशिया में भारत अकेली उम्मीद

कई देशों में लोकतंत्र का बुरा हाल है, लेकिन अनेक दार्शनिक, ऐतिहासिक कारणों व अनुभवों के चलते 'आइडिया ऑफ इंडिया' का विचार भारत को टकराव से बचाकर समावेशी बनाता है।

यहां स्कैन करें

बद्री नारायण | निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

बांग्लादेश भयानक उथल-पुथल से गुजर रहा है। वहां जनतंत्र इस्लामिक कट्टरवाद, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद, सैन्य तानाशाही की आकांक्षा के प्रसार जैसे अनेक संकटों से जूझकर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा बंग बंधु शेख मुजिबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना अनेक मोर्चों पर जूझते हुए भी देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के प्रयास में लगी थीं। अफसोस, विगत महीनों में यह प्रयास बाधित हो गया और ऐसी आंतरिक उथल-पुथल मची कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब वहां फिर सेना की ताकत बढ़ गई है।

यह कहने में हर्ज नहीं कि बांग्लादेश के 'राष्ट्र इन द मेकिंग' की प्रक्रिया को इससे गहरा धक्का लगा है। वहां मची हिंसा ने सामाजिक, जनतांत्रिक एवं राष्ट्रीय तंतुओं को छिन्न-भिन्न कर दिया है। न केवल बांग्लादेश, वरन आज पूरी दुनिया में अनेक तरह के पूर्वाग्रह, विघटनकारी धार्मिक या नस्लीय भाव एवं सैन्य प्रेरित आतंककवाद सिर उठाने लगे हैं। अनेक मुल्कों में आक्रामक भू-राजनीति, विघटन एवं विभाजन केंद्रित हिंसा को पड़ोसी मुल्कों से भी हवा दी जा रही है। इस नकारात्मक कार्य में अनेक महाशक्तियां और उनसे प्रभावित समर्थक देशों की भी बड़ी भूमिका है। ऐसी ही कुचेष्टाओं ने दक्षिण एशिया के अनेक मुल्कों जैसे - पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि में जनतंत्र को संकटग्रस्त कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिकता ने जो सबसे मूल्यवान नीधि दुनिया को सौंपी थी, वह थी जनतांत्रिक व्यवस्था एवं जनतंत्र को पाने की चाह। वही बहुमूल्य नीधि आज के संदर्भ में संकटग्रस्त दिखने लगी है। इसके ज्वलंत उदाहरण हम बांग्लादेश में देख रहे है। यह हमारी सरकारों और समाज के लिए गहरे विचार का विषय होना चाहिए।

यहां प्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अनेक देशों में जनतंत्र क्यों बार-बार संकटग्रस्त हो जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह वे आधार तत्व हैं, जिन पर इन मुल्कों में समाज और राष्ट्र निर्मित हुआ है। इनमें पहला आधारभूत तत्व इन देशों में हिंसा या टकराव की बुनियाद पर खड़ा समाज है। एक अच्छे समाज को समावेश पर आधारित होना चाहिए, जबकि एक बुरा समाज टकराव पर खड़ा होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 'चिड़ियों की दो आंख' या द्वि-राष्ट्र के सिद्धांत के अनुसार ही भारत का विभाजन प्रस्तावित किया था। हम सब यह जानते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के लिए हुए भयंकर टकराव या हिंसा की बुनियाद पर हुआ। अफसोस, बाद में बांग्लादेश भी हिंसा की बुनियादी पर ही अलग हुआ या बना।

टकराव के दर्शन पर खड़े समाज अपने अंदर और बाहर हमेशा टकराव की ही दृष्टि पालते देखे जाते हैं। टकराव या अलगाव की इस संस्कृति और विश्व दृष्टि का एक बड़ा पोषक तत्व मजहब आधारित राष्ट्र की कल्पना है। मजहब आधारित राष्ट्रवाद हमेशा अपने भीतर आतंकवाद, कट्टरता को गति देता रहता है। ऐसे में, बाहरी व भीतरी विभाजनकारी तत्व योजनाबद्ध ढंग से काम करते हुए समाज और राष्ट्र के पूरे ढांचे को हिलाते एवं ध्वस्त करते रहते हैं। हम आसानी से देख सकते हैं कि अनेक देशों में इस्लाम अपने आध्यात्मिक एवं धार्मिक समाहार की शक्ति खोते हुए राजनीतिक अस्त्र में बदल गया है, जिसका इस्तेमाल प्रायः सैन्य तानाशाह एवं अन्य किस्म के तानाशाह करते रहे हैं।

इस तरह के समाज एवं राष्ट्रों में 'जनतंत्र' के संकट का दूसरा बड़ा आधारभूत तत्व इन राष्ट्रों में उपजा आर्थिक संकट है। यह संकट इनके गलत एवं असंतुलित आर्थिक नीतियों की वजह से पैदा हुआ है। इसी आर्थिक संकट ने इन देशों में बेरोजगारी, जलालत एवं जहालत का भंवरजाल रचा है, जिसमें जनतंत्र का बार-बार खून होता है। अर्थव्यवस्था से निराश आबादी का इस्तेमाल तानाशाही, कट्टरपंथी एवं गैर-जनतांत्रिक शक्तियां ही करती हैं, जिससे समाज और राष्ट्र अव्यवस्थित हो जाता है। गौर कीजिए, बांग्लादेश में बेरोजगारी की वजह से ही आरक्षण विरोधी आंदोलन को बल मिला, जिसे कट्टरपंथियों ने हवा देकर हिंसक बना दिया। अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बांग्लादेश की विकास यात्रा को अपूरणीय नुकसान हो चुका है? यह एक सबक है कि जो आरक्षण हाशिये के समूहों के सशक्तीकरण एवं सम्मान के लिए एक जनतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में हमें मिला है, वह जब नकारात्मक मोड़ लेता है, तो समाज एवं राष्ट्र को तोड़ने के बड़े हथियार में बदल जाता है।

जिन दक्षिण एशियाई देशों में असंतुलित एवं हिंसक धार्मिक भाव राष्ट्र निर्माण के आधार होते हैं, वहां सैन्य तानाशाह प्रायः इन्हीं भावों का उपयोग करते हुए जनतंत्र को कमजोर कर देते हैं। हालांकि, बांग्लादेश का समाज भाषा, मजहब के साथ-साथ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के भाव से निर्मित हुआ था, इसलिए इसमें जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं विकास की संभावना पाकिस्तान से कहीं ज्यादा रही है। बांग्लादेश की समकालीन राजनीति पर भारत का प्रभाव तो रहा है, पर इसकी 'भू राजनीति' पर पाकिस्तान का सीधा हस्तक्षेप बना हुआ है।

यहां हमें यह विचार करना ही चाहिए कि 'भारत का समाज एवं राष्ट्र' ऐसी विनाशक संहारक प्रवृत्तियों से क्यों और कैसे बार-बार उबरता रहता है? भारत के समाज में कई बार ऐसे संकट आते हैं, जनतंत्र कमजोर होता दिखता है, पर पुनः उन संकटों से उबरकर यहां जनतंत्र नई जीवन-शक्ति के साथ बहाल हो जाता है। इसका मुख्य कारण है- भारतीय समाज के ऐसे बुनियादी तत्व, जो इसे टकराव या अलगाव से बचाते हैं। अनेक दार्शनिक, ऐतिहासिक कारणों और अनुभवों के चलते 'आइडिया ऑफ इंडिया' का विचार हमें टकराव से बचाकर समाहार की राह पर रखता है।

आजादी के बाद हमारे प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं - महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, बाबा साहेब आंबेडकर ने 'आइडिया ऑफ इंडिया' को नव-निर्मित करते हुए एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी, जहां जनतंत्र निरंतर विकसित होता रहे। ऐसा राष्ट्र बने, जिसमें पंक्ति में खड़े अंतिम नागरिक तक देश के संसाधनों को पहुंचाया जा सके, ताकि वह विभाजनकारी ताकतों के हाथ में विघटन का औजार न बने। जिन्ना ने 'हम साथ नहीं रह सकते' के टकराव भाव के साथ पाकिस्तान को बनाया था, जबकि गांधीजी मिलकर रहने या समाहार की बात लगातार करते चले गए। अब भारत को लगातार कोशिश करनी चाहिए कि उसके चरित्र में समाहार और सद्भाव का भाव वैसे ही बना रहे, जैसी उम्मीद संविधान ने की थी, तभी हम हर संकट से बचे रहेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

देश को हम कैसे बना पाएंगे प्रतिभाओं की महाशक्ति

यहां स्कैन करें

आईवी सुब्बा राव | पूर्व आईएएस एवं शिक्षाविद्

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी। विकास के सभी क्षेत्रों में उनकी इस बात का व्यापक असर पड़ा है। पिछले साल हमने वैश्विक आर्थिक विकास में 7.2 प्रतिशत का योगदान दिया है। मगर इस आर्थिक वृद्धि को बनाए रखते हुए एक विकसित देश बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान दें। अनुमान है कि 2047 तक दुनिया भर की 20 प्रतिशत कामकाजी आबादी भारत से आएगी। इस प्रकार हम प्रतिभाओं की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मगर इस कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा इस समय प्रारंभिक कक्षाओं में है, जहां की एक कड़वी सच्चाई यह है कि तीसरी कक्षा पास करने वाले करीब तीन चौथाई बच्चे वाक्य पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। वे गणित के सरल प्रश्नों को भी हल नहीं कर पा रहे हैं।

देश के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका को देखते हुए साल 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को सबसे अहम माना गया है। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 2021 में भारत के प्रारंभिक शिक्षा मिशन-निपुण भारत (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऐंड न्यूमेरेसी) की शुरुआत की, जो प्रारंभिक कक्षा में पठन-पाठन को नए सिरे से परिभाषित करते हुए शिक्षा के संपूर्ण इकोसिस्टम में बदलाव ला रहा है। इसके तहत यह कोशिश की गई है कि सभी बच्चे अर्थ समझते हुए पढ़ना सीखें व गणित के बुनियादी सवाल हल कर सकें। चूंकि निपुण का संकल्प है कि सभी बच्चे 'सिद्धि' के स्तर तक पहुंच सकें, इसलिए भारत की शिक्षा प्रणाली को 'संकल्प से सिद्धि तक' शिक्षा के सात स्वरों पर जोर देना चाहिए।

आज भारत के 26 करोड़ स्कूली बच्चे कल के वैश्विक नागरिक हैं। ऐसे में, हमें शिक्षा में 'संकल्प' से 'सिद्धि' की ओर बढ़ना चाहिए।

सबसे पहला स्वर है साधन। इसमें हमें बुनियादी बातों से शुरुआत करनी होगी। हमारी स्कूली इमारतें ऐसी हों, जहां रोशनी की पूरी व्यवस्था हो। खेल के लिए बड़ा मैदान हो। शौचालय व पानी की अच्छी सुविधा हो। एक बड़ी चुनौती अलग-अलग कक्षाओं की जटिल स्थिति को सही तरीके से संभालना भी है। इसका एक हल यह हो सकता है कि विद्यालय प्रणाली को पुनर्गठित करके सभी प्राइमरी स्कूलों की हर कक्षा में एक शिक्षक की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों के पास ऐसी शिक्षण सामग्री भी होनी चाहिए, जिसमें बेहतर शिक्षण की रूपरेखा और कार्ययोजना के साथ-साथ छात्रों की कार्य-पुस्तक और मूल्यांकन सामग्री भी शामिल हो। इसका अगला भाग है, एडटेक, यानी उपकरण के सहारे समझ विकसित करना। इससे बच्चों का सीखने का समय बढ़ाया जा सकता है।

अगला स्वर 'साधना' है। कक्षा में शानदार पढ़ाई के लिए शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग व पेशेवर विकास व मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके लिए हमें उन्हें इस अभियान से जोड़ना होगा। अगला स्वर 'समीक्षा' के लिए हमें सीखने के परिणामों का आकलन करना होगा। यह रचनात्मक आकलन नियमित रूप से शिक्षकों को बच्चों की समझ परखने में मदद करेगा। सीखने और सिखाने के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में भारत की प्रौद्योगिक शक्ति बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश का निपुण गुणवत्ता एप इसका उदाहरण है। वहां इसकी मदद से व्यक्तिगत आधार पर शिक्षण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है।

अगला स्वर है, संवाद। शिक्षकों के सहकर्मी शिक्षण समूहों, क्लस्टर और जिला समीक्षा बैठकों, अभिभावक-शिक्षक बैठकों और राज्य के प्रमुख अधिकारियों द्वारा की गई जिला समीक्षा बैठकों में चर्चा का केंद्र बच्चों की शिक्षा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण संवाद, जिस पर हमें ध्यान देने की खास जरूरत है, वह है पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक सभी की आसान पहुंच। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे के मष्तिष्क का 90 फीसदी विकास छह वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। 'सिद्धि' तक पहुंचने के लिए आखिरी स्वर है, सुधार। इसके लिए जरूरी है कि निपुण को एक सामाजिक मिशन बनाया जाए और तमाम हितधारकों की इसमें सक्रिय भागीदारी कराई जाए। आज भारत के 26 करोड़ स्कूली बच्चे कल के वैश्विक नागरिक हैं। ऐसे में, हमें 'संकल्प' से 'सिद्धि' की ओर बढ़ना चाहिए। सुशिक्षित भारत बनाने के लिए जरूरी है कि हम अमृत काल के सकारात्मक माहौल का उपयोग करें।

(साथ में श्वेता शर्मा कुकरेजा)

मनसा वाचा कर्मणा

भोजन और भाव की समानता

भगवान के धाम जब कोई जीव पहुंचता है, तो भगवान अपनी शक्ति से उसका रूप बदल देते हैं। ऐसा भारतीय शास्त्रों में लिखा है। रूप कैसा? वैसा ही, जैसा स्वयं भगवान का है, अर्थात परमधाम में पहुंचने वाले हरेक जीव को भगवान अपने जैसा बना देते हैं। वैसे ही पहनना, वैसे ही खाना, वैसे ही व्यवहार करना, वैसे ही सोचना। भगवान के धाम में कोई भेद नहीं है।

किसी माता-पिता में यह क्षमता नहीं कि वे अपनी संतान को अपने जैसा बना लें, पर भगवान की शक्ति है कि वह अपने पास पहुंचने वालों को अपने जैसा बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूप अगर दो तरह के हों, तो भाई-बहन में भी झगड़ा होता है। भाई कहेगा, ऐ काली जी, इधर आ, तो बहन कहेगी, लंगूर जी, इधर आइए। सुंदरता की जो असमानता है, वह समाज में आत्म-ग्लानि का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। वैसे, आदर्श स्थिति यही है कि किसी को न कुरूप कहना चाहिए और न सुंदर कहना चाहिए। अगर मैं किसी को सुंदर कहूं, तो दूसरों का क्या होगा? दूसरों का मन दुखेगा, तो कुरूप है, उसे तो दुख होगा ही और जो स्वयं को सुंदर समझता है, उसका भी जी दुखेगा।

ध्यान दीजिएगा, स्वामी रामानंदाचार्य जी किसी से जाति तक नहीं पूछते थे। कोई किसी से पूछे कि किस जाति के हो, तो एक दूरी तत्काल बन जाती है। ठीक इसी तरह से सबके पद का समान स्तर नहीं होता, सबका धन समान नहीं होता, सबका ज्ञान समान नहीं होता, सबका बल समान नहीं होता, सबका परिवेश समान नहीं होता, सबके माता-पिता एक समान सशक्त नहीं होते, सबका आवास-निवास एक सा नहीं होता है, तो बहुत अच्छा करते थे रामानंदाचार्य जी कि किसी से जाति नहीं पूछते थे। किसी से धर्म या मत भी नहीं पूछना चाहिए। जब भगवान के यहां कोई भेद नहीं, तो हमें भी भेद नहीं करना चाहिए।

यहां तो लोग स्वयं जैसा भोजन करते हैं, वैसा अपने सेवकों को नहीं खिलाते। एक अरबपति श्रद्धालु मुझे अपने यहां बहुत प्रेम से ले गए। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके यहां ही प्रसाद ग्रहण करूं। वहां मैंने स्वयं अपना भोग तैयार किया और इसी क्रम में मैंने वहां ऐसा भोजन देखा, जो खाने योग्य नहीं था। पता किया, तो वह भोजन वहां काम करने वाले नौकरों के लिए बना था। मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने तय कर लिया, अब यहां दोबारा नहीं आना है। जहां बहुत धन होने के बावजूद अमीर लोग अपने जैसा भोजन सेवकों को नहीं दे सकते, वहां क्यों जाना? जहां भोजन में ही साम्यता नहीं है, वहां समानता कैसे आ सकती है? परस्पर प्रेम-लगाव कैसे बढ़ सकता है? हमें ईश्वर के धाम से सीखना चाहिए, जहां कोई भेद नहीं है। जैसा भोग ईश्वर लगाते हैं, वैसा ही भोग बाकी सभी को सहज उपलब्ध होता है।

जहां भोजन में ही साम्यता नहीं है, वहां समानता कैसे आ सकती है? परस्पर प्रेम-लगाव कैसे बढ़ सकता है? हमें ईश्वर के धाम से सीखना चाहिए, जहां कोई भेद नहीं है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 अगस्त, 1949

हिन्दी और देवनागरी

नई दिल्ली, ७ अगस्त। यहां एकत्र हुए भारतवर्ष की समस्त मुख्य भाषाओं के विद्वानों की परिषद ने सर्वसम्मति से यह व्यवस्था दी है कि भारतीय संविधान में भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी स्वीकृत की जाये। परिषद ने यह भी निश्चय किया है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरप्रान्तीय कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी प्रतिष्ठित की जाये और इस परिवर्तन कार्य में १० वर्ष से अधिक समय न लगाया जाये। परन्तु परिषद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत संघ के विभिन्न प्रान्त अपने-अपने क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने में स्वतंत्र रहेंगे।

राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न भागों के विविध भाषाओं के विद्वानों की यह परिषद हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा बुलाई गई थी, जो दो दिन के अधिवेशन के बाद आज रात को ८ बजे तीन प्रस्ताव पास करके समाप्त हो गई। लगभग एक सौ विद्वानों ने परिषद की बैठक में भाग लिया। काशी विश्वविद्यालय के श्री एन एन गोडबोले सभापति थे। यह एक उल्लेखनीय बात है कि इन प्रस्तावों के प्रस्तावक, अनुमोदनकर्ता व समर्थक सभी अहिन्दीभाषी हैं। आज राष्ट्रभाषा व्यवस्था-परिषद का दूसरा और अन्तिम दिन था। परिषद की कार्रवाई तीसरे पहर दो बजे आरम्भ हुई।

राष्ट्रभाषा सम्बन्धी प्रथम प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मद्रास विश्वविद्यालय के डा. कुन्हन राजा (मलयालम) ने कहा कि भारतीय विधान परिषद को राष्ट्रभाषा का प्रश्न संविधान के सबसे पहले निर्देश-पत्र में ही एक बुनियादी सिद्धान्त के रूप में लेना चाहिए था। जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रभाषा कभी विद्वानों के बनाने से नहीं बना करती, वह जन-साधारण द्वारा अपने आप बना करती है, वे गलती पर हैं। अंग्रेजी भाषा को क्या लन्दन के टैक्सी ड्राइवरों ने बनाया है? भाषाएं हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बल पर ही फलती-फूलती हैं। आपने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिन्दी को केवल राष्ट्रभाषा घोषित करके ही न छोड़ दिया जाये। यदि बाद में भी सब आवश्यक कार्यों में अंग्रेजी को ही बनाये रखना है, तब तो हिन्दी को बतौर नाम की राष्ट्रभाषा स्वीकार करना व्यर्थ है। लिपि के बारे में डा. कुन्हन राजा ने कहा कि जब आप हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं, तो देवनागरी अपने आप उसमें आ जाती है।

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

हथकरघा और हस्तशिल्प की गौरवशाली परंपरा में अलग-अलग प्रदेशों की कलात्मक संस्कृति और विशिष्टता प्रदर्शित होती है। स्वदेशी के उत्थान और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में निश्चय ही इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

आज भी अदालतों में मिलती सिर्फ तारीखें

अनुलोम-विलोम
अदालतों पर बोझ

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के मौके पर लोक अदालत लगाई गई थी और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग अदालती मामलों से 'इतने तंग' आ गए हैं कि वे बस समझौता चाहते हैं। ऐसे में, लोक अदालतें ऐसा मंच हैं, जहां न्यायालयों में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों व मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से होता है। चूंकि यह पारस्परिक रूप से स्वीकृत समझौता होता है, इसलिए इसके विरुद्ध अपील भी नहीं दायर की जाती। बेशक प्रधान न्यायाधीश की मंशा असंदिग्ध है और वह चाहते हैं कि अदालती-प्रक्रिया कहीं अधिक सुगम और सरल बने, लेकिन सवाल यह है कि लोग मुकदमों से आखिर इतने त्रस्त या परेशान क्यों होते हैं? क्या यह सच नहीं है कि इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए वे कोई भी समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यह नहीं किया, तो अदालतों में सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिलेंगी?

आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? दरअसल, भारत में आज भी जजों की कमी एक बड़ा मसला है। माना जाता है कि निचली अदालतों में ही पांच हजार के करीब जजों की कमी है। इसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा लंबित मामले भी निचली अदालतों में ही हैं। वहां सवाल सिर्फ जजों का नहीं है, बुनियादी ढांचे का भी काफी अभाव है। दुखद है कि यह कमी बदस्तूर ऊपरी अदालतों तक कायम है। बेशक, वहां निचली अदालतों की तुलना में जजों की कमी का प्रतिशत कम है, लेकिन समस्याएं वहां भी कम नहीं हैं। ऐसे में, होना तो यही चाहिए कि अदालतों में सुधार के प्रयास किए जाते, लेकिन इसको लेकर गंभीर प्रयासों का अभाव रहा है।

बहरहाल, प्रधान न्यायाधीश की इस टिप्पणी के बाद उम्मीद है कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने की दिशा में ठोस प्रयास किया जाएगा। उन्होंने लोक अदालतों से उम्मीद जताई है, दुआ कीजिए कि उनकी यह आशा पूरी हो। लोक अदालतों का असर तभी सकारात्मक नजर आएगा, जब निचली अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम होगा। आज वक्त न्यायिक व्यवस्था में सुधार का है। तमाम विश्लेषक यही मानते हैं कि लोग अदालतों में आते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन यहां आकर उन्हें हमेशा दुख और परेशानी ही मिलती है, जिसे आप एक तरह से सजा ही कह सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अदालत आकर पीड़ित ही दोषी बन जाता है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास आवश्यक हों, वे संबंधित विभागों अथवा मंत्रालय को करना चाहिए।

मनमोहन राजावतराज, टिप्पणीकार

शीघ्र सुनवाई का रखा जा रहा ख्याल

यह सच है कि तमाम प्रयासों के बावजूद अदालतों की प्रक्रिया अब भी सरल नहीं बन सकी है। यहां मुकदमों के निपटारे में आज भी काफी वक्त लगता है। आंकड़े भी बताते हैं कि देश भर में सात करोड़ से अधिक मुकदमे विभिन्न स्तर पर लंबित पड़े हैं। मगर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालतें भी इसी का एक हिस्सा हैं, जिनका सकारात्मक असर दिखा है। कहा तो अब यह भी जा रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालयों में 12 प्रतिशत के करीब और शीर्ष अदालत में महज एक प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं। साफ है, लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों में कमी लाने की सार्थक पहल की गई है। इतना ही नहीं, मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वमान्य समाधान की खोज भी गंभीरता से की जा रही है, ताकि अदालतों का बोझ तेजी से कम हो सके।

एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि मुकदमों की प्रकृति के अनुसार उनको विभाजित करना सुखद हो सकता है। इससे समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनको निपटाना आसान हो जाएगा। इसी तरह, कुछ ऐसे मुकदमे भी होते हैं, जिनको आसानी से निपटाने की योजना बनाई जा सकती है। इनमें विशेषकर यातायात नियमों से जुड़े मामले हो सकते हैं, जिनके निपटारे की त्वरित व्यवस्था बनाना लाभदायक हो सकता है। वैसे, अच्छी बात यह भी है कि लोगों को अदालती बोझ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और उन्हें या तो मुकदमों में बेवजह उलझने से बचने या फिर आपसी सामंजस्य से मामले का निपटारा करने को कहा जा रहा है। वाकई, आज किसी को कुछ भी हो, वह फौरन कोर्ट में 'देख लेने' की धमकी देने लगता है। ऐसा कहते हुए वह दरअसल खुद ही मजाक का पात्र बन रहा होता है। क्या उसको यह नहीं पता कि अदालतों पर मुकदमों को बोझ कम करने के प्रयास हो रहे हैं? ऐसे में, मामूली कहासुनी का उनका मामला कहां टिक सकेगा?

भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सच यह भी है कि यहां ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक मामलों की सुनवाई एक दिन में होती है। आंकड़ों की मानें, तो ब्रिटेन में जहां एक दिन में एक न्यायाधीश तीन से चार मामलों में फैसला सुनाते हैं, वहीं अपने देश में यह संख्या औसतन 40 से 50 मुकदमों की सुनवाई की है। ऐसे में, अधीरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मामले दिनोंदिन और कम होते जाएंगे और आने वाले दिनों में अदालतों में मुकदमों का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा।

सौरभ कुमार, टिप्पणीकार

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 अगस्त, 2024

दैनिक जागरण

पराजय में भी अगली विजय के लिए सबक छिपा होता है

ओलिंपिक में अनहोनी

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेरिस ओलिंपिक में पदक की सुनिश्चित दावेदार विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गईं। उनसे स्वर्ण पदक की आशा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले के सभी मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई नामी पहलवानों को हराया था, लेकिन अंतिम मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वजन सौ ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही उनका सपना तो टूटा ही, देशवासियों की आशाओं पर भी तुषारापात हो गया। चूंकि एक तरह से हाथ आया पदक फिसल गया, इसलिए अफसोस अधिक है। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रसंग से सबक भी लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो। इस ओलिंपिक में विनेश ने 53 किलोग्राम के अपने स्वाभाविक भार वर्ग को छोड़कर 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ना तय किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह अपने वजन को नियंत्रित रखने का उतना अभ्यास नहीं कर पाईं, जितना आवश्यक था। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जितनी किसी खिलाड़ी की होती है, उतनी ही उसके कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी। विनेश के मामले में कहां क्या चूक हुई, इसकी जवाबदेही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की है। उन्होंने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा है और यह स्पष्ट किया है कि विनेश का वजन नियंत्रित रखने के लिए वह सब कुछ किया गया, जो संभव था, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ भूल-चूक हुई ही। यह किन कारणों से हुई, यह सामने आना चाहिए।

विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने और इस तरह भारत के पदक से वंचित होने पर देशवासियों की ओर से अपनी निराशा व्यक्त किए जाने के बीच कुछ नेताओं की ओर से जैसे अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं, वे उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शा रहे हैं। यह समझ आता है कि उन्हें न खेल की जानकारी है और न ही खेल के नियमों की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे जो मन में आए, वह बोल दें। कोई विनेश के साथ साजिश की कहानी गढ़ रहा है तो कोई उन्हें अयोग्य करार देने में किसी नेता का हाथ देख रहा है। यह सब इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ धरना-प्रदर्शन में भाग लिया था। निःसंदेह विनेश का मुकाबले से बाहर हो जाना और उन्हें कोई पदक न मिलना आहत करने वाला है, लेकिन खेलों के अपने नियम होते हैं। वे हमारे या किसी अन्य के हिसाब से नहीं बन सकते। विनेश के मामले में साजिश की कहानियां गढ़ रहे लोग इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ था। इस मामले में कम से कम नेताओं की प्रतिक्रियाएं जगहंसाई कराने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है।

बच सकेंगी जानें

बिहार में दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से वे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस आशय का निर्देश राज्य के सभी सिविल सर्जन, निजी और सरकारी अस्पतालों को भेजा गया है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है और निश्चित तौर पर इससे सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम किए जाने में मदद मिलेगी। अभी बिहार में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। यहां सड़क हादसों के 78 प्रतिशत मामलों में घायलों की जान चली जाती है। मिजोरम के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य है, जहां इतनी ज्यादा जनहानि होती है। इन मौतों में तभी कमी लाई जा सकती है जब घायलों को समय पर उपचार मिल जाए। अभी अस्पताल ले जाने के बाद तमाम औपचारिकताओं में वक्त जाया होता है। ज्यादातर अस्पताल मरीज की तीमारदारी शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि इलाज का पैसा कौन देगा। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद अस्पताल बिना वक्त बर्बाद किए घायलों का उपचार करेंगे और कई परिवारों को जिंदगी भर मिलने वाले दर्द से दूर रखने में कामयाब होंगे। इस आदेश का ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि घायलों की मदद कर अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ना होगा। पैसे के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। लोगों को तो यह भी नहीं पता कि घायलों को मदद पहुंचाने वालों को सम्मानित तक किया जाता है। जाहिर तौर पर इसका प्रचार प्रसार होगा तो घायलों को मदद पहुंचाने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य में ट्रामा सेंटर व एंबुलेंस की व्यवस्था को भी और सघन किए जाने की जरूरत है। एनएच किनारे एंबुलेंस की संख्या बढ़ेगी तो शीघ्र से शीघ्र घायलों को डाक्टर के पास ले जाया जा सकेगा। गोल्डन आवर में समय पर इलाज शुरू हो जाए तो कई घायलों का जीवन बचाया जा सकता है।

अस्थिर पड़ोसियों से घिरता भारत

ऋषि गुप्ता

बांग्लादेश में तख्तापलट और अराजकता के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है। यह स्थिति भारत के हित में नहीं

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के मुद्दे पर भारतीय संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ बैठक के बाद स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया और 'कुछ समय के लिए' उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत में हैं और माना जा रहा है कि वह किसी तीसरे देश में शरण मिलने तक यहीं रहेंगी। यदि इस हालात को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक असाधारण स्थिति है, जहां भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मदद भी करनी है। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई अनधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम से देश के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति पैदा हो गई है। भारत के समक्ष 1971 वाली स्थिति फिर एक बार बन पड़ी है। बांग्लादेश में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समूह खासकर बड़ी संख्या में हिंदू भारत में शरणार्थी के तौर पर आने की गुहार लगा सकते हैं। इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं।

अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता है, जिसकी भरी-पूरी आशंका है तो भारत की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ गुटों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इसके चलते ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे हैं। पाकिस्तान आज तक भारत को अपने विभाजन यानी बांग्लादेश के निर्माण का कारण मानता रहा है और वह कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी और असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया जाए। बांग्लादेश में अराजकता के बीच दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है, जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीते दिनों ही नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। ओली को 'इंडिया आउट' अभियान का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी राजनीतिक साख मजबूत करने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया है। चूंकि ओली की 'राष्ट्रवादी छवि' भारत विरोध से बनी है, लिहाजा भारत के लिए जरूरी है कि वह स्थिति पर नजर रखे। यदि नेपाली जनता पुरानी पार्टियों और पुराने नेताओं की कार्यशैली से ऊबती है तो 2006 जैसा जन आंदोलन छिड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका सीधा असर खुली सीमा के चलते भारत पर होगा। नेपाल के बगल में ही भूटान है, जो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर फिक्रमंद है और एक मित्रतापूर्ण सहयोगी रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने वहां भी अपनी पैठ बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भारत के लिहाज से भूटान में स्थिति नियंत्रण में है।

अवधेश राजपूत

पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। यहां विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं। यहां अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा एजेंसिया भारत-म्यांमार सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। यदि बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश में साथ आती हैं तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। नई दिल्ली के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी लुक-ईस्ट और एक्ट-ईस्ट नीति में सुरक्षा पहलुओं को भी शामिल करे। म्यांमार में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। यह सही है कि श्रीलंका धीरे-धीरे भारत और आइएमएफ की मदद से आर्थिक मुसीबतों से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी वहां भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। मालदीव भी इस मामले में अलग नहीं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोध में लगे हुए हैं। उन्होंने भी ओली की तरह 'इंडिया आउट' अभियान चलाया, फिर वह चाहे भारतीय सैन्य अधिकारियों का मालदीव से भारत वापस भेजने का मुद्दा रहा हो या फिर उनकी सरकार के मंत्रियों का भारत और भारत के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ टीका-टिप्पणी का मामला।

पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही भारत के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हाल में जम्मू में हुए आतंकी हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाने का काम किया है। यदि पड़ोसी देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत इन सभी देशों की सीमाओं के जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दक्षिण एशिया में बड़े लंबे समय से भारत की केंद्रीयता को सभी समस्याओं की जड़ माना जाता रहा है और भारत पर लगभग सभी पड़ोसी देश हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते आए हैं, लेकिन क्या अब यही देश अपनी आंतरिक हलचल के चलते भारत के सामने मौजूद सुरक्षा संकट पर नई दिल्ली के साथ खड़े होंगे? इसका जवाब संभवतः नकारात्मक ही मिले। दक्षिण एशिया में जैसी असामान्य परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए भारत को असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत को हर कीमत पर अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है और पड़ोसी देशों में सिविल सोसायटी समूहों के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों और क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है कि वे भारत की चिंताओं को समझें और अपने स्तर पर पाकिस्तान और चीन पर दबाव डालें, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत को परेशान करने के लिए नई तिकड़में न कर सकें।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

युवाओं में कौशल विकास की चुनौती

डा. सुरजीत सिंह

यह समझा जाना बहुत आवश्यक कि अपने देश में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है

बजट पेश होने के बाद उसके प्रस्तावों पर अमल की दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में सभी की निगाहें रोजगार सृजन की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर टिकी हैं, जिन्हें हालिया बजट का सबसे विशिष्ट पहलू माना जा रहा है। कौशल, नवाचार और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विशेष प्रविधान किए हैं। इसमें इंटर्नशिप योजना को खासी चर्चा भी मिली है। इससे न केवल रोजगार के आकांक्षियों के हितों की पूर्ति होगी, बल्कि उद्योगों को भी अपने अनुकूल कौशल से लैस लोग मिलेंगे। इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बल्कि निवेश संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे सरकार की यह मंशा भी प्रकट हुई है कि अगले पांच वर्षों में वह रोजगार, कौशल और एमएसएमई पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को भुनाने की राह में कार्यशील आबादी में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी न होने का संज्ञान भी सरकार ने लिया है। इसके लिए कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल के निकट महिला हास्टलों और शिशु देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी फोकस किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में भी उल्लेख है कि देश में बढ़ते कार्यबल के समायोजन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करनी होंगी। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई। बजट में युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। कुल मिलाकर, पांच साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षित, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए बजट में प्रविधान है कि पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को शुरुआती चार वर्षों में ईपीएफओ में योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। नियोक्ताओं को सहायता देते हुए यह उपाय भी किया गया है कि सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के संबंध में नियोक्ता के ईपीएफओ में अंशदान के लिए उन्हें दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री की यह पहल औपचारिक रोजगार सृजन की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है, जिससे सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिकता के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी। इससे अधिक स्नातकों को नौकरी के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

बढ़ानेहोंगे रोजगार के अवसर। फाइल

भारत में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। बढ़ती श्रमशक्ति और कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की दृष्टि से पांच वर्षों में देश की 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना एक बाजी पलटने वाली योजना सिद्ध हो सकती है, लेकिन तभी जब कंपनियां इस योजना में रुचि दिखाएं। इस योजना में 5,000 रुपये के मासिक भत्ते और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता आकर्षक पहलू हैं। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल प्रदान करना है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान करने के साथ ही हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के तीन प्रतिशत ब्याज में छूट भी मिलेगी। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 1000 आइटीआइ को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा। उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे नई उभरती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर जोर देने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलने के आसार हैं। प्रत्येक वर्ष 25,000 कुशल व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक का गारंटीकृत ऋण प्रदान करना निश्चित रूप से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने से इस क्षेत्र की तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है। पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल विभाग का नाम भी बदलकर कौशल, रोजगार और आजीविका कर दिया है। बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन से आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, केंद्र के स्तर पर तमाम पहल तभी सफल हो पाएंगी, जब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करेंगी। इन कार्यक्रमों को यदि गंभीरता से लागू किया जाता है तो भारत को एक अग्रणी स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

संबंधों की सजीवता

किसी की संगति में ही उस व्यक्ति के प्रति गहरी समझ और संवेदना विकसित होती है। यह मेलजोल प्रायः लोगों की समान रुचियों, सोच और जीवन की दिशा पर आधारित होता है। एक दूसरे के सान्निध्य और संगति में दोनों एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और एक मजबूत संबंध की नींव रखते हैं। यह संबंध तब फलता-फूलता है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे के महत्व को समझते हैं। स्मरण रहे कि कोई भी संबंध सब कुछ सह लेता है, लेकिन उपेक्षा नहीं सह सकता है। समय के साथ व्यक्ति का सोच और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी-कभी ये बदलाव धीरे-धीरे व्यक्ति को अपने पूर्व संबंधों से दूर भी कर देते हैं। किसी नई जिम्मेदारी या नई रुचियों के कारण व्यक्ति पुरानी मित्रता को उतना समय और महत्व नहीं दे पाता है,जितना पहले देता था। इस प्रक्रिया में वह दूसरे व्यक्ति को उपेक्षित महसूस करा सकता है। प्रायः व्यक्ति को उस संबंध में वह अनुभूति नहीं मिलती, जो पहले अनुभव होती थी। जब किसी संबंध में नवीनता समाप्त हो जाती है, तो उदासीनता का भाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति उस संबंध को महत्व देना बंद कर देता है।

इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने संबंधों के प्रति संवेदनशील रहे। अगर किसी संबंध में कोई परिवर्तन आता भी है तो इसे ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है और उनके महत्व को पुनः स्वीकार कर सकता है। संबंधों में उतार-चढ़ाव और परिवर्तन सामान्य हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को महत्व देना और उसकी उपेक्षा न करना हमारे संबंधों की मजबूती के लिए एक आवश्यक अवयव है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

भुखमरी खत्म करने की जरूरत

रवि शंकर

यह कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है

दुनिया में आज हर 11वां इंसान खाली पेट सोने को मजबूर है। दुनिया में 73.3 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। यदि 2019 की तुलना में देखें तो इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह जानकारी 'द स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024'' नामक रिपोर्ट में सामने आई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है।

साफ है भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय करना है। यह कैसी विडंबना है कि एक ओर हमारे और आपके घरों में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और वे भूख से जूझ और मर रहे हैं। दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है, उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों के भोजन की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। दुनिया में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। खाद्यान्न की क्षति और बर्बादी न केवल संसाधनों के कुप्रबंधन का मुद्दा है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आठ प्रतिशत के लिए खाद्य अपशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं।

ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी धन और संसाधनों की कोई कमी है, दरअसल समस्या आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की है। वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्पविकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रयास भी करती हैं और विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहां तक कि विकास दर के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है कैसे आगे बढ़ रहा है? ऐसे में जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए जो आपको यह बताए कि अभी तो देश 'भूख' जैसी 'समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े झूठे लगने लगते हैं। यह कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भारत को रहना होगा सतर्क

'अराजकता में डूबा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में दिव्य कुमार सोती ने आशंका जाहिर की है कि चीन और अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। वहां उन्हें कठपुतली सरकार मंजूर थी। चूंकि चीन अधिनायकवादी देश है तो यह बात समझ में आती है, मगर अमेरिका जो पुराने लोकतंत्रों में से एक है। उसे तो बांग्लादेश में लोकतंत्र प्रेमी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए था। उसे भारत का भी ध्यान रखना चाहिए था, जिससे उसके मित्रतापूर्ण संबंधों के कई फायदे हैं। बहरहाल यह देखने वाली बात है कि उन राष्ट्रों में लोकतंत्र कभी सफल नहीं रहा, जहां मजहबी कट्टरपंथी ताकतें मजबूत रही हैं। लिहाजा लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी तरह के कट्टरपंथ को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। जहां कट्टरपंथ अपना सिर उठाता है या उठाने की आशंका रहती है, वहीं विदेशी महाशक्तियों के दखल संभव होते हैं। भारत को नई परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो

बांग्लादेश में रह रहे डेढ़ करोड़ हिंदुओं और 19,000 भारतीयों की सुरक्षा चिंतनीय विषय है। सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि हिंसा और आगजनी पर आमादा कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के समर्थक और तख्तापलट करने वाले तत्वों के साथ भारत सरकार का कोई संपर्क भी नहीं है। यही स्थिति पाकिस्तान में दशकों से है और इसी कारण हिंदुओं के साथ बड़े स्तर पर हिंसा हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या नगण्य होती जा रही है। यह तब की स्थिति है, जब बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा 95 प्रतिशत भारत से घिरी हुई है। ऐसी भौगोलिक स्थिति चीन के साथ होती तो चीन बांग्लादेश को निगल गया होता। वैश्विक मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीति अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा पर केंद्रित है। इसलिए जहां भी इस्लामिक राष्ट्रों में कट्टरपंथी सरकारें हैं वहां हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हिंसा लगातार होती है। उनके मंदिर और चर्च नष्ट किए जाते हैं। भारत को इस विषय में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा और भारत के विपक्षी दलों को भी वोटबैंक की राजनीति को छोड़कर विश्वभर में हिंदुओं की सुरक्षा के हित सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। इस्लामिक व्यवस्था में उनका भी कोई वजूद नहीं है। जब तक हिंदू हैं तभी तक उनका भी अस्तित्व है। किसी वामपंथी, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी पार्टी का किसी इस्लामिक देश में कोई वजूद ही नहीं है। भारत में सबसे अधिक मुस्लिम हैं और सौभग्यवश चैन से हैं अन्यथा शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरा के कुचक्र के दमनचक्र के शिकार हो रहे होते। भारत को सभी इस्लामिक देशों में हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए, जिससे वह आपत्ति के समय भारत वापस आ सकें। बांग्लादेश का जो भी भविष्य हो लेकिन दीर्घ समय तक वहां अस्थिरता रहेगी। उसको चीन और अमेरिका के लिए अपने धरती पर युद्ध भूमि तैयार करने की चुनौती है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

अराजकता में डूबा बांग्लादेश

चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार की दोस्ती नई दिल्ली से गहरी थी। शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंध बाधित हो सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच अच्छा-खासा व्यापार होता रहा है। शेख हसीना के जाने से दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। मसलन तीस्ता सिंचाई परियोजना पर चीन अपनी नजर जमाए हुआ था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग के आफर से शेख हसीना ने अपनी नीतियां भी बदलीं। युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है। वह सिर्फ अपने हित देखता है। -हेनरी किसिंजर

ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचने वाली विनेश फोगाट को कुछ ग्राम अधिक वजन होने के चलते अयोग्य घोषित किया जाना चौंकाने वाला है। गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण होना ही चाहिए, लेकिन उनका खाली हाथ रह जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कुछ ग्राम वजन और उम्मीदें

ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचने वाली विनेश फोगाट को ऐन फाइनल मुकाबले से पहले निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित किया जाना चौंकाने वाला है और यह उनके साथ उन करोड़ों देशवासियों के लिए भी झटका है, जो उनसे 'स्वर्ण' की उम्मीद लगाए हुए थे। उल्लेखनीय है कि ओलंपिक के नियमों के अनुसार, पहलवानों को प्रतियोगिता के दिनों में अपने वजन-वर्ग में ही रहना होता है। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही हैं, इससे पहले तक वह 53 किलोग्राम के वर्ग में हिस्सा लेती थीं। फाइनल वाले दिन तक विनेश का वजन पचास किलोग्राम की स्वीकार्य सीमा से करीब सौ ग्राम अधिक था और यही प्रतियोगिता में उनके बाहर होने की वजह बना। दरअसल वजन में कमी लाना एक ऐसी लड़ाई है, जिससे खासकर पहलवानों को जूझना ही पड़ता है। इसमें खिलाड़ियों को जो मुश्किल आती है, वह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक के शब्दों से जाहिर होती है कि पहलवान केवल वजन घटाने के लिए ही पदक के हकदार हो जाने चाहिए। हालांकि खासकर पहलवान अपने शरीर को पहचानते हैं और उसके अनुरूप ही अपने वजन को नियंत्रण में रखते हैं। फोगाट के साथ यह स्थिति कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में क्वालीफाइंग राउंड के दौरान भी वह कुछ सौ ग्राम ज्यादा वजन के चलते बाहर हुई थीं। हालांकि तब एक दूसरे वर्ग में खेलते हुए विनेश अच्छा कर रही थीं, लेकिन फिर चोट की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी वह कुछ खास नहीं कर पाई थीं। ऐसे में, पेरिस ओलंपिक में उन पर सबकी नजर थी। गौरतलब है कि पिछले साल की शुरुआत में, फोगाट उन तीन भारतीय पहलवानों में से एक थीं, जिन्होंने भारत के कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर

कथित आरोप लगाए थे। अब विनेश के ओलंपिक से बाहर होने पर बातें होंगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि उनके लिए अब तक यह ओलंपिक शानदार रहा था और उन्होंने फाइनल राउंड तक पहुंचने के क्रम में मौजूदा चैंपियन जापान की युई सुसाकी को हराने के साथ ही यूक्रेन व क्यूबा की खिलाड़ियों को भी हराया था। फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से होना था, जिन्हें वह पहले भी हरा चुकी हैं। गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ग्राम वजन अधिक होने की वजह से विनेश को ओलंपिक से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, तो यह दुर्भाग्य ही है।

शिकार बनीं हसीना

शेख हसीना दक्षिण एशिया की जटिल अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनीं। वह अमेरिका और चीन के हितों में बाधक बन रही थीं। आईएसआई और खालिदा जिया के पुत्र लंदन से साजिशें रच रहे थे। जमात के इरादे स्पष्ट थे। जाहिर है, छात्र आंदोलन की आग में कई ताकतें रोटियां सेंक रही थीं।

इसमें तनिक भर भी संदेह नहीं है कि शेख हसीना के नेतृत्व में दक्षिण एशिया में उभर रही राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग कई देशों की आंखों में चुभ रहा था। भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने न केवल विद्रोह और आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र में व्यवस्था कायम की, साथ ही, आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। ऐसे परिदृश्य में जब वह इसी वर्ष जून से पहले बांग्लादेश पर मजबूती से नियंत्रण रखती दिखाई दी हों, तो उनके तख्तापलट में विदेशी भागीदारी के होने का संदेह जताया जाना, चौंकाता नहीं है।

हसीना के तख्तापलट में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताने वाले अक्सर अमेरिका को प्रमुख संदिग्ध के रूप में इंगित करते हैं। दरअसल, बांग्लादेश की आजादी से भी पहले वहां के एक सैन्य अड्डे पर अमेरिका की नजर है। इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका ने सेंट मार्टिंस द्वीप पर सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति के बदले पूर्वी पाकिस्तानी नेताओं को समर्थन की पेशकश की थी। यह बात दीगर है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की आजादी के बाद भी अमेरिका इसके लिए प्रयास करता रहा। यह मुद्दा खासकर वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बांग्लादेश यात्रा के दौरान द्विपक्षीय यात्राओं में अक्सर उठता रहा। हाल ही में शेख हसीना ने भी खुलासा किया था कि अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने बांग्लादेश में अमेरिकी सैन्य अड्डे के प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया था। हालांकि अपने राष्ट्रवादी रुख और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को नहीं बेचेंगी। इसके अतिरिक्त, अमेरिका बांग्लादेश को अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति में शामिल करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसका लक्ष्य अमेरिका के साथ उसके रक्षा संबंधों को मजबूत करना और उसे

सैन्य उपकरण बेचना है। बांग्लादेश ने अमेरिकी हथियारों में तो रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें इंडो-पैसिफिक ढांचे के तहत खरीदने से इन्कार किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका प्राथमिक सैन्य आपूर्तिकर्ता चीन नाराज हो जाएगा।

हसीना को सत्ता से बेदखल करने में एक और विदेशी शक्ति के शामिल होने का संदेह है और वह है चीन। बहुआयामी संबंधों के बावजूद भारत और बांग्लादेश की बढ़ती निकटता से चीन के असंतोष का बढ़ना छिपा नहीं है। कई रिपोर्ट तो यह खुलासा भी करती हैं कि चीन ने हसीना को सलाह दी थी कि वह अपनी चीन यात्रा से पहले भारत की यात्रा न करें। हालांकि हसीना ने चीन की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था।

चीन मुख्य रूप से अपनी बेल्ट ऐंड रोड पहल (बीआरआई) परियोजनाओं और देशों के साथ व्यक्तिगत सैन्य सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का इच्छुक रहा है। गौरतलब है कि चीन और भारत दोनों ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी पर जल प्रबंधन परियोजना में रुचि जताई है। हालांकि अपनी भारत यात्रा के दौरान शेख हसीना ने यह पुष्टि की थी कि वह भारत के साथ संवेदनशील और राजनयिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को भारत को सौंपेंगी। दरअसल, बांग्लादेश की भविष्य की जल संबंधी जरूरतों के लिहाज से तीस्ता नदी के ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका के कर्ज संकट के बाद दक्षिण एशियाई देश चीन से कर्ज लेने में जो अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं, उसने भी हसीना के निर्णय में बड़ी भूमिका निभाई।

जुलाई की अपनी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा संकट को कम करने के लिए पांच अरब डॉलर के कर्ज को हासिल करने की हसीना की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं, जब चीन ने महज दस करोड़ डॉलर की पेशकश की। यही नहीं, उन्हें अपेक्षित प्रोटोकॉल भी नहीं मिला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें पर्याप्त समय तो नहीं ही दिया, चर्चा को आगे बढ़ाने का दायित्व भी प्रधानमंत्री ली केकियांग पर छोड़ दिया। निराश होकर हसीना को अपना दौरा छोटा करना पड़ा। चीन के इस तरह के व्यवहार से गहरी रणनीतिक गणनाओं के संकेत मिलते हैं, जो उनके तख्तापलट में चीन की भागीदारी के बारे में लगाए जा रहे अनुमानों को मजबूत आधार भी देते हैं।

दक्षिण एशिया में चीन का सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तान भी संदेह पैदा करता है। भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते पाकिस्तान को हमेशा से ही नागवार गुजरे हैं। हसीना के कार्यकाल से पहले पाकिस्तान के आतंकी समूह बांग्लादेश में अपेक्षया ज्यादा आजादी के साथ काम करते थे। 2009 में हसीना द्वारा बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने बांग्लादेश राइफल्स के भीतर विद्रोह भड़का कर उनकी सरकार को अस्थिर बनाने का असफल प्रयास भी किया था।

हालांकि हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन ने हसीना के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दीं। बीएनपी के साथ ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध करने वाले जमात-ए-इस्लामी कैडरों ने भी छात्र आंदोलन का पूरा फायदा उठाया। नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम लड़ा गया, तब जमात ने अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उनके सदस्यों को ही रजाकार कहा जाता था। यह संकेत भी मिलते हैं कि विपक्षी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने कथित तौर पर लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों के चलते लंदन में रह रहे तारिक अब बांग्लादेश वापसी कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी भागीदारी साबित करना तो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये देश खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन यह स्पष्ट है कि छात्र आंदोलन ने अराजकता की जो आग भड़काई, उसमें कई विदेशी ताकतों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। भू-राजनीतिक पेचीदगियां यह भी रेखांकित करती हैं कि शेख हसीना किस तरह दक्षिण एशिया की जटिल अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनीं।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपी-आईडीएसए

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

अल्बर्ट आइंस्टीन

हम सभी कलाकार हैं और अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तर्क और ज्ञान 'ए' से 'जेड' तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी।

कल्पना करना सीखें और सुंदर संसार बनाएं

जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि मानो कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा यह कि मानो सब कुछ चमत्कार है। हम सभी एक कलाकार हैं और अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है। कल्पना दुनिया को घेर लेती है। तर्क और ज्ञान आपको 'ए' से 'जेड' तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। हमारा जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। और कभी गलती करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मनुष्य उस समग्रता का एक हिस्सा है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, समय और स्थान में सीमित एक हिस्सा। वह खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी सब से अलग अनुभव करता है, यह चेतना का एक प्रकार का दृष्टि संबंधी भ्रम है। यह भ्रम हमारे लिए एक प्रकार का कारागार है, जो हमें हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारे सबसे करीबी कुछ लोगों के प्रति स्नेह तक सीमित कर देता है।

हमारा काम सभी जीवित प्राणियों और पूरी प्रकृति को उसकी सुंदरता में गले लगाने के लिए अपनी करुणा के दायरे को बढ़ाकर खुद को इस कैद से मुक्त करने का होना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग छोटी-छोटी बातों में सत्य के प्रति लापरवाह हैं, उन पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा जो सोचते हैं, उससे चीजें अलग होती हैं। कुछ बातें, जो सही हैं, वे हमेशा लोकप्रिय नहीं होतीं और जो लोकप्रिय है, वह हमेशा सही नहीं होता। और आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसको हम लोगों ने ही बनाया है, वह हमारी सोच की प्रक्रिया है। सोच बदले बिना हम इसे बदल नहीं सकते। इस बदलाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग हार मानते हैं, जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बुद्धि स्कूली शिक्षा का परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयास करने होते हैं। हमें उस एकांत में रहना चाहिए, जो युवावस्था में कष्टदायक है, लेकिन परिपक्वता के वर्षों में सुखद हो। कुछ लोग हमारे आसपास केवल इसलिए अच्छे हैं, क्योंकि वे दंड से डरते हैं और पुरस्कार की आशा करते हैं, तो यह वास्तव में बहुत दुखद है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा न हो और भविष्य में आपके बच्चे बुद्धिमान बनें, तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान बनें, तो उन्हें अधिक परियों की कहानियां सुनाएं। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब कोई अनंत काल, जीवन और वास्तविकता की अद्भुत संरचना के रहस्यों पर विचार करता है, तो वह विस्मय में पड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस रहस्य को थोड़ा-बहुत समझने का प्रयास करता है, तो यह पर्याप्त है।

प्रकृति को गहराई से देखें

सूत्र

केवल दूसरों के लिए जीया गया जीवन ही जीने योग्य है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए नहीं जीना चाहता, सभी अपने लिए जीना चाहते हैं। और इसका परिणाम उन्हें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को गहराई से देखना होगा, और तभी हम कुछ सीख पाएंगे और सब कुछ बेहतर समझ पाएंगे।

दूसरा पहलू

वैज्ञानिक डेविड कीथ सूर्य की कुछ रोशनी को रोकने के लिए आकाश में एक प्रदूषक पदार्थ का छिड़काव करना चाहते हैं।

सूरज की किरणों को रोकने की खतरनाक योजना

डेविड कीथ 1991 में जब स्नातक के विद्यार्थी थे, तब फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फटा और आकाश में दूर तक राख के बादल छा गए थे। माउंट पिनाटूबो से निकला 1.7 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में फैल गया, जो सूर्य की कुछ ऊर्जा को धरती तक आने से रोक रहा था। इसी वजह से अगले वर्ष उत्तरी गोलार्ध के औसत तापमान में एक डिग्री फारेनहाइट की गिरावट आई थी। उस घटना का जिक्र करते हुए, 60 वर्षीय डॉ. कीथ कहते हैं कि उससे उन्हें एक अद्भुत विचार आया कि समताप मंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छिड़कने से दुनिया भर के तापमान को कम किया जा सकता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सकेगा।

डेविड गेल्स

पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की दिशा को तकनीकों के सहारे उलट देने के प्रयासों में पूरी दुनिया रुचि दिखा रही है, जिसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं।

डॉ. कीथ कहते हैं, 'अगर तकनीक से तापमान को केवल एक डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फारेनहाइट तक भी कम कर दिया जाता है, तो यह हर दशक में गर्मी से होने वाली लाखों मौतों को रोकने में मदद कर सकती है।'

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर, इस तरह के हस्तक्षेपों को गंभीरता से लिया जा रहा है। वैश्विक तापमान लगातार रिकॉर्ड 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिससे चरम मौसमी घटनाएं, घातक गर्मी की लहरें और समुद्र का स्तर बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह गर्मी अगले कई दशकों तक यों ही बढ़ेगी। वार्मिंग का मुख्य कारक, जीवाश्म ईंधन का जलना बताया जाता है, जो बेरोकटोक जारी है। यही वजह है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की दिशा को तकनीकों के सहारे उलट देने के प्रयासों में पूरी दुनिया रुचि दिखा रही है, जिसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वैक्यूम करके भूमिगत करने के वृहद प्रयास पहले से चल रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक बादलों को चमकाने के प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस भेजने के तरीके ईजाद कर रहे हैं।

अन्य लोग महासागरों व पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में सक्षम बनाने के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। लेकिन समताप सोलर जियोइंजीनियरिंग इन सब विचारों से परे है। इस विधि के जो समर्थक हैं वे इसे तापमान को कम करने का सस्ता और तेज तरीका मानते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक व पर्यावरणविद आशंकित हैं कि इस तकनीक के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित आपदाएं भी आ सकती हैं। इसके विपरीत डॉ. कीथ कहते हैं, 'अगर तकनीक से तापमान को केवल एक डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फारेनहाइट तक भी कम कर दिया जाता है, तो यह हर दशक में गर्मी से होने वाली लाखों मौतों को रोकने में मदद कर सकती है।' वह कहते हैं, 'सोलर जियो इंजीनियरिंग पर जोर देने का तर्क मजबूत है।'

©The New York Times 2024

आंकड़े

राजकोष

देश के राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र का खास योगदान है। पांच वर्षों में केंद्र व राज्यों को मिलाकर करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

2023-24	7,51,156
2022-23	7,48,718
2021-22	7,74,425
2020-21	6,72,719
2019-20	5,55,370

आंकड़े करोड़ रुपये में और 2023-2024 के अनंतिम हैं। | स्रोत: PPAC

पृथ्वी पर अवतीर्ण होने से पहले गंगा के सवाल का जवाब देते हुए भगीरथ ने कहा कि जब संत आपके अंदर स्नान करेंगे, तो उनके स्पर्श से सारे पातक धुल जाएंगे।

गंगा ने पूछा-पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा

इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र भगीरथ भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर की तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा जब भगवान शंकर की जटा से निकलकर आगे बढ़ रही थीं, तो भगीरथ दिव्य रथ में सवार होकर आगे-आगे जा रहे थे। वह गंगासागर के पास पहुंचे और कपिल की तीव्र दृष्टि से भस्म हुए अपने पूर्वजों की राख को गंगाजल में प्रवाहित कर उनकी मुक्ति करवाई।

श्रीमद्भागवत में गंगा के अवतीर्ण होने से पहले उनके और भगीरथ के बीच संवाद का वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पाप धोएंगे, तो उनके पाप भी मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जब इतने सारे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा? भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, 'जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है, जो शांत, ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब आपके अंदर स्नान करेंगे, तो उनके अंग स्पर्श से आपके अंदर प्रवेश करने वाले समस्त पातक (पाप) धुल जाएंगे, क्योंकि समस्त पातकों का नाश करने वाले श्रीहरि संतों के हृदय में विराजमान रहते हैं।' इसके बाद गंगा जी ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। भागीरथ ने गंगा जी से कहा कि आपने हमारे ऊपर जो दया की है, उससे जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक ये पृथ्वीवासी आपका गुणगान करते रहेंगे।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 अप्रैल, 1957

डॉ. राजेंद्र प्रसाद फिर चुने जाएंगे राष्ट्रपति

कांग्रेस के संसदीय बोर्ड का निश्चय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। कांग्रेस के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने कल अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि वर्तमान राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद को पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा किया जाए।

कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि वर्तमान राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया जाए। राष्ट्रपति के पास इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा।

एआई के ऊर्जा खपत के आंकड़े चौंकाते हैं

एआई डाटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली-पानी का उपयोग हो रहा है। पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा।

मुकुल श्रीवास्तव — मुद्दा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन रही है। वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर स्मार्ट होम तक हर जगह एआई है। चाहे चैट-जीपीटी जैसे एआई जनित प्लेटफॉर्म पर जटिल प्रश्नों के हल जानना हो या गूगल व एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स पर अपनी आवाज से कोई काम कराना हो। क्या अचंभित करने वाली तकनीक के कुछ और पहलू हो सकते हैं? जो पर्यावरण व मानव सभ्यता के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं?

गूगल की वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में गूगल के डाटा केंद्रों पर कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट में तेरह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उसके डाटा केंद्रों और आपूर्ति शृंखलाओं में बिजली की खपत बढ़ने से हुई। वर्ष 2023 में उसके डाटा केंद्रों ने पहले की तुलना में 17 फीसदी अधिक बिजली का उपयोग किया। एआई टूल्स के इस्तेमाल से यह वृद्धि और बढ़ेगी। एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है, जिनमें जलवायु

परिवर्तन से जुड़े समाधान भी शामिल हैं। लेकिन बढ़ती एआई तकनीक ने एक भारी कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। अध्ययनों से पता चलता है कि एआई चैटबॉट चैट-जीपीटी पर पूछी गई एक साधारण जानकारी, गूगल खोज की तुलना में 10 से 33 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है। वहीं, इमेज आधारित प्लेटफॉर्म पर इससे कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होती है। दरअसल, एआई मॉडल सामान्य गूगल खोज की तुलना में अधिक डाटा को प्रोसेस और फिल्टर करते हैं। अधिक काम का मतलब है कि कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक काम करने से उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए डाटा केंद्रों पर अधिक शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग और अन्य ठंडे उपाय किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के एक अध्ययन के मुताबिक साल 2022 में, गूगल ने अपने डाटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए लगभग 20 अरब लीटर ताजे पानी का उपयोग किया। बीते साल माइक्रोसॉफ्ट की जल खपत में पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्तमान में डाटा केंद्रों की खपत वैश्विक बिजली की खपत का 1 से 1.3 प्रतिशत है, मगर जैसे-जैसे एआई टूल्स का उपयोग बढ़ेगा, यह खपत भी बढ़ती जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, यह आंकड़ा तीन प्रतिशत तक जा सकता है। इसके विपरीत, बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बावजूद, ई-वाहनों की वैश्विक बिजली खपत केवल 0.5 फीसदी है। वहीं, कई देशों में डाटा केंद्रों की ऊर्जा खपत उनकी राष्ट्रीय मांग की दहाई हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। आयरलैंड जैसे देश जहां टैक्स में छूट और प्रोत्साहन के कारण डाटा केंद्रों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। आयरलैंड सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यह हिस्सेदारी 18 प्रतिशत पहुंच गई।

भारत में भी एआई और डाटा केंद्रों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यहां इनके ऊर्जा और जल खपत के आंकड़े अभी सीमित हैं, लेकिन एआई के बढ़ते उपयोग के साथ, यह स्थिति बदल सकती है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बंगलूरू पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। बंगलूरू में डाटा केंद्रों की संख्या सोलह है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बंगलूरू के अलावा दिल्ली, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में भी डाटा केंद्रों में पानी की खपत बढ़ गई है। भारत में स्थापित डाटा केंद्रों की क्षमता दो हजार मेगावाट से 2029 तक 4.77 हजार मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। जिससे पहले से पानी की कमी से जूझ रहे भारत के सिलिकॉन वैली की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां डाटा केंद्रों के शीतलन के लिए अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकृत कर इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं भारतीय डाटा केंद्र अब भी ताजे पानी की आपूर्ति पर निर्भर हैं।

डाटा केंद्रों पर पानी की खपत को लेकर अभी पर्याप्त आंकड़े सामने नहीं आए हैं। डेन मोइन्स रिवर पर एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के आयोवा शहर में ओपन एआई के जीपीटी-4 मॉडल को सेवा देने वाला एक डाटा केंद्र उस जिले की पानी की आपूर्ति का करीब 6 प्रतिशत उपयोग करता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार, एआई के कॉरपोरेट और औद्योगिक कामों के उपयोग से 2030 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में पांच से दस प्रतिशत की कमी हो सकती है, वहीं 1300 अरब से 2600 अरब डॉलर के राजस्व की भी बचत हो सकती है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमें एआई के विकास के साथ-साथ इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए एआई के फायदों का लाभ उठा सकते हैं और इसके पर्यावरणीय असर को कम कर सकते हैं।

पराजय में भी अगली विजय के लिए सबक छिपा होता है

ओलिंपिक में अनहोनी

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेरिस ओलिंपिक में पदक की सुनिश्चित दावेदार विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गईं। उनसे स्वर्ण पदक की आशा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले के सभी मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई नामी पहलवानों को हराया था, लेकिन अंतिम मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वजन सौ ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही उनका सपना तो टूटा ही, देशवासियों की आशाओं पर भी तुषारापात हो गया। चूंकि एक तरह से हाथ आया पदक फिसल गया, इसलिए अफसोस अधिक है। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रसंग से सबक भी लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो। इस ओलिंपिक में विनेश ने 53 किलोग्राम के अपने स्वाभाविक भार वर्ग को छोड़कर 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ना तय किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह अपने वजन को नियंत्रित रखने का उतना अभ्यास नहीं कर पाईं, जितना आवश्यक था। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जितनी किसी खिलाड़ी की होती है, उतनी ही उसके कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी। विनेश के मामले में कहां क्या चूक हुई, इसकी जवाबदेही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की है। उन्होंने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा है और यह स्पष्ट किया है कि विनेश का वजन नियंत्रित रखने के लिए वह सब कुछ किया गया, जो संभव था, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ भूल-चूक हुई ही। यह किन कारणों से हुई, यह सामने आना चाहिए। विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने और इस तरह भारत के पदक से वंचित होने पर देशवासियों की ओर से अपनी निराशा व्यक्त किए जाने के बीच कुछ नेताओं की ओर से जैसे अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं, वे उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शा रहे हैं। यह समझ आता है कि उन्हें न खेल की जानकारी है और न ही खेल के नियमों की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे जो मन में आए, वह बोल दें। कोई विनेश के साथ साजिश की कहानी गढ़ रहा है तो कोई उन्हें अयोग्य करार देने में किसी नेता का हाथ देख रहा है। यह सब इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ धरना-प्रदर्शन में भाग लिया था। निःसंदेह विनेश का मुकाबले से बाहर हो जाना और उन्हें कोई पदक न मिलना आहत करने वाला है, लेकिन खेलों के अपने नियम होते हैं। वे हमारे या किसी अन्य के हिसाब से नहीं बन सकते। विनेश के मामले में साजिश की कहानियां गढ़ रहे लोग इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ था। इस मामले में कम से कम नेताओं की प्रतिक्रियाएं जगहंसाई कराने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है।

कम होंगे हादसे

सड़कों पर दौड़ते वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने का फैसला सराहनीय है। अनियंत्रित गति सीमा की वजह से ही प्रदेश में आए दिन हादसे होते हैं। इसपर नियंत्रण के लिए सरकार ने नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे समेत सभी श्रेणी की सड़कों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग सड़कों का आकलन कर वहां वाहनों की गति सीमा तय करेगा। अब विभाग इस कार्य को प्राथमिकता से करे। इसके साथ ही नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी तय कर दे, ताकि हादसों की संख्या कम हो। दरअसल, नियम बनते हैं, लेकिन उसका लोग पालन नहीं करते। यातायात नियमों के शत-प्रतिशत अनुपालन से ही दुर्घटनाएं कम होंगी। आमजन को यह समझना होगा कि नियमों का अनुपालन नहीं करना कितना भारी पड़ सकता है। सड़कों पर वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी है, किंतु यह अक्सर देखा जाता है कि लोग तेज रफ्तार के कारण अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, उनके कारण दूसरे की जान भी चली जाती है। राज्य सरकार ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला इससे पहले भी लिया था। यातायात और परिवहन अधिकारियों को गाड़ी की जांच के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस दिए गए। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से आनलाइन जुर्माना वसूला भी जा रहा है, लेकिन हादसे रुक नहीं रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जिम्मेवार अधिकारियों को सख्ती बढ़ानी होगी। सभी यातायात चेकपोस्ट के साथ प्रमुख चौक-चौराहों पर कड़ी चौकसी की व्यवस्था करनी होगी, ताकि लोग नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकें।

लोग अपने वाहन नियंत्रित तरीके से चलाएं। सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन जरूरी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए?

आज का सवाल
क्या स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी वापस लेने की मांग सही है?

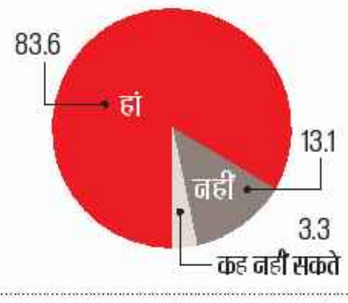

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अस्थिर पड़ोसियों से घिरता भारत

ऋषि गुप्त

बांग्लादेश में तख्तापलट और अराजकता के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है। यह स्थिति भारत के हित में नहीं

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के मुद्दे पर भारतीय संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ बैठक के बाद स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया और 'कुछ समय के लिए' उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत में हैं और माना जा रहा है कि वह किसी तीसरे देश में शरण मिलने तक यहीं रहेंगी। यदि इस हालात को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक असाधारण स्थिति है, जहां भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मदद भी करनी है। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई अनधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम से देश के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति पैदा हो गई है। भारत के समक्ष 1971 वाली स्थिति फिर एक बार बन पड़ी है। बांग्लादेश में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समूह खासकर बड़ी संख्या में हिंदू भारत में शरणार्थी के तौर पर आने की गुहार लगा सकते हैं। इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं।

अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता है, जिसकी भरी-पूरी आशंका है तो भारत की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ गुटों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इसके चलते ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे हैं। पाकिस्तान आज तक भारत को अपने विभाजन यानी बांग्लादेश के निर्माण का कारण मानता रहा है और वह कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी और असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया जाए। बांग्लादेश में अराजकता के बीच दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है, जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीते दिनों ही नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। ओली को 'इंडिया आउट' अभियान का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी राजनीतिक साख मजबूत करने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया है। चूंकि ओली की 'राष्ट्रवादी छवि' भारत विरोध से बनी है, लिहाजा भारत के लिए जरूरी है कि वह स्थिति पर नजर रखे। यदि नेपाली जनता पुरानी पार्टियों और पुराने नेताओं की कार्यशैली से ऊबती है तो 2006 जैसा जन आंदोलन छिड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका सीधा असर खुली सीमा के चलते भारत पर होगा। नेपाल के बगल में ही भूटान है, जो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर फिक्रमंद है और एक मित्रतापूर्ण सहयोगी रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने वहां भी अपनी पैठ बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भारत के लिहाज से भूटान में स्थिति नियंत्रण में है।

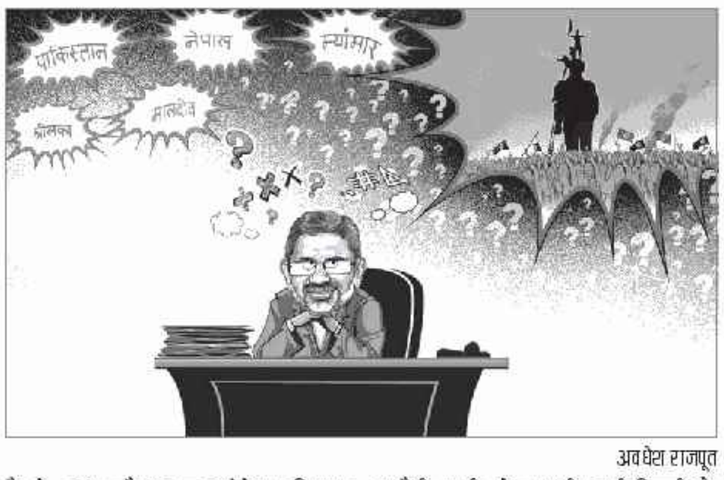

अवधेश राजपूत

पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। यहां विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं। यहां अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा एजेंसिया भारत-म्यांमार सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। यदि बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश में साथ आती हैं तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। नई दिल्ली के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी लुक-ईस्ट और एक्ट-ईस्ट नीति में सुरक्षा पहलुओं को भी शामिल करे। म्यांमार में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। यह सही है कि श्रीलंका धीरे-धीरे भारत और आइएमएफ की मदद से आर्थिक मुसीबतों से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी वहां भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। मालदीव भी इस मामले में अलग नहीं, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोध में लगे हुए हैं। उन्होंने भी ओली की तरह 'इंडिया आउट' अभियान चलाया, फिर वह चाहे भारतीय सैन्य अधिकारियों का मालदीव से भारत वापस भेजने का मुद्दा रहा हो या फिर उनकी सरकार के मंत्रियों का भारत और भारत के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ टीका-टिप्पणी का मामला।

पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही भारत के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हाल में जम्मू में हुए आतंकी हमलों ने भारत की चिंता बढ़ाने का काम किया है। यदि पड़ोसी देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत इन सभी देशों की सीमाओं के जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दक्षिण एशिया में बड़े लंबे समय से भारत की केंद्रीयता को सभी समस्याओं की जड़ माना जाता रहा है और भारत पर लगभग सभी पड़ोसी देश हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते आए हैं, लेकिन क्या अब यही देश अपनी आंतरिक हलचल के चलते भारत के सामने मौजूद सुरक्षा संकट पर नई दिल्ली के साथ खड़े होंगे? इसका जवाब संभवतः नकारात्मक ही मिले। दक्षिण एशिया में जैसी असामान्य परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए भारत को असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत को हर कीमत पर अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है और पड़ोसी देशों में सिविल सोसायटी समूहों के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों और क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है कि वे भारत की चिंताओं को समझें और अपने स्तर पर पाकिस्तान और चीन पर दबाव डालें, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत को परेशान करने के लिए नई तिकड़में न कर सकें।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

युवाओं में कौशल विकास की चुनौती

डा. सुरजीत सिंह

यह समझा जाना बहुत आवश्यक कि अपने देश में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है

बजट पेश होने के बाद उसके प्रस्तावों पर अमल की दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में सभी की निगाहें रोजगार सृजन की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर टिकी हैं, जिन्हें हालिया बजट का सबसे विशिष्ट पहलू माना जा रहा है। कौशल, नवाचार और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विशेष प्रविधान किए हैं। इसमें इंटर्नशिप योजना को खासी चर्चा भी मिली है। इससे न केवल रोजगार के आकांक्षियों के हितों की पूर्ति होगी, बल्कि उद्योगों को भी अपने अनुकूल कौशल से लैस लोग मिलेंगे। इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक आपूर्ति शृंखला मजबूत होगी, बल्कि निवेश संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे सरकार की यह मंशा भी प्रकट हुई है कि अगले पांच वर्षों में वह रोजगार, कौशल और एमएसएमई पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को भुनाने की राह में कार्यशील आबादी में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी न होने का संज्ञान भी सरकार ने लिया है। इसके लिए कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल के निकट महिला हास्टलों और शिशु देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी फोकस किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में भी उल्लेख है कि देश में बढ़ते कार्यबल के समायोजन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करनी होंगी। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई। बजट में युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। कुल मिलाकर, पांच साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षित, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए बजट में प्रविधान है कि पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को शुरुआती चार वर्षों में ईपीएफओ में योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। नियोक्ताओं को सहायता देते हुए यह उपाय भी किया गया है कि सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के संबंध में नियोक्ता के ईपीएफओ में अंशदान के लिए उन्हें दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री की यह पहल औपचारिक रोजगार सृजन की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है, जिससे सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिकता के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी। इससे अधिक स्नातकों को नौकरी के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

बढ़ाने होंगे रोजगार के अवसर • फाइल

भारत में रोजगार की नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों की कमी है। बढ़ती श्रमशक्ति और कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की दृष्टि से पांच वर्षों में देश की 500 दिग्गज कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना एक बाजी पलटने वाली योजना सिद्ध हो सकती है, लेकिन तभी जब कंपनियां इस योजना में रुचि दिखाएं। इस योजना में 5,000 रुपये के मासिक भत्ते और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता आकर्षक पहलू हैं। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल प्रदान करना है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्रदान करने के साथ ही हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के तीन प्रतिशत ब्याज में छूट भी मिलेगी। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 1000 आइटीआइ को और अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा। उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे नई उभरती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर जोर देने से इस क्षेत्र को संजीवनी मिलने के आसार हैं। प्रत्येक वर्ष 25,000 कुशल व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक का गारंटीकृत ऋण प्रदान करना निश्चित रूप से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने से इस क्षेत्र की तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी सराहनीय है। पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल विभाग का नाम भी बदलकर कौशल, रोजगार और आजीविका कर दिया है। बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन से आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, केंद्र के स्तर पर तमाम पहल तभी सफल हो पाएंगी, जब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करेंगी। इन कार्यक्रमों को यदि गंभीरता से लागू किया जाता है तो भारत को एक अग्रणी स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

संबंधों की सजीवता

किसी की संगति में ही उस व्यक्ति के प्रति गहरी समझ और संवेदना विकसित होती है। यह मेलजोल प्रायः लोगों की समान रुचियों, सोच और जीवन की दिशा पर आधारित होता है। एक दूसरे के सान्निध्य और संगति में दोनों एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और एक मजबूत संबंध की नींव रखते हैं। यह संबंध तब फलता-फूलता है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे के महत्व को समझते हैं। स्मरण रहे कि कोई भी संबंध सब कुछ सह लेता है, लेकिन उपेक्षा नहीं सह सकता है।

समय के साथ व्यक्ति का सोच और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी-कभी ये बदलाव धीरे-धीरे व्यक्ति को अपने पूर्व संबंधों से दूर भी कर देते हैं। किसी नई जिम्मेदारी या नई रुचियों के कारण व्यक्ति पुरानी मित्रता को उतना समय और महत्व नहीं दे पाता है,जितना पहले देता था। इस प्रक्रिया में वह दूसरे व्यक्ति को उपेक्षित महसूस करा सकता है। प्रायः व्यक्ति को उस संबंध में वह अनुभूति नहीं मिलती, जो पहले अनुभव होती थी। जब किसी संबंध में नवीनता समाप्त हो जाती है, तो उदासीनता का भाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति उस संबंध को महत्व देना बंद कर देता है।

इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने संबंधों के प्रति संवेदनशील रहे। अगर किसी संबंध में कोई परिवर्तन आता भी है तो इसे ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है और उनके महत्व को पुनः स्वीकार कर सकता है। संबंधों में उतार-चढ़ाव और परिवर्तन सामान्य हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को महत्व देना और उसकी उपेक्षा न करना हमारे संबंधों की मजबूती के लिए एक आवश्यक अवयव है। आपसी सम्मान, संवाद और समझदारी से ही हम अपने संबंधों को सार्थक और सजीव बनाए रख सकते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

भारत को रहना होगा सतर्क

'अराजकता में डूबा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में दिव्य कुमार सोती ने आशंका जाहिर की है कि चीन और अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। वहां उन्हें कठपुतली सरकार मंजूर थी। चूंकि चीन अधिनायकवादी देश है तो यह बात समझ में आती है, मगर अमेरिका जो पुराने लोकतंत्रों में से एक है। उसे तो बांग्लादेश में लोकतंत्र प्रेमी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए था। उसे भारत का भी ध्यान रखना चाहिए था, जिससे उसके मित्रतापूर्ण संबंधों के कई फायदे हैं। बहरहाल यह देखने वाली बात है कि उन राष्ट्रों में लोकतंत्र कभी सफल नहीं रहा, जहां मजहबी कट्टरपंथी ताकतें मजबूत रही हैं। लिहाजा लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी तरह के कट्टरपंथ को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। जहां कट्टरपंथ अपना सिर उठाता है या उठाने की आशंका रहती है, वहीं विदेशी महाशक्तियों के दखल संभव होते हैं। भारत को नई परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

तकनीक से सरल हो न्याय प्रक्रिया

देश की न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों की बेतहाशा वृद्धि गंभीर समस्या बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी ने इस स्थिति की गंभीरता को सामने लाया है, जिसमें बताया गया कि लोग अब न्याय से थक कर समझौते की ओर रुख कर रहे हैं। यह स्थिति संपूर्ण न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता के लिए चुनौती है। इस परिदृश्य में एक नवीनतम और प्रभावशाली समाधान हो सकता है, 'न्याय की स्मार्ट प्रणाली'। इसके अंतर्गत, अदालतों में एक केंद्रीय डिजिटल मंच स्थापित किया जाए, जिसमें सभी मामलों की स्थिति, तारीखें और सुनवाई की जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध हो। इसके अलावा, 'समय-सीमा आधारित केस प्रबंधन प्रणाली' लागू की जाए। इसमें प्रत्येक केस के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि सुनवाई और निर्णय प्रक्रिया में विलंब न हो। निचली अदालतों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए और विशेष फास्ट-ट्रैक पैनल बनाए जाएं, जो त्वरित निर्णय सुनिश्चित करें। स्थानीय स्तर पर, छोटे शहरों और कस्बों में अदालतों के कामकाज को सुधारने के लिए वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल दस्तावेज प्रणाली को अपनाया जाए। इससे न केवल अदालतों की भीड़ कम होगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी सरल और त्वरित हो सकेगी। यह प्रणाली पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगी, जिससे जनता को न्याय की शीघ्र और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर न्याय प्रणाली को नया दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है। न्याय व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके लोगों को शीघ्र और प्रभावी न्याय मिल सकेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित होगी। आम व्यक्ति को जब कहीं से उम्मीद नहीं रह जाती तो वह न्यायालय की ओर रुख करता है। आज भी आमजन का न्याय व्यवस्था विश्वास है कि उसे इंसाफ यहीं से मिलेगा। ऐसे में लोगों को सहज और त्वरित न्याय मिलेगा तो उनका विश्वास और बढ़ेगा। वैसे मामलों के निष्पादन में तेजी आ रही है।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

बांग्लादेश से मजबूत संबंध आवश्यक

'अराजकता में डूबा बांग्लादेश' शीर्षक आलेख में दिव्य कुमार सोती ने वहां का बढ़िया विश्लेषण किया है। बांग्लादेश अपने गठन के बाद से ही कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, जो ना केवल उस देश के भीतर बल्कि पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वर्तमान में वहां की राजनीतिक अस्थिरता दक्षिण पूर्व एशिया की बड़ी समस्या बन गई है। वहां शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आने के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर जिस तरह क्रूरतापूर्ण हमला किया गया और आतंक का माहौल बना, यह भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है। बांग्लादेश में जारी अस्थिरता क्षेत्र में अशांति पैदा कर सकती है, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में, जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा देती है। इस संकट ने दक्षिण एशिया की राजनीति को भी अस्थिर कर दिया है। इधर, चीन और पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। पाकिस्तान तो बांग्लादेश के साथ अपने पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने की कोशिश में ही लगा है। पश्चिम और यूरोपीय देशों के बांग्लादेश के प्रति वर्तमान रुख को देखते हुए भारत को इस स्थिति पर नजदीकी नजर रखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के साथ मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखना और इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का सामना करना, भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए।

डा. संजीव कुमार, राजेन्द्र पथ, गया

पोस्ट

अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है तो उनके मंदिरों की रक्षा क्यों और किससे करनी पड़ रही है? हारिस सुल्तान@TheHarrisSultan

फलस्तीन के मसले पर लगातार बोल रहे देश के प्रमुख मुसलमानों से सवाल है कि क्या आपके पास अपने पड़ोस में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द है?

आमना बेगम अंसारी@Amana_Ansari

बांग्लादेश में फैली अराजकता की आड़ में बहुत से एक्स हैंडल बहुत ही धूर्तता से लिख रहे हैं, 'भारत में यह सब कब?' ऐसे सभी लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं। राष्ट्र के होने से हम सबका अस्तित्व है। राष्ट्रहित सदैव सर्वोपरि है।

इमरान शकील खान@Imran_Shakeel_

विनेश फोगाट का 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य सिद्ध होना बेहद अफसोसनाक है। उनके अपने खून-पसीने के साथ पूरे देश के साधनों और आशाओं पर पानी फिरा है, लेकिन एक-दूसरे को कोसने में लगे नियमतोड़ मानसिकता वालों के लिए सबक है कि थोड़ा-बहुत चलता है का जुगाड़ बाकी दुनिया में नहीं चलता।

शिवकांत@shivkant

जनपथ

खेला ऐसा हो गया बिगड़ गया सब काम,
बाहर हुई विनेश जी वजन बढ़ा सौ ग्राम।
वजन बढ़ा सौ ग्राम हुआ ये इतना मुश्किल,
खुद विनेश के साथ देश का भी टूटा दिल।
दर्द दे गया आज बड़ा पेरिस का मेला,
बुरे स्वप्न सा याद रहेगा अब यह खेला।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 118

****

कल्पमेधा

क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। इसलिए हमें सदैव शांत और स्थिरचित्त रहना चाहिए।

– इंगरसोल

पदक से दूर

महिला पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अंतिम दौर से ऐन पहले, वजन अधिक होने के कारण, अयोग्य करार दिए जाने से स्वाभाविक ही सारे देश को निराशा हुई है। पूरे खेल के दौरान जिस तरह विनेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उससे उनसे देश के लिए स्वर्ण पदक लाने की उम्मीद बनी हुई थी। वे अब तक की अपराजेय जापान की युई सुसाकी को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंची थीं। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की गुजमैन लोपेज को हराया था। ये दोनों खिलाड़ी दुनिया की श्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। युई सुसाकी तो अब तक किसी मुकाबले में पराजित नहीं हुईं। इसलिए उन्हें हराने पर फोगाट को अधिक प्रशंसा मिली। मगर अंतिम दौर में खेलने से पहले उन्हें इसलिए अयोग्य करार दे दिया गया कि उनका वजन निर्धारित पचास किलोवर्ग में करीब सौ ग्राम अधिक था। दरअसल, विनेश पहली बार पचास किलोवर्ग में खेल रही थीं। इससे पहले वे तिरपन किलोवर्ग में खेलती थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने विनेश का वजन पचास किलो के भीतर बनाए रखने की भरसक कोशिश की, मगर फिर भी कहीं कोई चूक रह गई। चूंकि विनेश पर विशेष रूप से सबकी नजरें टिकी थीं, इसलिए उनकी अयोग्यता को कुछ लोग राजनीतिक रंग देते भी देखे जा रहे हैं।

खेल में हार और जीत चलती रहती है, मगर कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अंतिम दौर में पहुंच कर कुछ तकनीकी खामियों के चलते खेलने से रोक दिया जाए, तो उसकी टीस उसके भीतर जीवन भर बनी रहती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि महिला पहलवानों के लिए पचास किलो से नीचे वजन लाना कठिन होता है, पर यह सवाल तो बना ही है कि आखिर विनेश के साथ गया विशेषज्ञों का दल कैसे तकनीकी पक्षों पर ध्यान देने से चूक गया। विनेश के साथ उनके कोच, मैनेजर, आहार विशेषज्ञ भी गए होंगे। उन्हें कहीं न कहीं तो भरोसा रहा होगा कि विनेश तिरपन किलो से पचास किलो भार वर्ग में उतर कर खेल सकती हैं। मगर इसके लिए वजन घटाने की जिस तैयारी की जरूरत थी, वह कैसे नाकाम रही, यह जांच का विषय है। अब विनेश कोई पदक नहीं ला सकेंगी। इस तरह देश भी एक पदक से चूक गया।

विनेश को लेकर राजनीति इसलिए भी शुरू हो गई कि वे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वालों की अगली कतार में थीं। उन्हें आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादतियां भी सहनी पड़ीं, कई तरह के मानसिक दबावों से गुजरना पड़ा। इस तरह उन्हें सत्ता विरोधी मुहिम का हिस्सा मान लिया गया था। विपक्षी दलों ने उन्हें खुल कर समर्थन दिया। तब कहा गया कि विनेश में अब ओलंपिक में खेलने की क्षमता नहीं रह गई है, इसलिए वे राजनीति के रास्ते पर चल पड़ी हैं। हालांकि लंबे समय तक आंदोलन में संघर्ष करते रहने की वजह से उनके नियमित अभ्यास में बाधा आई थी, मगर उन्होंने आखिरकार साबित किया कि उनकी क्षमता कहीं से कम नहीं हुई है। बेशक वे तकनीकी वजहों से अंतिम दौर में खेलने से रह गईं, पर इसके पहले के खेलों में जिस तरह उन्होंने अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया, वह अपने आप में एक कीर्तिमान है। मगर, उन्हें जिस तरह से अयोग्य ठहराया गया, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बात की जांच तो होनी ही चाहिए कि विनेश के साथ गए अधिकारियों से चूक कहां हुई।

लापरवाही की हद

दिव्यांग बच्चों और अन्य विशेष व्यक्तियों को उनके परिजन इसलिए आश्रय गृहों में भर्ती कराते हैं, कि प्रशिक्षण और बेहतर देखरेख से उनके जीने की राह आसान हो सकेगी। मगर, इंदौर के एक बाल आश्रम में हैजा के प्रकोप से कई बच्चों और दिल्ली में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के आश्रय गृह में कई की मौत ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आश्रय गृहों में दिव्यांगों का खास खयाल रखना तो दूर, उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। मसलन, स्वच्छ पेयजल, संतुलित आहार, स्वच्छता, समय पर चिकित्सीय जांच आदि की माकूल व्यवस्था न होना। विडंबना है कि जिन आश्रयों में दिव्यांगों की उचित देखरेख की उम्मीद की जाती है, वहां वे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इंदौर के बाल आश्रम में बच्चों की मौत की वजह हैजा बताई जा रही है, जो दूषित भोजन-पानी के कारण फैलता है। इंदौर के शासकीय बाल चिकित्सालय की अधीक्षक का कहना है कि बाल आश्रम की एक बच्ची को हाल में जब गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया तो तब वह उल्टी-दस्त और शरीर में पानी की कमी की समस्या से पीड़ित और कुपोषण का शिकार थी। चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

जांच के दौरान इंदौर के आश्रम में क्षमता से अधिक बच्चों को भर्ती किए जाने, उनका चिकित्सीय रेकार्ड न रखे जाने और रखरखाव संबंधी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। जांच रपट के बाद प्रशासन ने इस आश्रम के कुछ पदाधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं, लेकिन सवाल है कि क्या इससे समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी? दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में मौतों का मामला अब न्यायालय के समक्ष है। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को आश्रम में पानी की गुणवत्ता और साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अब दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश जारी कर स्थिति रपट देने को कहा है। जब तक आश्रय गृहों में भर्ती लोगों की समुचित देखरेख की जवाबदेही तय नहीं होती और जरूरी सुविधाओं के निरीक्षण की कारगर व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इनकी दशा सुधरने की उम्मीद धुंधली ही रहेगी।

कुदरत पर कहर बनता मानव निर्माण

कंक्रीट और कोलतार की सड़कें, फुटपाथ, कांच, धातु और कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों, कपड़ों, कंप्यूटरों तक लोगों द्वारा बनाई गई हर चीज का भार अब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के द्रव्यमान के बराबर हो चुका है।

कुशाग्र राजेंद्र

एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर मानव निर्मित वस्तुओं का वजन धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के वजन के बराबर हो चुका है। 2020 में 'नेचर' पत्रिका में प्रकशित एक गणनात्मक शोध के मुताबिक मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं का कुल वजन 1.1 लाख करोड़ टन तक पहुंच गया, जो ग्रह पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के वजन को पार कर गया है। यानी पृथ्वी पर मौजूद ब्रह्मांड में उसकी खास पहचान, जीवन का दायरा ही सिकुड़ता गया है। यानी 'जैवभार' तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है। कंक्रीट और कोलतार की सड़कें, फुटपाथ, कांच, धातु और कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों, कपड़ों, कंप्यूटरों तक लोगों द्वारा बनाई गई हर चीज का भार अब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के द्रव्यमान के बराबर हो चुका है। मानव निर्मित वस्तुओं का वजन तेजी से बढ़ रहा है, जो हर दो दशक में दो गुना हो जा रहा है, वहीं वैश्विक 'जैवभार' का वजन लगभग स्थिर बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान पेड़-पौधों का है। मानव निर्माण के संपूर्ण दायरे को एक साथ 'टेक्नोस्फीयर' के नाम से जाना जाने लगा है।

पृथ्वी की उम्र के लिहाज से हाल तक इस धरती पर मनुष्य और अन्य प्राणी विभिन्न रूपों में एक अदद जीव जैसे ही रहे, जो पूरी तरह यहां के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के अनाम हिस्से जैसा रहते आए हैं। पर शरीर में आए कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव ने मानव विकास को एक गति दी और देखते-देखते बहुत कम समय में मनुष्य धरती पर एक मुख्य जीव के रूप में उभरा, आग और खेती के विकास और पालतू जानवरों की मदद से अपने लिए एक नई दुनिया गढ़नी शुरू की और ज्ञान-विज्ञान के क्रांतिकारी विस्तार से न सिर्फ जीवित प्राणियों, बल्कि पूरी धरती का भाग्य विधाता बन बैठा। और ये सारे परिवर्तन अरबों वर्ष पुरानी पृथ्वी के लिहाज से एक लाख वर्षों में ही हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव के रूप में मानव पर ठीक से नियंत्रण प्रणाली विकसित नहीं हो पाई, जैसे प्रकृति में अन्य प्राणियों के साथ हुआ। यहां तक कि आहार शृंखला के सिरमौर जीव शेर, बाघ, वेल, गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसके उलट मनुष्य एक मनमौजी और उच्छृंखल जीव के रूप में पनपा, जो अपनी सुविधा के लिहाज से प्रकृति पर हावी होता चला गया।

पृथ्वी पर बड़े बदलाव की शुरुआत कृषि की शुरुआत से हो चुकी थी, पर औद्योगिक क्रांति के बाद निर्माण कार्य और धरती के स्वरूप में व्यापक स्तर पर परिवर्तन शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मानव निर्माण अब समग्र जीवन तंत्र से भारी हो चला है। मानव निर्मित वस्तुओं से तात्पर्य उन सारी वस्तुओं से है, जिसका निर्माण पूर्णतः या आंशिक रूप से मनुष्य द्वारा हुआ है। इसमें कुछ पूर्णतया नई वस्तुएं शामिल हैं, जिनका अविष्कार मनुष्य ने किया है, जो पहले धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थीं, जैसे प्लास्टिक और हजारों किस्म के नए रसायन, जिनमें कीटनाशक और दवाइयां भी शामिल हैं। बाकी वस्तुओं का निर्माण पहले

से मौजूद चीजों के स्वरूप में बदलाव कर हुआ है, जिसमें कंक्रीट, धातु, बजरी, ईंट, डामर यानी कोलतार आदि शामिल हैं। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या और उपभोग करने की क्षमता में बेतहाशा वृद्धि व्यापक स्तर पर बढ़ रहे मानव निर्माण के मूल में है। वजन के हिसाब से मानव निर्मित

> **पिछली सदी की शुरुआत तक मानव निर्मित वस्तुओं का अनुमानित वजन लगभग 35 अरब टन था, जो उस समय के सारे प्राणियों के वजन का मात्र तीन फीसद था, मगर नेशनल जियोग्राफी की एक रपट के मुताबिक केवल एक साल में हम 30 अरब टन निर्माण कर ले रहे हैं। मात्र सौ-सवा सौ सालों में मानव निर्माण पृथ्वी पर मौजूद कुल 'जैवभार' के बराबर जा पंहुचा। यह एक भयावह स्थिति है और अगर हम इसी तरह उपभोग करते रहे तो 2040 आते-आते पृथ्वी पर जीवन का दायरा सिकुड़ कर मानव निर्माण का एक-तिहाई ही रह जाएगा।**

सामान में सबसे पहले कंक्रीट है, जो आधुनिक विकास के मूल में है, उसके बाद क्रमशः धातु, मुख्य रूप से स्टील, बजरी, ईंट, डामर का स्थान आता है, यहां तक प्लास्टिक का योगदान कम नहीं है। प्लास्टिक का इस्तेमाल इस कदर व्यापक हो चला है कि अब तक लगभग आठ अरब टन प्लास्टिक का निर्माण हो चुका है। मतलब, अभी मौजूद हर व्यक्ति के निमित्त लगभग एक टन तक प्लास्टिक इस धरती पर बन चुका है। हालांकि प्लास्टिक का कुल वजन मानव निर्माण का मात्र एक फीसद है, फिर भी एक अनुमान के मुताबित धरती पर मौजूद कुल प्लास्टिक का वजन सारे जानवरों के वजन का दो गुना हो चुका है।

मौजूदा तुलनात्मक अध्ययन के लिए मानव निर्मित वस्तुओं के साथ जीवन के सभी रूपों के वजन का अनुमान परोक्ष रूप से किया गया, जिसमें पेड़-पौधे, जीव-जंतु, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस शामिल हैं। आधुनिक मानव विकास के कालक्रम को तीन प्रमुख कालखंडों में बांट कर समझा जा सकता है। पहला, जब कृषि का विकास हुआ और मानव बसावट बसी, सभ्यता विकसित हुई। दूसरा, जब मशीनों के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और तीसरा, सूचना और ज्ञान क्रांति हुई और मानव एक अदद संसाधनों के बड़े पैमाने पर उपभोग करने की इकाई बन कर रह गया। इसी दूसरे और तीसरे काल खंड में मानव निर्माण ने ज्यामितीय गति पकड़ी। पिछली सदी की शुरुआत तक मानव निर्मित वस्तुओं का अनुमानित वजन लगभग 35 अरब टन था, जो उस समय के सारे प्राणियों के वजन का मात्र तीन फीसद था, मगर नेशनल जियोग्राफी की एक रपट के मुताबिक केवल एक साल में हम 30 अरब टन निर्माण कर ले रहे हैं। मात्र सौ-सवा सौ सालों में मानव निर्माण पृथ्वी पर मौजूद कुल 'जैवभार' के बराबर जा पंहुचा। यह एक भयावह स्थिति है और अगर हम इसी तरह उपभोग करते रहे तो 2040 आते-आते पृथ्वी पर जीवन का दायरा सिकुड़ कर मानव निर्माण का एक-तिहाई ही रह जाएगा।

मानव के आधुनिक विकास का असर न केवल मानव निर्माण में झलकता है, बल्कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र और जंगली जानवरों की विविधता पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है। 2022 की 'लिविंग प्लानेट' रपट के अनुसार पिछले पचास वर्षों में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवन के विविध रूपों में 69 फीसद तक गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया क्षेत्र में यह गिरावट बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लैटिन अमेरिका में वन्य जीवों में यह कमी 94 फीसद तक हुई है। पिछले सौ-सवा सौ सालों में ही जंगली जानवरों (स्तनपायी) का वजन मनुष्य और पालतू जानवरों के मुकाबले 17 फीसद से घट कर मात्र 4 फीसद तक रह गया है। यही प्रवृत्ति समुद्र की जैव विविधता में भी दिख रही है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का वजन 39 करोड़ मीट्रिक टन है, वहीं पालतू स्तनधारी जानवरों का वजन 63 करोड़ मीट्रिक टन है, जबकि वन्य प्राणी (स्तनधारी) धरती पर और समुद्री दोनों मिलाकर 6 करोड़ मीट्रिक टन ही बचे हैं।

इन आंकड़ों से जाहिर है कि पृथ्वी पर प्रकृति का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है, जिसमें पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप, जंगल, नदी, पहाड़, झील, पेड़-पौधे, वन्य-जीव शामिल हैं। ये सारे भौतिक परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे हैं, कि युगों में होने वाला बदलाव वर्षों में हो जा रहा है। बड़े पैमाने पर और तेजी से हो रहे ये परिवर्तन हमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास के ग्रहीय त्रिदुश्चक्र में धकेल रहे हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नए नजरिए की जरूरत

नीलम सिंह

दुनिया मेरे आगे

अगर महिलाओं के दुख-सुख और उसकी व्यवस्था पर केंद्रित बातचीत हो रही हो तो उसके बीच में किसी के मुंह से अक्सर यह सुना जा सकता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो इस मसले की तहों से दूर रहते हैं, वे सहमत होते हैं, जो इसकी परतों को समझते हैं, उनके लिए इससे सहमत होना मुश्किल होता है। दरअसल, एक स्त्री जो पाती है, वही ज्ञान संस्कार अपनी बेटी, बहू या अन्य लड़कियों को देती है। आज के दौर में जब आमतौर पर हर लड़की और महिला को अपने हाथ में बसे इंटरनेट के माध्यम से घर, बाहर और संसार की सारी खबरें मिल रही हैं, ऐसे में अगर कोई महिला यह कहती है कि मुझे आजकल की लड़कियों से डर लगने लगा है, तो हैरानी होती है। अपने बेटे के लिए पुत्रवधू खोजते हुए एक परिचित ने कहा कि आजकल की लड़कियों से जरा डर लगता है... आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं... वे लड़के से सारा पैसा लेकर अपने पास रखती हैं।

इस तरह की बातें सुन कर एकबारगी ऐसा लगता है कि उन्हें किसी एकाध खास लड़की से कोई नाराजगी होगी, इसलिए वे ऐसा कह रही हैं, मगर विडंबना यह है कि यह राय उनकी सोच से जुड़ी थी। क्या वास्तव में आज के दौर की एक पढ़ी-लिखी जिम्मेदार महिला को थोड़ी-सी प्राप्त आजादी से सपने देखने वाली लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखना ठीक है? इस तरह की बातें जब पुरुषों के मुंह से निकले तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की सत्ता में कोई घुसपैठ करता है तो उसे कष्ट होता है। मगर जब एक पढ़ी-लिखी स्त्री बार-बार ऐसे विचारों को दोहराती है, तो इस पर सोचने की जरूरत महसूस होती है। महादेवी वर्मा इस बात पर बल देती हैं कि एक पढ़ी-लिखी महिला को हमेशा अपनी अनपढ़ बहनों का साथ देना चाहिए, ताकि अन्य महिलाएं भी आगे बढ़ सकें। अगर सावित्रीबाई फुले ने भी यही सोचा होता तो क्या आधी आबादी जो आज पढ़-लिखकर अपने घरों से निकल पा रही है, निकल पाती? शायद नहीं।

दरअसल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पहलू अगर आज के दौर में लड़कियों का घर से बाहर निकलने का संघर्ष है, तो दूसरा पहलू उन स्त्रियों की सोच का है जो यह माने बैठी हैं कि स्त्रियों के घर से बाहर निकलने की आजादी ने गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर दिया है। इसे कुछ यों भी देख सकते हैं कि वे स्त्रियां जो घर के बाहर काम कर रही हैं, वे घर में काम करने वाली स्त्रियों के सामने चुनौती हैं।

हमने बचपन से सुन रखा है कि एक उम्र के बाद लड़कियों को घर संभालने का काम सीख लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को दूसरे के घर जाना है। आजादी के पचहत्तर साल बाद भी हमारा समाज इस सोच से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी हम लड़कों की जगह तुलना में लड़कियों को घर का काम सिखाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। परिणामस्वरूप कामकाजी महिलाएं घर और बाहर, दोनों को संभालने की पूरी कोशिश करती हैं, ताकि उनके ऊपर यह इल्जाम न आए कि नौकरी कर रही हैं, तो घर को छोड़ दिया है। एक बड़ी समस्या स्त्रियों के लिए सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया महिलाओं को सर्वगुण संपन्न नारी की छवि से मुक्त नहीं होने दे रहा है। ऐसे में पुरुष प्रधान समाज को अगर आसानी से सर्वगुण संपन्नता के रोग से ग्रस्त आधी आबादी मिल जाए तो किसका दोष है। जब स्थितियों की इतनी मांग हो तो ऐसे में स्त्रियों को स्वयं को साबित करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे में तुर्रा यह कि इतना करने के बाद भी यह सुनना पड़ता है कि आजकल की लड़कियां ज्यादा चालाक हो गई हैं... भोले-भाले लड़कों को फंसा लेती हैं। कई दफा तो ऐसा लगता है कि जो माताएं अपने पुत्रों से अतिरिक्त प्रेम करती हैं और उन्हें अपने और अपने लड़कों के भोलेपन पर इतना नाज है, उन्हें एहतियातन बच्चों को विवाह के लिए ही मना कर देना चाहिए। खुद जब रोटी-दाल पकाने लगेंगे तो औरतों की दोहरे दबाव में घिरी जिंदगी का दर्द समझ में आ जाएगा।

> **हमने सुन रखा है कि एक उम्र के बाद लड़कियों को घर संभालने का काम सीख लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को दूसरे के घर जाना है। आज भी हमारा समाज इससे सोच मुक्त नहीं हुआ है। आज भी हम लड़कों की जगह तुलना में लड़कियों को घर का काम सिखाने में ज्यादा ध्यान देते है।**

एक समस्या और भी है। आज के समय की स्त्रियां दो स्तर पर कार्य कर रही हैं। एक कि वे स्वयं को साबित करने में लगी हैं, दूसरी कि वे अपनी आजादी को भी जीना चाहती हैं। इन दोनों दबावों से निजी जिंदगी में विरोधाभास पैदा होना स्वभाविक ही है। यह विरोधाभास और भी प्रबल तब हो जाता है जब आज के समय में सबको पढ़ी-लिखी आधुनिक बहू और पत्नी तो चाहिए, मगर वह उसकी आजादी को एक सीमा में ही बांध कर रखना चाहता है।

ऐसे में अक्सर लोग मुट्ठी भर स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत करके हर महिला की आजादी को एक ही पैमाने पर तौल देते हैं। समस्या यह है कि जब यहां एक घर से दूसरे घर में आजादी के मायने बदल जाते हैं तो इतने सारे सामाजिक वर्गीकरण में सभी महिलाओं की आजादी को हम एक ही चश्मे से कैसे देख सकते हैं! ऐसे में आज पुरानी पीढ़ी की महिलाओं को अपने घर की नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए नए नजरिए की जरूरत है।

उदासीनता का हश्र

हाल ही में देश की राजधानी में सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले तीन युवाओं की मौत ने हमारी व्यवस्था की पोल खोल दी। चाहे कोटा हो या अन्य शहर, सब जगह कोचिंग संस्थानों की हालत एक जैसी है। लाखों युवा हर साल देश की प्रतिष्ठित सेवाओं या कालेजों में अपनी जगह बनाने के लिए दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेते हैं। जब ये युवा यहां नामी-गिरामी संस्थानों में भी ज्यादा अच्छे हालत नहीं पाते तो समझौता कर लेते हैं। एमसीडी के कठोर नियम और विभिन्न कानून भी इन कोचिंग संस्थानों पर लागू नहीं होते। कारण क्या है, सबको पता है। सरकार कुआं तब खोदती है जब आग लग जाए। इस बार भी कुछ लोगों के निलंबन और गिरफ्तारी के बाद मामला दबा दिया जाएगा। देश के होनहार बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार 58 हजार करोड़ का कोचिंग व्यवसाय इतना तो कर ही सकता है कि उसके यहां आने वाले बच्चे एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें। सिर्फ अपना लाभ न देखकर थोड़ा-सा बच्चों का भी सोच लें तो इन हादसों की शायद पुनरावृत्ति न हो।

– मुनीश कुमार, रेवाड़ी, हरियाणा

संकट का तापमान

धरती के बढ़ते तापमान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड, केदारनाथ, हरिद्वार, हल्द्वानी, हिमाचल प्रदेश, सोनप्रयाग आदि धरती के बढ़ते तापमान का खमियाजा भुगत रहे हैं। हाल ही में वायनाड में फटे बादल, दरके पहाड़, उफनी नदियों के साथ हुए जबरदस्त और अनायास भूस्खलन जलवायु के संकट का ही परिणाम है, जिसमें लगभग कई सौ की जान चली गई, सैकड़ों गुमशुदा हैं। वायनाड में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया गया होता, तो यह स्थिति नहीं आती। 'मुसीबत की बरसात' (संपादकीय, 3 अगस्त) में उल्लेख है कि बढ़ रही गर्मी से भारी और अचानक वर्षा को तत्काल रोकना संभव नहीं है, किंतु बचाव के इंतजाम किए जा सकते हैं, जिसके लिए हमें भौतिक सुख तजना होगा और पर्यावरण में सुधार के लिए जल और पौध संरक्षण के साथ रोपण को बढ़ावा देना होगा। विलासिता की आदतों को छोड़ कर जीवन शैली में सुधार और बदलाव भी लाना होगा।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

सबकी जिम्मेदारी

स्वतंत्रता दिवस के उमंग और जोश में आसमान छूती पतंगें चार चांद लगाती हैं, लेकिन पतंगबाजी में चीनी और सिंथेटिक मांझे का प्रयोग करके अति उत्साही युवा अक्सर खतरनाक स्थितियां पैदा करते हैं। दिल्ली सरकार, पुलिस या संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने वाले और इसको बेचने, खरीदने और जमा करने वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और बेपरवाह होकर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा करते हैं। 2017 में एनजीटी ने इस पर दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया था। वर्तमान में अगर कोई मांझे का भंडारण करता पाया जाता है तो उसे एक लाख का जुर्माना और पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। स्कूली छात्रों और स्कूल प्रबंधन को शामिल करते हुए जागरूकता अभियान चलना चाहिए और प्रचार तंत्र के जरिए दिल्ली वालों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि दिल्ली में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को इस खतरनाक मांझे को खरीदने से रोक सकें।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

भाईचारे के खिलाफ

पिछले चार दशक के दरमियान ग्रेट ब्रिटेन में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी नहीं फैली थी, जितनी इस वक्त। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर आप्रवासी-विरोधी, मुसलिम विरोधी दंगे फैल गए, जिसकी शुरुआत पिछले सप्ताह तीन बच्चियों की हत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में गलत सूचना दिए जाने से हुई। उग्र दक्षिणपंथी लोग वहां तांडव मचा रहे हैं। उग्र दक्षिणपंथियों ने सोशल मीडिया में इस हत्यारे की धार्मिक पहचान के बारे में झूठ फैला दिया। इस तरह के विचार अगर फले-फूले तो सामाजिक सौहार्द तो खत्म होगा ही, साथ में समाज में उग्रपंथ एवं चरमपंथ भी पनपना शुरू हो जाएगा। हत्या जैसे अपराध को अगर एक खास जाति, नस्ल, धर्म और आप्रवासियों से जोड़ कर अपनी विचारधारा को समाज के ऊपर थोपा जाएगा, तो इससे प्रेम और भाईचारे को नुकसान होगा।

– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सवालों के कटघरे में विनेश का सपोर्ट स्टाफ

पेरिस ओलंपिक की महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने का जो सपना करोड़ों भारतीयों ने देखा था वह बुधवार को उस वक्त टूट गया जब विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। निश्चित ही यह दिन भारतीय ओलंपिक के इतिहास में सबसे पीड़ादायक दिनों में शुमार किया जाएगा। फोगाट का अयोग्य घोषित होना इसलिए भी तकलीफदेह है क्योंकि जिस वजह से उसको अयोग्य घोषित किया गया उसके लिए उसका सीधे तौर पर कसूर नजर नहीं आ रहा।

विनेश 50 किलो कैटेगरी में भाग्य आजमा रही थी। बुधवार की सुबह पचास किलो से थोड़ा अधिक वजन आने के कारण उसे नियमों के तहत फाइनल खेलने से मना कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी दिल तोड़ देने वाली इस घटना की पुष्टि तो की है लेकिन उसका बयान ही कई सवाल खड़े कर रहा है। संघ का कहना है कि रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक निकला। यह बयान इस बात की भी पुष्टि करता है कि विनेश के सपोर्ट स्टाफ (कोच, फिजियो, डाइटिशियन) को अहसास था कि वजन को लेकर विनेश पर संकट आ सकता है। फिर ऐसा जोखिम क्यों उठाया गया जिससे न केवल विनेश बल्कि पूरे मुल्क को शर्मसार होना पड़ा। इसमें दो राय नहीं कि विनेश एक बेहतरीन और देश की सबसे कामयाब महिला पहलवानों में से है। वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में उसने 48 किलोग्राम वर्ग की फ्रीस्टाइल श्रेणी में भाग्य आजमाया था। टोक्यो ओलंपिक में विनेश 53 किलो कैटेगरी में उतरी और अब इस बार फिर श्रेणी बदल ली। सेमीफाइनल में क्यूबा की गुलजान लोपेजी पर जीत हासिल कर उसने ओलंपिक की महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का गौरव भी हासिल कर लिया था। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती नियमों के अनुसार, मुकाबलों की प्रत्येक सुबह संबंधित भार श्रेणी के पहलवानों का वजन लिया जाता है। विनेश का मंगलवार को वजन सही पाया गया तभी वह सभी मुकाबलों में उतरी और जीती। सेमी-फाइनल रात को था। मुकाबले के बाद उसकी डाइट की जिम्मेदारी तो सपोर्ट स्टाफ की ही मानी जाती है।

विनेश के सपोर्ट स्टाफ को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लापरवाही पाए जाने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए कि विनेश के भार वर्ग में बार-बार बदलाव की वजह क्या है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी खिलाड़ी और देश को ऐसा दिन दोबारा न देखना पड़े।

भारत छोड़ो आंदोलन : वर्षगांठ पर विशेष

जिसने हिला कर रख दी थी ब्रिटिश राज की नींव

डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा
सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार
@patrika.com

भारत छोड़ो आंदोलन को स्वंतत्रता के लिए चले लंबे संघर्ष की कड़ी के रूप में देखा जाता है। इस आंदोलन के पूर्व देश ने अनेक आंदोलन देखे। सबसे पहले के प्रमुख आंदोलन की बात की जाए तो जंगल महल आंदोलन को अवश्य याद करना होगा जो 1857 की क्रांति से पूर्व किया गया। यह 1771 से 1809 तक चला। जल, जंगल और जमीन के लिए किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया था।

1857 की क्रांति से पूर्व देखा जाए तो जंगल महल आंदोलन एवं संबलपुर विद्रोह को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय ने किया था। वह अंग्रेजों को लगातार परेशान करते रहे। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। इसके कुछ समय बाद देश में आंदोलनों की एक शृंखला प्रारम्भ हुई। आजादी की इस लड़ाई को हिंसक एवं अहिंसक आंदोलनों द्वारा लड़ा गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारतीय राजनीति के पटल पर महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद आजादी के लिए किए जा रहे संघर्षों की दिशा बदली। इसके पूर्व जहां शक्ति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना लक्ष्य था किन्तु अब अहिंसक एवं सविनय आंदोलनों का रास्ता अपनाया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने अपना सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बम्बई अधिवेशन में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा दिया गया।

भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के पश्चात गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर में युवा कार्यकर्ता इस आंदोलन को चलाते रहे। सभाएं चलती रहीं। जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। सतारा, मेदिनीपुर इत्यादि स्थानों पर स्वतंत्र सरकारें स्थापित हुईं। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने सम्पूर्ण आंदोलन को विशाल स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुम्बई में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया किन्तु शीघ्र ही 19 अगस्त 1942 को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक एवं सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को संचालित किया। इन नेताओं ने आगे चलकर भारतीय राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन का एक पहलू यह भी है कि इसमें महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता जैसी महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित किया और वह लगातार आंदोलनकारियों को संदेश देती रहती थीं। यद्यपि इस आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश शासन द्वारा भी सख्त रुख अपनाया गया। फिर भी यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त रूप से एक वर्ष तक चलता रहा। इस आंदोलन की बहुत चर्चा होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि यह भारत के उन आंदोलनों में से एक था जो देश की आजादी की नींव बनें।

भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे समय किया गया, जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था और अंग्रेजों की जड़ें काफी कमजोर हो चुकी थीं। साथ ही आजाद हिंद फौज का दबाव और नौसेना विद्रोह से अंग्रेजों को यह आभास हो गया कि इस देश में अब ज्यादा दिन नहीं रुका जा सकता। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दी थी। इससे जनता काफी उत्साहित हुई और समानांतर सरकारों के गठन से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। यह पहला आंदोलन था जिसमें जनता की सम्प्रभुता स्वीकार करने की बात की गई। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, फिर भी अपार जन समूह इस आंदोलन से जुड़ा। आगे चलकर 1947 में देश आजाद हुआ जिनकी नींव में थे भारत छोड़ो आंदोलन जैसे संघर्ष।

डिजिटल अर्थव्यवस्था : विशेषज्ञों की टीम आवश्यक

कौशल विकास कार्यक्रमों से पाटें डिजिटल विभाजन

प्रो. डी.पी. शर्मा
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़े डिजिटल डिप्लोमेट एवं सूचना तकनीकी विशेषज्ञ
@patrika.com

हाल ही पेश किया गया केंद्रीय बजट यानी देश का एक वार्षिक आर्थिक खाका, भारत की क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी को प्रदर्शित करता है। इसमें डिजिटलीकरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सही दिशा में कदम उठाया गया है। हालांकि, स्थायी और दीर्घकालिक नौकरी के अवसर पैदा करने में इन उपायों की प्रभावशीलता पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि कहीं यह सारी कवायद सिर्फ कागजी घोड़े और घोषणाओं के कर्मकांड तक सीमित तो नहीं है?

'डिजिटल इंडिया' सरकार के आर्थिक एजेंडे की आधारशिला रहा है। बजट में इस पहल पर लगातार जोर दिया जाना सराहनीय है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, कौशल और अनुसंधान में निवेश महत्त्वपूर्ण है। सरकारी समर्थन से प्रेरित बढ़ता स्टार्टअप इको सिस्टम भारत की डिजिटल शक्ति का प्रमाण है। हालांकि, इस डिजिटल उछाल को व्यापक रोजगार में बदलने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों को एक्सपोर्ट एवं घरेलू उत्पादों पर और अधिक सहूलियतें दी जाएं ताकि वे अत्यधिक रोजगार सृजन कर सकें। जहां डिजिटल अर्थव्यवस्था नई नौकरियां पैदा कर रही है, वहीं यह पारंपरिक क्षेत्र की नौकरियां को भी बाधित कर रही है। रोबोटाइजेशन, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार को स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन से प्रभावित श्रमिकों के लिए कोई ठोस योजना बनानी चाहिए। कौशल विकास के कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और एक कुशल कार्यबल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, मगर सिर्फ वैज्ञानिक सोच के साथ। इसके अलावा सरकार को देश भर में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल उद्यमिता के लिए एक मजबूत और बेहतर वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

रोजगार सृजन योजनाओं के लिए बजट का आवंटन एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास पहल को उद्योग की मांगों के साथ और अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां भारत की अधिकांश आबादी रहती है, स्थायी आजीविका के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए गांवों तक एक्सपोर्ट- इंपोर्ट पॉलिसी पहुंचाने के प्रयास होने चाहिए। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

सरकार का डिजिटल इंडिया का विजन सराहनीय है। हालांकि, सच्ची परीक्षा एक सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्षमता में निहित है, जहां डिजिटलीकरण के लाभ समान रूप से साझा किए जाते हैं। कौशल, उद्यमिता और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपनी डिजिटल क्षमता को रोजगार और समृद्धि के एक शक्तिशाली इंजन में बदल सकता है। मगर इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनानी होगी। देश की ब्यूरोक्रेसी एवं टेक्नोक्रेसी दोनों को भूमंडलीकृत अवधारणाओं के मॉडल पर सोचना होगा।

बजट तो मात्र एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करती है। जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, तकनीकी प्रगति और मानव विकास के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है। इसके लिए एक भूमंडलीकृत मॉडल और उसको लागू करने वाले विशेषज्ञों की टीम की जरूरत होगी जिसे भारत सरकार को ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी से मुक्त रखना होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

फैक्ट फ्रंट

चमकीले रंगों और बड़ी चोंच वाले टूकैन

- **आहार** : सर्वाहारी
- **जीवनकाल** : 20 वर्ष तक
- **वजन** : 850 ग्राम तक

मूलतः अमरीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले टूकैन बड़ी और चमकीले रंगों वाली चोंच के कारण पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। चोंच, शरीर के आकार की तुलना में असामान्य रूप से बड़ी होती है। टूकैन परिवार में 50 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 11 वैश्विक रूप से खतरे में हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। टूकैन ज्यादातर फल खाते हैं, पर कभी-कभी अवसर मिलने पर कीड़े, छोटे पक्षी और छिपकलियां भी खा लेते हैं। इन्हें बीज फैलाने में बहुत मददगार माना जाता है।

प्रसंगवश

सेहत से खिलवाड़ के प्रयासों के खिलाफ सख्ती की जरूरत

कीटनाशकों के इस्तेमाल से खाने में जहर मिल जाता है। यह सेहत के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है

फलों पर लगे स्टीकर व इनके कोड का मतलब न तो फल विक्रेताओं को पता होता और न ही खरीदारों को। उधर केमिकल से उगाए और पकाए गए फल सेहत को खतरा बनते जा रहे हैं। हाल ही नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने स्टीकर लगे फलों को लेकर चेतावनी दी है कि स्टीकर लगे फल सेहत बिगाड़ सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी एडवाइजरी जारी कर चुका है कि व्यापारी फलों को अच्छा दिखाने के लिए स्टीकरों का प्रयोग न करें। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद फलों पर स्टीकरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। होना तो यह चाहिए कि यदि स्टीकर लगाना आवश्यक ही हो तो इन्हें फलों के बजाय इनकी पैकिंग बॉक्स पर लगाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीकर के पीछे लगा गोंद टॉक्सिक हो सकता है जो कैंसर जैसी कई घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में साफ प्रावधान है कि फल और सब्जियों में मोम, खनिज तेल या फिर रंगों की पॉलिश नहीं की जा सकती। नियम-कायदों की अनदेखी कर फल-सब्जी मंडी के गोदामों में फलों को घातक केमिकल व गैस से पकाया जाना आम है। आम, केला समेत अन्य फलों को पकाने के लिए इनके बीच केमिकल की पुड़िया रखी जा रही हैं। कहा जाता है कि चीन में निर्मित केमिकल की इन पुड़ियाओं पर बहुत ही बारीक अक्षरों में चेतावनी भी लिखी होती है कि इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए घातक है। खास तौर से इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। दरअसल, प्राकृतिक रूप से फल को पकने में काफी समय लगता है। ऐसे में रसायनों का इस्तेमाल कर फल पकाए जा रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इनमें इस्तेमाल कई रसायन शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों से पहले ही हमारे खाने में जहर मिल रहा है। फलों को पकाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल तो और भी खतरनाक है। यह मिलावट सेहत के लिए खतरा बन गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और स्वास्थ्य महकमे के अन्य जिम्मेदारों को समय-समय निरीक्षण करना चाहिए। सेहत से खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रक्रिया को रोकने की जरूरत है। किसानों व व्यापारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी इनसे होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए। कार्रवाई भी ऐसी हो जो नजीर बने। - **आशीष जोशी**
ashish.joshi@epatrika.com

चंद्रमा @708जीबी

81,000 छवियों से सामने आई सबसे दिलचस्प टोपोग्राफी!

एस्ट्रोफोटोग्राफी *का शौक रखने वाले इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाले शहर एरबिल के निवासी दारया कावा मिर्जा ने हाल ही चंद्रमा की यह छवि अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की। एस्ट्रोफोटोग्राफी खगोलीय या आकाशीय पिंडों की तस्वीर लेने की कला है। मिर्जा ने इस छवि से जुड़े कुछ तथ्य भी साझा किए, जैसे कि शूटिंग में उन्हें चार दिन लगे, 81 हजार से अधिक छवियां जुटाईं, चंद्रमा के चार अलग-अलग चरणों और छाया क्षेत्र को मर्ज किया और कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल न करते हुए 708 जीबी के आकार की अपनी (मिर्जा की) अब तक की सबसे स्पष्ट चंद्रमा की टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति बताने वाली छवि तैयार की।*

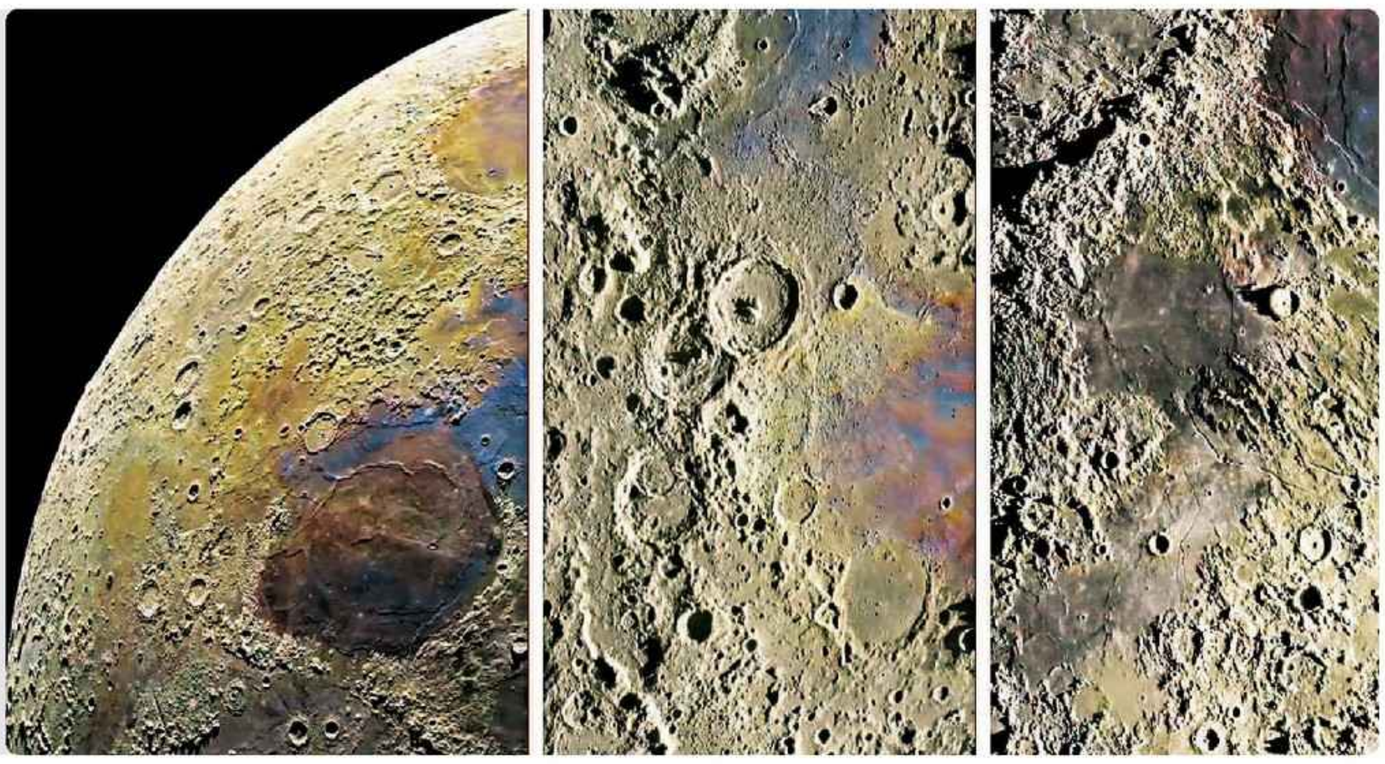

राजनीतिक दलों की कथनी और करनी का अंतर खत्म हो | अब आ गया है संकल्पों को उपलब्धियों में बदलने का वक्त

न बनें ऐसे कारण जिनसे डगमगाए युवाओं का भरोसा

सचिन पायलट
कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री
@patrika.com

बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बीच नौकरियों की चयन प्रक्रिया में सेंध उन युवाओं के लिए झटका है जो परीक्षाओं की तैयारियों में काफी समय खपा देते हैं। परीक्षा व भर्ती प्रक्रियाओं में शुचिता तय करने वाली संस्थाएं भी मजाक बन कर रह गई हैं।

लगभग प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी युवा मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने में रात-दिन एक कर देते हैं। निश्चित रूप से ये प्रयास उनके लिए फायदा देने वाले भी होते हैं। राजनीतिक दलों और राजनीतिक लोगों की भी सबसे ज्यादा कोशिश युवाओं का समर्थन हासिल करने की रहती है। इसके लिए युवाओं से वादे भी किए जाते हैं पर सत्ता पाने के बाद इनको भुला दिया जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी अब यह वक्त आ गया है जब वे अपने संकल्पों को उपलब्धियों में बदलें।

वर्ष 2014 का आम चुनाव आशाजनक संकेत लिए था जब कुल 66 फीसदी मतदान हुआ। मतदान करने वालों में भी 68 फीसदी युवा थे। तब तक यह माना जाता था कि कुल औसत मतदान की तुलना में युवा 3 से 5 फीसदी कम मतदान करते हैं। लेकिन दस साल बाद यानी इसी साल वर्ष 2024 के आम चुनावों में 1.8 करोड़ युवा पहली बार मतदाता बने। हालांकि चुनाव आयोग के अनुसार नए पात्र मतदाताओं में से बमुश्किल 40 प्रतिशत ने ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया। यह सचमुच चिंता का विषय है। अगर हम युवा वोटर्स को चुनावी प्रक्रियाओं में पूरी तरह हिस्सेदार नहीं बना सके तो यह हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए कैंसर की तरह साबित होगा। ऐसे में जरूरत कुछ तात्कालिक कदम उठाने की है - (अ) सत्ता और संगठन में मुख्यधारा के नेतृत्व वाले पदों पर युवाओं को लाना होगा, (ब) पेपर लीक होने से रोकने के लिए जो भी करना पड़े, वह करना होगा, (स) अवसाद के कारण छात्रों की आत्महत्या की प्रवृत्ति से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए पूरे समाज को योगदान देना होगा, और (द) नौकरियों के अवसर शीघ्र प्रदान करने होंगे, कहीं बहुत देर न हो जाए।

सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वह है - राजनीतिक ताने-बाने में युवा नेताओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। युवा प्रतिनिधित्व की असली कसौटी वह प्रतिनिधित्व है जो पार्टी के युवा या छात्र इकाई के बाहर युवाओं को मिल पाता है। युवाओं की भूमिका केवल वाहन बाइक रैली या बैनर, पोस्टर और नारे लगाने तक ही सीमित नहीं है। सही मायने में उनको ऐसा अवसर देना होगा जिसमें हम उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के साथ उनकी भावनाओं से भी सहमत हो सकें।

मेरी नजर में सबसे घृणित अपराध किसी व्यक्ति का पेपर लीक घटनाओं में लिप्त होना है। बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बीच नौकरियों की चयन प्रक्रिया में सेंध लगाना उन युवाओं के लिए झटका है जो इन परीक्षाओं की तैयारियों में अपना काफी समय खपा देते हैं। परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में शुचिता तय करने में लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं भी मजाक बन कर रह गई हैं। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिसूचित किया है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार सिर्फ सेवा प्रदाता के जरिए नहीं हो सकता। सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े सदस्यों की संलिप्तता के बिना ऐसा संभव नहीं। ऐसे मामलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत भी रहती है। ऐसे में नकल व पेपर लीक की रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से समूची प्रक्रिया सुरक्षित बनानी होगी। अपराधों की अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक करनी होगी। उन सबको कानून के दायरे में लाना चाहिए जो परीक्षाओं के आयोजन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आर्थिक दंड भी व्यापक होना चाहिए। यह सेवा प्रदाताओं के वार्षिक राजस्व का एक गुणक या परीक्षा के आवेदन शुल्क के एक अनुपात में हो सकता है। अनुचित साधनों के खिलाफ यह पहला कानून नहीं है। यह कानून भी इस बुराई से छुटकारा तब तक नहीं दिलाएगा जब तक कि समूचे सिस्टम में सार्थक बदलाव नहीं होगा।

भारत में आत्महत्याओं के आंकड़ों में चिंताजनक बिन्दु तो यह है कि इनमें 41 फीसदी युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी। वर्ष 2022 में 2,095 युवाओं ने परीक्षाओं में असफल होने के कारण आत्महत्या की। किसी भी रोजगार या शिक्षा का मूल्य जीवन से बढ़कर तो नहीं है। इस समस्या का एक झटके में कोई समाधान भी नहीं है। लेकिन सामाजिक आउटरीच शुरू कर घरों में डिनर टेबलों पर इस मुद्दे पर चर्चा को अहमियत दी जानी चाहिए। ऐसा माहौल उत्पन्न करना चाहिए जिससे उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ स्थायी विकल्प भी तैयार हों।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, देश के कुल बेरोजगारों में लगभग 83 प्रतिशत युवा हैं। वर्ष 2030 तक, भारत को नए गैर-कृषि क्षेत्र में कम से कम 9 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करने की जरूरत है अगर 5.5 करोड़ अतिरिक्त महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो नौकरियों की मांग और बढ़ जाएगी।

पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक यह संदर्भ न हो कि यह ढांचा रोजगार पैदा करने वाला है या बेरोजगारी में इजाफा करने वाला। सरकार वाकई में इस मुद्दे का समाधान करना चाहती है तो उसे प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। रोजगार सृजन के मुद्दे पर विफलता से हमारी राजनीतिक और गवर्नेंस प्रणालियों में युवाओं का भरोसा तो डगमगाता ही है, हमारे सामाजिक सरोकार सुनिश्चित करने के उपायों की सफलता भी खतरे में पड़ जाती है।

आपकी बात

जनता में बढ़ा रोष

शेख हसीना पर विपक्ष का दमन और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगे। अन्य कारणों से भी बांग्लादेश की जनता में रोष बढ़ा और उनको देश छोड़ना पड़ा। **-अनुराग गिरि,** रावतसर, हनुमानगढ़

आज का सवाल

क्या विनेश फोगाट किसी षड्यंत्र का शिकार हुई हैं?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'क्या बांग्लादेश का सियासी तूफान विपक्ष के दमन का नतीजा है?' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/1w85q

चिंतन

विनेश आप चैंपियन हो पूरे देश का दिल जीता

पूरा देश इंतजार में था, जश्न की तैयारियां हो रही थी। बुधवार की सुबह भारत के लिए खास थी। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने विनेश फोगाट की जीत पर जश्न मनाने की तैयारी न की हो। हो भी क्यों ना, भारत की लाडली बेटी ने रात को इतिहास जो रचा था। वो पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली पहलवान थीं। हर किसी को गोल्ड की उम्मीद थी। हर देशवासी उसे फाइटर बता रहा था। सोशल मीडिया पर वह छाई हुई थीं, लेकिन अचानक एक खबर आई और झटके में वक्त और जज्बात बदल गए। हर तरफ मातम का माहौल छा गया। मात्र सौ ग्राम वजन के लिए गोल्ड से मात्र एक कदम दूर विनेश ओलंपिक से डिसक्वालीफाई हो गई। जिसे गोल्ड मेडल इवेंट में उतरना था, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डिसक्वालीफाई होने की खबर सुनकर विनेश बेहोश हो गई। विनेश अखाड़े में ही नहीं असल जिंदगी में भी फाइटर है। छोटी उम्र में पिता को खोने के बाद जिस बहादुरी से उसने खुद को खड़ा किया और ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची, ऐसी मिसाल कम ही हैं। गोल्ड न मिलने से हर देशवासी निराश है, लेकिन जरा खुद को विनेश मानकर कल्पना करें कि वो किस दौर से गुजर रही होंगी। रातभर वजन कम करने की कोशिश में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। उनकी निराशा को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। यह वो वक्त है जब उन्हें सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर खेल प्रेमी ने देश की बेटी को भावनात्मक सपोर्ट किया। हर किसी ने दिलासा दी है कि टूट न जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश को कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। देखा जाए तो ओलंपिक में फाइनल तक का सफर तय करना भारत की इस लाडली के लिए आसान नहीं था। उसे प्री-क्वार्टर में ही 4 बार की विश्व चैंपियन और पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट का सामना करना पड़ा। चुनौतीपूर्ण मुकाबले में विनेश ने सुसाकी को 3-2 से हराया। सुसाकी ने अपने करियर के सभी 95 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जीते थे, लेकिन, विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैंतरे से मात दी। क्वार्टर फाइनल में विनेश ने कड़ी टक्कर में यूक्रेन की लिवाच को 7-5 से हराया और सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मारी। सेमीफाइनल मुकाबले में विनेश के खिलाफ क्यूबा की रेसलर गुजमन लोपेज थी। सिर्फ 6 मिनट तक चलने वाले रेसलिंग मैच में विनेश ने 5-0 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई। विनेश की फॉर्म देखकर ये साफ था कि वो गोल्ड की प्रबल दावेदार हैं लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलने के कारण वो इस ऐतिहासिक जीत से चूक गईं। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। कहा जाता है कि वक्त हर दर्द को भर देता है। विनेश फोगाट फाइटर है, वो भी जल्द ही दर्द से उभर जाएगी और एक बार फिर अखाड़े में उतरेगी। यह कोई अंतिम मुकाबला नहीं, फिर ओलंपिक होगा, विनेश फिर दंगल में उतरेगी। हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि वह पिछले मौकों की तरह इसे भी पीछे छोड़कर फाइटर की तरह वापसी करें और अगले ओलंपिक में इस अधूरे सपने को पूरा करें। भारत के एक सौ चालीस करोड़ देशवासी उसके साथ हैं। उसका दर्द हर देशवासी का दर्द है। हम सब इस मौके पर विनेश के साथ हैं, वो गोल्ड नहीं जीत पाई तो क्या हुआ। विनेश आपने पूरे देश का दिल जीता है। वो किसी गोल्ड से कम नहीं, शाबाश विनेश फोगाट।

शेख हसीना का तख्ता पलट असामान्य

आस-पड़ोस
अवधेश कुमार

इस आंदोलन का सच समझने के लिए सबसे पहले शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद के दृश्यों पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। जीत का ऐसा जश्न मनाया जा रहा था मानो बांग्लादेश को दूसरी आजादी मिली है। फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही थी तो दूसरी ओर शेख मुजीब संग्रहालय में आग लगा दी गई। पूरे आंदोलन में 300 लोगों के मारे जाने के विरुद्ध गुस्सा समझ में आ सकता है पर पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्ति दिलाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान को दुश्मन या खलनायक मानकर व्यवहार करने वाले कौन हो सकते हैं? गोली चलाने का आदेश शेख हसीना ने नहीं दिया।

बांग्लादेश का संपूर्ण घटनाक्रम भयभीत करने वाला है। हमने पूरा अराजकता का वातावरण देखा जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री आवास से लेकर कार्यालय संसद भवन, सचिवालय सब पर हुआ कब्जा। लूट और अराजकता का आलम बांग्लादेश की दुर्दशा बताने के लिए पर्याप्त था। देश में अत्यंत संघर्ष के बाद संसदीय लोकतंत्र पटरी पर स्थापित होता लग रहा था। वहां कुछ घंटे के अंदर ऐसा लगा है जैसे सब कुछ पुरानी अवस्था में जा रहा हो। बांग्लादेश आगे किस दिशा में मुड़ेगा, अभी कहना कठिन है। किंतु आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग में शेख हसीना की प्रधानमंत्री कुर्सी चली जाएगी और उन्हें विवश होकर देश छोड़ना पड़ेगा इसकी कल्पना एक दिन पहले तक नहीं की गई थी।

प्रश्न है कि ऐसा हुआ क्यों? आरक्षण विरोधी आंदोलन सामान्य नहीं था। पहले 56% आरक्षण था, जिसमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए, 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों, 10% महिलाओं ,10% पिछड़े और एक प्रतिशत दिव्यांगों के लिए था। शेख हसीना ने ही 2018 में इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया। तो उनको आरक्षण का खलनायक नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने फिर इस आरक्षण को लागू किया और उसके विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। किंतु उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश में केवल 7% आरक्षण बचा जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 5% एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए दो प्रतिशत शामिल हैं। यानी 93% आरक्षण से बाहर था। शेख हसीना ने आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। ऐसा लगा भी कि आंदोलन अब समाप्त हो गया। अचानक आंदोलनकारी छात्र समूह ने शेख हसीना को सत्ता से हटाने का आह्वान करते हुए ढाका मार्च की घोषणा कर दी। मार्च हजारों की संख्या में हिंसा, तोड़फोड़ करते आगे बढ़ गया। कह सकते हैं कि जितनी संख्या में आंदोलन के दौरान लोग मारे गए, उसके विरुद्ध गुस्सा था। मामला यहां तक कैसे पहुंचा और एक दिन 4 अगस्त में 98 से ज्यादा लोग कैसे मारे गए? इस आंदोलन का सच समझने के लिए सबसे पहले शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद के दृश्यों पर गहराई से दृष्टि डालने की आवश्यकता है। जीत का ऐसा जश्न मनाया जा रहा था मानो बांग्लादेश को दूसरी आजादी मिली है। फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही थी तो दूसरी ओर शेख मुजीब संग्रहालय में आग लगा दी गई। पूरे आंदोलन में 300 लोगों के मारे जाने के विरुद्ध गुस्सा समझ में आ सकता है पर पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्ति दिलाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान को दुश्मन या खलनायक मानकर व्यवहार करने वाले कौन हो सकते हैं? गोली चलाने का आदेश शेख हसीना ने नहीं दिया। पुलिस ने शेख हसीना का साथ क्यों छोड़ा? पुलिस प्रमुख की ओर से कहा गया कि हम संभालने में सक्षम नहीं है। उसके बाद सेना को उतारा गया और सेना ने विशेष कुछ किया हो ऐसा लगा ही नहीं।

सेना प्रमुख वकार उज जमां ने ऐलान किया कि औनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, सारी जिम्मेवारी हमारे हाथों हैं, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। सेना प्रमुख ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जिसमें उनके

अनुसार अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति बनी। इसके बाद सेना के जवानों द्वारा विजय मुद्रा में फायर करने के वीडियो सामने आने लगे। जहां-जहां से शेख हसीना की तस्वीर हटती, वहां सुरक्षा में लगे जवान खुशियां मनाते। कुल मिलाकर पूरा तख्ता पलट सामान्य घटना नहीं है। इसे किसी लोकतांत्रिक आंदोलन की परिणति नहीं माना जा सकता। शेख हसीना 2009 से लगातार चुनाव जीतकर शासन में आतीं रहीं। वह अलोकप्रिय या तानाशाह होतीं तो मतदान में वोट कैसे मिलता। कहा जा रहा है कि 2024 संसदीय चुनाव का सभी पार्टियों ने बहिष्कार किया इसलिए लोगों के पास एक ही विकल्प था। आप पूरे आंदोलन में ध्यान से शामिल लोगों के बयान देखेंगे तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी।

हसीना पहली प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विश्व में देश की छवि बदली, शिक्षा में सुधार किया, विदेश नीति में बांग्लादेश को अमेरिका या चीन किसी के पाले में जाने से बचाया, सेना को न निष्प्रभावी किया न ज्यादा प्रभावी होने दिया, कट्टरपंथियों, इस्लामवादियों, जिहादी एवं अन्य उग्रवादी समूहों को नियंत्रित कर बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बनाए रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की, पाकिस्तान की साजिशों को सफल नहीं होने दिया तथा अमेरिका के दबाव को भी अस्वीकार किया। ये नीतियां एक साथ देश के अंदर और बाहर उनके विरोधियों - दुश्मनों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। उनके विरुद्ध पांच तरह की शक्तियां सक्रिय थीं।

पाकिस्तान तथा देश के अंदर कट्टरपंथी जिहादी समूह, वैश्विक वाम इकोसिस्टम, अमेरिका और चीन। पाकिस्तान, जिसके अंदर टीस बनी हुई है कि शेख हसीना के पिता ने विभाजन कराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र किया। हमेशा पाकिस्तान वहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी, जमाते इस्लामी, हिफाजत ए इस्लाम आदि संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश को अस्थिर करने तथा शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद उन्हें लगातार हटाने की कोशिशें करता है।

पूरे आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा सक्रियता, वक्तव्य और बहस पाकिस्तान से सामने आये। बीएनपी, जमात ए इस्लामी, इसका छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर आदि आंदोलन की आड़ में पूरे देश में हिंसा व आगजनी कर रहे थे। उससे साफ दिखता था कि भारी संख्या में प्रशिक्षित लोग लगे हैं। पाकिस्तान ने इन सबको प्रशिक्षित किया और समय पर इन्होंने हिंसा, आगजनी से अपना और पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा करने में भूमिका निभाई। शेख हसीना का यह बयान कि आंदोलन के नाम पर आतंकवादी कट्टरपंथी तत्व हिंसा कर रहे हैं गलत नहीं था। वहीं, अमेरिका हसीना से कितना परेशान था, इसका अनुमान इसी से लगाइए कि उनकी पार्टी अवामी लीग के सदस्यों के लिए उसने वीजा पर रोक लगा दी तथा मांग की कि हसीना त्यागपत्र दें और चुनाव के पहले अंतरिम सरकार बनाई जाए। चीन की समस्या थी कि शेख हसीना अन्य देशों की तरह उसके आर्थिक चंगुल में नहीं फंसी। जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपनी बलि चढ़ा कर पाकिस्तान की तानाशाही , निर्दयता से बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई, उनके बच्चों को आरक्षण देने या उन्हें सम्मान देने का विरोध कौन कर सकता है?

आप देखेंगे कि पूरे आंदोलन के दौरान अवामी लीग के सदस्यों पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, यहां तक कि चुन-चुन कर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अगर इसे कोई सरकार के विरुद्ध स्वाभाविक असंतोष की परिणति मानता है तो उसकी बुद्धि पर तरस आएगा। इस समय अमेरिका भले खुश हो, लेकिन आने वाले समय में इस्लामवादी कट्टरपंथी तत्वों तथा पाकिस्तान की भूमिका जबरदस्त चुनौती बनेगी। भारत के लिए नए सिरे से चुनौती खड़ी हुई है जिसका सामना करने के लिए हमें लंबी तैयारी करनी पड़ेगी।

(लेखक विदेशी मामलों के जानकार हैं,, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

आनंद

डॉ. टीना चावला

ध्यान संगीत के जरिए पाएं तनावों से मुक्ति

अगर आपकी संगीत (म्यूजिक) और ध्यान (मेडिटेशन) दोनों में रुचि है और सुकून चाहते हैं तो ध्यान संगीत (म्यूजिक मेडिटेशन) आपके लिए है। आनंद महसूस करने का शानदार तरीका है ध्यान संगीत। जीवन में अनेक दुख हैं, संघर्ष है, भागमभाग है, अशांति है, बोरियत है, चिड़चिड़ापन है। मन में बहुत शोर है, कोलाहल है, अस्थिरता है। इन सबके चलते तनाव बढ़ रहे हैं, मन का दर्द बढ़ रहा है, मानसिक उदासी बढ़ रही है। सुख, शांति, संतोष जैसे शब्दों का अस्तित्व हमारे जीवन में कमतर हो रहा है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तकलीफ में है। कोई अपने रिश्ते से खुश नहीं है, कोई संतान से या कोई माता-पिता से प्रसन्न नहीं है, कोई परिवार के हालात से तो कोई आर्थिक तंगी से तनाव में है। कोई किसी बीमारी के चलते दुखी है। चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, सब तनावग्रस्त नज़र आते हैं। इन दुख-तकलीफों व तनावों से मुक्ति के अनेक उपाय हैं, लेकिन आजकल सबसे अधिक ट्रेंड में है म्यूजिक मेडिटेशन।

ध्यान संगीत वह संगीत है जो ध्यान के अभ्यास में सहायता के लिए बजाया जाता है। इसे आधुनिक संगीतकार अपना रहे हैं, जो अपनी रचना की प्रक्रिया में ध्यान तकनीकों का उपयोग करते हैं। मधुर संगीत में ध्यान करना ही म्यूजिक मेडिटेशन है। भारत में संगीत का उद्भव सामवेद से है। भारतीय परंपरा में लगभग हर अवसर और मूड के लिए संगीत है। भगवान बुद्ध ने ध्यान की विपस्यना विधि को आगे बढ़ाया जिसमें मौन को प्रमुखता दी गई। मौन रह कर संगीत को मन के आंतरिक भाव से महसूस किया जा सकता है, इससे आनंदित हुआ जा सकता है। 20वीं सदी में आधुनिक ध्यान संगीत की शुरुआत तब हुई जब जॉन केज, स्टुअर्ट डेम्पस्टर, पॉलीन ओलिवरोस, टेरी रिले, ला मोंटे यंग और लॉरेंस बॉल जैसे संगीतकारों ने ध्यान तकनीकों व अवधारणाओं और संगीत को मिलाना शुरू किया। विशिष्ट कार्यों में कार्लहेन्ज़ स्टॉकहॉसन की इनोरी (1974), मंत्रा (1970), हाइमन (1966-67), स्टिममुंग (1968), और ऑस डेन सिबेन टेगेन (1968), और बेन जॉनस्टन शामिल हैं, जिनके विज़न एंड स्पेल्स (विजिल (1976) का एक एहसास) को प्रदर्शन से पहले ध्यान की अवधि की आवश्यकता होती है। आर. मुरे शेफ़र की क्लैरॉडियंस (स्वच्छ श्रवण) की अवधारणाएं और साथ ही उनकी द ट्यूनिंग ऑफ़ द वर्ल्ड (1977) स्टॉकहॉसन ने ऑस डेन सिबेन टैगेन को 'सहज संगीत' के रूप में वर्णित किया है। श्रीश्री रविशंकर कहते हैं, ध्यान जीवन को संगीतमय बना सकता है, और संगीत गहरी आंतरिक शांति ला सकता है। बंद आंखों से अच्छा मधुर संगीत सुनना एक आनंददायक अनुभव होता है। सुखदायक संगीत तनाव को दूर करने और मन को शांत करने में मदद करता है। म्यूजिक मेडिटेशन के लिए एक शांत स्थान पर बैठें, हेडफोन लगाएं, ध्यान संगीत चलाएं, अपनी आँखें बंद करें और एक शांतिपूर्ण आंतरिक यात्रा पर चलें। शोध से पता चलता है कि संगीत सुनने की गतिविधि व्यक्तियों को अपने परिवेश से अलग होने में सहायता करती है, अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। संगीत माइंडफुलनेस, विजुअलाइज़ेशन और चिंतन में सहायता कर सकता है। एनएचएस (नेशनल हेल्थ सर्वे) के अनुसार, ध्यान संगीत व्यक्तिगत जागरुकता बढ़ा सकते हैं और तनाव और चिंता दूर करने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से व्यक्तियों को अपने वर्तमान विचारों और कार्यों के प्रति अधिक चौकस रहने में मदद मिल सकती है। शोध से पता चलता है कि ध्यान संगीत ध्यान के अभ्यास के दौरान आत्मविश्वास में सुधार कर सकता है। आध्यात्मिक ध्यान नशे की लत से उबरने में मदद कर सकता है और अवसाद, चिंता व तनाव के लक्षणों को कम करके मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है।

हमें जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। हम स्वयं के लिए कुछ समय निकालें। इस समय में हम ध्यान अभ्यास कर सकते हैं, या अकेले बैठकर संगीत का आनंद ले सकते हैं। संगीत तनाव मुक्ति का एक अच्छा साधन है। आदिकाल से ही संगीत की शक्ति को पहचान कर संत जन संगीत का प्रयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए करते आए हैं। वर्तमान युग में तनाव को कम करने के लिए ध्यान अभ्यास पर अत्यधिक ज़ोर दिया जा रहा है। संगीत में अद्भुत शक्ति विद्यमान है। संगीत मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को शांति प्रदान करता है। इस तनावग्रस्त ज़िंदगी में ध्यान संगीत की शरण लेकर सरलता से तनाव मुक्त खुशहाल ज़िंदगी जी जा सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार, स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शिखंडी को याद आईं पूर्वजन्म की घटनाएं

संकलित
दर्शन

कौरवों-पांडवों के युद्ध की घोषणा के बीच महारथी शिखंडी को अपने पूर्वजन्म की घटनाएं याद आने लगीं। भीष्म का अपने अनुज विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशीराज की तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण। अंबा के यह बताने पर कि वह शाल्व नरेश को पहले ही अपना पति मान चुकी हैं, अंबा को शाल्व के पास भेज देना। लेकिन शाल्व ने अंबा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। तब, अपने नाना राजर्षि होत्रवाहन के कहने पर अंबा ने परशुराम से सहायता मांगी परंतु भीष्म ने अपने गुरु परशुराम की अंबा से विवाह करने की आज्ञा नहीं मानी। परशुराम की पराजय से आहत अंबा ने यमुना तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। फिर अगले जन्म में वत्सदेश के राजा की कन्या के रूप में जन्म लिया। तप के प्रभाव से उसे अपने पूर्वजन्म की घटना याद थी। इसलिए वह भीष्म से बदला लेने के लिए पुन तप करने लगी। उसके तप से प्रसन्न शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। महादेव ने कहा कि तुम्हारा अगला जन्म भी स्त्री के रूप में होगा। लेकिन युवा होने पर वह पुरुष बन जाएगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव को प्रसन्न करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। शिव ने कहा तुम्हारे घर कन्या का जन्म होगा, लेकिन बाद में वह पुरुष बन जाएगी। द्रुपद ने अपनी कन्या शिखंडी का लालन-पालन राजकुमारों की तरह किया। और उसका विवाह दशार्णराज हिरण्यवर्मा की कन्या से कर दिया। राजकुमारी को शिखंडी के स्त्री होने का पता चल गया। इधर अपमानित शिखंडी आत्महत्या के उद्देश्य से वन में चली गई।

ज्ञान प्राप्त करने मन को खाली करें

संकलित
प्रेरणा

एक बार व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन बदल सके। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो तो तुम आज से दस दिन बाद मेरे पास आना।' वह व्यक्ति दस दिन बाद फिर बुद्ध के पास आया और कहा, अब दस दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें।' बुद्ध का उत्तर फिर यही था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो दस दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि दस दिन बाद आना। आखिरकार उस व्यक्ति का धैर्य टूट गया। इस बार उसने बुद्ध से पूछा, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने उससे एक गिलास पानी लाने को कहा। वह व्यक्ति पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, 'जाओ, एक गिलास पानी और ले आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब बुद्ध ने कहा, 'पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो।' उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह गंदा हो गया। अब बुद्ध ने उससे कहा, 'पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल बाहर गिरेगा, बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पानी से भरा हुआ है, उसमें दूसरे गिलास का पानी कैसे आ सकता है? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बुरे ज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा।

अंतर्मन

आज की पाती

सड़क पर मवेशी

राजधानी की सड़कों पर मवेशी यातायात व्यवस्था को बदहाल कर रहे हैं। हर जगह मवेशी दिखाई देते हैं। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं भी इसी से हो रही हैं। इसके बाद भी शासन-प्रशासन ने सुध नहीं ली। कमल विहार से संतोषी नगर के रास्ते पर जगह-जगह मवेशियों का जमावड़ा जाम को बढ़ा रहा है। रिंग रोड तक आने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

-शाहीन बेगम, रायपुर

ट्रेंड

चैंपियनों में चैंपियन

विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं ! आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मजबूत होकर वापस आओ ! हम सब आपके पक्ष में हैं। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

माटी की बेटी

विनेश तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो। माटी की बेटी हो इसलिए ये मेडल भी माटी का है। बहुत हौसले से लड़ी हो। कल जब खेलने से पहले ओलंपिक ऑफिशियल्स ने आपका वजन लिया तो वजन एकदम परफेक्ट था। आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। **-बजरंग पुनिया, पहलवान**

राजनैतिक अखाड़ेबाज़ी

समाज के तौर पर हम सड़ गए हैं शायद। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर मवाद बह रहा है। या शायद ये सब ही था हमारे अंदर। बस अब बह निकलने के रास्ते दिखने लगे हैं। राजनैतिक अखाड़ेबाज़ी ने हमारी मनुष्यता, हमारी राष्ट्रीयता की सोच को कुंठित और घेराबंदी में क़ैद कर दिया है। **-कुमार विश्वास, हिन्दी कवि**

रीको अधिनियम

मैं किसी भी कंपनी को मुकदमा दायर करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं जिसका विज्ञापनदाताओं द्वारा व्यवस्थित रूप से बहिष्कार किया गया हो। रीको अधिनियम के माध्यम से आपराधिक दायित्व भी हो सकता है। **-एलन मस्क, उद्योगपति**

करंट अफेयर

शेख हसीना को अब इन दो मुस्लिम देशों से उम्मीद

बांग्लादेश की पूर्व पीएम को भारत आए करीब 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वह अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं तलाश पाई हैं। इसके चलते यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वह कब तक भारत में रहेंगी। पहले खबर थी कि वह ब्रिटेन जाने की तैयारी में हैं, लेकिन वहां से इनकार कर दिया गया। ब्रिटेन ने कूटनीतिक बयान देते हुए कहा कि शरण को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम कहता है कि व्यक्ति जहां भी सबसे पहले सुरक्षित पहुंचता है। वहीं उसे शरण मांगने का अधिकार है। इसके अलावा राजनीतिक शख्सियतों को शरण देने के किसी प्रावधान के होने से भी ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। इसके अलावा अमेरिका की ओर से भी उन्हें इनकार ही नसीब हुआ है। इस बीच चर्चा है कि शेख हसीना विकल्पों पर विचार कर रही हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना अब मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई जाने की कोशिश में हैं। यही नहीं फिनलैंड को भी वह विकल्प के तौर पर देख रही हैं। वह अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ भारत आई हैं और तब से यहीं बनी हुई हैं। उन्हें बुधवार को ही हिंडन एयरबेस से निकालकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। लेकिन अब तक साफ नहीं हो सका है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी और आगे क्या प्लान है।

ऑफ बीट

चंद्रमा को पानी कैसे मिला अब तक कोई निश्चित नहीं

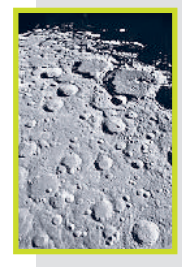

हम भाग्यशाली हैं कि हम पानी वाली दुनिया में रह रहे हैं। पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी से ढका हुआ है। युगों पहले, धूमकेतु – जो मूल रूप से जमे हुए, गंदे बर्फ के गोले होते हैं – अपने धूमकेतु पानी को छोड़कर, पृथ्वी से टकराए थे। यह उन तरीकों में से एक है जिनसे पृथ्वी ने अपने महासागरों को विकसित किया; शायद इसी तरह चंद्रमा को भी अपना कुछ पानी मिला। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर प्राचीन ज्वालामुखी अरबों साल पहले फूटने पर जलवाष्प छोड़ते थे। आख़िरकार, वह वाष्प पाले के रूप में सतह पर उतरा। समय के साथ, उस पाले की परतें जमा हो गईं, विशेषकर ध्रुवों पर; इसका अधिकांश भाग बर्फ के रूप में चंद्रमा के गड्ढों के अंदर पहुंच गया होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने का पानी पानी भारी होता है। इसे अंतरिक्ष यान से चंद्रमा तक पहुंचाना महंगा होगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा पर पहले से मौजूद पानी का उपयोग करने का तरीका खोजना अधिक सार्थक है। लेकिन चंद्रमा का पानी वैसे भी पीने योग्य नहीं है; इसमें चंद्रमा की मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़े और संभवत: अन्य अणु भी मिश्रित होंगे। चंद्रमा की कॉलोनियों में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अपने द्वारा एकत्र किए गए पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता होगी।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।